राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

धौनी के चयन को लेकर असमंजस में बीसीसीआइ

>> 14

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 39

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 19 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

वेब सीरीज पर सेंसरशिप का फैसला सबके साथ चर्चा के बाद ही : जावड़ेकर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली के सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में गुरुवार को जागरण फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वेब सीरीज को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। कहा जाता है कि इस पर तो सेंसरशिप है ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि फिल्म एक लोकतांत्रिक माध्यम है और यही इसकी ताकत है। इसकी सेंसरशिप पर कोई भी निर्णय सबसे चर्चा करके ही लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विदेशी फिल्मकारों को देश में शूटिंग के लिए एक ही अनुमति लेनी होगी, जो उन्हें एक सप्ताह में मिल जाएगी। उद्घाटन समारोह में फिल्म अभिनेता अनिल कपूर, मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशिका फराह खान, निर्देशक केतन मेहता, ताइपे के राजदूत चुंग वांग तिन, ईरान के उप राजदूत मसूद रेजवेनियन, दैनिक जागरण समूह के

चेयरमैन व प्रबंध निदेशक महेंद्र मोहन गुप्त, सीईओ और प्रधान संपादक संजय गुप्त, डीएस गुप के निदेशक अतुल जैन समेत अन्य प्रसिद्ध शख्सियतें मौजूद थीं।

रजनीगंधा के सहयोग से 18 से 21 जुलाई तक आयोजित होने जा रहे जागरण फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह की शुरुआत दैनिक जागरण के संस्थापक स्वर्गीय पूर्ण चंद्र गुप्त व पूर्व प्रधान संपादक स्वर्गीय नरेंद्र मोहन गुप्त की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर और दीप जलाकर की गई। जावड़ेकर ने दस साल तक फिल्म फेस्टिवल के भव्य आयोजन के लिए जागरण को बधाई दी। 18 शहरों में दिखाई जाने वाली ये फिल्में दर्शकों से सीधा संवाद करती हैं। सिनेमा जिंदगी का अहम हिस्सा है। यह समाज को जोड़ता है। इस फिल्म फेस्टिवल में हर साल सिनेमा के नए आयाम दिखें, इसकी कामना है। उन्होंने कहा कि परसों मेरे पास कुछ दृष्टिबाधित लोग आए थे। उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर दिखाया जो फिल्मों में दो संवाद के बीच के स्थान में क्या घटित हो रहा है, उसे भी सुनाता है। मैं फिल्मकारों से अनुरोध करूंगा कि वे इसे प्रोत्साहित करें।

केतन मेहता ने कहा कि सबसे ज्यादा फिल्में बॉलीवुड में बनने के बावजूद एक कमी महसूस की जा रही थी, जिसे जागरण फिल्म फेस्टिवल ने पूरा किया। जागरण ने एक अनोखी सिनेमा संस्कृति तैयार की है। कार्यक्रम में संजय गुप्त ने कहा कि सिनेमा सोसायटी की जरूरत को दिखा रहा है।

(विशेष सामग्री पेज-10,11 पर)

नई दिल्ली स्थित सिरीफोर्ट सभागार में 10 वें जागरण फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर(मध्य में), फिल्म अभिनेता अनिल कपूर, फिल्म निर्देशिका व कोरियोग्राफर फराह खान, फिल्म निर्माता शोबू यरलागड्डा व केतन मेहता। साथ में हैं दैनिक जागरण के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक महेंद्र मोहन गुप्त (दाएं से छठे), जागरण समूह के प्रधान संपादक व सीईओ संजय गुप्त (बाएं से तीसरे) एवं डीएस ग्रुप के निदेशक अतुल जैन और अन्य अतिथि। जागरण

सरोकार

अब धरा की प्यास बुझा रहे सालों से सूखे पड़े हैंडपंप

श्योपुर : मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के आदिवासी विकास खंड कराहल के चार

गांवों के 11 सूखे हैंडपंप और दो कुएं जमीन के अंदर बारिश और गांव से उपयोग के बाद निकलने वाले दूषित पानी को फिल्टर करके जमीन के अंदर पहुंचा रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि क्षेत्र का भूजल स्तर लौट आया।

जागरण विशेष

वादी-ए-कश्मीर में महकने लगे आजीविका के फूल

अल्मोड़ा : उत्तराखंड के गोविंद बल्लभ पंत संस्थान की राष्ट्रीय हिमालयी मिशन की

परियोजना ने कश्मीर के लोगों के चेहरों पर मुस्कान खिला दी है। दो साल से जारी प्रयास सफल होते दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर में फूलों की खेती अब आजीविका का आधार बन रही है। **(पेज-13)**

न्यूज गैलरी

सिटी न्यूज ▶ पृष्ठ 2

अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले पाएंगे मालिकाना हक

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया है कि जल्द ही उन्हें अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। सभी कॉलोनियों में रजिस्ट्री भी शुरू होगी। उन्होंने कहा, दिल्ली का विकास तभी हो सकता है। जब केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम करे।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

बजट प्रस्तावों से होगा ईज ऑफ लिविंग में और सुधार

नई दिल्ली : टैक्स प्रस्तावों में कोई बदलाव नहीं करते हुए सरकार ने कहा है कि बजट प्रस्ताव देश में ईज ऑफ लिविंग की स्थिति में और सुधार लानेके उद्देश्य से किए गए हैं। वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि इनसे देश में मेक इन इंडिया और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

हंगामे के कारण अटका शक्ति परीक्षण

कर्नाटक का नाटक ▶ सदन स्थगित, राज्यपाल ने सीएम को आज दोपहर 1.30 बजे तक का दिया वक्त

विरोध में भाजपा विधायक रातभर सदन में धरने पर बैठे

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में एक पखवाड़े से चल रहा सियासी नाटक गुरुवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर बहस के साथ चरम पर पहुंच गया। विधानसभा के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप और हंगामे के कारण शक्ति परीक्षण पर मतदान टालना पड़ा। विरोधस्वरूप भाजपा विधायक रातभर सदन में धरने पर बैठे रहे। राज्यपाल वजूभाई वाला ने अब एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जदएस गठबंधन सरकार को बहुमत साबित करने के लिए शुक्रवार दोपहर 1.30 बजे तक का समय दिया है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि कांग्रेस-जदएस के 15 विधायकों के इस्तीफे, दो निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने और पहली नजर में अन्य परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री बहुमत या सदन का विश्वास खो चुके हैं। उन्होंने आगे लिखा, 'राज्य का प्रमुख होने के नाते इस तथ्य के मद्देनजर मैंने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया कि सदन बुलाया गया है और विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। मुझे बताया गया है कि विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए बुलाए गए सदन की कार्यवाही रोक दी गई और बाद में बिना किसी निर्णय पर पहुंचे स्थगित कर दी गई। भारतीय संविधान द्वारा संचालित लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह नहीं चल सकता।' इससे पहले

बेंगलुरु में गुरुवार को विधानसभा में विश्वास मत के दौरान अपनी कैबिनेट के सदस्यों से चर्चा करते कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी। प्रेट्र

गुरुवार सुबह लंबी जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने विधानसभा में एक पंक्ति का विश्वास प्रस्ताव 'यह सदन 14 माह पुरानी मेरी सरकार में विश्वास प्रकट करता है' पेश किया। इसके बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और विपक्षी भाजपा को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, चूंकि बागी विधायकों ने साझा सरकार को लेकर देशभर में शंकाएं प्रकट की हैं इसलिए सच्चाई पेश करना जरूरी है। पूरा देश कर्नाटक के इस घटनाक्रम को देख रहा है। विधायकों ने इस्तीफे में सिर्फ एक लाइन लिखी है कि उनका इस्तीफा वास्तविक और स्वैच्छिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि राज्य भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।

कुमारस्वामी बोले, जल्दी में हैं येद्दयुरप्पा : कुमारस्वामी के भाषण के बीच ही विपक्ष के नेता बीएस येद्दयुरप्पा खड़े हुए और स्पीकर से कहा कि विश्वास मत की प्रक्रिया एक दिन में ही पूरी होनी चाहिए। इस पर कुमारस्वामी ने तंज किया, 'विपक्ष के नेता जल्दी में दिखाई देते हैं।' वहीं, येद्दयुरप्पा ने कहा कि कुमारस्वामी सरकार विश्वास खो चुकी है।

20 विधायक रहे गैरहाजिर : शुक्रवार को गठबंधन के 15 बागी विधायक, समर्थक दल बसपा का एक विधायक और दोनों निर्दलीय विधायकों समेत 20 विधायक सदन से अनुपस्थित रहे। हालांकि कांग्रेस को उस वक्त आंशिक राहत मिली जब 15 बागियों के इस्तीफों से पहले ही पार्टी छोड़ चुके विधायक रामलिंगा रेड्डी उसके खेमे में लौट आए।

कांग्रेस का एक विधायक बीमार : कांग्रेस को एक झटका तब लगा जब उसके विधायक श्रीमंत पाटिल सदन में दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस ने पाटिल के अपहरण का आरोप लगाया। बाद में पता चला कि सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें मुंबई में भर्ती कराया गया है। उन्होंने वीडियो संदेश में अपहरण की बात को गलत बताया। बसपा विधायक महेश भी सदन में नहीं पहुंचे। **(पेज-4 भी देखें)**

सरकार के खिलाफ आंकड़े

- चूंकि जदएस गठबंधन के 15 विधायक इस्तीफे दे चुके हैं और एक बीमार हो गए हैं इसलिए उनकी सदन में ताकत घटकर 101 रह गई है।
- 224 सदस्यीय विधानसभा में मौजूद विधायकों की संख्या 16 कम होकर 208 रह जाएगी।
- दो निर्दलीय विधायकों ने मंत्री पद छोड़कर भाजपा को समर्थन का एलान किया है।
- ऐसे में वोटिंग होने पर 208 सदस्य यदि मतदान करेंगे तो बहुमत 105 पर मिलेगा।
- चूंकि कांग्रेस-जदएस के 101 सदस्य रह गए हैं और भाजपा नीत विपक्ष के 105 और दो निर्दलीय विधायक मिलाकर 107 हो गए हैं, इसलिए विश्वास मत पर सरकार का गिरना तय है।

जाधव पर पाक को मानना ही होगा फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विदेश मंत्री ने संसद में कहा, जाधव को रिहा करे और वापस भेजे पाक

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) में कुलभूषण जाधव मामले पर मिली जीत के बाद भारत ने पाक पर दबाव बनाने की रणनीति अख्तियार कर ली है। यह जानते हुए कि पाकिस्तान सरकार अपनी आवाम को आइसीजे के फैसले के बारे में गलत सूचना दे रही है, भारत ने दो टूक कहा है कि यह फैसला अंतिम है और पूरी तरह से बाध्यकारी है। इस बारे में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। जयशंकर ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह जाधव को रिहा करे और उन्हें वापस भारत भेजे।

जयशंकर ने कहा, जाधव न सिर्फ पाक की अवैध हिरासत में हैं बल्कि वहां की सैन्य अदालत ने उन्हें मनगढ़ंत आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। आइसीजे के फैसले के बाद पाक जाधव को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराने और उन्हें काउंसलर सुविधा प्रदान

कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में सदस्यों को जानकारी दी। प्रेट्र

करने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने यह इच्छा जताई है कि पाक में जाधव को मिली सजा की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए और उस पर पुनर्विचार प्रभावी तरीके से होना चाहिए। उन्होंने सरकार की तरफ से आश्वस्त किया कि जाधव की सुरक्षा व देखरेख सुनिश्चित करने और उन्हें यथाशीघ्र भारत वापसी की कोशिश जारी रखी जाएगी। जयशंकर ने कहा, आइसीजे का फैसला सिर्फ भारत और जाधव की जीत नहीं है बल्कि उन सभी की जीत है जो न्याय व्यवस्था और इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय समझौते में भरोसा करते हैं। जयशंकर के बयान के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'आइसीजे के फैसले में कोई संदेह नहीं है और अब गेंद पूरी तरह से पाक के पाले में है कि वह इसे लागू करे।' यह पूछे जाने पर कि पाक में अब आगे की कार्यवाही सैन्य कोर्ट में होगी या सामान्य कोर्ट, इस पर रवीश का जवाब था कि यह फैसला पाक को करना है। भारत चाहेगा कि फैसले के मुताबिक जाधव को जल्द उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, उन्हें भारतीय राजनयिकों की पहुंच (काउंसलर एक्सेस) दी जाए और उनको दी गई सजा की नए सिरे से समीक्षा की जाए।

मुगालते में पाकिस्तान, आइसीजे के फैसले में दिख रही जीत पेज>>4

अब 22 जुलाई को मिशन पर रवाना होगा चंद्रयान-2

चेन्नई : भारत के महत्वाकांक्षी दूसरे मून मिशन चंद्रयान-2 को 22 जुलाई को दोपहर 2.43 बजे लांच किया जाएगा। 15 जुलाई को जीएसएलवी रॉकेट में तकनीकी खराबी के कारण लांचिंग आखिरी वक्त में रोक दी गई थी। इसरो ने गुरुवार को ट्वीट किया, ' चंद्रयान-2 की लांचिंग अब 22 जुलाई को होगी। तकनीकी खामी को दूर हो गई है। **(पेज-5)**

देश में इस हफ्ते औसत से 20 फीसद कम रही बरसात

नई दिल्ली : निजी एजेंसी स्काईमेट ने कहा है कि बुधवार को खत्म हुए पूरे एक हफ्ते में पूरे देश में औसत से 20 फीसद कम बारिश हुई है। देश के मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में फसलों की उपज को लेकर चिंता गहराने लगी है। स्काईमेट के मुताबिक, जुलाई में भले ही मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन अल-नीनो का प्रभाव पड़ने वाला है। **(पेज-7)**

मायावती के भाई आनंद पर कसा शिकंजा, 400 करोड़ की संपत्ति जब्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति कानून के तहत की नोएडा के सेक्टर-94 के प्लॉट पर कार्रवाई
- बसपा सुप्रीमो के भाई-भाभी की 1350 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई अन्य संपत्तियां भी रडार पर

बेनामी संपत्ति कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भाई व बसपा के उपाध्यक्ष आनंद कुमार और उसकी पत्नी की संपत्ति जब्त कर ली है। आयकर विभाग के अनुसार इस संपत्ति की मूल कीमत लगभग 400 करोड़ रुपये है, जबकि मौजूदा बाजार कीमत इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है।

आयकर विभाग लंबे समय से आनंद कुमार की बेनामी संपत्तियों की जांच कर रहा था। नोएडा के सेक्टर 94 स्थित सात एकड़ (28,328.07 वर्ग मीटर) जमीन के सारे दस्तावेजों को खंगालने के बाद यह पुख्ता हो गया है कि दूसरी कंपनियों के नाम पर दिखाई गई यह जमीन दरअसल आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्रलता की है और वे ही इसके असली लाभार्थी हैं। जब्त की गई जमीन संख्या 2ए पर पांच सितारा होटल समेत कई आलीशान इमारतें बनाने की योजना थी। आयकर विभाग का कहना है कि इस जमीन को हासिल करने के लिए हवाला के मार्फत पैसे को कई बार घुमाकर इन कंपनियों तक पहुंचाया गया था, ताकि इसके असली मालिक का पता नहीं चले।

दरअसल आनंद कुमार आयकर विभाग के रडार पर 2007 से लेकर 2012 के दौरान ही आ गए थे, जबकि उनकी कई संपत्तियों में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई। उसी दौरान मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं। लेकिन आयकर विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हथियार तब मिला जब 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 1988 के बेनामी संपत्ति कानून को लागू कर दिया। 28 साल बाद लागू किया गया यह कानून आयकर विभाग को बेनामी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देता है। बेनामी रोधी कानून को तोड़ने वालों पर सात साल के सश्रम कारावास और संपत्ति की मूल कीमत के 25 फीसद तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।

आयकर विभाग ने हाल ही में मायावती के भाई आनंद के कई ठिकानों पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किये। इसमें कई बेनामी संपत्तियों का कच्चा-चिट्ठा मौजूद था। विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार आनंद कुमार की अन्य कई संपत्तियों की जांच की जा रही है और भविष्य में उन्हें भी जब्त किया जा सकता है। गुरुवार को 400 करोड़ की संपत्ति की गई है, जबकि आयकर विभाग के रडार पर आनंद कुमार की 1350 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां हैं। साथ ही आनंद कुमार जिन 12 कंपनियों के निदेशक हैं उनकी भी जांच चल रही है। इनमें कम से कम छह खोखा कंपनियां हैं, जो सिर्फ कागजों पर ही करोड़ों रुपये का खेल कर रही थीं और हकीकत में उनका कोई अता-पता नहीं था। इन खोखा कंपनियों की पहचान विजन टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड, बीपीटीपी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, यूरो एशिया मरकेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, करिश्मा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और एड-फिन कैपिटल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुई है।

आनंद कुमार। जागरण आर्काइव

भूमाफिया घोषित किए गए सपा सांसद आजम खां

रामपुर : जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीनें कब्जा करने के आरोप में फंसे सपा सांसद आजम खां को प्रशासन ने भूमाफिया घोषित कर दिया है। उप जिला अधिकारी की ओर से उनका नाम एंटी भू माफिया पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया है। इस पोर्टल पर उन्हीं लोगों के नाम दर्ज कराए जाते हैं जो जमीनों पर कब्जा करते हैं और उन्हें छोड़ते नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति आजम खां के खिलाफ पिछले एक सप्ताह के दौरान जमीन कब्जाने के 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। **(पेज-5)**

कोयला घोटाले को भी पीछे छोड़ सकता है भूमि आवंटन घोटाला पेज>>5

दुविधा के बीच

कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा को कमान सौंपने की उठ रही आवाज के बीच पार्टी महासचिव ने नेल्सन मंडेला के सहारे अपनी बड़ी राजनीतिक भूमिका का इशारा किया है...

प्रियंका ने दिया अपनी राजनीतिक दावेदारी का संकेत

संजय मिश्र, नई दिल्ली

कांग्रेस में नए अध्यक्ष की तलाश पर जारी असमंजस के बीच पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भविष्य में पार्टी में अपनी सियासी भूमिका और दावेदारी का बड़ा संकेत दे दिया है। कांग्रेस महासचिव ने नेल्सन मंडेला के हवाले से इशारों में साफ कर दिया है कि राजनीति जहां उनके मिजाज में है तो सियासत में जगह बनाने का इरादा भी दृढ़ है। बेशक वह इस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी के उत्तराधिकारी की दौड़ में शामिल नहीं हैं मगर उनके इस संकेत से उन नेताओं-कार्यकर्ताओं में उम्मीद व उत्साह का संचार होना तय है जो पार्टी की कमान उन्हें सौंपने की आवाज उठाने लगे हैं।

राजनीति में डटे रहते हुए अपनी जगह बनाने का संदेश प्रियंका ने बड़ी चतुराई से दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला को उनकी जयंती पर एक ट्वीट के जरिये याद करते हुए दिया। मंडेला के साथ 18 साल पुरानी एक निजी खुशनुमा तस्वीर साझा करते हुए प्रियंका ने कहा है कि दुनिया को नेल्सन मंडेला जैसी शख्सियत की आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। उनका जीवन सत्य, प्रेम

प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर अकांउट पर साझा की वर्ष 2001 की पिक्चर जिसमें वे दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला के साथ नजर आ रही हैं। (ट्विटर से)

और आजादी की मिसाल है। उन्होंने मंडेला से आत्मीय लगाव के साथ अपने राजनीतिक मिजाज का खुला संदेश देते हुए कहा 'मेरे लिए वह अंकल नेल्सन थे जिन्होंने कोई और कहे इससे पहले ही कह दिया था कि मुझे राजनीति में होना चाहिए। वे हमेशा मेरे प्रेरणास्रोत और मार्गदर्शक रहेंगे।'

राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद नेतृत्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस के बेचैन नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए प्रियंका का यह संदेश भविष्य की संजीवनी से कम नहीं माना जाएगा। उनका यह संदेश इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने राजनीति से कदम पीछे नहीं खींचने का इरादा ऐसे समय में जाहिर किया है जब राहुल कह चुके हैं पार्टी का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा।

राहुल ने 25 मई को कार्यसमिति की बैठक में चुनावी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने के साथ ही साफ कर दिया था कि पार्टी को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर किसी गैर गांधी को ही चुनना पड़ेगा। इस वजह से राहुल के इस्तीफे के डेढ़ महीने बाद तक चुप रहने के बाद अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बनने से बेचैन पार्टी नेताओं ने प्रियंका को कमान सौंपने की आवाज उठानी शुरू कर दी है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, अनिल शास्त्री के अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कहा है कि पार्टी के नाजुक संकट के इस दौर में प्रियंका को कांग्रेस की कमान थामना चाहिए। इन आवाजों के बीच प्रियंका की टिप्पणी के दूरगामी सियासी मायने तो हैं ही। कांग्रेस महासचिव ने इस ट्वीट में जो तस्वीर साझा की है उसमें मंडेला प्रियंका के साथ उनके बेटे को गोद में लिए दुलार रहे हैं। प्रियंका ने इसी कड़ी में दूसरा ट्वीट कर बताया कि यह तस्वीर 2001 की है और मंडेला उनके बेटे की फैंसी टोपी देख हर्षित हो रहे हैं।

रामलला को अब मिली 2 अगस्त की तारीख

माला दीक्षित, नई दिल्ली

पिछले नौ वर्षों से अपीलों पर सुनवाई की बाट जोह रहे रामलला को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को 2 अगस्त की नई तारीख मिली है। कोर्ट ने 31 जुलाई तक मध्यस्थता जारी रखने की इजाजत देते हुए मामले पर सुनवाई की नई तारीख 2 अगस्त तय कर दी। कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल से एक अगस्त तक प्रगति रिपोर्ट मांगी है और दो अगस्त को सुनवाई में कोर्ट आगे की कार्यवाही पर फैसला लेगा।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह आदेश आपसी सुलह से विवाद का हल ढूंढ़ रहे मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद गुरुवार को दिये। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल से 18 जुलाई तक प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर रिपोर्ट देखकर उन्हें लगेगा कि मध्यस्थता समाप्त कर दी जानी चाहिए तो वे ऐसा आदेश देंगे और मामले पर 25 जुलाई को सुनवाई करेंगे। अगर जरूरी हुआ तो 25 जुलाई से रोजाना सुनवाई करेंगे।

अयोध्या मामला

- सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कार्यवाही 31 तक जारी रखने को दी मंजूरी
- मध्यस्थता पैनल से एक अगस्त तक मांगी रिपोर्ट, कोर्ट 2 अगस्त को मामले पर फिर करेगा विचार

कोर्ट के गत 11 जुलाई के आदेश के मुताबिक गुरुवार को संविधान पीठ के सामने मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष एफएमई कलीफुल्ला की ओर से रिपोर्ट पेश हुई। कोर्ट ने रिपोर्ट देखी लेकिन उसके तथ्यों को यह कहते हुए सार्वजनिक नहीं किया कि कोर्ट का शुरुआती आदेश था कि मध्यस्थता कार्यवाही में गोपनीयता बरती जाएगी।

ऐसे में रिपोर्ट के तथ्य रिकार्ड पर दर्ज करना उचित नहीं लगता। हालांकि कोर्ट ने रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों पर विचार करते हुए मध्यस्थता प्रक्रिया 31 जुलाई तक जारी रखने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल से अनुरोध किया है कि वह एक अगस्त को रिपोर्ट दाखिल कर 31 जुलाई तक मध्यस्थता में हुई प्रगति बताए। 2 अगस्त को मामले पर फिर विचार होगा। कोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा है कि वह मामले को सुनवाई के लिए तैयार रखे।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

मुख्य सुनवाई के दौरान उठाई जा सकती हैं अनुवाद की विसंगतियां : इस बीच सर्वोच्च न्यायालय में मुस्लिम पक्षकार जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से याचिका दाखिल हुई थी जिसमें अयोध्या मामले के मुकदमें से जुड़े कुछ अनुवादों में विसंगतियों का जिक्र करते हुए मुख्य मामले पर सुनवाई के दौरान उन्हें उठाने की इजाजत मांगी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को इसकी इजाजत दे दी।

40 बीघा जमीन दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी में दिल्ली विश्वविद्यालय को आवंटित की गई है महिला डिग्री कॉलेज खोलने के लिए। कॉलेज में खेल परिसर के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा और छात्राओं के लिए छात्रावास भी होगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 19 जुलाई 2019

अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मिलेगा संपत्ति का मालिकाना हक

सौगात ▶ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा– केंद्र सरकार भी इन कॉलोनियों को पक्का करने के लिए तैयार है, जल्द शुरू हो जाएगी रजिस्ट्री

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया है कि जल्द ही उन्हें अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा। इन सभी कॉलोनियों में रजिस्ट्री भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली का विकास तभी हो सकता है। जब केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम करे। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दे रही है।

बृहस्पतिवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि अभी तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के साथ हमेशा धोखा होता आया है। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हों, चुनाव से पहले कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ बड़े-बड़े वादे किए जाते थे और चुनाव खत्म होने के बाद सभी सरकारें अपने वादों को भूल जाती थी। पांच साल तक कुछ नहीं किया जाता था। पांच साल बाद जब दोबारा चुनाव आते थे, फिर से वही वादे दोहराए जाते थे। लेकिन ,जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने पहले ही दिन से ठान लिया था कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनका हक दिलवाकर रहेंगे।

दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। जागरण

उन्होंने बताया, दो नवंबर 2015 को कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया और 12 नवंबर, 2015 को केंद्र सरकार को भेज दिया था। उन्होंने कहा कि यह जानकारी साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से हमें इस प्रस्ताव पर बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार इन कॉलोनियों को पक्का करने के लिए तैयार है। मैं दिल्ली की जनता और दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र का धन्यवाद करना चाहता हूं और कच्ची कॉलोनियों में रहने वाली जनता को बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव आया है, उसमें उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों और मुख्य सचिव की एक बैठक बुलाकर सभी को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वह जल्द से जल्द इन प्रश्नों के उत्तर केंद्र की संतुष्टि के मुताबिक तैयार करके केंद्र सरकार को भेज दें।

उन्होंने कहा, रजिस्ट्री करने वाले विभाग को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस प्रस्ताव की मंजूरी मिलते ही दिल्ली में बड़े स्तर पर रजिस्ट्रियां शुरू हो जाएंगी। इसके लिए विभाग अभी से तैयारियां शुरू कर ले ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न हो। अगर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाने की जरूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार कैंप भी लगाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक जनवरी, 2015 से पहले जिन कच्ची कॉलोनियों ने नियमित करने के आवेदन दिए थे, उन सभी कॉलोनियों को सरकार की इस पहल का लाभ मिलेगा।

अब तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत बदतर हालत में थी। यहां कभी कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। हमारी सरकार इन कॉलोनियों में सड़क, नाली, गलियों इत्यादि के लिए 3500 और पानी एवं सीवर के लिए करीब 2500 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है या खर्च करने जा रही है। कुल करीब छह हजार करोड़ रुपये इन कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए लगाए जा रहे हैं।

तीन श्रेणियों में बांटकर नियमित की जाएंगी 1,797 कॉलोनियां

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली की तमाम अनधिकृत कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में बांटकर नियमित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ही हरी झंडी देने जा रही है।

इस रिपोर्ट में दिल्ली की सभी 1,797 अनधिकृत कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की गई है। पहली श्रेणी में वैसी कॉलोनियां होंगी जो सरकारी जमीन पर बसी हैं। दूसरी श्रेणी में वे कॉलोनियां शामिल रहेंगी जो ग्रामसभा की उस जमीन पर बसी हैं, जिस पर सरकार कब्जा नहीं ले सकी। तीसरी श्रेणी में प्राइवेट जमीन पर बसी अनधिकृत कॉलोनियां रहेंगी। पहली श्रेणी में रहने वालों को नाममात्र के शुल्क पर मालिकाना हक दिया जाएगा। अगर मकान का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से कम है तो सर्किल रेट का एक फीसद और अगर इससे ज्यादा है तो दो फीसद की दर से भुगतान करना होगा। दूसरी श्रेणी में मालिकाना हक का शुल्क तय करने पर विचार चल रहा है। हालांकि इस श्रेणी की कॉलोनियों को उपराज्यपाल की मंजूरी से शहरीकृत गांव में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि तीसरी श्रेणी के लिए कोई शुल्क नहीं होगा।

सूत्र बताते हैं कि एलजी की रिपोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की भी इन कॉलोनियों को नियमित करने के संदर्भ में बड़ी भूमिका तय की गई है। सबसे पहले डीडीए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की मदद से इन कॉलोनियों की रिमोट सैंसिंग और ड्रोन के जरिये मैपिंग करेगा, ताकि उनका डाटा अपडेट किया जा सके। इसके बाद डीडीए एक सिंगल विंडो या पोर्टल शुरू कर शुल्क लेने की व्यवस्था करेगा।

डीडीए और केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो एलजी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर उच्चस्तरीय बैठकों का दौर जारी है। बहुत ही जल्द इस पर कैबिनेट नोट तैयार हो जाएगा। संभावना है कि अगले कुछ ही दिनों में इन कॉलोनियों को नियमित करने की नीति को स्वीकृति दे दी जाए। इसके बाद डीडीए युद्ध स्तर पर इन्हें नियमित करने की नीति पर क्रियान्वयन शुरू कर देगा।

रोड़ा अटकाने वाले केजरीवाल अब लेना चाहते हैं श्रेय : भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा का कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर लोगों को सिर्फ गुमराह किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बार-बार कहने के बावजूद आप सरकार इन कॉलोनियों की रिपोर्ट देने में टालमटोल करती रही। इस वजह से केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब राजनीतिक नुकसान होता देख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस काम का श्रेय लेने की कोशिश में जुट गए हैं।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के अनुमोदन से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया जाएगा। यहां के निवासियों को अपने मकानों का मालिकाना हक मिल जाएगा। यह दिल्लीवासियों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा तोहफा होगा।

पंजाब नेशनल बैंक की नजफगढ़ शाखा में फर्जीवाड़ा, पूर्व क्रेडिट मैनेजर धरा

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

पंजाब नेशनल बैंक की नजफगढ़ शाखा के दो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक व्यवसायी को अवैध रूप से पांच करोड़ रुपये लोन देने का मामला सामना आया है। अधिकारियों ने कमीशन के रूप में मोटी रकम लेकर व्यवसायी पति-पत्नी को पहले एक-एक करोड़ रुपये होम लोन दिया, फिर उन्हें फर्म चलाने के लिए भी तीन करोड़ रुपये का लोन दे दिया। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा पहले लोन लेने वाले व्यवसायी राजेश दुआ समेत तत्कालीन मुख्य प्रबंधक एसके उपाध्याय को गिरफ्तार कर चुकी है। बुधवार को बैंक के तत्कालीन मैनेजर क्रेडिट एचएल मान को गिरफ्तार कर लिया गया।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर आर्थिक अपराध शाखा सुभाशीष चौधरी के मुताबिक एचएल मान रायकोट, लुधियाना, पंजाब का रहने वाला है। 2015 में वह पंजाब नेशनल बैंक की नजफगढ़ शाखा में मैनेजर क्रेडिट था। इसी ने आवास लोन व कंपनी चलाने के लिए बैंक के मुख्य प्रबंधक को लोन देने के लिए संस्तुति की थी। राजेश दुआ राजौरी गार्डन इलाके में रहता है। उसने राजौरी गार्डन में ही दो फ्लैट खरीदने के लिए अपने व पत्नी के नाम से पंजाब नेशनल बैंक की नजफगढ़ शाखा में एक-एक करोड़ रुपये लोन के लिए आवेदन किया था।

लोन के लिए ग्राहक का सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए, साथ ही दस्तावेज भी पूरे होने चाहिए। राजेश दुआ का न तो सिविल स्कोर ठीक था और न दस्तावेज पूरे थे। मोटा कमीशन लेकर तत्कालीन मैनेजर क्रेडिट एचएल मान ने तत्कालीन मुख्य प्रबंधक एसके उपाध्याय के साथ साजिश रचकर पति-पत्नी को दो करोड़ रुपये लोन दे दिया। उसके आधार पर बाद में दोनों अधिकारियों ने फर्म को ठीक तरीके से चलाने के लिए तीन करोड़ रुपये और लोन दे दिया। फर्म के नाम पर जो लोन देने की शर्तें होती हैं, उसका भी पालन नहीं किया गया।

राजेश दुआ ने रिकार्ड में बैंक को बताया था कि उसकी दुआ मैकेनिक नाम से बड़ी फर्म है। फर्म के नाम पर लोन देने के लिए कुछ गिरवी रखने का भी प्रावधान है, इसकी भी अनदेखी की गई। ऑडिट में बैंक को इस मामले में फर्जीवाड़ा का पता चलने पर बैंक की ओर से आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत कर दी गई।

जांच में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर आर्थिक अपराध शाखा ने 25 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद ग्राहक राजेश दुआ व तत्कालीन मुख्य प्रबंधक एसके उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में ईओडब्ल्यू आरोप पत्र भी दायर कर चुकी है। बैंक ने भी उपाध्याय को नौकरी से हटा दिया है। राजेश दुआ की पत्नी को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है, इसलिए उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। जांच के बाद अब तत्कालीन मैनेजर क्रेडिट एचएल मान को भी दबोच लिया गया। बैंक ने भी उसकी आठ वेतन बढ़ोत्तरी रोककर आधी पेंशन कर नौकरी से हटा दिया है।

केजरीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिख बजट आवंटन पर जताई आपत्ति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री व गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार को केंद्रीय करों में मात्र 325 करोड़ रुपये दिए जाने पर आपत्ति जताई है। साथ ही इस मद में 65 सौ करोड़ की राशि निर्गत करने की मांग की है। केजरीवाल ने वित्त व गृह मंत्री से मांग की है कि 15 वें वित्त आयोग को दिल्ली के लिए विचारणीय विषयों पर अपने स्तर से अनुशंसा करें ताकि केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी बढ़ सके। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली अब राज्य का आकार ले चुका है इसलिए इसे करों के वितरण के मामले में अन्य राज्यों के बराबर माना जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 से अब तक दिल्ली सरकार को केंद्रीय कर के मद से मात्र 325 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। इसका खामियाजा केंद्र शासित उन राज्यों पर ज्यादा है जिसके पास विधानसभा भी है। बगैर विधानसभा वाले केंद्र शासित राज्यों को पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। केजरीवाल ने कहा कि देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली पर खर्च का बोझ काफी ज्यादा है।

अब शीला के वार पर हारून और देवेंद्र का पलटवार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रदेश प्रभारी पीसी चाको और प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के बीच चल रहे सियासी टकराव के बीच अब प्रदेश कांग्रेस में भी खुली बगावत शुरू हो गई है। पार्टी के दो कार्यकारी अध्यक्ष हारून यूसुफ और देवेंद्र यादव ने शीला के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें एआइसीसी (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) ने नियुक्त किया है और वे सिर्फ आलाकमान के प्रति जवाबदेह हैं। अपनी सहमति के बगैर प्रदेश कांग्रेस में एक के बाद एक लिए जा रहे फैसलों से खासे आहत इन दोनों नेताओं ने गुरुवार को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रदेश कार्यालय में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बैठक भी की। बैठक में इन्होंने यह भी साफ शब्दों में कहा कि ब्लॉक समितियों को भंग करने का फैसला अमान्य है, सभी ब्लॉक अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि वो अपने अपने इलाके में जाकर बूथ स्तर पर विधानसभा चुनाव के लिए काम शुरू कर दें।

मालूम हो कि बुधवार को ही शीला ने चाको समर्थक इन दोनों कार्यकारी अध्यक्षों के पर कतरते हुए इन्हें केवल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव और एनएसयूआइ तक सीमित कर दिया था। इसी के जवाब में बृहस्पतिवार को देवेंद्र और हारून ने ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की बैठक रख ली।

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हारून यूसुफ व देवेंद्र यादव। जागरण

बैठक में देवेंद्र ने कहा कि पिछले दिनों कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे नीचे के कार्यकर्ता परेशान हो गए। जबकि हमें एक साथ मिलकर काम करने को कहा गया था। इस फैसले से संगठन को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो ब्लॉक अध्यक्ष थे वो यथावत काम करें, हमें संगठन को मजबूत करना है, इसलिए ब्लॉक स्तर पर काम करने की जरूरत है। शीला के नाम पर मनमानी कर रहे नेताओं को चेतावनी देते हुए देवेंद्र ने कहा कि ऐसे शरारती तत्व प्रदेश को छोड़कर अपने क्षेत्र में ध्यान दें तो बेहतर रहेगा।

वहीं हारून ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व को एआइसीसी ने नियुक्त किया है और एआइसीसी ने इस मामले में जो चिट्ठी दी है उसके अनुसार ब्लॉक अध्यक्ष बने रहेंगे। हम उसी आदेश को मान रहे हैं और इसी के तहत अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर काम करने का आह्वान करने के लिए बैठक बुलाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि शीला दीक्षित के नेतृत्व में सभी एकजुट होकर विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और भाजपा एवं आप को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हम नई जिम्मेदारी भी निभाएंगे और पुरानी भी नहीं छोड़ेंगे।

इस बैठक में वरिष्ठ पार्टी नेता चतर सिंह और पूर्व मीडिया प्रभारी मेहंदी माजिद समेत ज्यादातर जिला एवं ब्लॉक अध्यक्ष भी उपस्थित रहे।

दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को बांटे 20308 करोड़ : तिवारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी (आप) पर निजी बिजली वितरण कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर विद्युत वितरण कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। उस समय केजरीवाल छह सौ करोड़ रुपये के अनुदान के नाम पर विद्युत वितरण कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन करने और यह राशि वसूलने की बात कहते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने पिछली सरकार से कई गुना ज्यादा राशि बिजली कंपनियों को अनुदान के तौर पर बांटी है।

तिवारी ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों की अनुदान राशि 621 करोड़ रुपये से घटाकर 301 करोड़ रुपये कर दी थी, लेकिन सत्ता में आते ही केजरीवाल सरकार ने 2015 में इसे बढ़ाकर 1427 करोड़ रुपये कर दिया। प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि की गई है। पिछले चार वर्षों में विद्युत वितरण कंपनियों को 6379 करोड़ रुपये अनुदान के तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा इस दौरान उपभोक्ताओं से स्थाई शुल्क के तौर पर 11429 करोड़ रुपये और अन्य अधिभार के तौर पर 2500 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। इस तरह से साढ़े चार वर्षों में बिना विद्युत वितरण कंपनियों को 20308 करोड़ रुपये का लाभ सरकार ने दिया है। इसके अलावा उपभोक्ताओं से निर्धारित दर के हिसाब से विद्युत उपभोग का खर्च अलग से वसूला गया है।

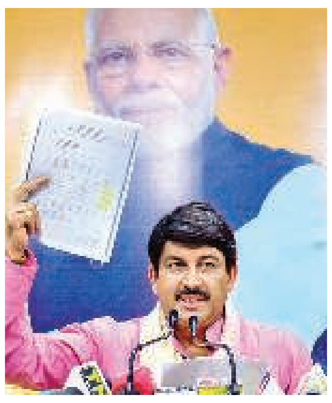
पंडित पंत मार्ग स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी। जागरण

इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेश भाटिया, प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना, अश्वनी उपाध्याय, मीडिया सह-प्रभारी नलकांत बख्शी एवं मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराहा उपस्थित थे।

'कूड़े के पहाड़ हटाने को जमा कराएं 250 करोड़'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार और नागरिक निकायों को लैंडफिल साइटों (कूड़े के पहाड़) से कूड़ा हटाने के लिए 250 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश दिए हैं।

एनजीटी ने कहा है कि यह रकम एस्क्रो खाते (विशेष कार्यों के लिए खोला जाने वाला खाता) में जमा कराई जाए। इस पैसे का इस्तेमाल जैविक उपचार योजना पर किया जाएगा। इसके साथ ही एनजीटी ने सख्त चेतावनी भी दी है कि अगर दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित विभागों के अधिकारियों की तनख्वाह रोक दी जाएगी।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भलस्वा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइट में 2.8 करोड़ टन से ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। इससे आसपास की जमीन का पानी तो दूषित हो ही रहा है, इसके अलावा यमुना में भी गंदगी पहुंच रही है।

एनजीटी ने आदेश दिया है कि इन लैंडफिल साइटों से कूड़े के निस्तारण का काम मानसून खत्म होने के बाद एक अक्टूबर से शुरू करना होगा। काम पूरा करने के लिए एक साल का समय दिया है। एनजीटी ने इस कार्य योजना के लिए एक समिति का भी गठन करने को कहा है। समिति में दिल्ली के प्रमुख सचिव, शहरी विकास सचिव, तीनों निगमों के साथ ही नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के आयुक्त, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव शामिल होंगे।

शपथ पत्र दाखिल न करने पर एनजीटी ने जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नई दिल्ली जिला अधिकारी द्वारा दक्षिणी रिज क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर कब्जे की जानकारी से संबंधित शपथ पत्र दाखिल न करने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नाराजगी जताई। एनजीटी ने कहा कि जब दूसरे जिलों के अधिकारियों ने शपथ पत्र दाखिल कर दिया तो नई दिल्ली जिला अधिकारी ने ऐसा क्यों नहीं किया? हालांकि नई दिल्ली जिला अधिकारी द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने के लिए और समय मांगने पर एनजीटी ने एक हफ्ते का समय दे दिया।

एनजीटी ने दक्षिणी रिज वन क्षेत्र की जमीन पर कब्जे को लेकर सभी जिला अधिकारियों से शपथ मांगा था, जिसमें जमीन के बारे में जानकारी हो। एनजीटी ने कहा था कि अधिकारी कब्जे वाली जमीन की पहचान कर पूरी रिपोर्ट और शपथ पत्र दाखिल करें। साथ ही संबंधित अधिकारी खुद पेश होकर अपना पक्ष रखें।

वन विभाग की जमीन पर कब्जे का मामला नई दिल्ली जिला अधिकारी ने नहीं जमा किया शपथ पत्र

एनजीटी में दक्षिण दिल्ली निवासी सोनया घोष व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि रिज क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर कई अवैध कब्जे हैं। याचिका में मांग की गई थी कि वन क्षेत्र की जमीन से कब्जा हटाया जाना चाहिए।

कूड़ा निपटान को अपनाएं इंदौर मॉडल : एनजीटी ने कूड़ा निपटान के लिए इंदौर मॉडल को परखने के लिए भी कहा है। वहां पर काम कर चुके विशेषज्ञ डॉ. असद वारसी ने एनजीटी को बताया कि तीस लाख टन कूड़ा एक साल में हटाया जा सकता है, अगर 20 ट्रोमेल मशीनों से काम लिया जाए। अहमदाबाद में ऐसी 12 मशीनें लगाई गई थीं, जिन्हें बढ़ाकर अब 50 करने की तैयारी है।

हाई कोर्ट ने पूछा, बिना लाइसेंस व अग्नि सुरक्षा वाले बैंक्वेट हॉल पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ **याचिकाकर्ता ने कहा है कि तीनों नगर निगम और सरकार जुलाई 2017 से ही दिखा रहे हैं आदेशों को ठेंगा**

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरवार को नगर निगमों से पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी में बिना लाइसेंस व पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरणों के संचालित बैंक्वेट हॉल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने नगर निगम से पूछा, क्या आपने बैंक्वेट हॉल के संचालकों को अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाने के संबंध में नोटिस जारी किया। अगर हां, तो क्या उन्होंने कुछ कदम उठाए। अगर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो आपको उन्हें बंद कर देना चाहिए। मुख्य पीठ ने कहा कम से कम एक या दो हॉल तो बंद ही कर देने चाहिए। याचिका पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

पीठ ने यह आदेश एवं सुझाव तब दिए जब याचिकाकर्ता अर्पित भार्गव ने अदालत को बताया कि उसके आदेश को तीनों नगर निगमों के साथ ही दिल्ली सरकार आदेशों को जुलाई 2017 से ही ठेंगा दिखा रहे हैं। पीठ ने यह भी रिकॉर्ड पर लिया कि अदालत द्वारा कई बार ऐसे बैंक्वेट हॉल एवं सामुदायिक हॉल के संबंध में सूची मांगने के बाद भी नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पीठ को सूची नहीं उपलब्ध कराई।

पीठ ने पूछा कि आखिर आप सूची देते हुए घबरा क्यों रहे हैं। इसके साथ ही तीनों नगर निगमों व दिल्ली सरकार को सूची देने के लिए अंतिम तीन महीने का समय दिया है। साथ ही नगर निगमों को यह भी आदेश दिया कि ऐसे बैंक्वेट हॉल जिनमें अग्नि सुरक्षा के उपकरण मानक के अनुरूप नहीं लगे हैं, उन संचालकों को नोटिस जारी किया जाए। इसके अलावा बिना लाइसेंस चल रहे बैंक्वेट हॉल के संचालकों को आवेदन कराने के भी निर्देश दिए जाएं। पीठ ने कहा कि अगर नोटिस का हॉल संचालक संज्ञान नहीं लेते हैं और उपकरणों को नहीं लगाते हैं तो उनमें से कुछ को बंद करके यह संदेश दिया जाए कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों का अधिकारियों को अनुपालन कराना ही होगा। याचिकाकर्ता ने होटल, बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक केंद्र समेत अन्य में अग्नि सुरक्षा के संबंध में एक नीति तैयार कर इसे लागू कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।

सिफारिश

हेपेटाइटिस मरीजों से भेदभाव खत्म करने को बने कानून

आइएलबीएस के निदेशक डॉ. एसके सरीन ने कहा कि कानून बनाना इसलिए जरूरी है ताकि हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित लोगों को नौकरियों व मान-सम्मान में सामाजिक भेदभाव का सामना न करना पड़े

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

यकृत व पित्त विज्ञान संस्थान (आइएलबीएस) ने यकृतशोध (हेपेटाइटिस) के मरीजों से भेदभाव व सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से कानून बनाने की सिफारिश की है ताकि यकृतशोध बी व सी से पीड़ित लोगों को नौकरियों व मान सम्मान में सामाजिक भेदभाव का सामना न करना पड़े। संस्थान के निदेशक डॉ. एसके सरीन ने कहा कि यकृतशोध के मरीजों को भी मानव रोगक्षम-अपर्याप्ता विषाणुओं (एचआइवी) से पीड़ितों की तरह कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए कानून में प्रावधान होना जरूरी है। इससे यकृतशोध पीड़ितों का जीवन बेहतर हो सकेगा और वे समाज में मान-सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

एचआइवी पीड़ितों की तरह मिले कानूनी अधिकार : उन्होंने कहा कि अमेरिका, एशिया व यूरोप सहित दुनियाभर के पांच बड़े यकृत चिकित्सक अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इसके लिए सिफारिश कर चुके हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) भी इसके लिए कदम उठाने की सिफारिश करता रहा है। एचआइवी पीड़ितों के अधिकार के लिए तमाम कानूनी प्रावधान हैं। नौकरियों में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन यकृतशोध के पीड़ितों के लिए मौजूदा समय में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा यकृतशोध को लेकर बहुत भ्रांतियां भी हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने की भी जरूरत है।

छुआछूत की बीमारी नहीं है यकृतशोध : कई हिस्सों में लोग इसे छुआछूत की तरह संक्रामक मानते हैं, जबकि यह छुआछूत की बीमारी नहीं है। रक्त में संक्रमण से यह बीमारी होती है। डॉ. सरीन ने कहा कि देश में करीब साढ़े चार लाख लोग यकृतशोध बी व करीब 1.20 करोड़ लोग यकृतशोध सी से पीड़ित हैं। यकृतशोध बी संक्रमण जन्मजात होता है और बच्चे को मां से मिलता है। 90 फीसद लोगों में बीमारी का पता ही नहीं चल पाता है। पता चलने पर मरीजों को नौकरियां नहीं मिल पाती। मध्य पूर्व के देशों का वीजा नहीं मिलता। इस तरह की कई परेशानियों से गुरजना पड़ता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि यकृतशोध छुआछूत की बीमारी नहीं है।

इलाज मुमकिन है : यकृतशोध सी का संक्रमण रक्त से फैलता है और इसका कारगर इलाज उपलब्ध है। इसके अलावा यकृतशोध बी को भी दवाओं से नियंत्रित रखा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि मरीज समय रहते अस्पताल पहुंचे और उसे समुचित इलाज मिले।

जागरूकता है जरूरी: बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण के साथ मिलकर 'एंपथी' नाम से अभियान शुरू किया गया है। 28 जुलाई को विश्व यकृतशोध दिवस के मद्देनजर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, कानूनविद व डॉक्टर शामिल होंगे, जो यकृतशोध पीड़ितों से होने वाले भेदभाव की समस्या पर चर्चा करेंगे।

यकृतशोध बी से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी : यकृतशोध बी से बचाव के लिए हर बच्चे का टीकाकरण जरूरी है। बचपन में जिन्हें यह टीका नहीं लगा है, वे कभी भी यह टीका लगवा सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर मामलों में संक्रमण के 20 से 30 साल बाद यह बीमारी के रूप में सामने आता है।

गैंगस्टरों को हथियार आपूर्ति करने वाला अरुण मान गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली-एनसीआर के बड़े गैंगस्टरों को हथियार आपूर्ति करने वाले कुख्यात तस्कर अरुण मान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने आइजीआइ एयरपोर्ट से उसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपित के पास से पांच पिस्टल व एक कट्टा सहित 23 कारतूस बरामद किए हैं। अरुण पर दो मुकदमे दर्ज हैं।

स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि एसीपी संजय दत्त की टीम को दिल्ली एनसीआर में हो रही हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी और गोलीबारी इत्यादि की घटनाओं पर नजर रखने के लिए लगाया गया था। पुलिस को टेक्निकल सर्विलांस से पता चला कि अरुण मान जीतेंद्र गोगी, लोकेश सूर्या व कपिल कालू इत्यादि को हथियार की आपूर्ति कर रहा है। पुलिस से बचने के लिए वह थोड़े-थोड़े समय पर अपना स्थान बदलता रहता है। पता चला कि आरोपित का कई अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करों से संपर्क है। वह हथियार की तस्करी के सिलसिले में उनसे मिलने नेपाल जाने वाला है। इसके बाद इंस्पेक्टर संजीव कुमार और मान सिंह की टीम ने अरुण मान को 12 जुलाई को आइजीआइ एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसकी निशानदेही पर पांच पिस्टल व एक कट्टा सहित 23 कारतूस बरामद किए गए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के खेड़ाखुर्द निवासी अरुण मान ने बीच में ही कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर मोबाइल की दुकान खोल ली थी। इसी दौरान वह स्थानीय बदमाश बबलू के संपर्क में आया। इसी बीच गांव में आपसी रंजिश में प्रवेश मान ने बबलू की हत्या कर दी थी। बबलू की हत्या के बाद अरुण मान जीतेंद्र गोगी गिरोह से जुड़कर अपने गिरोह के साथ ही अन्य गिरोह के गैंगस्टर के बीच हथियार की आपूर्ति करने लगा। पुलिस अब उसके अन्य संपर्कों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

आठ सप्ताह में यौन उत्पीड़न शिकायत पर फैसला करे आइआइटी दिल्ली : हाई कोर्ट

जासं, नई दिल्ली : छात्रा द्वारा आइआइटी दिल्ली के प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आइआइटी की अनुशासन समिति को आठ सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू की पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए शिकायत पर त्वरित निर्णय लेने का निर्देश अनुशासन समिति को दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर पीड़ित छात्रा समिति के निर्णय से सहमत नहीं होती है तो वह दोबारा कोर्ट आ सकती है। पीठ ने यह निर्देश पीड़ित छात्रा की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

एक छात्रा ने प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत आंतरिक समिति में की थी। उसका आरोप था कि प्रोफेसर उसका पीछा करते हैं। समिति ने इस आरोप को सही पाया। समिति की रिपोर्ट अनुशासन समिति के पास लंबित है। याचिका के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर को सौंप दी थी।

67 से 72 फीसद भारतीयों को एच1–बी वीजा मिला है पिछले पांच वर्षों के दौरान। एच1–बी गैर आव्रजक वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष पेशे में विदेशी कामगारों को नियोजित करने की अनुमति देता है।

बजट प्रस्तावों से होगा ईज ऑफ लिविंग में और सुधार

बजट सत्र ▸ लोकसभा में चर्चा के बाद ध्वनिमत से वित्त विधेयक पारित, वित्त मंत्री ने कहा– मेक इन इंडिया और डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

टैक्स प्रस्तावों में कोई बदलाव नहीं करते हुए सरकार ने कहा है कि बजट में किए गए सभी प्रस्ताव देश में ईज ऑफ लिविंग की स्थिति में और सुधार लाने और जनता की तकलीफों को कम करने के उद्देश्य से किए गए हैं। वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि इनसे देश में मेक इन इंडिया और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। करीब छह घंटे चली चर्चा के बाद लोकसभा ने वित्त विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में वित्त मंत्री ने गुरुवार को तकरीबन सभी सदस्यों की तरफ से उठे सवालों के जवाब दिए। उच्च आय पर सरचार्ज लगाने को लेकर विपक्षी सदस्यों की तरफ से उठे सवालों के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इसे लेकर अधिक चिंतित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि एफपीआइ उच्च आय पर लागू सरचार्ज नहीं चाहते तो उन्हें ट्रस्ट के बजाय भारत में कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना होगा। दो करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक की कर योग्य आय पर लगे सरचार्ज के संबंध में सदस्यों द्वारा उठाई गई आशंकाओं का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि यह व्यक्तिगत करदाताओं पर लगाया गया है और अभी जो एफपीआइ ट्रस्ट के तौर पर यहां काम कर रहे हैं वे इसके दायरे में आएंगे। अलबत्ता वित्त मंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर

लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान जवाब देती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एएनआइ

सरचार्ज लगाने के सरकार के फैसले के पक्ष में एक बार फिर कहा कि राष्ट्र निर्माण में उच्च आय वालों को भागीदारी करनी चाहिए।

चर्चा के दौरान विपक्ष ने नोटबंदी से लेकर एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर टीडीएस लगाने समेत कई मुद्दे उठाए। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने नोटबंदी की वजह से बंद हुए एमएसएमई पर श्वेत पत्र लाने की मांग की। जबकि राकांपा की सुप्रिया सुले ने प्रत्यक्ष कर के नए कोड के लिए यशवंत सिन्हा समिति की रिपोर्ट पर विचार करने को कहा। चर्चा के दौरान यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे।

इससे पहले चर्चा में कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम सदस्यों ने गैर कर प्रस्तावों को वित्त विधेयक में शामिल करने का विरोध किया। चर्चा की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पर सवाल उठाया। चौधरी ने कहा कि राजग सरकार बजट की पवित्रता को समाप्त कर रही है। सरकार ने ऐसे कई संशोधन वित्त विधेयक में शामिल किये हैं जिन पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। चौधरी ने कहा कि बजट में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिससे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिले। हालांकि बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2016 और 2017 के वित्त विधेयक के समय भी इस तरह का मामला उठने और स्पीकर द्वारा आपत्ति खारिज कर देने का हवाला देते हुए वित्त मंत्री को इन प्रस्तावों के साथ वित्त विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर दी।

सीतारमण ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने कुछ गैर कर प्रस्तावों को वित्त विधेयक में इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग बिल में संशोधन के आठ प्रस्ताव भी शामिल है। विपक्ष के सदस्यों की आशंका का निवारण करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इनमें से छह संशोधन मौजूदा प्रावधानों के स्पष्टीकरण हैं जिन्हें कानून में शामिल किया जा रहा है। जीएसटी कानून में किये जा रहे पांच संशोधनों पर उठे सवालों के जवाब में सीतारमण ने कहा कि इन सभी प्रस्तावों को जीएसटी काउंसिल की मंजूरी मिल चुकी है। जीएसटी कानून में वित्त विधेयक के जरिए केवल इसीलिए संशोधन किया जा रहा है क्योंकि ये अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा हैं।

जहां तक रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन का सवाल है वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा एनबीएफसी के मामले में केंद्रीय बैंक की नियामक शक्तियां बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद रिजर्व बैंक के पास एनबीएफसी के बोर्ड के फैसलों को पलटने की शक्ति आ जाएगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक अब न केवल किसी भी एनबीएफसी का विभाजन कर सकेगा बल्कि उनके नेट ओन फंड को भी बढ़ा सकेगा। प्रत्यक्ष कर के नए कोड को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही इसके लिए टास्कफोर्स बना चुकी है। इसे 31 जुलाई तक रिपोर्ट देनी है। सरकार उसके बाद उस पर विचार कर उचित कदम उठाएगी।

भाजपा की तरफ से चर्चा में निशिकांत दुबे ने हिस्सा लिया। दुबे ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि देश में टैक्स टैररिज्म और नीतिगत जड़ता बनी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों की नीतियों की वजह से देश में फैले भ्रष्टाचार को मोदी सरकार दूर करने में जुटी है।

न्यूजप्रिंट पर संशोधन प्रस्ताव खारिज

वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष की तरफ से न्यूजप्रिंट पर 10 फीसद कस्टम ड्यूटी लगाने का मुद्दा भी उठाया गया। बीजेडी के भर्तृहरि महताब ने न्यूजप्रिंट पर ड्यूटी वापस लेने के प्रस्ताव से संबंधित एक संशोधन भी पेश किया। लेकिन उनका प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया। इससे पहले चर्चा के दौरान केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदस्य मोहम्मद बशीर ने कहा कि न्यूजप्रिंट पर कस्टम ड्यूटी लगाने से समाचार पत्र उद्योग के विकास को नुकसान होगा।

अडानी–अंबानी के नाम पर सदन में हंगामा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कॉरपोरेट टैक्स की दर में कमी को लेकर तृणमूल सांसद सौगात रॉय जैसे ही अडानी-अंबानी का नाम लिया सदन में हंगामा खड़ा हो गया। इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाने पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नियम का हवाला देते हुए कहा कि व्यक्तिगत नाम नहीं लिए जा सकते। पूरे विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये दोनों नाम किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि कंपनियों के लिए कहे गए हैं।

स्पीकर के आसन पर बैठीं मीनाक्षी लेखी ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए रॉय से कहा कि वे किसी का नाम न लें। लेकिन विपक्ष अपनी बात पर अड़ा रहा कि उनका तात्पर्य कंपनियों से है। अंत में बीजद के भृतहरि महताब ने कहा कि अब से पहले भी कॉरपोरेट घरानों का नाम चर्चा में आता रहा है। इसके लिए उन्होंने टाटा-बिड़ला का उदाहरण दिया। इस बीच विपक्ष के कुछ सदस्यों और लेखी के बीच सदस्यों के अधिकारों को लेकर हुई टीका टिप्पणी पर संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि लेखी इस वक्त स्पीकर के आसन पर हैं इसलिए वह जो भी कह रही हैं वह आसन की तरफ से कह रही हैं।

बच्चों की यौन प्रताड़ना के लिए मौत का प्रावधान वाला विधेयक रास में पेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : बच्चों के साथ यौन अपराधों की बढ़ती घटना पर काबू पाने के मकसद से सरकार ने राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया है। गुरुवार को पेश विधेयक में ऐसे अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। विधेयक में अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों के उपयोग (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) पर भी काबू पाने का प्रावधान किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया। इस विधेयक में 2012 के मूल कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक के कारण एवं उद्देश्यों में कहा गया है कि देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए विभिन्न अपराधों के लिए दंड में वृद्धि के लिए उपबंध करने की खातिर कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में कहा गया है कि हाल के समय में देश में अमानवीय मानसिकता दर्शाने वाले बाल यौन अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। बालक अपनी अल्पव्यस्कता, शारीरिक दुर्बलता और जीवन तथा समाज का अनुभव नहीं होने के कारण इन अपराधों के आसान शिकार बन जाते हैं। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अल्पवय के खिलाफ गंभीर यौन अपराध के साबित होने पर दोषी को कम से 20 वर्ष की कठिन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। इसमें ऐसे अपराध के लिए उम्रकैद, मृत्युदंड और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।

लोकसभा ने रचा इतिहास, 128 फीसद हुआ इस सत्र में काम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : 17वीं लोकसभा ने अपने पहले ही सत्र में कामकाज का नया इतिहास रच दिया है। गुरुवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पारित होने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक सदन ने 128 फीसद काम किया है। सदन में किए गए इस कामकाज को लेकर उन्होंने खुशी भी जताई।

नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा में इस बार कामकाज का माहौल बदला हुआ है। सदन की बैठकें देर रात तक चल रही हैं। कामकाज निपटाए जा रहे हैं। हाल ही में संसद के कामकाज का अध्ययन करने वाली संस्था पीआरएस ने इसे लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की है। इसमें बताया गया है कि लोकसभा में पिछले बीस साल में अब तक सबसे ज्यादा काम हुआ है। राज्यसभा के कामकाज का औसत अब तक 98 फीसद रहा है। हालांकि, अभी संसद का सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। इस बीच सत्र के कार्यकाल को एक सप्ताह तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है। उम्मीद है कि इसे मंजूरी भी मिल जाएगी। सरकार का मानना है कि मौजूदा सत्र को बढ़ाने से जनोपयोगी कुछ और विधेयकों को मंजूरी मिलने में आसानी होगी।

उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के आरोप में जज अनुराधा गर्ग बर्खास्त

जागरण संवाददाता, नैनीताल

▸ राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रमुख सचिव कार्मिक ने जारी किया आदेश

▸ वर्ष 2015 में हाई कोर्ट ने अनुराधा को किया था निलंबित

उत्तराखंड में हाई कोर्ट की संस्तुति और राज्यपाल की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर की निलंबित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अनुराधा गर्ग को बर्खास्त कर दिया है। 2008 की न्यायिक सेवा की अधिकारी अनुराधा को वर्ष 2015 में हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित किया था। राज्य बनने के 19 साल में किसी न्यायिक अधिकारी को पहली बार भ्रष्टाचार में बर्खास्त किया गया है।

दरअसल, भ्रष्टाचार की शिकायत पर 2015 में हाई कोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार विजिलेंस नरेंद्र दत्त की प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर अनुराधा को निलंबित किया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने आरोपों की जांच वर्तमान में हरिद्वार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक भारती को सौंपी थी। जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद हाई कोर्ट ने राज्यपाल को एसीजेएम अनुराधा गर्ग की बर्खास्तगी की संस्तुति भेजी। राज्यपाल की मंजूरी पर दो दिन पहले मंगलवार को कार्मिक विभाग की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से उनको बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया।

15 से 20 लाख रुपये की आय के स्रोत का नहीं लगा पता

वर्ष 2015 में काशीपुर की एसीजेएम अनुराधा गर्ग ने देहरादून में 15 से 20 लाख की जमीन का सौदा किया तो इसके लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी। हाई कोर्ट ने अनाम स्रोतों की इस आय के बारे में पूछा तो उनके द्वारा जमीन मां के नाम पर खरीदने की जानकारी दी गई। तत्कालीन रजिस्ट्रार विजिलेंस की प्रारंभिक जांच पड़ताल में इस आय के स्रोत का पता नहीं लग सका। इसके बाद एसीजेएम को निलंबित कर दिया गया था।

शत्रु संपत्ति की जमीन व इमारतें बेचेगी सरकार

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्र सरकार शत्रु संपत्ति की अचल संपत्तियों जैसे जमीन और इमारतों को इस वित्तीय वर्ष में बेचकर राजस्व हासिल करेगी। इसके अलावा सरकार केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) की अनुपयोगी संपत्तियों को भी बेचकर उसमें अपना हिस्सा लेगी। इससे विनिवेश का राजस्व भी बढ़ेगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी राजग सरकार ने 1800 करोड़ रुपये में 'शत्रु संपत्ति' बेची थी। शत्रु संपत्ति वह होती है जिसे कोई अपराधी या देशद्रोही छोड़कर विदेश भाग जाएं। बटवारे के समय पाकिस्तान या बांग्लादेश जाकर बसने वाले लोगों की संपत्तियां भी शत्रु संपत्ति के दायरे में आती हैं।

नए कानून के तहत ऐसी संपत्तियों को अब सरकार अपने कब्जे में ले लेती है और उसे जरूरत के हिसाब से बेच या उपयोग भी कर सकती है। अधिकारी ने बताया कि ऐसी शत्रु संपत्तियों को बेचा जाएगा जिनके दस्तावेज दुरुस्त होंगे। डीआइपीएएस के सचिव अतनु चक्रवर्ती ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020 के लिए सरकार ने अपना विनिवेश का लक्ष्य बढ़ा लिया है। पहले यह लक्ष्य 90 हजार करोड़ रुपये था जो अब 1,05,000 करोड़ रुपये हो गया है। इसलिए विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।

एम्स के डॉक्टर करेंगे हेलीकॉप्टर घोटाले के गवाह सक्सेना की जांच

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपित से गवाह बने राजीव सक्सेना को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एम्स के मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होने को कहा है। घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में सक्सेना सरकारी गवाह बन गया है। उसके ब्लड कैंसर और अन्य बीमारियों की जांच होनी है।

जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने मेडिकल बोर्ड से सक्सेना की जांच करने के एक हफ्ते के भीतर अदालत में रिपोर्ट देने को कहा है। पीठ ने कहा, 'राजीव सक्सेना के वकील ने भरोसा दिलाया है कि उनका मुवक्किल एम्स के निदेशक द्वारा गठित किए जाने वाले मेडिकल बोर्ड के समक्ष 2 अगस्त, 2019 को उपस्थित होगा। इसके एक हफ्ते के भीतर बोर्ड अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपे।' शीर्ष अदालत ने सक्सेना की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की जांच करने को कहा है। इस मामले पर अब 26 अगस्त को सुनवाई होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जून के अपने आदेश में सक्सेना को ब्लड कैंसर और अन्य बीमारियों

▸ सुप्रीम कोर्ट ने सक्सेना से मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होने को कहा

▸ शीर्ष अदालत ने इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति पर लगाई है रोक

राजीव सक्सेना फाइल फोटो

के इलाज के लिए 25 जून से 24 जुलाई तक संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और यूरोप जाने की अनुमति दे दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट के आदेश को सुपीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 26 जून को शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी थी।

राजीव सक्सेना यूएई स्थित कंपनी यूएचवाई सक्सेना ऐंड मैट्रिक्स होल्डिंग में निदेशक है। ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उसे आरोपी बनाया था। बाद में वह सरकारी गवाह बना गया।

ईडी की याचिका पर हथियार डीलर सुशेन मोहन को नोटिस

जासं, नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपित सुशेन मोहन गुप्ता की जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुनील गौर की पीठ ने सुशेन मोहन से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। मनी लांड्रिंग मामले में एक जून को निचली अदालत ने पांच-पांच लाख रुपये के दो निजी मुचलके पर सुशेन की सशर्त जमानत मंजूर की थी। उस पर कोर्ट की मंजूरी के बगैर देश न छोड़ने और जांच को प्रभावित न करने से सहित कई पाबंदियां लगाई गई हैं। सुशेन को मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में आरोपित से सरकारी गवाह बन चुके राजीव सक्सेना की जमानत निरस्त करने की ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी गई।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ रक्षा मंत्रालय का दावा, पाकिस्तानी सेना ही भारत में करा रही है आतंकियों की घुसपैठ

पाकिस्तान के खतरनाक आतंकी मंसूबों के बारे में रक्षा मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जो गंभीर खुलासे किए हैं वह बेहद चौकाने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब आर्थिक स्थिति से जूझने के बाद भी पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों और मिसाइलों में तेजी से इजाफा कर रहा है। यह भारत और विश्व शांति के लिए चिंता का विषय है। दूसरी ओर वह सीमापार आतंकवाद, क्रास बॉर्डर गोलीबारी और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं। रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक इस बात का उल्लेख किया गया है कि, पाकिस्तानी सेना जम्मू एवं कश्मीर में सीमा पार फायरिंग करवा कर आतंकी संगठनों को भारत की सीमा में पहुंचने में लगातार मदद करने का काम कर रही है।

रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, जैश-ए-मुहम्मद द्वारा करवाए गए पुलवामा हमले से सिद्ध होता है कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमापार आतंकवाद की नीति के निशाने पर भारत है। रिपोर्ट में लिखा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकी गिरोहों को समर्थन न देने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले आतंकी ढांचे को नष्ट करने के विश्वसनीय और बड़े फैसले नहीं लेता, तब तक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत मजबूत और निर्णायक कदम उठाता रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने ऐसे जिहादी और अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करना बंद कर दिया जिनके निशाने पर उसके पड़ोसी देश हैं।

दरअसल पाकिस्तान की कुछ सैन्य तैयारियां न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को चिंता में डालने वाली हैं। अंतरराष्ट्रीय आकलन के अनुसार, पाकिस्तान के पास आज की तारीख में 140-150 एटमी हथियार हैं। हथियार बढ़ाने की उसकी यह रफ्तार कायम रहती है तो पाकिस्तान का परमाणु भंडार 2025 तक बढ़कर 220-250 तक हो जाएगा। उसके हथियारों में इस प्रकार की बढ़ोतरी पूरी दुनिया को चिंता में डाल रही है। कारण यह कि उसकी स्थिति अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देशों से बहुत अलग है। पाकिस्तान में सत्ता के कई केंद्र हैं। लोकतांत्रिक सरकार की हालत कमजोर है। फौज और आइएसआइ अपने तरीके से फैसले करती रहती हैं, जबकि कट्टरपंथी और आतंकियों की अपनी अलग सत्ता है। ऐसे में यह आशंका जताई जाती रही है कि अगर ये हथियार आतंकियों के हाथ लग गए तो इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं। यह बात भी किसी से नहीं छुपी है कि पाकिस्तानी फौजी ठिकानों को ये आतंकी कई बार अपना निशाना बना चुके हैं। ऐसे में एक रास्ता यही बचता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की निगरानी में लाया जाए।

राफेल से वायु सेना को मिलेगी रणनीतिक ताकत : रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राफेल विमान भारतीय वायु सेना को रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता तथा लंबी दूरी तक लक्ष्यों पर निशाना साधने की क्षमता प्रदान करेगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि फ्रांस की वायु सेना के साथ अधिकारियों और तकनीशियनों के पहले बैच का प्रशिक्षण चल रहा है।

मंत्रालय ने 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि फ्रांस द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान भारत को दुश्मनों से पार पाने की मजबूत क्षमता प्रदान करेगा। भारत ने दोहरे इंजन वाले विमानों के दो बेड़े (36) खरीदने के लिए करार किया है और उनका बेस पाक तथा चीन के साथ पश्चिमी एवं पूर्वी मोर्चों पर स्थापित करने का फैसला किया है। परमाणु आयुधों को ले जाने की क्षमता वाले विमानों की आपूर्ति इस साल सितंबर से शुरू हो सकती है। स्ट्रेटेजिक डिटरेंस (रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता) एक ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल कोई देश किसी दुश्मन से हमले की संभावना को समाप्त करने के लिए प्रभावी तरीके से करता है। वायु सेना प्रमुख बी एस धनोआ ने पिछले साल राफेल और रूसी एस-400 मिसाइलों के बल में शामिल होने को क्रांतिकारी पहल कहा था।

रक्षा निर्यात 10 हजार करोड़ के पार पहुंचा : रक्षा मंत्रालय ने अपनी सलाना रिपोर्ट में कहा है कि साल 2018-19 में रक्षा निर्यात 10,745 करोड़ रुपये के आंकड़े के छू लिया। वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में यह वृद्धि 100 फीसद से ज्यादा है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान दर्जनों सुधारों या उठाए गए कदमों के चलते रक्षा निर्यात के क्षेत्र में यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है।

उच्च शिक्षण संस्थानों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बढ़े कदम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ सरकार ने 'दीक्षारंभ' और 'परामर्श' नाम से शुरू की दो नई योजनाएं

▸ संस्थानों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और छात्रों के विकास की होगी कोशिश

उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार की ओर से नई कोशिशें शुरू हुई हैं। सरकार ने 'दीक्षारंभ' और 'परामर्श' नाम की दो नई योजनाएं शुरू की हैं।जो इसी शैक्षणिक सत्र से देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को इसे अमल में लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को इन दोनों ही योजनाओं का शुभारंभ किया। छात्रों की मदद के लिए तैयार की गई दीक्षारंभ योजना एक तरीके का प्रबोधन कार्यक्रम(इंडक्शन प्रोग्राम) है। इसमें छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के साथ ही उसे संस्थान से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। इनमें संस्थान की रैंकिंग, वहां से पढ़कर निकलने वाली बड़ी शख्सियतों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही संस्थान में कौन-सी सुविधा किस जगह मौजूद है, जैसी जानकारियां भी दी जाएगी। इस योजना में संस्थानों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्रों का शामिल होना अनिवार्य होगा। इसी तरह यूजीसी की ओर से शुरू की गई परामर्श योजना में उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी गुणवत्ता को मजबूत बनाने के लिए लेकर मदद दी जाएगी।

इनमें विश्वविद्यालय और कॉलेज दोनों ही शामिल हो सकेंगे। यह मदद नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) और यूजीसी से जुड़े विशेषज्ञों की ओर से दी जाएगी। सरकार की मंशा देश के उच्च शिक्षा के सकल नामांकन दर (जीईआर) को बढ़ाकर दोगुना करना है। सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले लाने की एक पांच साल की योजना भी तैयार की है। जिसमें राष्ट्रीय नामांकन दर में पिछड़े उच्च शिक्षण संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय मदद की भी सिफारिश की गई है। इनमें राज्यों में मौजूद ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय को पचास करोड़ और कॉलेज को दस करोड़ देने की योजना बनाई गई है। मौजूदा समय में देश में उच्च शिक्षा का औसत नामांकन दर करीब 25 फीसद है।

चुनाव आयोग ने तृणमूल, भाकपा व राकांपा को दिया कारण बताओ नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : चुनाव आयोग ने गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), तृणमूल कांग्रेस व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों का कहना है कि हालिया लोकसभा चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन कर पाने वाली इन पार्टियों से आयोग ने पूछा है कि क्यों न उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया जाए। इन दलों को पांच अगस्त तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में राकांपा को छह सीटें मिली थीं, जबकि इस बार वह केवल पांच सीटें जीत पाई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। इसी प्रकार वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल को 34 सीटें मिली थीं, जो इस बार केवल 22 रह गई हैं। भाकपा को वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में एक सीट मिली थी, जबकि इस बार उसे दो सीटें मिली हैं। बंगाल समेत दूसरी विधानसभा चुनावों में भी भाकपा का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है। हालांकि, हालिया लोकसभा चुनाव में 10 सीटें और विधानसभा चुनावों में कुछ सीटें जीतने वाली बसपा राष्ट्रीय दर्जा खोने के खतरे से बाहर आ चुकी है।

मिली अनुमति

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की कार्य परियोजना है 'कोशिश', सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के पुनर्वास की योजना तैयार करने के लिए बातचीत करने की अनुमति दी है

शेल्टर होम पीड़ितों से बातचीत कर सकेगी 'कोशिश'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआइएसएस) की कार्य परियोजना 'कोशिश' को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन हिंसा मामले की पीड़ितों और उनके परिजनों से बातचीत करने की अनुमति प्रदान कर दी। इससे वह पीड़ितों के पुनर्वास की योजना तैयार कर सकेगा। टीआइएसएस की रिपोर्ट से ही बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित शेल्टर होम में कई लड़कियों के यौन शोषण का मामला सुर्खियों में आया था। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में दिल्ली की कोर्ट में 21 आरोपितों पर मुकदमा चल रहा है।

शीर्ष कोर्ट को केंद्र ने सूचित किया कि वह बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के इरादे से चार से छह महीने के भीतर ही बाल संरक्षण नीति को अंतिम रूप दे देगा। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही है। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के 44 बच्चों को उनके संबंधित परिवारों को सौंपने की अनुमति मांगी है। इस पीठ में जस्टिस एमएम शांतनागौदर और जस्टिस अजय रस्तोगी भी शामिल हैं। पीठ ने राज्य सरकार से कहा, 'हर रोज हम बिहार की समस्या का सामना करते हैं। क्या

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

हर समस्या का (बिहार की) समाधान कोर्ट को ही करना होगा?' बिहार सरकार के वकील ने कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बच्चों को इस समय अलग-अलग बाल देखरेख संस्थाओं में रखा गया है और इनमें से कुछ के व्यवहार में आक्रामकता नजर आ रही है और वे खुद नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

मामले में एमिकस क्यूरी वकील अपर्णा भट ने पीठ को सूचित किया कि मुजफ्फरपुर कांड के मुकदमे की सुनवाई चल रही है और इस प्रकरण में हत्या के पहलू की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है। भट ने कहा कि इन बच्चों का पुनर्वास करना होगा लेकिन उन्हें उनके परिवारों पास भेजना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मुजफ्फरपुर प्रकरण के आरोपी प्रभावशाली लोग हैं और वे मुकदमे की सुनवाई होने तक उनके परिवारों तक पहुंच सकते हैं। टीआइएसएस की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि अप्रैल महीने में यूनिसेफ के सदस्यों के साथ राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग, कोशिश और अन्य की बैठक में पुनर्वास योजना पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि पुनर्वास योजना तैयार नहीं हो सकी क्योंकि इसके लिए प्रत्येक बच्चे और उनके परिवार के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है।

इस पर पीठ ने कहा, 'सवाल यह है कि इसका रास्ता क्या है? हमें इसका समाधान कैसे करना चाहिए।' पीठ ने साथ ही यह भी जानना चाहा कि हत्याओं के बारे में क्या हुआ और कितनी हत्याएं हुई थीं। भट ने कहा कि लड़कियों के बयानों के अनुसार, आश्रय गृह में तीन लड़कियों की हत्या की गई थी और सीबीआइ को जांच में अस्थियां मिली हैं। पीठ ने कहा कि वह 'कोशिश' को बच्चों और उनके परिजनों के साथ मिलने और बातचीत करने की अनुमति देगी और वह चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

भविष्य में चिप वाले ई–पासपोर्ट जारी करने की है केंद्र की योजना

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार चिप जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर वाले ई-पासपोर्ट जारी करने की योजना पर काम कर रही है। पासपोर्ट पुस्तिका में लगने वाले इस चिप में आवेदक का निजी ब्योरा स्टोर होगा।

राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने बताया कि अगर कोई इस चिप से छेड़छाड़ करेगा तो सिस्टम उसकी पहचान कर लेगा और पासपोर्ट का सत्यापन नहीं हो सकेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने इंडिया सिक्योरिटी प्रेस (आइएसपी) को ई-पासपोर्ट उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटेक्टलेस इनलेस खरीदने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संबंध में आइएसपी को त्रिस्तरीय वैश्विक टेंडर जारी करने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया है। मुरलीधरन ने बताया कि आइएसपी द्वारा खरीद प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद ही ई-पासपोर्ट का उत्पादन शुरू होगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 2017 में 1.08 करोड़ और 2018 में 1.12 करोड़ पासपोर्ट जारी किए गए।

कह के रहेंगे माधव जोशी

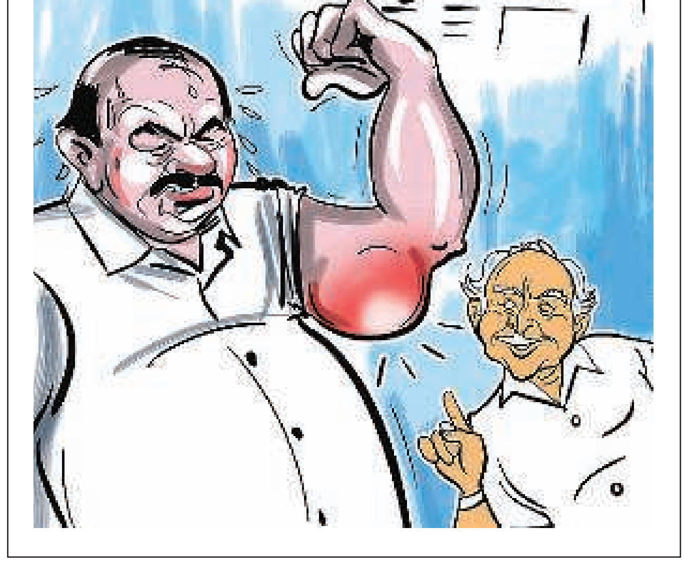

10,500 से ज्यादा दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास के मामले राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने आए हैं पिछले पांच वर्षों में। यह जानकारी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 19 जुलाई 2019

मुगालते में पाकिस्तान, आइसीजे के फैसले में दिख रही जीत

खरी खरी ▸ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री के बयान पर भारत ने कसा तंज, कहा, किसी और फैसले पर जश्न मना रहा पाक

अदालत के फैसले को अपनी जीत के रूप में दुनिया के सामने पेश कर रहे नेता व मीडिया

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

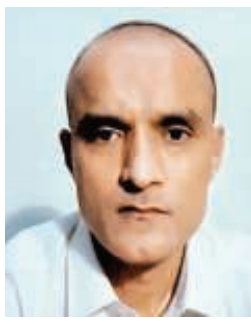

कुलभूषण जाधव की फाइल फोटो।

हेग में बुधवार को इसी अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। प्रेट्र

अद्भुत है पाकिस्तान, वहां की सरकार और वहां का मीडिया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की खंडपीठ के 16 न्यायाधीशों में से 15 ने भारत के रुख का समर्थन किया और कुलभूषण जाधव को दी गई सजा पर रोक लगाने के साथ ही उस पर पुनर्विचार का आदेश दिया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने वियना समझौते की अनदेखी के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई। जाधव को भारतीय राजनयिक की पहुंच की व्यवस्था की। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके विदेश मंत्री और वहां का मीडिया इसे एक जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बारे में इमरान खान सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त मुहिम छेड़ दी गई है। दूसरी तरफ, भारत ने पाकिस्तान में जीत के इस जश्न पर तंज कसते हुए कहा, 'ऐसा लगता है कि वहां की सरकार किसी दूसरे फैसले को पढ़ रही है।'

आइसीजे ने गुरुवार को कुलभूषण जाधव पर दिए गए फैसले पर सात पन्नों का प्रेस रिलीज जारी किया गया है जो खुद ही पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए काफी है। इसमें उन तथ्यों का कोई जिक्र ही नहीं है जिस पर पाकिस्तान फैसले को अपनी जीत करार दे रहा है। पाकिस्तान का कहना है, चूंकि आइसीजे ने जाधव को रिहा नहीं करने या उसे भारत को सौंपने के बारे में कुछ नहीं कहा है इसलिए उसकी जीत हुई है। जबकि इस प्रेस रिलीज से साफ है कि यह पूरा मामला जाधव की रिहाई से संबंधित नहीं था। बल्कि जिस तरह से पाकिस्तान में वियना समझौते की अनदेखी करते हुए जाधव के कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया, उससे ज्यादा संबंधित है।

भारत ने निश्चित तौर पर कानूनी कार्यवाही के दौरान जाधव की रिहाई की मांग उठाई थी जिसे अमान्य करार दिया गया है। लेकिन यह मूल फैसले का हिस्सा नहीं है। आइसीजे की खंडपीठ ने जिन आठ मुद्दों पर फैसला सुनाया है वे सभी भारत के पक्ष में हैं।

मसलन, इसमें पहला फैसला है कि आइसीजे को इस मामले में भारत के प्रस्ताव पर सुनवाई करने का अधिकार है। दूसरा, वियना समझौते की धारा 36 के तहत जाधव के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तीसरा, भारत को समय पर जाधव की गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई और उन्हें राजनयिक सुविधा नहीं दी गई। चौथा, पाकिस्तान को बिना किसी देरी के अब जाधव को राजनयिक पहुंच देनी चाहिए। पांचवा, जाधव को उनकी मर्जी का कानूनी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। छठा, जाधव को मिली सजा की प्रभावशाली समीक्षा होनी चाहिए। यही नहीं इसमें भारत ने जब मामले को आइसीजे में ले जाने के फैसला किया था तो पाकिस्तान ने जो तीन मामले उठाए थे उसे भी एक सिरे से खारिज कर दिया गया है। इसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरान इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार का कहना है कि पाकिस्तान सरकार अपनी अंदरूनी वजहों से ऐसा कर रही है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने जाल बिछाकर ईरान में व्यापार करने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को धोखे से अगवा किया। इसके बाद उसे पाकिस्तान ले गए और उसे काफी दिनों के बाद देश में जासूसी करने का आरोप लगाते हुए दुनिया के सामने पेश किया। विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाधव को जेल में डाल दिया, जहां उन्हें हैवानियत की हद तक प्रताड़ित किया गया। बाद में सैन्य अदालत ने एकतरफा सुनवाई करते हुए फांसी की सजा भी सुना दी थी। भारत के बढ़ते दवाब के बीच जाधव को उनकी मां और पत्नी से मिलने की अनुमति दी, लेकिन उसके तौर तरीकों पर सवाल उठे।

पाक के लिए अपनी न्यायिक प्रणाली को सुधारने का सुअवसर : जेटली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ फेसबुक पर ब्लॉग में पूर्व वित्त मंत्री ने आइसीजे के फैसले को बताया भारत की 'संपूर्ण जीत'

अरुण जेटली फाइल फोटो

पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) के फैसले को भारत की 'संपूर्ण जीत' बताते हुए इसे पाकिस्तान के लिए अपनी न्यायिक प्रणाली को पारदर्शी और सुचारू बनाने का बड़ा अवसर करार दिया है।

फेसबुक पर लिखे ब्लॉग में जेटली ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान किस दिशा में जाता है। उन्होंने कहा कि आइसीजे के फैसले से बेगुनाहों को सजा देने वाली पाकिस्तान की दिखावटी न्यायिक प्रक्रिया का चेहरा बेनकाब हो गया है।

यह फैसला पाकिस्तान के लिए एक सुअवसर लेकर आया है कि वह अपनी इस दिखावटी न्यायिक प्रणाली को बदलकर कानून का शासन लागू करे। अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले को जीत बताने वाली पाकिस्तान की कोशिशों पर तंज कसते हुए जेटली ने कहा कि असल में फैसले ने पाकिस्तान के ऊपर जाधव को फांसी की सजा देने के सैन्य अदालत के फैसले पर पुनर्विचार करने की जिम्मेदारी डाल दी है। यह पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है कि वह यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है या नहीं। दुनिया की नजरों में पाकिस्तान को अब अपनी स्थिति साफ करनी होगी।

हाफिज सईद पर पाक कर रहा ड्रामा : विदेश मंत्रालय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित अंतरराष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन भारत उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है। भारत ने इसे पाकिस्तान का दिखावा और ड्रामा करार दिया है। हाफिज को इसके पहले भी पाकिस्तान सरकार आठ बार गिरफ्तार कर चुकी है और हर बार कुछ दिनों बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। ऐसे में भारत को तभी विश्वास होगा जब गिरफ्तार सईद के खिलाफ पाकिस्तान में गंभीरता से कार्रवाई की जाए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार का कहना है कि सईद संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आतंकवादी घोषित है। संयुक्त राष्ट्र के हर सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ जो भी संभव हो कार्रवाई की जाए। सईद और उसके संगठन के खिलाफ कार्रवाई करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अब यह देखना होगा कि इस बार की गई गिरफ्तारी भी सिर्फ दिखावा है या गंभीरता है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस और प्रभावशाली कदम नहीं उठाता, हमें भरोसा नहीं होगा।

ईरानी टैंकर से गिरफ्तार भारतीयों के मामले कानून करेगा काम

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्पेन के तट के समीप रॉयल जिब्राल्टर मरीन द्वारा जब्त किए गए ईरान के तेल सुपरटैंकर से गिरफ्तार भारतीय नागरिकों के मामले में कानून उचित तरीके से काम करेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन कर सीरिया को तेल आपूर्ति के आरोप में चार जुलाई को ईरान के ग्रेस 1 सुपर टैंकर को जब्त किया गया था। रवीश कुमार ने कहा, 'उन सभी को राजनयिक संपर्क मुहैया करा दिया गया है। मेरा मानना है कि कानून की उचित प्रक्रिया जारी रहेगी।

शिष्टाचार भेंट

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रामनाइक ने गुरुवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। एएनआइ

पूर्व कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर भाजपा में शामिल

राज्य ब्यूरो, गांधीनगर

▸ पूर्व विधायक धवलसिंह ने भी थामा पार्टी का दामन

अल्पेश ठाकोर एवं पूर्व विधायक धवल सिंह झाला ने गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए।

गुजरात के ओबीसी नेता व पूर्व विधायक अल्पेश ठाकोर ने भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया।

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गुजरात यात्रा से एक दिन पहले ठाकोर सेना के अध्यक्ष अल्पेश ठाकोर व पूर्व विधायक धवलसिंह झाला सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदेश भाजपा कार्यालय श्रीकमलम पहुंचे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जीतूभाई वाघाणी ने केसरिया पट्टिका ओढ़ाकर पार्टी में उनका स्वागत किया।

ओबीसी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष तथा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्टतौर पर कहा कि गरीब व आम लोगों की सेवा के लिए सत्ता में होना आवश्यक है। कांग्रेस में रहकर भी उन्होंने गरीब व आम लोगों के हित की बात की, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ही दो माह से खाली है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी व गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा संवेदनशील हैं। उम्मीद है कि राज्य में संपूर्ण शराबबंदी व नशाबंदी की दिशा में वे उल्लेखनीय कार्य करेंगे।

ज्ञात हो, नशाबंदी आंदोलन के कारण चर्चा में आए अल्पेश ने ओबीसी एकता मंच का गठन करते हुए पाटीदारों के ओबीसी में शामिल किए जाने का विरोध किया था। वर्ष 2017 में वह कांग्रेस में शामिल हुए और राधनपुर सीट से विधायक चुने गए। पार्टी से मनमुटाव होने पर उन्होंने हालिया राज्यसभा उपचुनाव के बाद साथी विधायक धवलसिंह के साथ कांग्रेस व विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अल्पेश का राधनपुर से तथा धवलसिंह का बायड से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है।

टॉलीवुड के कई कलाकारों ने थामा भाजपा का झंडा

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल में विभिन्न दलों एवं वर्गों के लोगों का भाजपा में शामिल होना बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को टॉलीवुड के कई कलाकारों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने दिल्ली में बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष, पार्टी के नेता संबित पात्रा एवं मुकुल राय की उपस्थिति में पार्टी का झंडा थामा।

जिन कलाकारों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, उनमें ऋषि कौशिक, पर्ण मित्रा, रूपांजना मित्रा, विश्वजीत गांगुली, देवरंजन नाग, अरिंदम हल्दर, मौमिता गुप्ता, अनिंद्य बनर्जी, सौरभ चक्रवर्ती, रूपा भट्टाचार्य, अंजना बसु व कौशिक चक्रवर्ती शामिल हैं। बंगाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने उक्त कलाकारों का पार्टी में स्वागत किया। घोष ने कहा कि पहले भी बंगाल के कई फिल्म कलाकार भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन वहां के फिल्म माफियाओं ने उनके कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया। घोष ने आरोप लगाया कि बंगाल के फिल्म माफियाओं ने मनोरंजन जगत पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में इन कलाकारों का भाजपा में शामिल होना बड़ी बात है। घोष ने और भी लोगों के भाजपा में शामिल होने की उम्मीद जताई।

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में टॉलीवुड अभिनेत्री दाएं से कंचन मोइत्रा, रूपा भट्टाचार्य, रुपंजना मित्रा, मौमिता गुप्ता और प्रनो मित्रा ने पार्टी की सदस्यता ली। प्रेट्र

रॉबर्ट वाड्रा ने हाई कोर्ट से वापस लिया आवेदन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कठोर कार्रवाई करने से रोकने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल आवेदन को उद्यमी रॉबर्ट वाड्रा ने वापस ले लिया।

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ के समक्ष रॉबर्ट वाड्रा ने कहा,उन्हें निचली अदालत से पहले ही अग्रिम जमानत मिल गई है, ऐसे में इस आवेदन को वह वापस लेना चाहते हैं। वाड्रा ने यह आवेदन एक लंबित याचिका पर दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि मनी लांड्रिंग कानून 2002 के कई प्रावधान असंवैधानिक घोषित हो चुके हैं और एक ही मामले में अधिकार का गलत इस्तेमाल कर कई जांच करने के बाद एफआइआर दर्ज की गई है। इसलिए ईडी द्वारा दर्ज की गई एफआइआर को खारिज किया जाए। ईडी की तरफ से स्टैंडिंग काउंसल अमित महाजन ने पीठ को बताया कि वाड्रा की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया गया है। इस पर पीठ ने वाड्रा को जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई को 21 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। वाड्रा के अलावा उनके करीबी मनोज अरोड़ा ने भी एफआइआर रद करने की मांग की है।

चौटाला परिवार के रिश्तों पर भारी राजनीतिक दुश्मनी की खटास

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

▸ कभी भतीजे दुष्यंत चौटाला की शादी में चाचा अभय ने जमकर डाला था भंगड़ा

▸ लोकसभा नतीजों के बाद अभय ने खुद आगे बढ़कर की थी सुलह की कोशिश

करीब दो साल पहले जब भतीजे दुष्यंत चौटाला की शादी हुई थी, तब चाचा अभय सिंह चौटाला इस महफिल की खास रौनक थे। मारे खुशी के भतीजे दुष्यंत ने चाचा अभय को कंधों पर उठा लिया था। पिता अजय सिंह चौटाला और मां नैना चाचा-भतीजे के प्यार को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। काली शेरवानी पहने दादा ओमप्रकाश चौटाला की आंखों में भी चश्मे के पीछे अलग ही चमक दिखाई दे रही थी।

गुरुवार का दिन इस पारिवारिक माहौल से पूरी तरह अलग था। इस बार जश्न का माहौल अभय सिंह चौटाला के घर में बना। मौका था, अभय के छोटे बेटे अर्जुन चौटाला की सगाई का। राजनीतिक गलियारों में ओमप्रकाश चौटाला के पगड़ी बदल भाई पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल सगाई की इस रस्म के मुख्य गवाह बने। अर्जुन की सगाई में अगर कोई नजर नहीं आया तो ताऊ अजय, ताई नैना और भाई दुष्यंत व दिग्विजय चौटाला। ताऊ देवीलाल के परिवार में राजनीतिक दुश्मनी की यह इंतेहा थी। दोनों भाइयों अजय सिंह और अभय सिंह के बीच राजनीतिक खटास का असर उनके पारिवारिक रिश्तों में साफ नजर आया। आज हालात यह हैं कि दोनों परिवारों ने एक दूसरे की खुशियों से किनारा कर लिया।

दरअसल, ताऊ देवीलाल के इस परिवार में कलह की नींव गोहाना में राज्य स्तरीय जयंती समारोह के दौरान ही पड़ गई थी। दादा ओमप्रकाश चौटाला ने अनुशासनहीनता के आरोप में पहले दुष्यंत और फिर अजय को पार्टी से निकाला। इसके बाद अजय व दुष्यंत ने अलग जननायक जनता पार्टी बना ली। इनेलो विधायक दल के नेता अभय सिंह ने पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने कांग्रेस, इनेलो और जननायक जनता पार्टी को बुरी तरह से शिकस्त दी तो कार्यकर्ताओं को लगा कि अब देवीलाल और चौटाला परिवार की राजनीतिक एकजुटता बेहद जरूरी हो गई है।

चौटाला परिवार के करीबियों का कहना है कि अभय ने इस एकजुटता के लिए शिद्दत से प्रयास भी किए। चाचा रणजीत सिंह को मध्यस्थ बनाया। खुद अभय अजय से मिलने जेल गए। पार्टी के मजबूत सारथी अशोक अरोड़ा और रामपाल माजरा ने भी परिवार की एकजुटता की तमाम कोशिशें कीं, मगर बात नहीं बनी। देवीलाल परिवार के सबसे बड़े मुखिया ओमप्रकाश, उनके अभिन्न मित्र प्रकाश सिंह बादल और अभय के चाचा रणजीत सिंह के जरिये कोशिश की जा रही कि किसी तरह विस चुनाव से पहले दिलों की दूरियां खत्म करने के साथ-साथ दलों की दूरियां भी खत्म की जाएं।

आदिवासियों को गुड़ खिलाने पर 50 खर्च करेगी छग सरकार

रायपुर, नईदुनिया : छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का एलान कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार राज्य में नशाबंदी अभियान चलाएगी। इसके लिए अनुपूरक बजट में 68 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को सदन में बतौर वित्त मंत्री 4341 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इससे राज्य के चालू वित्तीय वर्ष के बजट का आकार 90 हजार 909 करोड़ से बढ़कर 95 हजार 250 करोड़ रुपये पहुंच गया है। अनुपूरक बजट में आदिवासी क्षेत्रों में गुड़ वितरण के लिए 50 लाख, किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने के लिए 768 करोड़ और धान बोनस के लिए 943 करोड़ रुपये रखा है।

सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की संचार क्रांति योजना के लिए अनुपूरक बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने इस योजना के तहत मुफ्त स्मार्ट फोन बांटने के साथ ही मोबाइल नेटवर्क विस्तार की योजना बनाई थी। कांग्रेस सरकार ने मोबाइल वितरण पर तो रोक लगा दी है है, लेकिन जिन क्षेत्रों में मोबाइल बंट चुका है वहां नेटवर्क दुरुस्त करने का फैसला किया है।

बिना व्हिप अधिकार कैसे हो बहुमत परीक्षण : सुरजेवाला

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को सवाल किया कि कर्नाटक में बहुमत परीक्षण कैसे कराया जा सकता है जबकि राजनीतिक पार्टी के व्हिप जारी करने के अधिकार को अदालत के आदेश से निष्प्रभावी कर दिया गया है।

सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बुधवार के आदेश से जितने जवाब नहीं मिले हैं उससे ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा फैसले को लागू करने को लेकर भी कई चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि शक्ति विभाजन का सिद्धांत न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को न सिर्फ अलग करता है, बल्कि एक दूसरे के कामकाज में हस्तक्षेप को भी प्रतिबंधित करता है।

सुरजेवाला ने कहा, 'तथ्य यह है कि शक्ति विभाजन बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। यह सरकार की एक शाखा को दूसरी शाखा पर हावी होने से रोकता है। क्या न्यायपालिका अपने नियम शर्तें थोप सकती है कि बहुमत परीक्षण कैसे कराया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप विधायिका की कार्यवाही को संचालित कर सकती है।'

राज्यपाल ने स्पीकर से कहा था पहले ही दिन कराएं वोटिंग

सदन में दिनभर चले हंगामे व ड्रामे के बाद गुरुवार रात को बेंगलुरु में विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बीएस येद्दयुरप्पा और पार्टी के अन्य विधायक। प्रेट्र

▸ पहले पेज का शेष

सत्तारूढ़ कांग्रेस-जदएस गठबंधन सरकार के इरादे भांपकर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल वजुभाईवाला से मुलाकात कर मांग की थी कि वह स्पीकर रमेश कुमार को गुरुवार को ही वोटिंग कराने का निर्देश दें। स्पीकर ने बताया कि उन्हें राज्यपाल ने मतदान गुरुवार को ही कराने की सलाह दी है। हालांकि देर शाम तक बहस चलने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दिन में भाजपा नेताओं ने आशंका प्रकट की थी कि कुमारस्वामी सरकार अंतिम समय की जोड़तोड़ जारी रखने के लिए बहस को लंबा खींच सकती है। यही बात उन्होंने राज्यपाल से भी कही थी।

कठुआकांड

न्यायाधीश की टिप्पणी, ऐसे मामले को लंबे समय तक लटकाया नहीं जा सकता

सभी अर्जियां को एक साथ सुनेगा हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में पीड़िता के पिता की याचिका पर जस्टिस राजीव शर्मा पर आधारित खंडपीठ ने कहा कि अदालत न्याय करने के लिए है और ऐसे मामले को लंबे समय लटकाया नहीं जा सकता। पीठ ने पीड़िता के पिता की याचिका और पठानकोट अदालत के फैसले के खिलाफ अभियुक्तों की अपीलों पर एक साथ सुनवाई करने के निर्देश दिए।

पीड़िता के पिता ने याचिका दायर कर पठानकोट अदालत की तरफ से दोषी ठहराए गए छह अभियुक्तों की सजा बढ़वाने की मांग थी। जस्टिस राजीव शर्मा ने टिप्पणी तब की जब जम्मू और कश्मीर सरकार की पैरवी करने आए सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा ने थोड़ी लंबी तारीख दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार इन दिनों इस मामले में एक अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने सुनवाई को कम से कम चार सप्ताह के लिए टाले जाने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले का रिकॉर्ड काफी बड़ा है, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 114 गवाहों की गवाहियां दर्ज की थीं। मुख्य अभियुक्त सांझी राम के वकील जेएस बेदी ने भी चीमा की इस मांग का समर्थन किया। चीमा की सुनवाई को 15 अगस्त के बाद तक के लिए स्थगित किए जाने की मांग को अस्वीकार करते हुए जस्टिस राजीव शर्मा ने कहा कि ऐसा कौन सा मामला होता है, जिसका रिकॉर्ड बड़ा न हो। अगर अन्य पक्षों के वकील अपनी दलीलें पेश करने के लिए तैयार नहीं हैं तो उन्हें ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड नहीं मंगवाना चाहिए था। उन्होंने सुनवाई को 7 अगस्त तक स्थगित करते हुए कहा कि अदालत इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी।

कोर्ट का प्रतीकात्मक फोटो

दोषी पुलिस अधिकारियों के वकील ने की सजा निलंबित करने की मांग

सुनवाई के दौरान दोषी ठहराए गए तीन पुलिस अधिकारियों के वकील ने उनकी सजा निलंबित किए जाने की मांग की। पीड़िता के पिता के वकील उत्सव बैंस ने कहा कि यह सिर्फ साक्ष्यों से छेड़छाड़ का केस नहीं किसी को हत्या के लिए उकसाने का मामला है।

पिता ने कहा, मिले फांसी की सजा

छह अभियुक्तों को सुनाई गई सजा को नाकाफी बताते हुए मृतका के पिता ने याचिका में कहा है कि यह मामला 'रेअरेस्ट ऑफ दि रेअर' की श्रेणी में आता है और अभियुक्तों को सजा देने में ट्रायल कोर्ट ने नरमी बरती है। उन्होंने पठानकोट अदालत द्वारा बरी किए गए सातवें आरोपी विशाल जंगोत्रा की रिहाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है।

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज ने राहुल को कहा रणछोड़ दास गांधी

नईदुनिया, रायपुर : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके राहुल गांधी को रणछोड़ दास गांधी बताया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के सदस्यता अभियान की समीक्षा करने पहुंचे चौहान ने कहा कि जब कप्तान ही नाव छोड़ भागे तो विधायक क्यों नहीं भागेंगे।

भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में शिवराज ने कहा कि जब कोई जहाज डूबता है तो कैप्टन अंतिम समय तक जहाज में रुक कर सबको बचाता है, लेकिन जब कांग्रेस की नैया डूबी तो सबसे पहले अध्यक्ष ही भागे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के बयान पर शिवराज सिंहने पलटवार करते हुए कहा कि जब कैप्टन ही नाव छोड़कर भाग गए तो विधायक क्यों नहीं भागेंगे। कर्नाटक के सियासी संकट पर उन्होंने कहा कि वहां जब से जनता दल (सेकुलर) और कांग्रेस सरकार बनी है, उसी दिन से सिद्धारमैया डंडे लेकर कुमारस्वामी के पीछे पड़े हैं। सिद्धारमैया ही सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं।

2.32 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। तीन साल बाद यात्रा का आंकड़ा तीन लाख के पार पहुंचने की उम्मीद है। अभी यात्रा शुरू हुए 18 दिन ही हुए हैं। 15 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन यह संपन्न होगी।

कोयला घोटाले को भी पीछे छोड़ सकता है भूमि आवंटन घोटाला

कार्रवाई ▸ घोटाले को उजागर करने के लिए आयकर विभाग की टीम 2017 से है सक्रिय

दो लाख करोड़ रुपये के पार जाने की संभावना

कुंदन तिवारी, नोएडा

देश में सबसे बड़े घोटाले के तौर पर अब तक लोग केवल कोयला आवंटन घोटाले को जानते हैं, लेकिन जल्द ही इसका रिकार्ड नोएडा में भूमि आवंटन घोटाला तोड़ने वाला है। यह घोटाला दो लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है। इसको उजागर करने के लिए आयकर विभाग की टीम नोएडा में 2017 से सक्रिय है। गुरुवार को नोएडा में बसपा प्रमुख मायावती के भाई की पत्नी विचित्र लता की सेक्टर-94 की प्रॉपर्टी अटैच किया जाना इसी कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है।

आयकर सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संयुक्त निर्देश पर नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भूमि आवंटन की फाइल को दोबारा 2017 में खोला गया था। यह उसी फाइल की जांच का हिस्सा है, जिसे तत्कालीन भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने 2011-12 में दिल्ली आयकर विभाग को सौंपी थी। इसमें दो लाख करोड़ रुपये से अधिक भूमि आवंटन घोटाले को उजागर करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व उनके भाई की जांच करने को भी कहा था। इसमें उन 13 लोगों की सूची भी उपलब्ध कराई गई थी, जो इस घोटाले के सूत्रधार थे और जिनका काम घोटाले की रकम को विभिन्न जगहों पर खपाना था।

हालांकि उन दिनों केंद्र में कांग्रेस व राज्य में समाजवादी की सरकार थी। केंद्र की सरकार सपा व बसपा के सहयोग से चल रही थी। ऐसे में इस शिकायत की फाइल को सुबूत होने के बावजूद दबा दिया गया। बाद में आनंद को आयकर विभाग से क्लीन चिट मिल गई। इस शिकायत सूची में यादव सिंह सहित अन्य के नाम भी शामिल रहे।

यादव सिंह नोएडा प्राधिकरण की अंडर ग्राउंड केबलिंग के घोटाले में सीबीआइ के शिकंजे में पहले ही फंस चुका है। इसलिए अब यादव से तो वहीं पूछताछ होगी, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार आने और केंद्र में पहले से मोदी सरकार के मौजूद होने से इस शिकायत पर दोबारा से जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों का कहना है कि इस जांच और कार्रवाई की सिफारिश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी। इसमें उनके पास इस मामले पर आरोपितों की शिकायत आने का हवाला दिया गया है। इसके बाद भूमि आवंटन घोटाले को उजागर करने का प्रयास शुरू कर दिया गया।

नोएडा के सेक्टर-44 बी-182 स्थित आनंद कुमार की कोठी। जागरण

सात सौ रुपये की नौकरी से अकूत संपत्ति के मालिक

नोएडा में आनंद कुमार नामी-बेनामी अकूत संपत्ति के मालिक हैं। अनुमान के मुताबिक आनंद व उनकी पत्नी के नाम कुल 1350 करोड़ रुपये की चल अचल संपत्ति है। उन पर सत्ता का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। आनंद कुमार नोएडा विकास प्राधिकरण में महज दो सौ रुपये ग्रेड पे पर 1996 में जूनियर असिस्टेंट के पद पर तैनात हुए थे। उस दौरान आनंद का मासिक वेतन महज सात सौ रुपये था, लेकिन वह सात वर्ष की छोटे समय की नौकरी में ही अचानक चर्चा में आ गए और आयकर विभाग ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच शुरू कर दी। उस समय आनंद ने नोएडा के पॉश सेक्टर-44 में 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 450 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित कराया था। बाद में विवाद के कारण यह भूखंड प्राधिकरण में सरेंडर करना पड़ा। 2003 में नौकरी भी छोड़नी पड़ी। हालांकि इसके बाद आनंद ने खूब संपत्ति अर्जित की। वर्तमान में आनंद और उनकी पत्नी 12 कंपनियों के मालिक हैं, अधिकांश संपत्ति बसपा शासन काल में आवंटित हुई हैं। बिल्डरों को पहले भू आवंटन के दौरान 30 प्रतिशत राशि जमा करनी होती थी, बसपा शासन काल में इस दर को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। इसका फायदा आनंद ने उठाया।

बढ़ेंगी मायावती की सियासी मुश्किलें

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▸ भाई आनंद कुमार की अकूत संपत्ति को लेकर असंतोष बढ़ना संभव

आयकर विभाग द्वारा भाई आनंद कुमार की 400 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती की राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। परिवारवाद के आरोपों से घिरी मायावती को आनंद कुमार की संपत्ति को लेकर उठते विवादों पर सफाई देना आसान नहीं होगा। असली समस्या अनुसूचित जाति के वोटरों में उठते सवालों को लेकर होगी। आयकर की कार्रवाई के बाद भीम आर्मी जैसे संगठनों को आनंद की बेनामी संपत्ति पर बसपा को घेरने का मौका भी मिलेगा।

उत्तर प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के अलावा 2022 के आम चुनाव पर दुष्प्रभाव पड़ने की खतरा जता रहे दलित चिंतक डा. चरण सिंह का दावा है कि बहुजन हिताय, बहुजन समाज के नारे को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय में बदलकर सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी बसपा प्रमुख अपने ही जाल में उलझ रहीं हैं। परिवारवाद का विरोध करने वाली बसपा कांशीराम के मूल मिशन से भटक चुकी है। समर्पित कार्यकर्ताओं को किनारे कर भाई व भतीजे को संगठन में सर्वोपरि बनाने के फैसले का पार्टी के भीतर अभी खुलकर विरोध भले ही न दिख रहा हो परंतु असंतोष से इन्कार नहीं किया जा सकता।

मायावती फाइल फोटो

एक कोआर्डिनेटर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पार्टी को परिजन हिताय परिजन सुखाय की राह पर ले जाने का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मायावती द्वारा मनमाने एकतरफा फैसले लेने का ही नतीजा है कि पार्टी से पुराने समर्पित व विश्वसनीय नेता एक एक कर किनारा करते जा रहे हैं।

विरोधियों को दुष्प्रचार का मौका : आनंद की संपत्ति में सात वर्ष के भीतर 18 हजार प्रतिशत बढ़ोत्तरी होना, विरोधियों के लिए बसपा पर हमलावर होने का हथियार सिद्ध होगा। एडवोकेट लीलापत का कहना है कि अनुसूचित जाति के गरीबों को गुमराह कर अपने परिवार को धन्ना सेठों की श्रेणी में ले जाने का जवाब तो मायावती को समाज को देना ही होगा। बसपा से निष्कासित एक नेता का कहना है कि पार्टी को पैसे और परिवार में ही समेट देने वालों से बाबा साहब का मिशन पूरा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

मायावती बोलीं-न डरेंगे और न झुकेंगे

राब्यू, लखनऊ : भाई आनंद कुमार पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा पर निशाना साधा। गुरुवार रात ट्वीट में उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से बसपा डरने व झुकने वाली नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, 'भाजपा केंद्र की सत्ता का अभी भी दुरुपयोग करके अपने विपक्षियों को षड्यंत्र के तहत जबरन फर्जी मामलों में फंसाकर प्रताड़ित कर रही है। इसी क्रम में अब मेरे भाई-बहनों आदि को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, जो अति निंदनीय है। इससे बसपा डरने व झुकने वाली नहीं है। ऐसी ही घिनौनी हरकत इसी पार्टी की सरकार ने वर्ष 2003 में भी आयकर व सीबीआइ आदि के जरिये हमारे विरुद्ध की थी, जो सर्वविदित है। जिसमें फिर हमें अंत में काफी संघर्ष के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला था।'

रामपुर के सपा सांसद आजम खां को प्रशासन ने भूमाफिया घोषित किया

जागरण संवाददाता, रामपुर

▸ रामपुर जिला प्रशासन ने भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज कराया उप्र सरकार के पूर्व मंत्री का नाम

▸ जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप

▸ जमीनों पर कब्जे के आरोप में थाने में दर्ज हो चुके हैं 14 मुकदमे

जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीनें कब्जा करने के आरोप में फंसे सपा सांसद आजम खां को प्रशासन ने भूमाफिया घोषित कर दिया है। उप जिला अधिकारी की ओर से उनका नाम एंटी भू माफिया पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया है। इस पोर्टल पर उन्हीं लोगों के नाम दर्ज कराए जाते हैं जो जमीनों पर कब्जा करते हैं और उन्हें छोड़ते नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति आजम खां के खिलाफ पिछले एक सप्ताह के दौरान जमीन कब्जाने के 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

आलियागंज के 26 किसानों ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खां ने उनकी जमीन जबरन जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली है। इनमें से 12 किसानों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जबकि 14 किसानों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी है। एक मुकदमा 12 जुलाई को प्रशासन की ओर से दर्ज कराया गया। साथ ही उसी रात यूनिवर्सिटी परिसर में सुरक्षा अधिकारी आले हसन खां के आवास पर छापा मारा। तब आले हसन हाथ नहीं लग सके, लेकिन पुलिस ने उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आले हसन के बेटे और पत्नी के खिलाफ भी सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया।

इससे पहले एक जून को भी प्रशासन ने आजम खां और आले हसन के खिलाफ कोसी नदी क्षेत्र की पांच हेक्टेयर सरकारी जमीन कब्जाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस तरह आजम खां और आले हसन खां के खिलाफ जमीन कब्जाने के आरोप में 14 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पिछले साल 14 मुकदमे राजस्व परिषद में भी दर्ज कराए गए थे। इनमें आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए बिना अनुमति लिए अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन खरीदी गई। ग्राम समाज की जमीन के बदले में कम उपयोगी जमीन दी गई।

स्पेशल टीम करेगी जांच : पुलिस अधीक्षक डाक्टर अजय पाल शर्मा का कहना है कि सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमों की विवेचना तीन सदस्यीय स्पेशल टीम करेगी। इस टीम में निरीक्षक और उपनिरीक्षक शामिल रहेंगे। उन्होंने बताया कि आजम खां सांसद हैं, अभी उनकी हिस्ट्रीशीट नहीं खोली गई है।

आजमा खां का फाइल फोटो। आर्काइव

शासनादेश के मुताबिक ऐसे लोगों को भूमाफिया घोषित किया जाता है जो दबंगई से जमीनों पर कब्जा करने के आदी हैं। जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है वे लोग अवैध कब्जे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश एंटी भू माफिया पोर्टल पर नाम दर्ज होने के बाद सरकार भी इसकी निगरानी करती है।

-आन्जनेय कुमार सिंह, डीएम, रामपुर

मेरे खिलाफ दर्ज कराए जा रहे सारे मुकदमे फर्जी हैं। यह हमारे खिलाफ सरकार और प्रशासन द्वारा रची गई गहरी साजिश है। हमने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए एक-एक इंच जमीन नियमानुसार खरीदी है। जिन किसानों से मुकदमे कराए जा रहे हैं, उनसे हमने 14 साल पहले जमीन का बैनामा कराया। चेक से भुगतान किया। हमें परेशान और बदनाम किया जा रहा है।

-आजम खां, सांसद, रामपुर और कुलाधिपति, जौहर विवि

चंद्रयान-2 को अब 22 जुलाई को किया जाएगा लांच : इसरो

चेन्नई, प्रेट्र : भारत के महत्वाकांक्षी दूसरे मून मिशन चंद्रयान-2 को अब 22 जुलाई को दोपहर 2.43 बजे लांच किया जाएगा। 15 जुलाई को जीएसएलवी रॉकेट में कुछ तकनीकी खराबी के कारण लांचिंग आखिरी वक्त में रोक दी गई थी। इसरो ने गुरुवार को ट्वीट किया, 'चंद्रयान-2 की लांचिंग जो 15 जुलाई 2019 को तकनीकी खराबी के चलते रोक दी गई थी, वह अब सोमवार 22 जुलाई 2019 को दोपहर दो बजकर 43 मिनट पर होगी।' 'बाहुबली' कहे जा रहे भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी जीएसएलवी मार्क-।।। के जरिये 15 जुलाई को तड़के 2.51 बजे चंद्रयान-2 को लांच किया जाना था, लेकिन रॉकेट में खराबी का पता चलने पर तय समय से 56 मिनट 24 सेकेंड पर लांचिंग रोक दी गई थी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लांच पैड दो से जीएसएलवी रॉकेट से उपग्रह को छोड़ा जाएगा। इसरो ने कहा कि तकनीकी खराबी का पता लगाने और उसे दुरुस्त करने के उपाय सुझाने के लिए गठित कमेटी के सुझावों पर खामी को दूर कर लिया गया है।

मॉब लिंचिंग रोकने में विफल राज्यों के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं

▸ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने उन्मादी भीड़ की हिंसा (मॉब लिंचिंग) की घटनाओं पर लगाम लगाने में कथित रूप से विफल रहे कुछ राज्यों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि अवमानना की याचिका पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। पीठ ने वकील को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी कि शीर्ष कोर्ट के फैसलों पर कई राज्य सरकारों ने अमल नहीं किया है और ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

इन फैसलों में कोर्ट ने देश में भीड़ हिंसा एवं गोरक्षा के नाम पर होने वाली घटनाओं से निपटने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए थे। पीठ ने तत्काल सुनवाई से इन्कार करते हुए कहा कि मामलों पर तत्काल सुनवाई के संबंध के बारे में वकीलों के 50 फीसद बयान गलत पाए जाते हैं।

पिछले साल 17 जुलाई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि 'भीड़तंत्र के भयानक कृत्यों' को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीठ ने लिंचिंग एवं गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। पीठ ने यह भी कहा था कि केंद्र को ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटने के लिए नया कानून लाने पर विचार करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट फाइल

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, होमबायर्स का मुद्दा सुलझाने पर हो रहा काम

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह कानूनों में संशोधन का काम कर रही है ताकि बड़े बिल्डरों से अपना घर हासिल करने का अरसे से इंतजार कर रहे होम बायर्स को राहत मिल जाए। केंद्र सरकार ने घर खरीददारों की परेशानियों को दूर करने का आश्वासन देते हुए अदालत से कुछ मोहलत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक अगस्त की तारीख तय कर दी है।

केंद्र सरकार ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जिल) मामले की याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविल्कर और दिनेश महेश्वरी की खंडपीठ को बताया कि इंसोल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड (आइबीसी) में संशोधन किया जा रहा है। ताकि होम बायर्स के हितों की रक्षा की जा सके। केंद्रीय कैबिनेट विगत बुधवार को ही इन संशोधनों को मंजूरी दे चुकी है। इसके तहत कॉरपोरेट प्रस्ताव प्रक्रिया को 330 दिन की समय-सीमा दी गई है। इसमें मुकदमे और अन्य न्यायिक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। सरकार ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल जिल के होम बायर्स के मामले की सुनवाई 22 जुलाई को करेगा। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 21 हजार होम बायर्स के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 में पूर्ण शक्ति देने का उपाय करना चाहिए।

पत्नी अपूर्वा ने की थी रोहित शेखर की हत्या

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र

▸ वैवाहिक जीवन और प्रॉपर्टी नहीं मिल पाने से तनाव में थी अपूर्वा

▸ 518 पन्ने के आरोप पत्र में 56 लोगों को बनाया गया गवाह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी (40) हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बृहस्पतिवार को साकेत कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर दिया। इसमें पुलिस ने बताया है कि पत्नी अपूर्वा शुक्ला (35) ने रोहित का गला, मुंह व नाक दबा दिया था, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। 518 पन्ने के आरोप पत्र में पुलिस ने रोहित के परिवार के ही अधिकतर सदस्यों और उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी समेत 56 लोगों को गवाह बनाया है। सुबूत के तौर पर सभी के बयान, फॉरेंसिक व इलेक्ट्रानिक साक्ष्य, मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड व फोटोग्राफ को रखा गया है। शुक्रवार को कोर्ट आरोप पत्र पर संज्ञान लेगी। 15 अप्रैल की देर रात अपूर्वा ने रोहित की हत्या की थी।

आरोप पत्र में बताया गया है कि रोहित और उनके परिजनों के व्यवहार से अपूर्वा बेहद मानसिक तनाव में थी। घटना वाली रात 15 अप्रैल को रोहित के उत्तराखंड से घर लौटने पर पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। रोहित को कई बीमारियां थीं और उन्होंने अत्यधिक शराब पी रखी थी, जिससे वह प्रतिरोध नहीं कर पाए। झगड़े के दौरान अपूर्वा ने गुस्से में आकर रोहित का गला दबा दिया था। मूल रूप से इंदौर की रहने वाली अपूर्वा शुक्ला पेशे से अधिवक्ता है। उसके पिता व परिवार के अन्य सदस्य भी अधिवक्ता हैं, जिससे उसे कानून के हर दाव पेंच के बारे में जानकारी थी। अपूर्वा 2016 से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी। लिहाजा पहले कई दिनों तक पूछताछ में वह क्राइम ब्रांच को गुमराह करती रही, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों व फॉरेंसिक रिपोर्टों के आधार पर लगातार पूछताछ पर उसने 24 अप्रैल को हत्या करने की बात कुबूल ली थी।

जांच में सामने आया था कि बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाली अपूर्वा ने रोहित से शादी करने के पीछे बड़े-बड़े सपने संजो रखे थे। दरअसल 2017 में मेट्रीमोनियल साइट के जरिये उसका रोहित से परिचय हुआ था। अपूर्वा को लगा कि एनडी तिवारी कई बार उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। रोहित के नाना भी चार बाद कैबिनेट मंत्री रहे हैं। ऐसे में उनके जैविक पुत्र रोहित शेखर को विरासत में अकूत संपत्ति मिलेगी। उसे लगा कि रोहित से शादी कर उसकी जीवनशैली और भी ऊंची हो जाएगी। इस तरह की उम्मीदें पाल अपूर्वा ने पिछले साल 11 मई को रोहित से शादी की। शादी इंदौर में हुई थी। इसके बाद अपूर्वा ने जब दिल्ली आकर रोहित के साथ डिफेंस कॉलोनी स्थित घर सी-329 में रहना शुरू किया, तो उसे सच्चाई का पता चला। उसे लगने लगा था कि वह बुरी तरह ठगी गई है। उसे पता लग गया था कि रोहित के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तिलक लेन जहां उज्ज्वला रहती हैं, वह सरकारी क्वार्टर है। डिफेंस कॉलोनी वाला घर ही केवल उज्ज्वला के नाम पर है। जो 400 गज में बना है। उसकी भी वसीयत में उज्ज्वला ने लिखा है कि उनके मरने के बाद घर के 60 फीसद हिस्से का मालिक रोहित व 40 फीसद का सिद्धार्थ होंगे। सिद्धार्थ उज्ज्वला के दूसरे पति का बेटा है। वह डिफेंस कॉलोनी में ही रहते हैं। उन्होंने शादी नहीं की है। वह भी कई बीमारियों से ग्रसित हैं। उन्होंने भी कह रखा है कि उनकी मौत के बाद उनके हिस्से की प्रॉपर्टी राजीव के नौ वर्षीय बेटे पोलू को दे दी जाए। राजीव, उज्ज्वला के दूसरे पति के चचेरे भाई का बेटा है, जो उज्जवला की देखभाल करने के लिए उनके साथ तिलक लेन में रहते हैं। राजीव की पत्नी कुमकुम, बेटा के साथ वहीं रहती हैं।

जांच में पता चला था कि अपूर्वा ने अकेले हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। उसने हत्या के लिए घर के किसी सदस्य का सहयोग नहीं लिया।

यह था मामला : रोहित शेखर तिवारी 15 अप्रैल की रात शराब के नशे में उत्तराखंड के कोटद्वार से वोट डालकर डिफेंस कॉलोनी स्थित घर लौटे थे। देर रात खाना-खाने के बाद वे अपने कमरे में सोने चले गए थे। अनबन रहने के कारण पत्नी अपूर्वा बराबर वाले कमरे में अकेले सोती थी। अगले दिन मंगलवार दोपहर चार बजे घरेलू सहायक गोलू जब उनके कमरे में गया तो रोहित के मुंह व नाक से खून निकला हुआ था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

रोहित शेखर और उनकी पत्नी अपूर्वा की फाइल फोटो।

मणिपुर फर्जी मुठभेड़ मामलों की सुनवाई को पुनर्गठित होगी पीठ

▸ सुप्रीम कोर्ट ने पीठ गठित करने पर जताई सहमति

▸ जस्टिस लोकुर के सेवानिवृत्त होने के बाद नहीं हो रही थी सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में गैर न्यायिक हत्याओं के मामलों की सुनवाई के लिए पीठ पुनर्गठित करने पर सहमत हो गया है। उग्रवाद प्रभावित राज्य में सेना, असम राइफल्स और राज्य पुलिस पर इन हत्याओं का आरोप है।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह पीठ पुनर्गठित करने का प्रयास करेगी, क्योंकि इन मामलों की सुनवाई कर रहे जस्टिस एमबी लोकुर पिछले साल दिसंबर में सेवानिवृत्त हो गए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वेज ने कहा था कि जस्टिस लोकुर के सेवानिवृत्त होने के बाद से मामलों की सुनवाई नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में साल 2000 से 2012 के बीच सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा की गई कथित 1,528 गैर न्यायिक हत्याओं के मामलों की सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे। फर्जी मुठभेड़ों में हुई इन हत्याओं के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को फटकार भी लगाई थी। सेना ने 20 अप्रैल, 2017 को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जम्मू-कश्मीर और मणिपुर जैसे अशांत राज्यों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए उसके खिलाफ केस नहीं दर्ज किए जा सकते हैं। इन हत्याओं की न्यायिक जांचों पर सेना ने सवाल उठाते हुए उसे पक्षपातपूर्ण करार दिया था। सेना का कहना था कि स्थानीय जिला जजों द्वारा न्यायिक जांच की गई थी। केंद्र सरकार ने भी सुरक्षा बलों का बचाव किया था।

मिसाल

मगध महिला कॉलेज में 43 वर्षीय मां स्नातक प्रथम वर्ष में तो बेटी द्वितीय वर्ष में, सुलेखा ने बताया- शुरू में कॉलेज गेट पर सुरक्षाकर्मी करते थे टोकाटाकी, अब सब कुछ सामान्य

एक ही कॉलेज में मां और बेटी कर रहीं ग्रेजुएशन

अंकिता भारद्वाज, पटना

सपने पूरे करने की राह में उम्र बाधा नहीं बन सकती। तभी तो सुलेखा ने 43 साल की आयु में भी अपनी बेटी श्रेया के साथ मगध महिला कॉलेज में इस शैक्षिक सत्र से अपना भी नामांकन कराया है। बेटी इसी कॉलेज से जीव विज्ञान विषय से ऑनर्स द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही, तो मां हिंदी विषय से ऑनर्स कर रही हैं। खास बात यह कि वह बेटी से कॉलेज में जूनियर हैं, क्योंकि वह प्रथम वर्ष में हैं।

43 की उम्र में फिर से पढ़ाई : शादी के 25 साल बाद बच्चों की जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर सुलेखा ने उच्च शिक्षा की ललक पूरी करने के लिए 2019 में मगध महिला कॉलेज में नामांकन कराया है। सुलेखा बताती हैं कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद 1994 में उनकी शादी वैशाली जिले के सुबोध कुमार सुमन से हुई थी। शादी के बाद जिम्मेदारियां पढ़ाई में बाधा बन गईं। हालांकि पारिवारिक झंझावातों के बीच भी पुस्तकों से नाता जोड़े रखा। जब भी मौका मिलता, वह अपने बच्चों की किताबें ही पढ़ती थीं।

छात्रा श्रेया और उनकी मां क्लास करने साथ कॉलेज जाती हुईं। सीपी मिश्र।

मां को लंच देकर भेजती हूं कॉलेज, फिर खुद होती हूं तैयार

बेटी श्रेया, जो स्वयं मगध महिला कॉलेज में जीव विज्ञान की द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं, बताती है कि पहले मां को लंच देकर कॉलेज भेज देते हैं, फिर खुद तैयार होती हूं। श्रेया ने कहा, 'शुरू में जैसे मां हमें स्कूल भेजती थीं, अब मैं उन्हें कॉलेज भेजती हूं।'

मुझे पता चला कि कॉलेज में 43 साल की महिला ने नामांकन कराया है तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर अगले ही पल सुलेखा के साहस और आत्मविश्वास पर गर्व भी हुआ।

-प्रो. शशि शर्मा, प्राचार्य, मगध महिला कॉलेज

बच्चों ने भरवाया फॉर्म : सुलेखा कहती हैं, 'शादी के बाद शुरू में उन्होंने कॉलेज में नामांकन करा पढ़ाई का प्रयास जरूर किया, पर घरेलू कारणों से कामयाबी नहीं मिल पाई।' 1996 में बेटे सुमित का जन्म हो गया और 1998 में बेटी श्रेया का। पति सुबोध कुमार सेना में सूबेदार थे, इसलिए घर-बच्चों की जिम्मेदारियां कंधे पर आ गई तो उन्हें समय ही नहीं मिल पाया। बच्चे बड़े हो गए। बच्चों को मेरे सपनों की जानकारी थी, इसलिए बेटे व बेटी ने मिलकर नामांकन फॉर्म भरवाया। सुलेखा ने बताया कि कॉलेज में नामांकन से लेकर परीक्षा तक की तैयारी बेटी व बेटे ने कराई। बेटा इंटरनेट से सवाल निकाल उन्हें सॉल्व कराने में मदद करता था, वहीं बेटी चाय-कॉफी देकर पढ़ाई कराती थी। बच्चों की बदौलत उनका सेकेंड लिस्ट में 46 प्रतिशत के साथ नाम आ गया।

कई बार हुई परेशानी : सुलेखा बताती हैं कि शुरू में जब वह परीक्षा देने या नामांकन के लिए कॉलेज जाती थीं, तो उन्हें गार्ड द्वारा गेट पर रोक लिया जाता था। यह कहकर कि अभिभावकों को अंदर जाने की मनाही है।

ओवर स्पीड पर तुरंत चालान अगले टोल पर होगा भुगतान

सौरभ शुक्ला, लखनऊ

यमुना एक्सप्रेस-वे पर पिछले दिनों हुए भीषण बस हादसे के बाद सुरक्षा के मद्देनजर कई कदम उठाए गए हैं। इसके तहत बढ़ते हादसों को रोकने के लिए ओवरस्पीड की जांच के लिए कैमरे लगा दिए गए हैं। एक्सप्रेस-वे पर हल्के वाहनों के चालकों के लिए 100 किमी प्रति घंटा और भारी (व्यावसायिक) वाहनों के लिए 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड तय की गई है। इससे अधिक रफ्तार होने पर टोल पर लगे कैमरों की मदद से उनका स्वतः चालान हो जाएगा। एक टोल पर अगर चालान हुआ तो अगले पर पहुंचते ही आपको जानकारी हो जाएगी। वहां जुर्माने की भरपाई कर छुटकारा भी पाना होगा। चालान की नई व्यवस्था 17 जुलाई से लागू हो गई है। पिछले दिनों आगरा एक्सप्रेस-वे पर हुए बस हादसे के बाद डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश पर आइजी यातायात निदेशालय दीपक रतन ने नियम तय किए हैं।

यमुना एक्सप्रेस-वे

एक्सप्रेस-वे पर बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर यह व्यवस्था की गई है। इस मार्ग पर दूसरे राज्यों के भी काफी लोगों का आना-जाना रहता है। चालान होने पर उन्हें भी वाहन छुड़ाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी।

दीपक रतन, आइजी यातायात निदेशालय, उप्र

टोल पर तैनात की गई जिलों की पुलिस : यमुना एक्सप्रेस-वे पर आगरा, मथुरा और जेवर मिलाकर तीन टोल प्लाजा हैं। तीनों पर संबंधित जिलों की पुलिस तैनात कर दी गई है, जो वाहन चालकों से जुर्माने की राशि वसूल कर उन्हें क्लीयरेंस स्लिप तत्काल दे देगी। टोल प्लाजा पर लगे कैमरों की जद में आते ही ओवर स्पीड वाहनों का चालान हो जाएगा। ओवर स्पीड पर वाहन चालकों को एक हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।

99 आतंकी हमले हुए हैं वर्ष 2016 से जम्मू-कश्मीर में सेना पर। वहीं 32 आतंकी हमले पूर्वोत्तर में सेना पर हो चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित जवाब में रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने यह जानकारी उपलब्ध कराई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 19 जुलाई 2019

झारखंड में मुठभेड़ में तीन उग्रवादी ढेर, दो एके-47 राइफल बरामद

कार्रवाई ▸ झारखंड जनमुक्ति परिषद के थे उग्रवादी, एक जख्मी को लेकर भागे उसके साथी

लोहरदगा के सहेदापाट जंगल में हुई मुठभेड़

जागरण संवाददाता, लोहरदगा

झारखंड में लोहरदगा जिले के सहेदापाट जंगल में गुरुवार को दिन में पुलिस और उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के हथियारबंद दस्ते के साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इसमें जेजेएमपी के पप्पू लोहरा दस्ते के तीन उग्रवादियों को पुलिस ने मार गिराया। एक अन्य उग्रवादी भी पुलिस की गोली से जख्मी हुआ है। उसे उसके साथी अपने साथ लेते गए। पुलिस ने उग्रवादियों से दो एके-47 राइफल बरामद की है। एसपी आलोक ने बताया कि उन्हें उग्रवादियों के पेशरार के सहेदापाट जंगल में होने की सूचना मिली थी। इस जानकारी के बाद लोहरदगा और लातेहार पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी अभियान शुरू किया। पुलिस की टीम जैसे ही सहेदापाट जंगल पहुंची, जेजेएमपी के कमांडर पप्पू लोहरा के दस्ते ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की है। इस दौरान तीन उग्रवादियों की मौत हो गई।

उग्रवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाती लोहरदगा और लातेहार जिले की पुलिस। जागरण

लातेहार में माओवादियों ने चार वाहनों में लगाई आग

जागरण संवाददाता, लातेहार : लातेहार जिले के बारेसाढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात भाकपा माओवादी के सशस्त्र दस्ते ने जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने चार वाहन को आग के हवाले कर दिया। इसमें एक ट्रक, एक बाइक व दो ट्रैक्टर शामिल हैं। बताया गया कि देर रात बड़ी संख्या में नक्सली बारेसाढ़ पहुंचे और स्थानीय निवासी अशोक प्रसाद गुप्ता की खोजबीन करने लगे। परिवार के लोगों ने जब यह बताया कि अशोक घर पर नहीं हैं तो नक्सलियों ने घर के बाहर खड़े दो ट्रैक्टर, एक ट्रक तथा एक बाइक को आग के हवाले कर दिया।

झारखंड में इस साल मारे जा चुके हैं 22 उग्रवादी

राज्य ब्यूरो, रांची : नक्सलियों पर लगातार दबिश जारी है। झारखंड पुलिस का हौसला बुलंद है। बुलंद हौसले का ही परिणाम है कि इस साल अब तक 25 मुठभेड़ में 22 उग्रवादी मारे जा चुके हैं। इनमें पीएलएफआइ के 11 उग्रवादी, भाकपा माओवादियों के पांच, तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के तीन व झारखंड जन मुक्ति परिषद् के तीन उग्रवादी शामिल हैं। यह जानकारी पुलिस मुख्यालय में गुरुवार की शाम संवाददाता सम्मेलन के दौरान आइजी ऑपरेशन आशीष बत्रा ने दी। इससे पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे ने दूरभाष पर लोहरदगा में हुई मुठभेड़ की पूरी जानकारी ली और इसमें शामिल जिला पुलिस तथा सीआरपीएफ के जवानों का हौसला बढ़ाया व शाबाशी भी दी। उन्होंने सभी जिलों को यह स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज होगा।

देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा दाऊद का भतीजा गिरफ्तार

मुंबई, प्रेट्र : देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भतीजे रिजवान कासकर को पुलिस ने बुधवार की रात मुंबई हवाईअड्डे से गिरफ्तार कर लिया। रिजवान की गिरफ्तारी रंगदारी मांगने के मामले में की गई है।

रिजवान दाऊद के भाई इकबाल कासकर का बेटा है। इकबाल भी रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और फिलहाल पड़ोसी जिले ठाणे की एक जेल में बंद है। अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो दिन पहले मुंबई पुलिस ने उगाही के मामले में अहमद रजा को गिरफ्तार किया था। वह दाऊद गिरोह के फहीम मचमच का करीबी है।

उन्होंने कहा, 'अहमद से पूछताछ के दौरान रिजवान व अन्य के नाम सामने आए जो मुंबई व दुबई में रहते हैं। इसके बाद जाल बिछाकर रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया।' अधिकारी ने बताया कि गुजरात के सूरत का रहने वाला अहमद कथित तौर पर दुबई में हवाला का काम करता है। जून 2017 में मुंबई के एक कारोबारी से फहीम ने रंगदारी मांगी थी। जांच के दौरान अहमद का भी नाम सामने आया था। पूर्व में भी वह मुंबई व गुजरात के कई लोगों से रंगदारी की मांग कर चुका है।

उन्होंने बताया कि रिजवान को जब अहमद की गिरफ्तारी की जानकारी हुई तो वह देश छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते वह पकड़ा गया।

देवास में पानी की कमी के चलते नहीं खुलेगी नोट के कागज की मिल!

आदर्श ठाकुर, देवास

▸ देवास और नासिक के बीच चल रही थी खींचतान

▸ अब होशंगाबाद पेपर मिल का ही होगा विस्तार

मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस (बीएनपी) में नोटों की छपाई और स्याही बनाने के साथ ही उम्मीद की जा रही थी कि नोट बनाने में उपयोग होने वाला कागज भी यहीं बनेगा, लेकिन ऐसा होता अब संभव नजर नहीं आ रहा। प्रस्तावित पेपर मिल अब न तो देवास में खुलेगी न नासिक में। सूत्रों की मानें तो नई जगह पेपर मिल खोलने के बजाय अब होशंगाबाद स्थित पेपर मिल का ही विस्तार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि पानी की कमी के चलते देवास में पेपर मिल पर विचार नहीं किया गया।

गौरतलब है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआइएल) की देश में एक मात्र पेपर मिल होशंगाबाद में है, जहां नोट छापने में उपयोग होने वाला कागज बनता है। जानकारी के अनुसार, नोट छपाई में काम आने वाला 80 से 90 फीसद कागज विदेश से आता है, शेष होशंगाबाद स्थित पेपर मिल में छपता है। इसे देखते हुए करीब तीन साल पहले वित्त मंत्रालय ने नई पेपर मिल खोलने पर विचार किया था। इसके तहत रिजर्व बैंक की एक पेपर मिल मैसूर में शुरू की गई थी। फरवरी 2017 में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीएनपी का दौरा किया था और तब भी तत्कालीन सांसद मनोहर ऊंटवाल सहित विभिन्न यूनियन पदाधिकारियों ने पेपर मिल देवास में खोलने की मांग की थी। इसके बाद से पेपर मिल को लेकर मशक्कत जारी थी।

अल्ट्रा मॉडर्न पेपर मिल को लेकर देवास और नासिक के बीच खींचतान चल रही थी। मामला लोकसभा तक पहुंच गया था और देवास के तत्कालीन सांसद मनोहर ऊंटवाल ने मामला उठाया था। नोटबंदी में बेहतरीन प्रदर्शन का हवाला देकर देवास बैंक नोट प्रेस ने दावेदारी जताई थी। वहीं, नासिक की टीम ने दौरा कर यह रिपोर्ट बनाई है कि मप्र को यह मिल क्यों नहीं मिलना चाहिए।

पानी की कमी के चलते हाथ से फिसली : देवास में पेपर मिल खोलने के लिए आवश्यक तमाम संसाधन हैं, लेकिन बस कमी पानी की है। बीएनपी के लिए शाजापुर जिले के लखुंदर डेम से पानी आता है। गर्मी में वहां पानी कम होने से बीएनपी में दिक्कत शुरू हो जाती है। ऐसे में नगर निगम से बीएनपी पानी लेता है। सूत्रों की मानें तो पेपर मिल देवास में नहीं खुलने का बड़ा कारण पानी की कमी है।

होशंगाबाद में 1968 में खुली थी मिल : होशंगाबाद में प्रतिभूति कागज कारखाने की स्थापना 1968 में हुई थी। यहां फिलहाल 500, 200, 100, 50, 10 के नोटों का कागज बनाया जाता है। यहां से कागज देवास व नासिक भेजा जाता है। सूत्रों के अनुसार, अब इसी कारखाने का विस्तार कर यहां नई यूनिट शुरू की जाएगी।

किश्तवाड़ में आतंकियों के छिपे होने का संदेह हो रही तलाशी

जासं, किश्तवाड़ : बीते नौ माह से किश्तवाड़ के लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। इन नौ महीने में आतंकी चार लोगों की हत्याएं करने सहित हथियार छीनने की घटना को अंजाम दे चुके हैं। इन घटनाओं में शामिल आतंकियों का सुरक्षा और जांच एजेंसियां अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई हैं। इसके कारण अब लोगों में किश्तवाड़ में फिर से आतंकवाद के पनपने की आशंका बनी हुई है।

सूत्रों के मुताबिक हत्याओं और हथियार छीनने की वारदात में शामिल थे, वे शहर में गुप्त ठिकाने पर छिपे हुए हैं। मगर किसी को कोई भनक नहीं लग रही है। यह भी कहा जा रहा है कि मोस्टवांटेड आतंकी ओसामा जावेद, हरुण वानी और नावेद किश्तवाड़ शहर के अंदर अलग-अलग ठिकानों में रह रहे हैं, जहां इन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। हालांकि, इस बात को सुरक्षा एजेंसियां भी स्वीकार कर रही हैं, मगर आतंकी उनकी पहुंच से बाहर हैं।

हालांकि इन चार हत्याओं के बाद सुरक्षाबल सतर्क हैं। जगह-जगह नाके लगाए गए हैं। रोजाना किसी न किसी क्षेत्र में तलाशी अभियान चल रहा है, लेकिन सुरक्षाबल आतंकियों का सुराग नहीं लगा पा रहे हैं।

सोनभद्र नरसंहार का मुख्य आरोपित ग्राम प्रधान गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सोनभद्र

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नरसंहार के मुख्य आरोपित ग्राम प्रधान यज्ञदत्त को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनभद्र के एसपी सलमान ताज पाटिल ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस ने मामले में 28 नामजद व 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 26 को गिरफ्तार कर लिया है। दो असलहे भी बरामद हुए हैं। बता दें कि उभ्भा गांव में बुधवार को ग्राम प्रधान यज्ञदत्त अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ विवादित जमीन को कब्जा करने के लिए पहुंचा था। वहां आदिवासियों व ग्रामीणों के विरोध पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें दस लोगों की जान चली गई। गुरुवार को सोनभद्र का उभ्भा गांव गम और गुस्से से दहक रहा था। अपने 10 लोगों को खो चुके गांव वालों के सामने पुलिस-प्रशासन इतनी बेबस दिखा कि शवों को दफनाने के लिए उसे करीब 14 घंटे तक उनकी मान-मनौव्वल करनी पड़ी। क्षेत्र में हर तरफ तनाव का माहौल दिखा। इस कारण जिला अस्पताल यानी पोस्टमार्टम हाउस, कलेक्ट्रेट व उभ्भा गांव पुलिस छावनी में तब्दील रहा। ग्रामीणों में उठ रहे भावनाओं के ज्वार के कारण कई बार प्रशासन से उनकी झड़पें भी हुईं।

घटना के बाद बुधवार की रात ही मृतकों का पोस्टमार्टम शुरू कराया गया। सुबह तक चले पोस्टमार्टम के बाद स्थिति तनावपूर्ण होते देख जिले के आला अधिकारियों के साथ ही एडीजी जोन वाराणसी बृजभूषण, डीआइजी विंध्याचल पीयूष श्रीवास्तव भी पहुंच गए। मृतकों के परिजनों से करीब नौ घंटे तक चली बातचीत के बाद दोपहर दो बजे शवों को सुरक्षा के बीच गांव ले जाया गया। इसके बाद वहां भी जिस भूमि को लेकर विवाद हुआ था उसमें दफनाने को लेकर विवाद हुआ लेकिन प्रशासन नहीं माना। अंत में कड़ी सुरक्षा के बीच जेसीबी से गड्ढा खोदवाकर सभी शवों को गांव से तीन किमी दूर नदी के किनारे दफन किया गया।

पूरी रात चला पोस्टमार्टम : मृतकों के पोस्टमार्टम को लेकर भी जिला अस्पताल में तनाव बना रहा। सीएमएस पीबी गौतम के नेतृत्व में डॉक्टरों की आठ सदस्यीय टीम ने बुधवार की रात 12 बजे के बाद शवों का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। नौ शवों का पोस्टमार्टम करने में सुबह के छह बज गए जबकि एक शव का पोस्टमार्टम वाराणसी में हुआ।

पंचायत ने दी नबील और उसके परिवार के बहिष्कार की धमकी

जागरण संवाददाता, यमुनानगर : संघ वर्कर की बेटी हुमायरा के नबील के साथ जाने के बाद हमीदा में बुधवार की रात पटाखे छोड़े गए। आरोप मुस्लिम समुदाय के युवकों पर लगा है। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं, बताया जा रहा है कि देर रात हमीदा में पंचायत भी हुई। जिसमें नबील और उसके परिवार के बहिष्कार करने का निर्णय लिया। हालांकि इस बारे में पंचायत में शामिल लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं। फिलहाल नबील के घर पर ताला है। सुरक्षा की दृष्टि से हमीदा में पीसीआर भी तैनात है। वहीं, नबील का कहना है कि अब कौन सी पंचायत बनी है। जब हमारे हक में कोर्ट ने फैसला दे दिया है। कुछ दिनों के लिए मेरा परिवार मेरे साथ है। मैं भी चाहता हूं कि किसी तरह बेवजह का कोई विवाद न हो। मैं भारत का नागरिक हूं और लोकतंत्र ने मुझे कहीं भी रहने का अधिकार दिया है। मैं अपने घर भी आऊंगा।

पंचायत में शामिल एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस घटना के बाद से ही सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। यह तो हमीदा के लोगों ने शांति व भाईचारे का परिचय दिया। नबील ने जो काम किया है, वह हमीदा के हित में नहीं है।

बंगाल में हनुमान चालीसा पाठ में भाग लेने पर इशरत जहां को धमकी

जागरण संवाददाता, हावड़ा

▸ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, पड़ोसी व मकान मालिक पर आरोप

▸ एक साथ तीन तलाक मामले की याचिकाकर्ता हैं इशरत जहां

उच्चतम न्यायालय में तीन तलाक मामले की याचिकाकर्ता इशरत जहां ने थाने में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि उन्हें हिजाब पहनकर हनुमान चालीसा पाठ में भाग लेने के लिए धमकाया गया है। उनसे गाली-गलौज किया गया। बंगाल के गोलाबाड़ी थाने में की गई शिकायत में उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार और मकान मालिक पर धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर उन्हें धमकी देने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है।

इशरत जहां ने कहा कि वह बुधवार को अपने बेटे के स्कूल से घर लौट रही थीं। गोलाबाड़ी इलाके के सैकड़ों स्थानीय लोगों ने हिजाब पहनकर पाठ में भाग लेने के लिए उन्हें घेरा और धमकाया। थाने के एक अधिकारी ने कहा, 'हमने शिकायत की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इशरत जहां ने बताया कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी है।' इशरत जहां ने अपनी शिकायत में कहा-'मैं यह कहना चाहती हूं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं। किसी भी पवित्र उत्सव में भाग लेना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैंने अपने देश के अच्छे नागरिक के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया है।

मैं एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक हूं। हालांकि, इसके कारण मुझे अपने परिवार के सदस्यों से जान का खतरा है।' जहां ने यह भी दावा किया कि उनके करीबी रिश्तेदार और मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर करने और जान से मारने की धमकी दी है।

इशरत जहां एक बार में तीन तलाक देने के खिलाफ मामले की पांच याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। उच्चतम न्यायालय ने 22 अगस्त, 2017 को फौरी तौर पर तीन तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया। इशरत जहां के पति ने 2014 में दुबई से फोन पर लगातार तीन बार 'तलाक' कहकर उनके साथ रिश्ता खत्म कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

नान घोटाले की 26 अगस्त से लगातार होगी सुनवाई

नईदुनिया, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन के दौरान नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में हुए करोड़ों के घोटाले की हाई कोर्ट में सुनवाई 26 अगस्त से रोजाना होगी।

चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग को लेकर दायर सभी याचिकाओं में निर्देश दिए हैं कि सभी को एक साथ सुना जाएगा। साथ ही शासन व याचिकाकर्ताओं को हिंदी के सभी दस्तावेज का अंग्रेजी में अनुवाद कर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। दो सितंबर तक मामले में सुनवाई होगी। किसी भी पक्ष को और समय नहीं दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम में चावल परिवहन घोटाले में ईओडब्ल्यू व एसीबी ने 26 लोगों को नामजद किया था लेकिन एसीबी ने 16 अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ चालन पेश किया। स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग को लेकर हमर संगवारी, सुदीप श्रीवास्तव, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडेय समेत अन्य ने अलग-अलग याचिका दाखिल की है। वहीं, नान के तत्कालीन एमडी अनिल टूटेजा ने अपने खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देने को चुनौती दी है।

बीजापुर में मुठभेड़ की जांच करने पहुंची सीबीआइ को पुलिस ने रोका

नईदुनिया, जगदलपुर

▸ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आई है टीम, सुरक्षा का हवाला दे नहीं दी अनुमति

करीब छह साल पहले छत्तीसगढ़ में बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के एड़समेटा गांव में हुई कथित मुठभेड़ की जांच करने पहुंची सीबीआइ की टीम को प्रशासन ने रोक दिया। सुरक्षा का हवाला देते हुए पुलिस ने सीबीआइ टीम को जाने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस के प्रदेश में सत्तासीन होने के बाद सरकार ने राज्य में सीबीआइ की जांच पर रोक लगा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में उसे अनुमति दी गई है। एक महिला समेत चार सदस्यीय टीम के सदस्य अब संभवतः शुक्रवार को सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता होने के बाद एड़समेटा जाकर पीड़ितों का बयान लेंगे।

जानकारी के अनुसार बुधवार की रात सीबीआइ की टीम बीजापुर पहुंची थी। गुरुवार दोपहर कलेक्टोरेट में अधिकारियों को तलब कर ब्योरा मांगा। करीब ढाई घंटे तक टीम ने कथित मुठभेड़ से जुड़े दस्तावेज खंगाले। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि सीबीआइ टीम को सुरक्षा का हवाला देते हुए एड़समेटा गांव में जाने रोका गया है। शुक्रवार को सीबीआई टीम को पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बीच एड़समेटा ले जा सकते हैं।

क्या था एड़समेटा कांड

17 मई 2013 की रात गंगालूर स्थित सीआरपीएफ कैंप से जवानों की टुकड़ी सर्च ऑपरेशन पर एड़समेटा के लिए निकली थी। पुलिस के दावों के मुताबिक देर रात माओवादियों से मुठभेड़ हुई थी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उस रात कोई मुठभेड़ नहीं हुई बल्कि जवानों ने बीज पंडुम (स्थानीय पर्व) मना रहे ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें तीन नाबालिग समेत नौ ग्रामीणों की मौत हो गई थी। 11 घायल हुए थे। इस कथित मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ था। कई मानवाधिकार संगठनों ने इस कथित मुठभेड़ पर सवाल उठाए थे।

हिमाचल में विद्यार्थी पढ़ेंगे कारगिल युद्ध के शहीदों की वीरता के किस्से

रविंद्र शर्मा, शिमला

▸ सरकार ने शिक्षा बोर्ड को पाठ्यक्रम तैयार करने के दिए हैं निर्देश

▸ बोर्ड कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा प्रदेश के शहीदों की जीवनी पर आधारित पाठ

कारगिल युद्ध में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के जवानों की वीरता के किस्से अब सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाए जाएंगे। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। कारगिल युद्ध के बाद पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को शहीदों की जीवनी पढ़ाने की चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इस संबंध में ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब एक बार फिर भाजपा सरकार ने कदम बढ़ाया है।

भाजपा सरकार ने प्रदेश के शहीदों की वीरता के किस्सों से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अवगत करवाने की कवायद तेज की है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कुछ महीने पहले प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान शहीदों की शहादत से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार करने के संबंध में निर्देश दिए थे।

इस पाठ्यक्रम पर परीक्षा भी ली जाएगी। फाइल

शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश के शहीदों की जीवनी पर आधारित पाठ बोर्ड की कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। इसे दसवीं और बारहवीं की कक्षाओं के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। वीरगाथा से जुड़े पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा भी ली जाएगी।

कारगिल युद्ध में हिमाचल के दो जवानों को परमवीर चक्र मिले थे। कैप्टन विक्रम बतरा व हवलदार संजय कुमार को परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। यह गौरव की बात है कि प्रदेश सरकार ऐसे वीरों की जीवनी को स्कूलों में पढ़ाना चाहती है। इससे युवाओं को देशसेवा की प्रेरणा मिलेगी। युवा आसानी से समझ पाएंगे कि हिमाचल को वीरों की भूमि क्यों कहा जाता है।

-कुशाल ठाकुर, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर

हिमाचल के वीर जवानों के जीवन और वीरता के किस्सों पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए शिक्षा बोर्ड को निर्देश जारी किए गए हैं। विशेषकर बोर्ड की कक्षाओं के सिलेबस में प्रदेश के वीर जवानों की वीरता के किस्सों को जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर कर दी गई है। शहीदों पर पाठ्यक्रम तैयार कर उसे जल्द लागू कर दिया जाएगा।

-सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश

दो बच्चियों की संदिग्ध मौत खराब वैक्सीन देने का आरोप

जागरण संवाददता, राजौरी

जम्मू संभाग के राजौरी जिला के अधीन सुंदरबनी की पंचायत नाला में वैक्सीन के 18 घंटे के भीतर दो बच्चियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक बच्ची माहीदा कोसर की आयु चार माह है, जबकि दूसरी आफरीन करीब 18 माह की है और दोनों की सगी बहने हैं। अचानक से दो बच्चियों की मौत हो जाने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। उधर, परिजनों का आरोप है कि बच्चियों को गलत वैक्सीन दी गई है, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चियों का पोस्टमार्टम करवाया है, जिसकी जांच के बाद ही बच्चियों की मौत के असल कारणों का पता चल सकेगा।

बताया जा रहा है मोहम्मद अबरीज ने बुधवार को साढ़े 11 बजे से 12 बजे के बीच गांव में ही स्वास्थ्य विभाग के सब सेंटर में अपनी दो बच्चियों का पेंटावेलेंट और डिफ्थिरिया, कालीखांसी और टेटनस (डीपीटी) वैक्सीन करवाया। इसके बाद घर आया गया। वीरवार तड़के जब बिस्तर पर चार बजे के करीब मोहम्मद अबरीज को बच्चियों के शरीर में कोई हरकत होती महसूस नहीं की तो उसके होश उड़ गए। सुबह छह बजे सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों की टीम अबरीज के घर पहुंची तो पाया कि दोनों बच्चियां मृत थीं। परिजनों ने आरोप लगाया कि वैक्सीन के बाद उनकी मौत हुई है।

सुंदरबनी अस्पताल ने मामले के बारे में सीएमओ डॉ. सुनील शर्मा को दी। सीएमओ के आदेश के बाद डॉ. अनीस चौधरी की अगुआई में पांच सदस्यीय चिकित्सकों की टीम ने बच्चियों का पोस्टमार्टम किया और शव परिजनों के हवाले कर दिए।

बच्चियों की मौत का कुछ और कारण भी हो सकता है। परिजनों के वैक्सीन खराब होने का आरोप लगाने के बाद पोस्टमार्टम करवा दिया है। यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को 15 अन्य बच्चों को भी वैक्सिन दी गई थी, सभी ठीक है। बच्चियों की मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा।

-डॉ. रघुवीर सिंह, बीएमओ।

जागरण पड़ताल

वंदे भारत प्रोजेक्ट

40 वंदे भारत एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों के तीन हजार करोड़ रुपये के टेंडर रद होने की खुलेंगी परतें, रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम जुटी जांच में, अफसरशाही में मचा हड़कंप

टेंडर मामले से जुड़े 20 हजार दस्तावेज जब्त

भाग-3

दीपक बहल, अंबाला

वंदे भारत सीरीज की 40 नई ट्रेनों के निर्माण और अन्य नई ट्रेनों के टेंडर रद करने के मामले की परतें जल्द खुल सकती हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आइसीएफ) चेन्नई में इन ट्रेनों का निर्माण होना था, जहां से करीब 20 हजार दस्तावेज रेलवे विजिलेंस ने कब्जे में लिए हैं। यह सभी दस्तावेज टेंडर (निविदा) प्रक्रिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। टेंडर में किस कंपनी ने क्या रेट भरे थे, अब इसकी जांच की जाएगी। रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम जांच में जुटी है और अफसरशाही में हड़कंप मचा हुआ है।

आपाधापी के बीच जारी किए गए कुल तीन हजार करोड़ रुपये के टेंडर रद किए जाने और टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद रेलवे बोर्ड ने विजिलेंस को जांच का जिम्मा दिया। सूत्रों के मुताबिक, जांच बैठाने के पीछे अब वजह स्पष्ट है कि टेंडर में जरूर कुछ गड़बड़ी थी।

बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस की 40 नई ट्रेनें बनाने के लिए आठ कंपनियों ने रेलवे द्वारा जारी टेंडर भरा था। जिसमें से रेलवे ने मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड को महज दो और स्पेन की एक कंपनी को मात्र एक रैक (ट्रेन) बनाने की मंजूरी दी थी, जबकि नेगोशिएशन (रेट निर्धारण) 40 ट्रेनों के निर्माण के हिसाब से किया गया था। रेलवे के इस फैसले पर मेधा ने सवाल उठाते हुए वंदे भारत ट्रेन के निर्माण से हाथ खींच लिए और 20 लाख रुपये की डिपाजिट राशि वापस मांगी।

बताया जाता है कि टेंडरों पर उठ रहे सवालों के बाद रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम ने आइसीएफ चेन्नई में छापामारी कर करीब पांच साल का रिकार्ड अपने कब्जे में लिया है। इस रिकार्ड में दिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़ रही वंदे भारत और शकूरबस्ती शेड में खड़ी दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के दस्तावेज भी शामिल हैं। इसके अलावा रेलवे मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (मेमू), इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ईएमयू), डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (डीईएमयू) के टेंडर की भी विजिलेंस जांच कर रही है। किस-किस टेंडर में कौन सी कंपनी ने भागीदारी की, कितना रेट भरा गया, किसको टेंडर अलाट किया गया, टेंडर कमेटी ने फाइल पर अपनी क्या टिप्पणी दी और अन्य अधिकारियों का फाइल पर क्या मार्किंग है, इन सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है।

बताया जा रहा है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस मामले (टेंडर प्रक्रिया) में बैठक भी की। दो जून को हुई बैठक में जहां रेलवे बोर्ड के 13 अधिकारी मौजूद थे, वहीं देशभर की रेल कोच फैक्ट्रियों सहित विदेशी कंपनियों के 19 पदाधिकारी भी मौजूद रहे। टेंडर प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या शर्तें रखी जाएं, कैसे विदेशी कंपनियों को भारत में काम की शर्तें हों, आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही यह चर्चा भी हुई अनुभव के आधार पर कंपनियों को शार्टलिस्ट किया जाए ताकि वे अधिक मात्रा में काम को पूरा कर सकें। जिसके बाद, पारदर्शिता और नई तकनीक का हवाला देकर सभी टेंडर रद कर दिए गए थे।

वंदे भारत ट्रेन। फाइल फोटो

अभी कुछ स्पष्ट नहीं : रेलवे

इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के सीनियर पीआरओ जीवी वेंकटेशन ने इस मामले पर दैनिक जागरण के सवाल के जवाब में कहा कि 'अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ दिन बाद ही पता चल पाएगा।' रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम 20 हजार दस्तावेज अपने साथ ले गई है, इस सवाल पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, कहा- ऐसा होता है।

आधा दर्जन वाहनों पर गिरा 20 टन वजनी कंटेनर, दो की मौत

जागरण संवाददाता, लुधियाना

नेशनल हाईवे नंबर एक से स्लिप-वे पर आया कंटेनर आधा दर्जन वाहनों पर जा गिरा। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। थाना छह की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद हाईवे पर दो घंटे तक जाम लगा रहा।

हादसा अंबाला रोड स्थित शेरपुर चौक के पास वीरवार सुबह आठ बजे हुआ। उस दौरान मजदूर फैक्ट्रियों की ओर जा रहे थे। तभी साहनेवाल से लुधियाना जा रहा 20 टन वजनी कंटेनर ऑटो, रेहड़े, साइकिल और मोटरसाइकिल पर पलट गया। इस दौरान कंटेनर से सामने जा रही पिकअप को भी टक्कर लगी थी, जिससे उसका चालक भी मामूली घायल हुआ है। इसमें साइकिल चालक अज्ञात व्यक्ति, मोटरसाइकिल पर सवार अर्जुन सिंह रावत, ऑटो चालक भोला सिंह, उसमें सवार राम जी मिश्रा, राकम सिंह शिमलापुरी घायल हो गए। कुछ ही समय बाद साइकिल चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायलों को एसपीएस अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहां अर्जुन सिंह रावत की भी मौत हो गई। भोला सिंह की हालत नाजुक बताई गई है। डाबा रोड स्थित अर्जुन सिंह रावत मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड का रहने वाला था।

लुधियाना के अंबाला रोड स्थित शेरपुर चौक के पास गुरुवार को हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कंटेनर व अन्य वाहन।

2,110 भारतीय बंदियों को पाकिस्तान वर्ष 2014 से अब तक प्रत्यर्पित कर चुका है। लोकसभा में विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने बताया कि मछुआरों समेत 362 बंदियों को इस साल मुक्त व प्रत्यर्पित कराया गया है।

डोसा किंग पी राजगोपाल के उदय और पतन की कहानी

डोसा किंग के नाम से मशहूर सरवण भवन रेस्तरां श्रृंखला के मालिक पी राजगोपाल का गुरुवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें प्रिंस संताकुमार नाम के व्यक्ति की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

ऐसे शुरू हुआ सफर

पी राजगोपाल के पिता तमिलनाडु के छोटे से गांव तूतीकोरिन में प्याज की किसानी करते थे। सपनों को साकार करने राजगोपाल बहुत छोटी सी उम्र में चेन्नई आ गए। किराने की दुकान खोलने के बाद रेस्तरां के व्यवसाय में प्रवेश किया। ज्योतिषी की सलाह को बहुत अधिक मानते थे। व्यावसायिक सलाहकारों द्वारा गुणवत्ता से समझौता करने या कीमतों में वृद्धि के बारे में बताने के बावजूद, राजगोपाल एक रुपये में पौष्टिक भोजन प्रदान करने की अपनी नीति पर अड़े रहे। देखते ही देखते उनका रेस्तरां जल्द ही प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने अन्य आउटलेट खोले और उनकी यह रेस्त्रां श्रृंखला पूरे देश में फैल गई। 2000 में दुबई में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय आउटलेट खोला, जिसके बाद अन्य देशों में भी उनके कई रेस्त्रां खुले।

कर्मचारियों के लिए थे बड़े भाई

अपने कर्मचारियों के बीच 72 वर्षीय पी राजगोपाल अन्नाची के नाम से प्रसिद्ध थे, जिसका अर्थ होता है बड़ा भाई। वह अपने कर्मचारियों का अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। सरवण भवन के कर्मचारियों को हर तरह की सहूलियतें दी जाती हैं। उपयुक्त वेतन के साथ पेंशन, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, आवास किराया, बेटियों के लिए विवाह निधि जैसी व्यवस्था है। जैसे-जैसे रेस्त्रां श्रृंखला में इजाफा हुआ, इन कर्मचारियों के लिए भत्तों में भी वृद्धि हुई।

ज्योतिषी को ठहराया जिम्मेदार

उनकी आत्मकथा वेट्री मीधु आसै वीथेन के मुताबिक उन्होंने अपने ज्योतिषी की सलाह के आधार पर अपने रेस्त्रां शुरू किए। उनके पतन और वर्तमान हालात के लिए भी एक ज्योतिषी की सलाह को जिम्मेदार ठहराया है, जिसने उन्हें देश के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए जीवज्योति नामक महिला से शादी करने के लिए कहा था।

धार्मिक व्यक्ति

राजगोपाल भगवान मुरुगा के परम भक्त थे। पारंपरिक लैंप और भगवान मुरुगा के विशाल चित्र सरवण भवन रेस्तरां में सजावट का हिस्सा हैं। उन्होंने मंदिरों में उदारतापूर्वक योगदान दिया, विशेष रूप से मुरुगा मंदिरों के लिए।

बड़ा कारोबार

सरवण भवन के भारत में 39 से अधिक और विदेश में 43 से अधिक रेस्तरां हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में सरवण भवन की कुल सालाना कमाई 29 अरब रुपये थी।

अपहरण और हत्या

जीवज्योति सरवण भवन की चेन्नई शाखाओं में से एक के सहायक प्रबंधक की बेटी थी। राजगोपाल की सलाह और धमकियों के बावजूद, जीवज्योति ने प्रिंस संताकुमार से शादी कर ली। अक्टूबर 2001 में दंपति का अपहरण कर लिया गया और संताकुमार की हत्या कर दी गई। उनका शव 31 अक्टूबर, 2001 को कोडाइकनाल स्थित टाइगर चोल जंगलों के अंदर से वन विभाग के अधिकारियों ने बरामद किया था। 2004 में चेन्नई की एक सत्र अदालत ने राजगोपाल और आठ अन्य को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। राजगोपाल ने मद्रास हाईकोर्ट में अपील की। 2009 में हाईकोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। तब राजगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और मार्च, 2019 को कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हालांकि राजगोपाल ने अपने खराब स्वास्थ्य को देखते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए और समय देने की गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

बाढ़ से असम में हाहाकार, अब तक 37 की मौत

आपदा ▶ 33 में से 28 जिले प्रभावित, 54 लाख लोग विस्थापित हुए, खतरे के निशान के ऊपर बह रहीं नदियां

सेना के हेलीकॉप्टर को नलबाड़ी जिले में आपात स्थिति में लैंड करना पड़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : असम और मेघालय सहित पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। असम में बाढ़ के कारण 54 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और मरने वालों की संख्या 37 हो गई है और मेघालय में आठ लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली है। राहत और बचाव में लगे सेना के हेलीकॉप्टर को नलबाड़ी जिले में आपात स्थिति में लैंड करना पड़ा।

असम के 33 में से 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गुवाहाटी एवं अन्य हिस्सों में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से पार बह रही हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के मुताबिक, 53,52,107 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गुरुवार को नौ लोगों की मौत होने के बाद मरने वालों की संख्या 37 हो गई है। पूरे राज्य में 4000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ में 130 पशु बह गए हैं और 25 लाख बड़े एवं छोटे पशु प्रभावित हुए हैं। असम में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बारपेटा है जहां 13.48 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। आपदा प्रबंधन ने बताया है कि 1080 कैंपों में 2.6 लाख विस्थापितों ने शरण ली है। जिला प्रशासनों ने 689 राहत कैंप स्थापित किए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें फंसे लोगों को निकालने में दिन-रात जुटी हैं।मेघालय का दक्षिण पश्चिम गारो सबसे ज्यादा प्रभावित : मेघालय के दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स में गुरुवार को दो और मौत होने के बाद मरने वालों की संख्या आठ हो गई है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से यह जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य में 1.55 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

केरल के तीन जिलों में रेड अलर्ट जारी : मौसम विभाग ने केरल के इदुक्की, पाथनमथिट्टा और कोट्टयम जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो तीन दिनों में यहां में 20 सेमी से ज्यादा बारिश होने की आशंका जताई गई है। संवेदनशील इलाकों से लोगों को शिविरों में पहुंचा दिया गया है। अन्य जिलों में रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

ट्वीट न करें, दान दें : अक्षय कुमार

मुंबई, एएनआइ : फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने देश के लोगों से बाढ़ पर ट्वीट करने की जगह दान करने की अपील की है। अभिनेता ने बुधवार को असम के लिए मुख्यमंत्री के राहत कोष में एक करोड़ रुपये दान किया है। उन्होंने अपने प्रशंसकों से राहत अभियान में सहयोग करने को कहा है।

काजीरंगा के हरमति इलाके में कबाड़ का काम करने वाले रफीकुल के घर में घुसा बाघ। एएनआइ

बाढ़ से बचने के लिए घर में घुसा बाघ

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम के बाढ़ प्रभावित काजीरंगा नेशनल पार्क के वन्यजीव भी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाना तलाशने पर मजबूर हो गए हैं। पांच गैंडे सहित 50 से ज्यादा जंगली पशुओं की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के साथ लगते विश्व विरासत स्थल के हारमोती के समीप बागोरी में एक घर में रॉयल बंगाल टाइगर घुस आया और बिस्तर पर जा बैठा। गुरुवार को उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर छाया रहा। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट आफ इंडिया ने ट्विटर पर आराम फरमाते हुए बाघ की तस्वीर पोस्ट की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह सात बजे के आसपास रफीकुल के घर में बाघ प्रवेश कर गया।

जनमत मुद्दा

क्या नदियों को उनका पुराना रूप-स्वरूप लौटाकर ही हम बाढ़ की विभीषिका से मानवता को बचा सकते हैं?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

facebook.com/muddajagran

mudda@jagran.com

देश में इस हफ्ते औसत से 20 फीसद कम रही बरसात

- मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में अलनीनो के असर ने बढ़ाई चिंता
- कपास और सोयाबीन की उपज वाले इलाकों में औसत से 68 प्रतिशत कम बारिश

71 फीसद औसत से कम बरसात हुई दक्षिण भारत में रबर और चाय के इलाकों में

नई दिल्ली, एएनआइ/रायटर : मौसम की भविष्यवाणी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट का कहना है कि जुलाई में भले ही मानसून ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन अल-नीनो का प्रभाव व्यापक स्तर पर पड़ने वाला है। भारत में मानसून कम होने की प्राकृतिक घटना को अल-नीनो कहा जाता है। लिहाजा, बुधवार को खत्म हुए पूरे एक हफ्ते में पूरे देश में औसत से 20 फीसद कम बारिश हुई है। इसके चलते देश के मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में फसलों की उपज को लेकर चिंता गहराने लगी है।

भारत में मानसून शुरू होने की तारीख एक जून से अब तक कुल मिलाकर औसत से 16 प्रतिशत कम बरसात हुई है। देश के आर्थिक विकास और खेतीबाड़ी के लिए मानसूनी बारिश बेहद जरूरी है। 55 फीसद कृषि योग्य भूमि में सिंचाई इसी बरसात पर आश्रित है। भारत में अमूमन हर वर्ष 75 प्रतिशत बरसात जून से सितंबर के बीच मानसून में होती है। मौजूदा समय में कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, असम और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है।

भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) के अनुसार 17 जुलाई के इस हफ्ते में देश के मध्य भाग में कपास और सोयाबीन की उपज वाले इलाकों में औसत से 68 फीसद कम बरसात हुई है। जबकि दक्षिण में रबर और चाय के इलाकों में 71 फीसद कम बरसात हुई है। पश्चिम में गन्ना और मूंगफली के इलाकों में भी औसत से कम बरसात हुई है। आइएमडी के हिसाब से औसत या सामान्य बरसात को 96 फीसद और 104 फीसद के बीच माना जाता है। यह आंकड़ा चार महीने के इस मौसम में औसत बरसात का पैमाना पचास साल की औसत 89 सेंटीमीटर बारिश मानी जाती है। जून-जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच भारतीय किसान धान, मक्का, कपास, सोयाबीन और मूंगफली आदि की खेती करते हैं।

उस्मानाबाद में पानी की भारी किल्लत

महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के 700 से अधिक गांवों में करीब 550 गांव पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र के इन इलाकों में पानी की भारी कमी हो गई है चूंकि यहां मानसून में बमुश्किल 15 फीसद बरसात हुई है। जिले के 225 जलाशयों में केवल 0.74 फीसद जलराशि बाकी रह गई है। मराठवाड़ा क्षेत्र के इन इलाकों में भूमिगत जल भी बहुत नीचे जा चुका है। यह बात स्थानीय किसानों और अन्य लोगों के लिए बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। इन इलाकों में जलसंकट से बचने के लिए पानी के 234 टैंकरों का इंतजाम किया गया है।

सरवण भवन रेस्तरां के मालिक राजगोपाल की अस्पताल में मौत

- कर्मचारी की हत्या में काट रहा था उम्रकैद की सजा
- कर्मचारी की पत्नी से करना चाहता था तीसरी शादी

चेन्नई, आइएएनएस : दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए मशहूर रेस्तरां चेन सरवण भवन के मालिक पी राजगोपाल की मौत हो गई है। 71 वर्षीय राजगोपाल अपने कर्मचारी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। नौ जुलाई को उसने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। उसी दिन घबराहट की शिकायत पर उसे सरकारी स्टैनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर उसे निजी अस्पताल विजया हेल्थ सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह निजी अस्पताल में राजगोपाल की मौत हो गई। डोसा किंग के नाम से मशहूर राजगोपाल अपने ज्योतिषी की सलाह पर अपने कर्मचारी प्रिंस संत कुमार की पत्नी से तीसरी शादी करना चाहता था। राजगोपाल की पहले से ही दो पत्नियां थी। संत कुमार की पत्नी और राजगोपाल की उम्र में भी बहुत अंतर था। संत कुमार की पत्नी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

इसके बाद राजगोपाल ने दोनों को अगवा कराकर उन्हें अगल होने की धमकी दी थी, ताकि वह शादी कर सके। उनके नहीं मानने पर उसने संत कुमार की 2001 में अपहरण के बाद हत्या करा दी थी। सत्र अदालत ने इस मामले में राजगोपाल को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ संत कुमार की पत्नी की अपील पर मद्रास हाई कोर्ट ने सजा को बढ़ाकर उम्रकैद में तब्दील कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस साल मार्च में मामले पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था और राजगोपाल से सात जुलाई तक समर्पण करने को कहा था। राजगोपाल ने बीमारी का हवाला देकर समर्पण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा था, लेकिन शीर्ष अदालत ने समय देने से इन्कार कर दिया था।

सरवण भवन के मालिक पी राजगोपाल की 9 जुलाई 2019 की पिक्चर। उन्हें इस दिन अदालत में पेश किया गया था। फाइल प्रेट्र

पूर्व सांसद अतीक से भी जल्द पूछताछ करेगी सीबीआइ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सीबीआइ पूर्व सांसद अतीक अहमद के घर समेत छह ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिले लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की परतें खंगालने में जुट गई है। सीबीआइ अहमदाबाद जेल में निरुद्ध अतीक अहमद से पूछताछ करने की तैयारी भी कर रही है। सीबीआइ ने बुधवार को प्रयागराज से गिरफ्तार अतीक के साले जकी अहमद को गुरुवार को लखनऊ स्थित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआइ की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपित जकी अहमद को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। सीबीआइ अब जकी अहमद को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है। सीबीआइ ने बुधवार को की छापेमारी में अतीक के घर से लैपटॉप व हार्ड डिस्क के अलावा बैंकों की चेक बुक व लेनदेन से जुड़े दस्तावेज बरामद किये थे।

गाजियाबाद में मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी ढेर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

- एसटीएफ के हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल भी गोली लगने से हुए घायल
- बीती 27 मई को उसने साथियों संग ग्रेटर नोएडा के जारचा में कैश वैन से 65 लाख रुपये लूटे थे

एसटीएफ की नोएडा यूनिट व साहिबाबाद थाने की पुलिस ने बुधवार रात मुठभेड़ में एक लाख के इनामी बदमाश मेहरबान को ढेर कर दिया। उसे छह गोलियां लगी थीं। मुठभेड़ में एसटीएफ के एक हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हो गए। बुलंदशहर में चावल कारोबारी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के बाद बदमाश जमानत पर था। बीती 27 मई को उसने साथियों संग ग्रेटर नोएडा के जारचा में कैश वैन से 65 लाख रुपये लूटे थे।

एसएसपी सुधीर कुमार ने बताया कि पुलिस टीम बुधवार रात करीब एक बजे एसटीएफ फील्ड यूनिट नोएडा के प्रभारी एसआइ राकेश कुमार टीम के साथ भोपुरा चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने एक लाख के इनामी बदमाश मेहरबान निवासी सराय मनिहारा वाला कुआं बुलंदशहर के साथियों संग इधर आने की सूचना दी। इसी बीच दिल्ली की ओर से एक सेंट्रो कार आती दिखी। हाथ देने पर कार सवार युवक पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे। फायरिंग में एसटीएफ के हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और कांस्टेबल हरिओम के हाथ में गोली लग गई।

पुलिस और एसटीएफ की टीम ने पीछा किया तो बदमाश निर्माणाधीन कोयल एंक्लेव में घुस गए। जहां पुलिस की फायरिंग में मेहरबान सिर और सीने में छह गोलियां लगीं, जबकि मेहरबान के दो साथी फरार हो गए। मेहरबान और घायल पुलिसकर्मियों को मोहन नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान मेहरबान की मौत हो गई।

घायल सिपाहियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। एसएसपी का कहना है कि 27 मई को ग्रेटर नोएडा के जारचा में कैश वैन से 65 लाख रुपये लूट के मामले में एडीजी मेरठ की ओर से उसपर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बदमाशों की कार से एक बंदूक, तमंचा, रिवाल्वर के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं।

पत्नी को गुजारा भत्ते में नकदी की जगह राशन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : वैवाहिक विवाद में पत्नी को गुजारा भत्ते में नकदी की बजाय राशन देने की एक पति की मांग को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। यह शायद इकलौता मामला होगा जिसमें गुजारा भत्ते में कोर्ट ने पैसे की जगह राशन देने की छूट दी हो।

हरियाणा के भिवानी जिले के एक व्यक्ति का पत्नी से घरेलू विवाद चल रहा है। भिवानी कोर्ट ने पति को आदेश दिया था कि वह पत्नी को हर महीने एक तय राशि का भुगतान करे। इसे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए पति ने कहा कि वह कोर्ट द्वारा तय राशि देने में सक्षम नहीं है। वह नकदी की बजाय पत्नी को गुजारे के लिए घर का राशन दे सकता है। याची ने कोर्ट को बताया कि वह पहले एक कंपनी में काम करता था। अब कंपनी बंद हो गई। ऐसे में अब वह पैसे नहीं दे सकता। उसने कहा कि वह अपनी पत्नी को 20 किलो चावल, पांच किलो चीनी, पांच किलो दाल, 15 किलो अनाज, पांच किलो देसी घी महीने के अलावा दो किलो दूध रोजाना दे सकता है।

हाई कोर्ट ने याची की मांग स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि वह तीन दिन के भीतर यह सामान अपनी पत्नी को दे। साथ में गुजारा भत्ते का पिछला भुगतान वह अदा कर अगली सुनवाई पर हलफनामा देकर जानकारी दे कि उसने पूरा भुगतान कर दिया है।

सावन के झूले...

सावन में वर्षा तन-मन को भिगोने लगी है, हृदय के तार झंकृत होने लगे हैं। ऐसे में गांव-गांव झूले पर झूलती युवतियों और बच्चियों के कोमल-मधुर कंठों से समधुर गीत गूंजने लगते हैं। सावन तीज पर तो ऐसा माहौल मन-मस्तिष्क को आल्हादित कर देता है। चाहे उत्तर प्रदेश का मथुरा-वृंदावन हो या पंजाब का पटियाला, सब जगह सावन तीज की रौनक छाई रहती है। ऐसे ही तीज उत्सव के एक अवसर पर पंजाब के पटियाला में अपनी पारंपरिक पोशाक में झूला झूलने का आनंद उठाती बच्चियां, युवतियां और महिलाएं। प्रेट्र

तीर्थयात्रा के दौरान पाक में होता है खालिस्तानी दुष्प्रचार

- भारत ने जताया कड़ा विरोध, सौंपा सुबूतों से भरा डोजियर

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने पाकिस्तान जाने वाले सिख तीर्थयात्रियों से जुड़ा मुद्दा उठाकर पड़ोसी देश से खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर कड़ा विरोध जताया है। पाकिस्तान को दिए डोजियर में भारत ने कहा है- पाकिस्तान पहुंचने वाले सिख तीर्थयात्रियों को खालिस्तान समर्थक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें बरगलाया जाता है। भारत विरोधी नारेबाजी होती है और राष्ट्रध्वज तिरंगा जलाया जाता है। इससे भारतीयों की भावनाएं आहत होती हैं।

डोजियर में कहा गया है कि पाकिस्तान के एक केंद्रीय मंत्री ने सिख तीर्थयात्रियों के समक्ष हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकी बुरहान वानी का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत सरकार सिखों और कश्मीरियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार कर रही है। उल्लेखनीय है कि भारतीय सिखों के चार जत्थे हर साल पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। दोनों देशों के बीच सन 1974 में हुए समझौते के तहत सिख तीर्थयात्रियों के ये दौरे होते हैं।

लेकिन हाल के वर्षों में पाकिस्तान इन दौरों के भारत के खिलाफ इस्तेमाल की कोशिश करता रहा है। 23 पेज के डोजियर में भारत ने फोटो समेत इस आशय के विस्तृत सुबूत पाकिस्तान को दिए हैं। एक फोटो में पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का महासचिव रहा गोपाल सिंह चावला भारतीय झंडे को जलाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों को यह डोजियर हाल ही में वाघा सीमा पर करतारपुर कॉरीडोर निर्माण पर हुई बातचीत के दौरान दिया गया।

डोजियर में कहा गया है कि दुर्भाग्य से यह सारा दुष्प्रचार धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने गए भारतीयों के समक्ष किया जाता है। खालिस्तान संबंधी भारत विरोधी गतिविधियों धार्मिक आयोजनों की आड़ में की जाती हैं। इससे श्रद्धालुओं की यात्रा का उद्देश्य बदल जाता है। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और उनके मन को ठेस लगती है। डोजियर में खालिस्तान समर्थक संगठनों के पाकिस्तान में बेरोक-टोक चलने और उन्हें सुविधाएं मिलने पर भी आपत्ति जताई गई है। इनमें से एक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस है।

आई बहार

जापान का राष्ट्रीय फूल है ब्लू पॉपी, खासकर विदेशी पर्यटकों को खींच रहा अपनी ओर, पहली जुलाई से 15 अगस्त के मध्य तक फूलों की घाटी की शोभा बढ़ाता है ब्लू पॉपी

फूलों की घाटी में 'हिमालयन क्वीन' की रंगत

रणजीत सिंह रावत, जोशीमठ (चमोली)

यूं तो समुद्रतल से 12995 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी में 500 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं, लेकिन इनमें हिमालयन क्वीन 'ब्लू पॉपी' की बात ही कुछ और है। जापान का यह राष्ट्रीय फूल इन दिनों फूलों की घाटी की शोभा बढ़ा रहा है और इसके दीदार को विदेशी पर्यटक भी खिंचे चले आ रहे हैं। इनमें जापानियों की संख्या सर्वाधिक है।

चमोली जिले में 87.5 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैली घाटी हिमालयी जैवविविधिता का अद्भुत खजाना है। यहां पर दुनियाभर की दुर्लभ प्रजाति के फूल, वन्य जीव-जंतु, औषधीय वनस्पति व पक्षी बहुतायत में पाए जाते हैं। यही वजह है कि फूलों की घाटी प्रकृति प्रेमियों और वनस्पति शास्त्रियों की पहली पसंद है। इन दिनों घाटी जापान के राष्ट्रीय पुष्प ब्लू पॉपी से महक रही है। 15 जुलाई से अब तक 50 से अधिक जापानी पर्यटक फूलों की घाटी पहुंच चुके हैं, जो 15 अगस्त तक यहीं रहेंगे।

अपने राष्ट्रीय पुष्प को देखना अनूठा अनुभव : फूलों की घाटी की सैर पर पहुंचे जापानी पर्यटक ताकाहाशी हिशाशी, याबे योजो, तोकुयामा हत्स्यू, वतनबे हिरोमी, मात्सुकुरा हिडको, सुजुकी तइरा, वतनबे ताकाशी, तस्कगी तोशीरो व मोमियामा मासायुकी बताते हैं कि घाटी में अपने राष्ट्रीय पुष्प को देखना अनूठा अनुभव है। सबसे खुशी की बात यह है कि ब्लू पॉपी आज घाटी में 'हिमालयन क्वीन' का दर्जा हासिल कर चुका है।

अस्सी के दशक में जापान से घाटी में पहुंचा ब्लू पॉपी : वर्ष 1984 तक फूलों की घाटी में ब्लू पॉपी कहीं नजर नहीं आता था। इसी वर्ष एक जापानी शोध छात्र चो बकाम्बे फूलों पर शोध के लिए घाटी पहुंचा। वह पहले भी घाटी के दीदार को आ चुका था और तब उसके मन में विचार आया था कि क्यों न जापान के राष्ट्रीय पुष्प ब्लू पॉपी को यहां उगाया जाए। इसलिए, इस बार वह ब्लू पॉपी के बीज भी साथ लेकर आया। उन बीजों को घाटी में बिखेरकर वह वापस लौट गया और तीन साल बाद वर्ष 1987 में जब फिर वापस लौटा तो पूरी घाटी में ब्लू पॉपी की रंगत बिखरी हुई थी। यह देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

चमोली स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में खिला ब्लू पॉपी फूल। जागरण

'फूलों की घाटी में ब्लू पॉपी को देखने हर साल जापान से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। ब्लू पॉपी घाटी में 15 अगस्त के आसपास तक खिला रहता है, जिससे घाटी की नीली रंगत देखते ही बनती है।'

-बृजमोहन भारती, वन क्षेत्राधिकारी, फूलों की घाटी वन प्रभाग, चमोली

रोजवैली चिटफंड घोटाले में अभिनेत्री रितुपर्णा से पूछताछ

जागरण संवाददाता, कोलकाता

रोजवैली चिटफंड घोटाले में टॉलीवुड अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता से गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ की। मामले में मनी लांड्रिंग की जांच कर रहे ईडी अफसरों ने रितुपर्णा का बयान रिकॉर्ड किया। सूत्रों के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे रितुपर्णा साल्टलेक के सीजीओ कांप्लेक्स स्थित ईडी के पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय पहुंची। जांच अधिकारियों ने मनी लांड्रिंग के बाबत उनसे मैराथन पूछताछ की। आरोप है कि रितुपर्णा की संस्था का रोजवैली के साथ करीब सात करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ था।

गौरतलब है कि रितुपर्णा वर्ष 2013 से पहले रोजवैली के स्टार प्रचारकों में शामिल थी। चिटफंड मामले में मनी लांड्रिंग की जांच कर रही ईडी को पता चला कि रितुपर्णा ने कई बार विदेश दौरे किए थे, जिसका पूरा खर्च रोजवैली समूह ने उठाया था। जांच अधिकारियों को अभिनेत्री के खाते में सात करोड़ रुपये के लेन-देन होने के तथ्य हाथ लगे थे। उनके विदेश दौरे के कई फ्लाइट टिकट भी जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं। जांच में गौतम कुंडू द्वारा मोटी रकम देकर कई बांग्ला फिल्मों को खरीदने के भी प्रमाण मिले। इसमें रितुपर्णा की कोई भूमिका थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। ईडी के अधिकारियों ने रितुपर्णा से पूछा कि रोजवैली समूह की ओर से उनके विदेशी दौरे का खर्च क्यों उठाया जाता था? समूह की ओर से रितुपर्णा के खाते में आर्थिक लेन-देन के बाबत भी पूछताछ की गई। ईडी दफ्तर में रितुपर्णा ने कहा कि उनसे जो भी जानकारी मांगी जाएगी, वह देंगी। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था के साथ रोजवैली का समझौता था। उसके तहत ही लेन-देन हुआ था। ईडी ने बांग्ला फिल्म के तीन बड़े कलाकारों रितुपर्णा सेन, शताब्दी राय और प्रसेनजीत चटर्जी को नोटिस भेजा था। प्रसेनजीत को 19 जुलाई को दोपहर 12 बजे पेश होने के लिए कहा गया है।

पत्नी के अवैध संबंध से नाराज पति ने ली तीन पड़ोसियों की जान

जागरण संवाददाता, कोलकाता : दक्षिण 24 परगना जिले के महेशतल्ला थानांतर्गत वोगा नोआपाड़ा इलाके में पत्नी के अवैध संबंध से नाराज एक व्यक्ति ने तीन पड़ोसियों की जान ले ली। उसने साजिश के तहत पड़ोसियों के घरों के सामने बिजली की नंगी तार बिछा दी, जिसकी चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों के नाम शेख जाकिर हुसैन, सुलतान शेख और रहमान हैं। इसी घटना में छह और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर, लोगों ने आरोपित को पकड़ कर पिटाई कर दी। उसका नाम रबीउल मिस्त्री है। वह पेशे से राजमिस्त्री है। उसे विद्यासागर स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मूल रूप से मुर्शिदाबाद जिले का रहने वाला रबीउल वर्तमान में महेशतल्ला के वोगा नोआपाड़ा के 21 नंबर वार्ड में पत्नी फरीदा बीबी के साथ रहता था। स्थानीय लोगों की मानें तो रबीउल पत्नी फरीदा के चरित्र पर संदेह करता था।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 19 जुलाई 2019

दैनिक जागरण
सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं

बेनामी संपत्ति पर लगाम

आयकर विभाग की ओर से बसपा प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार की चार सौ करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति जब्त किए जाने पर शायद ही किसी को हैरानी हो। अभी हाल में फिर से बसपा उपाध्यक्ष बनाए गए आनंद कुमार जिस तरह कुछ ही समय में अकूत संपदा के स्वामी बन गए थे उसके चलते इसके आसार थे कि एक न एक दिन वह आयकर विभाग अथवा प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। आखिरकार वह चपेट में आए। आयकर विभाग के अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी उनके खिलाफ जांच कर रहा है। पता नहीं यह जांच किस नतीजे पर पहुंचेगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में ढेरों ऐसे आनंद कुमार हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है। किसी ने स्वयं के राजनीतिक रसूख के बल पर संपदा बटोरी है तो किसी ने अपने सगे-संबंधी के राजनीतिक असर के जरिये। इनमें से ज्यादातर ने बेनामी संपत्ति भी एकत्र कर रखी है। करोड़ों-अरबों रुपये की बेनामी संपत्ति एकत्र करने वालों में नेताओं और नौकरशाहों की बड़ी संख्या यही बताती है कि ये लोग मौका मिलने पर दोनों हाथों से संपदा लूटते हैं। बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला न केवल कायम रहना चाहिए, बल्कि उसमें तेजी और सख्ती भी आनी चाहिए। वास्तव में हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए जिसने बेनामी संपत्ति हासिल कर रखी है। चूंकि बेनामी संपत्ति हासिल किया जाना अपने आप में भ्रष्टाचार का परिचायक है इसलिए ऐसी संपत्ति के धारकों पर कोई रहम नहीं किया जाना चाहिए।

हालांकि बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून पहले भी था, लेकिन उसे मजबूती तब मिली जब 2016 में मोदी सरकार ने इस कानून में संशोधन किया। कालेधन के खिलाफ अभियान छेड़ने के बाद बेनामी संपत्ति को लेकर कोई प्रभावी कानून बनाना समय की मांग थी। निःसंदेह बेनामी संपत्ति संबंधी कानून में संशोधन के बाद इस तरह की संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला बढ़ा है और बीते दो साल में सैकड़ों करोड़ रुपये की बेनामी संपदा जब्त भी की गई है, लेकिन अभी उपयुक्त माहौल का निर्माण नहीं हो सका है। मोदी सरकार को ऐसे किसी माहौल का निर्माण करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए जिससे बेनामी संपत्ति रखने वाले भय खाएं। ऐसे किसी माहौल का निर्माण तभी होगा जब बेनामी संपत्ति रखने के कुछ दोषियों को सजा देकर जेल भेजा जाएगा। इस आंकड़े से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि लगभग सात हजार करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इतने बड़े देश में दो-ढाई साल में केवल सात हजार करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति जब्त किया जाना पर्याप्त नहीं। संपत्ति जब्ती के साथ जुर्माना वसूलने और जेल भेजने का काम इसलिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बेनामी संपत्ति हासिल करने वाले नेता यह प्रचारित करने में जुटे हुए हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना के तहत कार्रवाई हो रही है। यह किसी से छिपा नहीं कि इस जुमले को उछाल कर चुनावी लाभ लेने की भी कोशिश की जाती है। यह कोशिश यही बताती है कि बेनामी संपत्ति वाले जनता की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में हैं।

ममता की रणनीति

लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी में नई जान फूंकने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी अपनी रणनीति को दुरुस्त कर रही हैं। राज्य की जनता में फिर से तृणमूल के प्रति पुराना प्रेम जगाने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं, जिससे जनता फिर से उन पर पहले की तरह भरोसा करना शुरू कर दे। उनका पहला प्रयास राज्य में भाजपा के बढ़ते प्रभाव पर लगाम कसना है। ममता अभी मुख्य रूप से तीन मोर्चों पर काम कर रही हैं। पहला, उन्होंने सरकारी बाबुओं को रिझाने के लिए उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं बढ़ानी शुरू कर दी हैं। दूसरा, वह लोकसभा चुनाव के समय से ही बंगाल की विभूतियों का उल्लेख कर बंगाली भावनाओं के जरिये लोगों को तृणमूल से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तीसरा, उनका जोर सवर्ण जातियों के लोगों को साथ लाने का है, क्योंकि उनकी छवि सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नेता की बन चुकी है या कम से कम भाजपा उनकी ऐसी छवि बनाने में सफल रही है। इसके अलावा कई और कारकों पर उन्होंने एक साथ काम शुरू किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए सुख-सुविधाएं बढ़ाना शामिल है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के हफ्ते भर बाद ही तृणमूल की एक बैठक में पार्टी नेताओं ने ममता का ध्यान इस ओर खींचा था कि लाखों सरकारी कर्मचारियों ने उनकी सरकार से नाराज होकर भाजपा को वोट दिया है, क्योंकि वे बकाया महंगाई भत्ता और वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक वेतन नहीं बढ़ाने को लेकर नाराज हैं। तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने स्वीकार किया था कि सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लाखों वोट भाजपा के खाते में चले गए। तृणमूल नेता पुलिस विभाग में असंतोष का मुद्दा भी उठाते रहे। इस पर ध्यान देते हुए राज्य में पुलिस महकमे के लिए बोनस को बढ़ा दिया गया है। हालांकि अभी बाबुओं की नाराजगी दूर करना बाकी है। ममता भाजपा के हिंदुत्व फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बंगाली गौरव का कार्ड भी खेल रही हैं।

लंबी खिंचेगी जाधव को बचाने की लड़ाई

विवेक काटजू

कुलभूषण मामले में त्वरित परिणाम की अपेक्षा उचित नहीं, क्योंकि सामने पाकिस्तान जैसा अड़ियल, नादान और नकारात्मक सोच वाला मुल्क है

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी आइसीजे में अपनी शानदार दलीलों से कुलभूषण जाधव मामले में सफलता के लिए भारतीय लीगल टीम बधाई की पात्र है। इस अदालत ने भारत के पक्ष में 15-1 से फैसला सुनाते हुए इस तर्क से सहमति जताई कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस मुहैया न कराकर वियना संधि का घोर उल्लंघन किया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान के इस तर्क को खारिज कर दिया कि जासूसी या आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को काउंसलर एक्सेस सुविधा नहीं मिलती। ध्यान रहे कि कोई देश किसी दूसरे देश में गिरफ्तार अपने नागरिक की काउंसलर एक्सेस के जरिये ही मदद करता है। यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने आदेश दिया कि किसी भी सूरत में काउंसलर एक्सेस से इन्कार नहीं किया जा सकता और न ही इसके लिए कोई शर्त रखी जा सकती है। उसने पाकिस्तान को कुलभूषण की गिरफ्तारी के समय ही भारत को सूचना न देने का भी दोषी ठहराया। पाकिस्तान ने 3 मार्च, 2016 को कुलभूषण को गिरफ्तार किया, जबकि भारत को इसकी सूचना 25 मार्च को 22 दिन बाद दी गई। वास्तव में कुलभूषण को गिरफ्तार नहीं, बल्कि ईरान से अगवा किया गया था।

चूंकि आइसीजे अंतरराष्ट्रीय कानूनों से बंधा है इसलिए उसने कुलभूषण जाधव मामले से जुड़े तमाम तथ्यों पर गौर नहीं किया। आइसीजे में व्यक्ति नहीं, बल्कि देश ही पक्ष होते हैं। आइसीजे के न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति समर्पित होने का प्रयास करते हैं ताकि न्यायालय अपने स्वरूप और प्रकृति से न्याय कर सके, मगर जब किसी न्यायाधीश का देश ही किसी मामले में पक्ष बना हो तो वह अक्सर निष्पक्ष रहने के बजाय अपने देश का प्रतिनिधि बनने का मोह नहीं छोड़ पाता। इस मामले में असहमति व्यक्त करने वाले इकलौते पाकिस्तानी अस्थायी न्यायाधीश ने यही किया। वहीं भारतीय न्यायाधीश ने भारतीय न्यायपालिका के उच्च आदर्शों का अनुपालन करते हुए बहुमत का ही साथ दिया जबकि भारत की एक मांग नहीं भी मानी गई। यह मांग कुलभूषण को बरी कर उनकी रिहाई से जुड़ी थी और इसका आधार यह था कि उन्हें काउंसलर एक्सेस सुविधा न देने से उनके उन मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ जिनका उल्लेख अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संविदा यानी आइसीसीपीआर में है। अदालत ने कहा कि वियना संधि उल्लंघन के मामले पर विचार करते हुए किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौते के प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में फैसला किया गया कि पाक को निर्देश दिया जाए कि वह जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा की उचित समीक्षा और पुनर्विचार करे। अब पाकिस्तान को उन्हें अच्छे वकील उपलब्ध कराने होंगे जो अदालत में उनके खिलाफ साक्ष्यों की पड़ताल कर सकें। पाकिस्तान सैन्य अदालतों के मामले में ऐसी सुविधाएं नहीं देता और कुलभूषण के मामले में भी यही हुआ। पाक को जो करना चाहिए था वह अब काउंसलर एक्सेस के बाद भारत को करना होगा।

यह महत्वपूर्ण है कि आइसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। उसने पाकिस्तान को निर्देश दिया है कि इस मामले में जब तक प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी न की जाए तब तक कोई कदम न उठाया जाए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद पाकिस्तान अपनी जीत के खोखले दावे इस आधार पर कर रहा है कि कुलभूषण को उसकी हिरासत में रहना होगा। यह दावा एकदम निरर्थक है और इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तानी जनता को गुमराह करना है ताकि अंतरराष्ट्रीय अदालत में हुई अपनी फजीहत पर पर्दा डाला जा सके जहां उसकी एक दलील नहीं टिकी। उसकी यह कानूनी नाकामी अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह समझाने में नाकाम रही कि पाकिस्तान में आतंक के लिए दोषी भारत है। वास्तव में तथ्य यही है कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

आइसीजे के फैसले पर प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने कहा कि वह अब कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगा। हालांकि कानून पालन को लेकर पाकिस्तान के संदिग्ध रवैये के बावजूद इसकी संभावना कम है कि वह काउंसलर एक्सेस उपलब्ध कराने के आइसीजे के आदेश की अवहेलना करेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या काउंसलर एक्सेस मिलने से कुलभूषण से जुड़े मसले का समाधान हो जाएगा और उनकी सुरक्षित भारत वापसी संभव हो सकेगी? अपनी असहमति में पाकिस्तानी न्यायाधीश ने जो कहा उसका इससे सीधा सरोकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कुलभूषण के खिलाफ दो मामले दायर हुए। एक मामला जासूसी और दूसरा आतंकवाद से जुड़ा है। पाकिस्तानी न्यायाधीश के अनुसार पहले मामले में फैसला हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में कुलभूषण के खिलाफ पर्याप्त सुबूत थे। इस मामले का फैसला सैन्य अदालत ने किया। वहीं आतंकवाद से जुड़े दूसरे मामले में पाकिस्तान ने भारत से कुछ जानकारियां उपलब्ध कराने को कहा है। पाकिस्तान ने पूछा है कि कुलभूषण को फर्जी पासपोर्ट कैसे मिला? इसके अलावा उसने उनके बैंक खाते और फोन कॉल्स का ब्योरा और उनके संगी-साथियों से पूछताछ में मदद मांगी है। इस न्यायाधीश ने दावा किया कि चूंकि भारत ने पाकिस्तान की इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो यह मामला आगे ही नहीं बढ़ा। तथ्य कुछ और ही कहानी कहते हैं। पाक ने 23 मई, 2017 को दावा किया कि कुलभूषण के संगी-साथियों की तथाकथित सूची में रॉ के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों समेत सेवानिवृत्त नौसेना प्रमुख का नाम शामिल था। एफआइआर में शामिल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम सूची से हटा दिया। यह सूची स्पष्ट रूप से दुष्प्रचार का हिस्सा थी और भारत ने इसे न तो गंभीरता से लिया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। अब यह पूरी तरह पाक पर निर्भर करता है कि कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस उपलब्ध कराने के बाद उनके खिलाफ जांच में भारत से सहयोग का दोबारा अनुरोध करेगा या नहीं? ऐसा इसलिए, क्योंकि वह इस मामले को लंबा खींचना चाहता है।

भारत का पहला काम यही होना चाहिए कि वह कुलभूषण को पूर्णतः और गोपनीय काउंसलर एक्सेस उपलब्ध कराए ताकि उन्हें यह भरोसा हो सके कि पूरा भारत उनके पीछे खड़ा है। इससे वह उन अत्याचार और जुल्मों का खुलासा कर सकेंगे जो तीन साल की कैद के दौरान पाकिस्तान ने उन पर ढाए। इसके साथ ही भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तानी अदालतें उनके मामले में प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करें जो पहले ही उन्हें मौत की सजा सुना चुकी है। पाकिस्तान को बेनकाब करना होगा, भले ही इसके लिए कानून ही क्यों न बनाना पड़े। कुछ ऐसा करना होगा कि वह अपने किए पर शर्मिंदा हो। इसके साथ ही भारत को कुलभूषण के खिलाफ आतंकवाद के मामले की हवा निकालने की पुख्ता रणनीति बनानी होगी। पाकिस्तान के छल-कपट और षड्यंत्र की परतें खोलने के लिए भी ठोस योजना की दरकार होगी। भारत को कुलभूषण को बचाने के लिए मेहनत करने के साथ ही धैर्य भी रखना होगा। इसमें त्वरित परिणाम की अपेक्षा उचित नहीं होगी, क्योंकि सामने पाकिस्तान जैसा अड़ियल, नादान और नकारात्मक सोच वाला मुल्क है।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

अर्थव्यवस्था का लक्ष्य और आम आदमी

श्रीराम अग्रवाल

यह देखना आवश्यक है कि आर्थिक विकास का आम आदमी की वास्तविक क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?

सभी इससे परिचित हैं कि मात्र पांच साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 2.7 लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचकर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब अगले पांच वर्षों में पांच लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचाकर उसे इंग्लैंड एवं जर्मनी से आगे ले जाने का लक्ष्य है परंतु यह आसान काम नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को अमेरिकी डॉलर में व्यक्त करना भारतीय मन की समझ से परे ही है। शायद केवल वैश्विक स्तर पर अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट करने के लिए ऐसा किया गया है। आम बजट भी वैश्विक महत्वाकांक्षा की ओर बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी लक्ष्य को प्राप्त करने की आर्थिक रणनीति का ही संकेत दे रहा है।

दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय अर्थनीति-एक दिशा नामक अपनी पुस्तक में आर्थिक प्रगति को राष्ट्रीय सकल उत्पाद (जीडीपी) को औसतन प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के रूप में प्रस्तुत करने को एक भ्रमपूर्ण विसंगति बताया था। उनका मानना था कि आर्थिक विकास का वास्तविक मानक होना चाहिए आम आदमी की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। आम आदमी का सरोकार इससे होता है कि विकसित होती अर्थव्यवस्था में वह अपनी आय से पहले की अपेक्षा आवश्यक एवं सम्मानपूर्ण जीवन स्तर जीने के लिए कितनी अधिक वस्तुएं एवं सेवाएं खरीद पा रहा है। यह देखना आवश्यक है कि आर्थिक विकास का आम आदमी की वास्तविक क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। समग्र आर्थिक लक्ष्यों को आम आदमी की उपलब्धियों में परिभाषित करने के लिए हमें अगले पांच वर्षों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि को भी ध्यान में रखना होगा। यह वृद्धि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के औसत को कम कर सकती है। उपभोक्ता को उच्चतम क्रय शक्ति प्रदान करने वाली उपभोग योग्य ही वास्तविक आय मानी जाती है। यह आय प्रभावित होती है-परिवार की सदस्य संख्या, बाजार में मूल्य स्तर, अधिकतम आय देने वाला क्षमतापरक रोजगार और सक्षम बेरोजगारों को रोजगार। वास्तविक उपभोग आय पर समाज कल्याणकारी योजनाओं का भी अप्रत्यक्षतः सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि अमीर/अति अमीर वर्ग की लगभग दस प्रतिशत जनसंख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष 90 प्रतिशत जनसंख्या में से मात्र 30 प्रतिशत कमाऊ मध्यमवर्गीय जनसंख्या ही उपभोक्ता बाजार की प्रभावी मांग को प्रभावित करती है। कहना न होगा कि यही वर्ग है जिसकी वास्तविक उपयोग आय ही समग्र मांग को प्रभावित करती है। इन्हीं उद्योगों की वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय की गई आय का अंश बाजार के माध्यम से उपरोक्त उद्योगों से जुड़े करोड़ों स्वरोजगारी मध्यमवर्ग को वास्तविक आय प्रदान करते हैं। इस मध्यम आय वर्ग की वास्तविक उपभोग आय के घटने का ही परिणाम है आटो क्षेत्र, वित्तीय सेवा क्षेत्र, बीमा क्षेत्र तथा बैंक सावाधिक जमा में शिथिलता।

इसमें संदेह नहीं कि बीते पांच वर्षों में उज्ज्वला योजना, घर-घर में विद्युत एवं जलापूर्ति योजना, कन्या विवाह योजना, स्वसहायता समूह योजना, कौशल विकास योजना, आयुष्मान योजना आदि से आम आदमी और गरीब लोगों की वास्तविक आय में अप्रत्यक्षः वृद्धि की है। बजट में इन योजनाओं को आगे भी चलाते रहने और नए लक्ष्य आपूर्ति करने की बात कही गई है। इनमें से कई योजनाओं में कई राज्यों के द्वारा समयावधि के पूर्व ही सौ प्रतिशत या अधिक लक्ष्यपूर्ति की घोषणा भी समाचारों में आती रही है, परंतु इसकी धरातलीय वास्तविकता जानने के लिए सरकार द्वारा कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किए गए कि कहीं कार्यपालक अधिकारियों द्वारा मात्र कागजी खानापूर्ति कर लक्ष्य प्राप्ति के आंकड़े तो नहीं दिए गए? आयुष्मान योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों ने सरकारी अस्पतालों में उन्नत चिकित्सा सुविधा का निःशुल्क लाभ उठाया है पर बजट में डाक्टरों की कमी दूर करने और ग्रामीण क्षत्रों में एक निर्धारित दूरी के अंदर नए उन्नत सरकारी चिकित्सालयों को खोलने के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया। प्राइमरी से लेकर सामान्य, तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा को निजी व्यावसीयकरण क्षेत्र के सहारे छोड़ दिया गया है। कौशल विकास योजना में प्रशिक्षित युवाओं के आंकड़े तो गिनाए गए, लेकिन उनमें से कितने युवाओं को प्रभावी एवं सार्थक रोजगार प्राप्त हुआ है, यह जानने का प्रयास नहीं किया गया। सरकार की स्टार्टअप योजना के तहत रोजगार बहुल विनिर्माण इकाइयां कम बल्कि डिजिटल मार्केटिंग, फाईनेंस सर्विस इकाइयां अधिक खोली गईं और उनकी भी सफलता दर कितनी है और उनमें कितने युवाओं को रोजगार मिला, यह जानना भी जरूरी था। बजट में नए रोजगार अवसर सृजन, जो मध्यम आयवर्ग की उपभोग आय में वास्तविक वृद्धि करते हैं, की स्थिति स्पष्ट नहीं है। एफडीआई के तहत आने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां और घरेलू उद्योग समूह अपनी लागत को कम करने के लिए रोजगार बहुल तकनीक की अपेक्षा, पूंजीगहन उन्नत तकनीक अपनाते हैं ताकि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता में बने रह सकें। ऐसे में इनसे देश में बहुत अधिक नए रोजगार सृजन अवसरों की आशा रखना व्यर्थ है। रेलवे जैसे सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाले सार्वजनिक उपक्रम में क्रमशः निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर वह भी तकनीक गहन होता चला जाएगा। सार्वजनिक बैंकों में भी लगातार सेवानिवृत्त होते जा रहे कर्मचारियों से रिक्त स्थानों पर कई वर्षों से नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। चुनाव पूर्व रेलवे, डाकतार विभाग एवं सरकारी बैंकों की ओर से हजारों की संख्या में रोजगार के विज्ञापन दिए गए पर बजट में उनका कोई उल्लेख नहीं है।

आर्थिक न्याय एवं तार्किक दृष्टि से विचार करें तो प्रति दस साल में जो वेतन पुनरीक्षण किया जाता रहा है, वह विगत दस वर्षों में बढ़ी हुई मंहगाई के सापेक्ष बढ़ाए गए मंहगाई भत्ते का समायोजन मात्र ही होता हैं। सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि यदि वास्तविक प्रभावी मांग ही कम होती गई तो बढ़ते उत्पादन को खरीदेगा कौन? सरकार आम आदमी की वास्तविक उपभोग योग्य आय को ध्यान में रखकर ही प्रभावी आर्थिक नीतियों का निर्धारण करे। आम बजट से पहले आए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि बजट निर्धारण रणनीति में नोबल विजेता अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर के व्यावहारिक अर्थशास्त्र को भी ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन बजट में आम आदमी की आर्थिक एवं वित्तीय सीमाओं और उसके उपभोग एवं बाजार व्यवहार को गंभीरता से नहीं लिया गया। महात्वाकांक्षी होना अपनी क्षमताओं पर विश्वास का परिचायक है, पर जिन बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की होड़ में हम तेज गति के घोड़े पर सवार हो रहे हैं उसी के चलते अब चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी जा रही है।

(लेखक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सफलता के मंत्र

प्रत्येक व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन सफलता आसानी से नहीं मिलती। क्या सफलता मिलना सचमुच मुश्किल है? जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसे प्राप्त न किया जा सके। साहस, मेहनत, शिक्षा और धैर्य के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हर व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें यह अहसास कराए कि वह भी उनकी चिंता करता है और उन्हें महत्वपूर्ण समझता है तो उसे उससे लगाव महसूस होगा। सफलता के तीन सूत्र हैं- रुचि के काम को रोजगार का साधन बनाना, प्रशंसा करना एवं कृतज्ञता व्यक्त करना। अक्सर लोगों को एक ही काम करते हुए बोरियत हो जाती है। कई तो इसी प्रयोजन से काम बदलते रहते हैं। इसी कारण वे सफल नहीं हो पाते। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि प्रत्येक व्यक्ति यथासंभव अपनी रुचि को ही अपनी आजीविका का साधन बना ले। सफलता पाने का यह पहला सूत्र है।

दूसरा सूत्र है प्रशंसा। इसका मूल अर्थ है महत्व में वृद्धि। प्रत्येक व्यक्ति को सदैव ऐसे व्यक्तियों की तलाश रहती है जो उनका महत्व बढ़ाएं। हालांकि यह जानने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति के भीतर कौन से ऐसे गुण छिपे हुए हैं जिनकी प्रशंसा की जा सके। यह कार्य इसलिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोगों को एक दूसरे के अंदर गुण कम और दोष अधिक देखने की आदत होती है। यदि प्रशंसा भाव से लोगों को देखा जाए तो न केवल बहुत से व्यर्थ के झगड़ों का अंत हो जाए, बल्कि भाईचारे की भावना भी हर ओर फैल जाए। कृतज्ञता व्यक्ति के शिष्टाचार और सम्मान का बोध कराती है। अगर सहायता लेने पर प्रेम से व्यक्ति को धन्यवाद बोला जाए तो सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति के अंतर्मन को एक असीम शांति का अनुभव होता है। जब व्यक्ति में ये त्रिसूत्र आ जाते हैं तो फिर उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर असफलता के कारक यही होते हैं कि व्यक्ति कृतघ्न था, अथवा उसने अरुचि के क्षेत्र को रोजगार बना लिया था या फिर लोगों की प्रशंसा के बजाय उनकी आलोचना में अधिक रुचि दिखाई। सफलता या जीवन में आगे बढ़ने के कारक बहुत मुश्किल नहीं होते। हम ही यह मुश्किल बना लेते हैं।

रेनू सैनी

गरीबी पर निर्णायक प्रहार का पड़ाव

रवि शंकर

भारत ने एक बड़ी आबादी को गरीबी की जद से बाहर निकाला है, लेकिन गरीबी के खिलाफ यह संघर्ष और तेज करना होगा

गरीबी एक प्रमुख वैश्विक समस्या है जिससे आज तमाम देश जूझ रहे हैं। गरीबी का मतलब है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन। इसमें जीवन की गुणवत्ता के कई स्तरों पर स्थिति बहुत खराब होती है। ऐसे में किसी भी स्वतंत्र देश के लिए गरीबी एक शर्मनाक स्थिति है। पिछले कुछ समय में भारत ने अपने नागरिकों को गरीबी के दलदल से निकालने की दिशा में ऊंची छलांग लगाई है। इसकी खूब सराहना भी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 से 2016 के बीच सर्वाधिक 27.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। वर्ष 2005-06 में भारत के करीब 64 करोड़ लोग गरीब थे जो संख्या 2015-16 में घटकर 36.9 करोड़ पर आ गई।

इस रिपोर्ट में यह खुलासा भी किया गया है कि गरीबी कम करने की दिशा में पहल करने वाले देशों में भारत समेत दक्षिण एशियाई देश सबसे आगे हैं। पिछले एक दशक में भारत में तेजी से कम हो रही गरीबी का अहम पहलू यह रहा कि समाज के सबसे गरीब तबके की स्थिति में खासा सुधार हुआ है। बेशक, ये आंकड़े देखकर हम खुश हो सकते हैं कि देश में गरीबी घटी है, लेकिन इस सच्चाई से भी इन्कार नहीं कर सकते कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब अब भी भारत में हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के चार राज्यों में गरीबी की मार सबसे अधिक है। हालांकि देशभर में छिटपुट रूप में गरीबी मौजूद है, लेकिन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है। इन चारों राज्यों में देश की आधी गरीब आबादी रहती है। इनकी संख्या लगभग 19.6 करोड़ है। साफ है कि गरीबी न केवल भारत के लिए, बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लिए भी अभिशाप बनी हुई है। इसीलिए अभी भी गरीबों की बेहतरी के लिए काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।

देश में गरीबी की दर घटने को लेकर लोगों की यह धारणा कुछ हद तक सही हो सकती है कि केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का इसमें योगदान है, लेकिन इन योजनाओं से कितना और किस तरह गरीबी दर में कमी आ रही है, यह दावा कुछ विवादों को ही जन्म दे रहा है, क्योंकि ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनमें भ्रष्टाचार पर अक्सर सवाल उठता रहा है।

एक तरफ तो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने की आत्ममुग्धता है तो वहीं विश्व के एक तिहाई गरीबों की संख्या भी हमें आईना दिखाती है। भारत की यह विरोधाभासी छवि वाकई सोचने को बाध्य कर देती है। बुलेट ट्रेन का सपना संजोते इस देश ने दूसरे देशों के उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की क्षमता तो हासिल कर ली, किंतु वह गरीबी के अभिशाप से मुक्त नहीं हो सका। देश में गरीबी मिटाने पर जितना धन खर्च हुआ वह कम नहीं है। केंद्र सरकार के प्रत्येक बजट का बड़ा भाग आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु आवंटित किया जाता है, लेकिन अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि प्रयासों में या तो प्रतिबद्धता नहीं है या उनकी दिशा ही गलत है। गरीबी का अभिशाप कैसे और कब तक दूर होगा यह एक विचारणीय मुद्दा है। गरीबी से निजात पाने के लिए अब निर्णायक प्रयास करने का वक्त आ गया है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

आरिफ मोहम्मद की व्यथा!

'देवबंद से जवाब का इंतजार' शीर्षक से प्रकाशित आरिफ मोहम्मद खान के आलेख से व्यक्त होता है कि देवबंद और नदवा जैसे बड़े इस्लामिक शिक्षा केंद्रों के पाठ्यक्रम में 'हिदाया' और 'अशरफुल हिदाया' जैसी किताबों में जिहाद आदि की जो परिभाषाएं पढ़ाई जाती हैं, उन पर आरिफ साहब को एतराज है और अपने अध्ययन के आधार पर वे इसे कुरान की धारणा के विपरीत मानते हैं। आरिफ साहब के अनुसार कुरान में जिहाद अपने भीतर की बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष है, जबकि उक्त किताबों में इसे गैर इस्लामिक वर्गों के विरुद्ध लड़ाई और उनके उत्पीड़न से जोड़ा गया है। लेखक के अनुसार यह धारणा सीधे-सीधे दुनिया के कई हिस्सों में चल रही इस्लामिक आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन है और उसे इस्लामसम्मत सिद्ध करना है। मुझे लगता है कि आरिफ मोहम्मद जैसे हर उदारवादी विद्वान मुस्लिम की यही व्यथा है, लेकिन उनकी आवाज मुस्लिम दुनिया के जुनून भरे कोलाहल में कभी नहीं सुनी जाती। इस आवाज को सुने जाने के लिए जिस शिक्षित, विवेकसम्मत और स्वतंत्र वैचारिक माहौल की आवश्कता है वह अभी मुस्लिम जगत में दूर-दूर तक नहीं है। मौलवियों की जकड़न में दबे, अशिक्षित और जुनूनी समुदाय में आरिफ साहब जैसे लोगों की बातों का क्या मतलब?

डॉ. राम रघुवंशमणि शुक्ल, बहराइच

बच्चों की उचित शिक्षा पर ध्यान जरूरी

एक तरफ नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हो रहा है और दूसरी ओर बाजार बच्चों को हिंसात्मक और गलाकाट प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें तैयार कर रहा है। मोबाइल पर उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय बाजार बच्चों का नकारात्मक विकास करता जा रहा है। बच्चों की दुनिया में हिंसा और दौड़ का बाजार गर्म है, हमने अपने नौनिहालों के हाथ में जो मोबाइल पर खेले जाने वाले खेल सौंप रखे हैं वे सब हिंसा की दौड़ से जुड़े हैं। ऐसी दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती। ये हिंसा और दौड़ की प्रतियोगिताओं का बाजार कभी खत्म होने वाला नहीं। भोगवाद की अंधेरी गली में तनिक निराश हुए अथवा मनमुताबिक बात नहीं बनी तो आत्महत्या करने की ओर मुड़ जाते हैं। हमने ही जाने-अनजाने अपने बच्चो को ऐसे खेल-खिलौने और युवा होते ही वाहन पकड़ा दिए हैं। देश भर में 80 प्रतिशत विद्यालय एक ही समाज के बच्चों को लैंगिक भेद की शिक्षा देते हैं अर्थात लड़के और लड़की के लिए सरकारें अलग-अलग विद्यालय खोलने में लगी हैं। प्राइमरी कक्षा में भी यह समावेशी शिक्षा की अवधारणा का मजाक है। समावेशी का अर्थ है बालक बालिका एक ही पाठशाला में पढ़ें। यदि नई शिक्षा नीति में अनिवार्य सह शिक्षा व्यवस्था लागू हो सकेगी तो यकीन मानिए कि लड़कियों के प्रति हिंसा और छेड़खानी की घटनाएं नगण्य हो जाएंगी।

b.mishraz9@gmail.com

हादसों को बुलावा देतीं जर्जर इमारतें

मुंबई में 100 साल पुरानी चार मंजिला इमारत ढहने से कई निर्दोष लोग मारे गए। इस इमारत में 15 परिवारों के लगभग 40 लोग थे। इन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस खतरनाक बिल्डिंग में रहना मुनासिब समझा। ये पुरानी इमारत जीर्ण शीर्ण इमारतों की सूची में भी नहीं थी। इसके पुनर्निर्माण का जिम्मा एक कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी भी हादसे के इंतजार में थी। सभी जिम्मेदार लोग देर सवेर इस अपराध से बरी हो जाएंगे, लेकिन जिनके घर के सदस्य इस हादसे के शिकार हो गए उनका क्या होगा। देश के अन्य महानगरों में भी ऐसी खस्ताहाल इमारतें मिल जाएंगी और उनमें भी लोग भगवान भरोसे रह रहे होंगे। जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता और निर्दोष जानें नहीं चली जातीं तब तक समूचा प्रशासनिक अमला इसी तरह आंखें बंद किए पड़ा रहता है।

चंद्र प्रकाश शर्मा, महारानी बाग, दिल्ली

लगातार बढ़ता जल संकट

बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण और शहरीकरण ने जंगल, जमीन और जीव जंतुओं को ही हड़प लिया है। इस वजह से आज हर तरफ पर्यावरण और जल का बड़ा संकट है। हरे-भरे घने जंगलों से ही अच्छी वर्षा होती थी जो आज नदारद है और भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है और नदियां सूख चुकी हैं। पिछले लगभग 40 वर्षों से विशेषकर उत्तर भारत में वर्षा न के बराबर होने से ऐसे हालात बने हैं। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जल संकट और विकराल रूप धर लेगा।

वेद मामूरपुर, नरेला

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

4.7 प्रतिशत ही औसतन खर्च करते हैं राज्य, स्वास्थ्य सेवाओं पर, अपनी जीडीपी का, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए इसमें व्यापक बढ़ोतरी की आवश्यकता है।

आजकल

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को प्राथमिकता

चंदन कुमार चौधरी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में विभिन्न राज्यों में घोर असमानताएं हैं। जहां कई दक्षिण भारतीय राज्यों में इस मोर्चे पर हालात बेहतर हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश में बेहद बदतर हैं। हाल ही में नीति आयोग ने इस संबंध में राज्यों का एक सूचकांक जारी किया है जिसमें बताया गया है कि झारखंड ने स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस सूचकांक का मकसद यह भी है कि राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करें और इन सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करें

नीति आयोग द्वारा हाल में जारी एक नई तुलनात्मक रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के मोर्चे पर पिछड़े राज्यों में शुमार बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा पहले से कहीं अधिक फिसड्डी साबित हुए हैं। इसके विपरीत हरियाणा, राजस्थान और झारखंड में हालात में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग से तैयार नीति आयोग की 'स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में राज्यों की रैंकिंग से यह बात सामने आई है।

नीति आयोग की इस रिपोर्ट से देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी अन्य सेवाओं पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। खासकर तब जब हम आजादी के सात दशक पूरे कर चुके हों और अब तक की इस क्षेत्र की उपलब्धियों को देखें तो तस्वीर निराशाजनक दिखती है। दरअसल यह रिपोर्ट दर्शाती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी किस तरह काम करने की आवश्यकता है। साथ ही इसमें सुधार के लिए स्थिर प्रशासन समेत महत्वपूर्ण पदों को भरे जाने समेत स्वास्थ्य बजट बढ़ाने की कितनी जरूरत है। राज्य सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी जीडीपी का औसतन 4.7 प्रतिशत ही खर्च करती हैं, जबकि इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। स्वास्थ्य बजट बढ़ाने से इसमें सुधार की भरपूर गुंजाइश नजर आती है। नीति आयोग के एक सदस्य ने कहा भी है कि केंद्र सरकार को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। साथ ही राज्यों को स्वास्थ्य पर राज्य जीडीपी का औसतन 4.7 प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत तक खर्च करना चाहिए।

मुख्य रूप से 23 संकेतकों के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में हालात पहले से अधिक खराब हुए हैं और संदर्भ वर्ष 2015-16 की तुलना में 2017-18 में स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार का संपूर्ण प्रदर्शन सूचकांक 6.35 अंक गिरा है। ऐसे में सवाल उठना जायज है कि एक ओर हमारा देश जहां विकास के पथ पर अग्रसर है, वहीं हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बजाय पिछड़ते चले जाएं, तो क्या यह चिंता का विषय नहीं है? स्वास्थ्य के विषय में पिछड़ापन सरकारों की घोर लापरवाही को दर्शाता है।

हमें याद रखना होगा कि हाल ही में बिहार में मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में चमकी बुखार के कारण 150 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि यह बीमारी इस क्षेत्र में पहली बार सामने आई है, बल्कि यह पहले भी कई बार भयावह तरीके से दस्तक दे चुकी है। इसके बावजूद इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और लापरवाही व सरकारी उपेक्षाओं के कारण हमारे करीब 150 बच्चे इस साल काल के गाल में समा गए। होना तो यह चाहिए था कि पहली बार जब यह बीमारी सामने आई थी तब समय रहते इस पर शोध किया जाता और यह समस्या फिर सामने नहीं आए इसके लिए तैयारी की जाती, लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोशिश नहीं की गई। मुजफ्फरपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के आसपास के इलाकों में भी दिमागी बुखार का कहर पिछले कई वर्षों से निरंतर बच्चों की जान ले रहा है, लेकिन वहां भी अब तक कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है।

ऐसे में सवाल उठता है कि हम स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर कब व्यापक तरीके से ध्यान देंगे? ऐसा नहीं है कि अगर सरकार चाहे तो इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन या सुधार संभव नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर काबू पाया है।

इतना ही नहीं, अगर हम सूचकांक में सुधार के पैमाने पर देखें तो हरियाणा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। उसके 2017-18 के संपूर्ण सूचकांक में 6.55 अंक का सुधार आया है। उसके बाद क्रमशः राजस्थान (दूसरा), झारखंड (तीसरा) और आंध्र प्रदेश (चौथे) का स्थान रहा। रिपोर्ट के मुताबिक जहां बिहार जैसा राज्य लापरवाही और उपेक्षा के कारण स्वास्थ्य संबंधी मामलों की सूची में पिछड़ता जा रहा है, वहीं इससे अलग होकर बने झारखंड राज्य में इस दिशा में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है।

आंकड़े बताते हैं कि नीति आयोग की स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के सूचकांक में झारखंड ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। इसके लिए राज्य ने कई ठोस कदम उठाए और प्रयास किए हैं। विशेषज्ञों और अधिकारियों की सहायता से कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई और उसे कुशलतापूर्वक लागू किया गया। राज्य में रोटावायरस और खसरा-रूबेला जैसे नए टीकों की शुरुआत की गई जिससे बच्चों को विशेष रूप से डायरिया से होने वाली बीमारियों से अधिक सुरक्षा मिली, जो छोटे बच्चों में मृत्यु का सबसे आम कारण है। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने का नतीजा रहा कि राज्य में शिशु मृत्यु दर में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत कमी आई।

झारखंड में सभी गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एंबुलेंस की सुविधा शुरू गई ताकि रास्ते में होने वाली मौतों को रोका जा सके। इतना ही नहीं, राज्य में बच्चों के उम्र के बीच अंतर रखने के लिए भी काम किया गया जिससे कुल प्रजनन दर में कमी सुनिश्चित हुई। साथ ही राज्य में दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए बहुत अधिक पारिश्रमिक पर विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त किए गए।

झारखंड जैसे राज्य के प्रयास से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को सबक सीखना चाहिए। अगर झारखंड स्वास्थ्य सुधार के लिए इतना प्रयास कर सकता है तो फिर अन्य राज्य क्यों नहीं कर सकते हैं? गौरतलब है कि बिहार के सूचकांक में गिरावट का मुख्य कारण प्रजनन दर, जन्म के समय कम वजन, जन्म के समय स्त्री-पुरूष अनुपात, टीबी (तपेदिक) उपचार की सफलता दर आदि से जुड़े प्रदर्शन मुख्य वजह हैं।

नीति आयोग भी चाहता है कि हमारे देश के राज्य एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें और सीखें। शायद यही वजह है कि रिपोर्ट जारी किए जाने के मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने स्वीकार किया था कि यह एक बड़ा प्रयास है, जिसका मकसद राज्यों को महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करना है।

दवाओं की गुणवत्ता पर ज्यादा जोर

डॉ. तनु प्रिया

दुनिया भर की फार्मेसी जिस रफ्तार से विकसित हो रही है, इसमें किसी को शक नहीं कि भारत उसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा है। वर्ष 2017 में 1.1 ट्रिलियन का आकलन और 20 प्रतिशत की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी दुनिया भर के बाजारों में हमारी स्थिति का बखूबी बयान करती है। वर्ष 2016 से 2021 के बीच भारतीय फार्मास्युटिकल मार्केट में नौ से 12 प्रतिशत की विकास दर से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आयुष्मान भारत के लॉन्च के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के बढ़ते निवेश को देखते हुए घरेलू बाजार में और ज्यादा विस्तार होने की उम्मीद है। हालांकि यह केवल कहानी का एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू वह गुणवत्ता मानक है जिसे स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी दी गई है और पश्चिमी देशों के दवा नियामक प्राधिकरणों जैसे एफडीए द्वारा दवाओं के आयात की मंजूरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत में उसे दरकिनार कर दिया गया है। हालांकि दवाओं के उसी बैच के निर्यात के समय भारत की ओर से जरूरी आवश्यकताओं मसलन- अच्छी लैब प्रैक्टिस, अच्छी निर्माण प्रैक्टिस और अच्छी क्लिनीकल प्रैक्टिस को पूरी तरह से देखा और परखा जाता है।

भारत में दवाओं की कई निर्माण इकाइयां विश्व स्वास्थ्य संगठन की अच्छी निर्माण प्रैक्टिस और अच्छी लैब प्रैक्टिस के मानकों का पूरी तरह पालन नहीं करती हैं। भारत में दवाओं के निर्माण की करीब 12 हजार इकाइयां हैं जिनमें से केवल 25 फीसद ही जीएमपी के गुणवत्ता मानकों का पालन कर रही है। इतना ही नहीं, भारत में कुछ ही लैब को मान्यता प्राप्त है।

भारत में 62 हजार फार्मास्यूटिकल उत्पादों की जांच के लिए उचित और उद्योग के लिए खासतौर पर बनाई गई दवाओं का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला होनी चाहिए। हालांकि मौजूदा समय में इस तरह की केवल 47 प्रयोगशालाएं नेशनल जीएलपी प्रोग्राम के तहत प्रमाणित हैं। इसमें से छह प्रयोगशालाएं प्रत्येक वर्ष आठ हजार दवाओं के सैंपल एकत्र करती हैं जिसके नतीजे के तौर पर दवाओं की संतुष्टिजनक तरीके से जांच नहीं हो पाती है। दवाओं का उचित परीक्षण नहीं होने, बेहद कम मात्रा में संतुष्टि पहुंचाने वाले नतीजे मिलने और निम्न गुणवत्ता की दवाओं के परिणामस्वरूप ऐसे रोग पनप रहे हैं, जिन पर दवाओं का कोई असर नहीं होता है। उदाहरण के लिए जब टीबी यानी तपेदिक का इलाज निम्न स्तर की घटिया दवाओं से किया जाता है तो उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे टीबी के रोब पर इन एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर नहीं होता। फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री की ओर से मौजूदा समय में जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, उससे यह निश्चित है कि रोगों की दवा प्रतिरोधक क्षमता भारत के हेल्थ प्रोफाइल को और बिगाड़ेगी।

जन औषधि का मामला : सरकार की ओर से उठाया गया एक और कदम जन औषधि के तहत मल्टी पर्पज स्टॉलों की स्थापना है जिसे प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत लॉन्च किया गया है। इस स्कीम से भारत में सिर्फ जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा मिला है। दवाओं की अच्छी आपूर्ति और बेहतर गुणवत्ता के लिहाज से आश्वासन के बिना जन औषधि केंद्र खोलने से स्वास्थ्य बजट बढ़ता है। क्या हम महज सस्ती दवाओं के लिए दवाओं की गुणवत्ता पर लापरवाही बरतना बर्दाश्त कर सकते हैं? यह सवाल आज फार्मास्युटिकल बाजार में काफी बड़ा हो गया है।

हालांकि मरीजों की परेशानियां बढ़ने का एक कारण यह भी है कि उनमें ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं और जेनेरिक दवाओं के बीच अंतर पहचानने के लिए जागरूकता की कमी है। सरकार ने डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाओं को लिखना अनिवार्य बनाकर इस दिशा में झटका दिया है। इससे केमिस्ट को जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता में कमी लाने और उन्हें और ज्यादा अक्षम बनाने का अधिकार मिल गया है। इससे जनसामान्य और सभी लोगों को सार्वभौमिक ढंग से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों में कमी आई है। इससे स्वास्थ्य में मूलभूत, पर आवश्यक समानता का तत्व पीछे छूट रहा है। इससे भारत में सभी मरीजों को जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। ऐसे में यह विचारणीय मसला है।

खरी-खरी

क्या फर्क पड़ता है जी!

ब्रजेश कानूनगो

किसी के कुछ भी हो जाने को कोई अब रोक नहीं सकता। न ही किसी को कोई फर्क पड़ता है कि वह क्यों कर ऐसा हो गया। वो जमाना लद गया जब बाप गुस्से में आगबबूला होते हुए, मां पर आंखें तरेरता हुआ चीख उठता था- 'सुनती हो! तुम्हारा लाड़ला 'आवारा' हो गया है।'

समय-समय की बात है। अब बेटा हत्यारा हो जाए, तो भी बाप के माथे पर शिकन तक नहीं आती। 'न्यू इंडिया' का बाप जानता है कि बेटा अब 'भारत' नहीं रहा। भारत के भीतर के 'प्रेम' को वक्त की हवा ने 'प्रेम चोपड़ा' बना दिया है।

मदन का चाकू पुरी हो या भटिंडा, कहीं भी खुलेआम अपने जलवे दिखा सकता है। अब कोई 'बलराज' अपने बेटे को 'परीक्षित' का तमगा लगवाना नहीं चाहता। नए जमाने में सब बेटे बिना मेहनत किए 'अजेय' बने रहना चाहते हैं। कोई बाप उन्हें बदलने का दुस्साहस चाहकर भी कर नहीं सकता। यह मजबूरी है मां-बाप की। दौलत और जायदाद के लालच में बाप की जान को बेटे की लाइसेंसी बंदूक से खतरा है।

खतरा तो बाप से बेटी को भी हो गया है। अब 'ओमप्रकाश' या 'नाजिर हुसैन' जैसे भावुक बाप नहीं मिलते। 'जीवन दादा' और 'के एन सिंह' के क्लोन मुहल्ले-मुहल्ले बेटा-बेटियों पर अत्याचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सब 'रंजीत' हुए जा रहे हैं।

बात केवल घर परिवार की ही नहीं है। बदलाव की यह प्रवृत्ति आगे बढ़ चुकी है। अच्छा भला आदमी जाने कब भेड़ में बदल जाए और फसल बर्बाद कर दे! गड़रिये को चतुर लोमड़ 'कन्हैयालाल' या खूंखार लॉयन 'अजीत' हो जाने से कोई रोक नहीं सकता।

अब कोई कभी भी शेर हो सकता है, गधा, बंदर, चूहा भी हो सकता है। भैंस भी हो सकता है। कोई भरोसा नहीं कि कौन कब क्या हो जाए। भरोसे की भैंस फिर कीचड़ में उतर कर मजे करे, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला! नेता अभिनेता हो जाए, अभिनेता अर्थशास्त्री, योगाचार्य व्यवसायी, टीवी एंकर जज में बदल जाए... क्या फर्क पड़ता है जी!

अब लेखक खुद ही अपने को 'परसाई' समझने लगे तो पाठकों को क्या फर्क पड़ने वाला! वाट्सएप विश्वविद्यालय से कितने ही नए गुलजार, नीरज, बच्चन और अटल बिहारी निकलकर आ रहे हैं। अब कोई प्रदीप के गीत को बीन की तरह सुन रहा हो तो जरूरी नहीं कि वह रसिक श्रोता ही हो। वह रूपांतरित इच्छाधारी भैंस भी हो सकती है।

ट्वीट-ट्वीट

कितना परेशान रहते हैं ये गीता-कुरान में भेद करने वाले और हम कितने सुकून में जिन्हें गीता भी प्यारी है और कुरान भी। कहते हैं कि जाहिल होना एक बात है, जाहिलियत का लबादा ओढ़ना एक बात, ऐसे विद्वान से पूछें जिसने दोनों पढ़ी हों, वह कहेगा दोनों में 80 प्रतिशत बातें कॉमन हैं।
समीर अब्बास@TheSamirAbbas

कुलभूषण की फांसी रोकना और काउंसलर एक्सेस मुहैया कराने का आइसीजे का फैसला अच्छा है। पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर यही होगा कि वह कुलभूषण जाधव को सकुशल भारत वापस भेज दे और दोनों देश इस प्रकरण का पटाक्षेप करें।
सुधींद्र कुलकर्णी@SudheenKulkarni

हनुमान चालीसा पाठ में शामिल होने पर इशरत जहां को मुस्लिम समुदाय से धमकियां मिल रहीं हैं। इस मौके पर सुधारवादी कहां हैं? आजादी के हिमायती कहां गायब हैं? नारीवादी कहां गुम हैं और तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने वाले किधर गए?
नूपुर जे शर्मा@UnSubtleDesi

राज्यनामा
झारखंड

नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने में अड़चन

झारखंड में नवनिर्मित पलामू, हजारीबाग तथा दुमका स्थित नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने से मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया ने इन्कार कर दिया है। इससे इन कॉलेजों में इसी साल से पढ़ाई शुरू नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट में तीनों मेडिकल कॉलेज के भवन तैयार होने तथा सभी पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी होने को आधार बनाते हुए आश्वस्त किया है कि पढ़ाई शुरू करने के पहले सभी पद भर लिए जाएंगे। यह भी दलील दी गई है कि राज्य में डॉक्टरों की भारी कमी है। एमसीआइ द्वारा गिनाई गई कमियां दूर नहीं होने के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने को भी जिम्मेदार बताया गया है। फिलहाल तीनों नए मेडिकल कॉलेज में पदों को भरने की वर्तमान स्थिति यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर संविदा पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू आयोजित करने का निर्णय किया है। प्रोफेसर के 76 तथा एसोसिएट प्रोफेसर के 93 पदों पर नियुक्ति होगी।

विधायकों की दादागिरी : झारखंड में विधायकों के कानून हाथ में लेने के किस्से अक्सर आते हैं। कुछ माह पूर्व ईचागढ़ के भाजपा विधायक साधुचरण महतो ने भूअर्जन पदाधिकारी की सरेआम पिटाई कर दी थी। उक्त अधिकारी का गुनाह इतना था कि वह विधायक की इच्छा के खिलाफ उनके क्षेत्र में जमीन की मापी करा रहे थे। इस पर पदाधिकारियों के संगठन ने दबाव बनाया तो विधायक की गिरफ्तारी हुई। बाद में उच्चस्तरीय हस्तक्षेप से मामला रफा-दफा हो गया। ताजा वाकया बोकारो का है। यहां के भाजपा विधायक विरंची नारायण ने बोकारो इस्पात के पदाधिकारी की पिटाई कर दी। बोकारो के शहरी क्षेत्र का प्रशासन केंद्रीय उपक्रम सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जिम्मे है और उक्त पदाधिकारी उससे जुड़े थे। उन्होंने एक जमीन

को लेकर आपत्ति प्रकट की थी, जो विधायक को रास नहीं आया। फिर क्या था, विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पदाधिकारी एवं उनके सहकर्मियों की पिटाई की। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल उठता है कि आखिर विधायकों को कानून हाथ में लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या वे इतने असहिष्णु हैं जो अपनी बात उचित मंच पर नहीं रख सकते। ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि खराब होती है और इसका अहसास विधायकों को भी होना चाहिए। भाजपा के इन विधायकों की दबंगई से विपक्षी दलों को घेराबंदी का मौका मिल गया है। मुख्य विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की करतूत से जोड़कर खिंचाई की है। विजयवर्गीय ने निगम कर्मचारियों की बल्ले से पिटाई की थी और इस मामले में प्रधानमंत्री ने भी कड़ी टिप्पणी की थी। विपक्षी दलों ने इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के समक्ष सवाल उठाया है कि क्या अधिकारियों पर हाथ उठाने वाले विधायकों के खिलाफ संगठन के स्तर से कोई कार्रवाई होगी या नहीं? फिलहाल यह मामला शांत होता नहीं दिखता। 22 जुलाई से आरंभ हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है।

सुखाड़ के आसार : झारखंड का पड़ोसी बिहार जहां बाढ़ से त्रस्त है, वहीं राज्य में सुखाड़ के आसार नजर आ रहे हैं। मानसून के आगमन में देरी और काफी कम बारिश से खरीफ फसल पर असर देखने को मिलने लगा है। जुलाई का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन राज्य की मुख्य फसल धान का आच्छादन लक्ष्य के महज 11 फीसद तक ही पहुंच सका है। दर्जन भर जिलों में तो अब तक धान की रोपाई का काम तक शुरू नहीं हुआ है। पिछले साल 129 प्रखंडों में पड़े सुखाड़ के बाद इस वर्ष भी संकेत कुछ अच्छे नहीं हैं। अगर यही स्थिति एक सप्ताह और बरकरार रही तो राज्य भीषण सुखाड़ की चपेट में आ सकता है। राज्य सरकार ने इस वर्ष धान के लिए 1,800 हजार हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके मुकाबले अब तक महज 198 हेक्टेयर में खेती हो सकी है। वैसे लोगों को अभी भी उम्मीद है कि इंद्रदेव की कृपा बरसेगी। कृषि विभाग को भरोसा है कि 31 जुलाई तक बेहतर बारिश होगी। जुलाई माह में झारखंड में औसतन 319 मिमी बारिश होती है। अभी तक 127 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है जो कि इस माह होने वाली बारिश का 40 प्रतिशत है। अगले पखवाड़े होने वाली अच्छी बारिश पर राज्य की फसल की उम्मीदें टिकी हुई हैं। झारखंड में छीटा और रोपा दो तरह से धान की खेती की जाती है। चाईबासा जैसे जिन जिलों में छीटा को अपनाया जाता है वहां कवरेज अच्छा है जबकि हजारीबाग व पलामू में रोपा किया जाता है, वहां शून्य परिणाम दिखाई दे रहा है। बादलों ने मेहरबानी नहीं दिखाई तो झारखंड के किसानों के समक्ष संकट पैदा होगा। ऐसे में सरकारी राहत उपलब्ध कराना ही एकमात्र विकल्प होगा।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

पाकिस्तान द्वारा भारत के लिए एयरस्पेस खोलना मोदी सरकार के दबाव का नतीजा है?

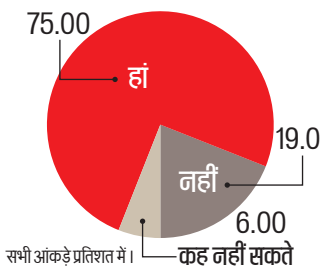

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या पाकिस्तान द्वारा आतंकी हाफिज सईद की गिरफ्तारी महज दिखावा है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

स्कुलभूषण लौटाइए बढ़े मित्रवत हाथ,
कब तक हाफिज को लिए पीटोगे तुम माथ।
पीटोगे तुम माथ लिए अपना दिल काला,
देश हुआ कंगाल पिट रहा है दीवाला।
भला न होगा यार पाल कर यूं खर-दूषण,
पा जाओगे मुक्ति हमें लौटा कुलभूषण।
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

जहरीले तेल से मुक्ति कब तक

रेणु जैन
स्वतंत्र टिप्पणीकार

होटल और रेस्टोरेंट आदि में खाद्य पदार्थों के निर्माण के बाद शेष बचा हुआ तेल नुकसानदायक होता है जिसे छोटे कारोबारियों को बेच दिया जाता है। इसे रोकने के उपाय जरूरी हैं

लगभग पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार के नमकीन बड़े शौक से खाए जाते हैं। इस तरह के नमकीन हमारे खानपान को ज्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखने में आया है कि खासकर भारत में इन नमकीन पदार्थों को बनाने में आवश्यक मसाले या तो मिलावटी होते हैं या स्वास्थ्य मानकों के अनुसार नहीं होते। इस बेहद परेशान करने वाली दिक्कत से निजात नहीं मिल पाई थी कि अब ऐसे नमकीन को तलने के लिए आवश्यक तेल को लेकर भारी संकट खड़ा हो गया है। यह संकट मिलावट का ही नहीं, बल्कि एक बार उपयोग में लाए गए तेल को बार-बार उपयोग में लाए जाने से संबंधित है। ऐसे तेल से हृदय रोग, एसिडिटी, अल्जाइमर जैसे रोगों के होने की आशंका बढ़ने के साथ ही पेट के विभिन्न प्रकार के कैंसर होने का खतरा भी बना रहता है।

भारतीय खाद्य संस्था एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने 2006 की धारा 16 (15) के तहत ये निर्देश जारी किए हैं कि रोजाना 50 लीटर से अधिक तेल की खपत करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को इस बात का हिसाब देना होगा कि उनके यहां कितना इस्तेमाल किया हुआ तेल बचा रह गया और उस बचे हुए तेल को किसे बेचा गया? यह व्यवस्था जल्द ही शुरू की जा सकती है। यह कदम इसलिए उठाया गया कि उपयोग किए हुए तेल का पुनः इस्तेमाल और छोटे दुकानदारों को 20 से 25 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बेचने की देश भर से लगातार कई तरह की शिकायतें मिली हैं।

एक मोटे अनुमान के आधार पर भारत में सालाना 2.3 करोड़ टन खाद्य तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 40 फीसद रेस्टोरेंट या खाद्य उद्योगों में काम में लिया जाता है। इसमें से 30 फीसद तेल उपयोग में आने के बाद बेकार हो जाता है। इसी तेल को बाजार में खुला तेल कहकर बेच दिया जाता है। छोटे होटलों से लेकर रेस्टोरेंट, कैटरर्स, हलवाई, छोटे दुकानदार, ठेले-खोमचे वाले, ग्रामीण इलाकों की दुकानों के लोग इस खुले तेल को धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। बार-बार गर्म करने के कारण तेल का टोटल पोलर कंपाउंड (टीपीसी) 25 फीसद से कहीं अधिक हो जाता है, जो इसे जहरीला बना देता है। एफएसएसएआइ के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तेल में टीपीसी की अधिकतम सीमा 25 फीसद ही होनी चाहिए। इससे अधिक टीपीसी वाला खाद्य तेल खाने के अलावा किसी दूसरे पदार्थ में मिलाया नहीं जा सकता है। दरअसल जले हुए तेल में धीरे-धीरे फ्री रेडिकल्स के रिलीज होने से तेल में एंटी ऑक्सीडेंट की मात्रा समाप्त हो जाती है। खासतौर से मांसाहारी भोजन बनाने के बाद बचे तेल में हेक्टोसाइक्लिक की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। इसी तेल को बार-बार इस्तेमाल करने से उसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो कैंसर का मुख्य कारक है।

चिंता की बात यह भी है कि इसी तेल के इस्तेमाल से तेल में ट्रांसफैट की मात्रा कम हो जाती है जिससे हार्ट संबंधी बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसफैट की वजह से दिल की बीमारी से हर वर्ष विश्व में पांच लाख लोगों की मौत होती है। कहा जाता है कि इस कारण से अकेले भारत में 60 हजार मौतें होती हैं। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2022 तक विश्व को ट्रांस फैट मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। चिंता की बात यह भी है कि कई बार जब तेल ज्यादा ही काला तथा गाढ़ा हो जाता है तो कई प्रतिष्ठान तेल को नालियों में भी बहा देते हैं जिससे प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है, जो एक अलग चिंता का विषय है।

खाद्य और आपूर्ति विभाग की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के बाद सरकार तत्काल विभिन्न राजकीय सरकारों से संबंधित विभाग इस बचे काले तेल को खरीदने की दिशा में काम कर रही है, ताकि इस तेल से बायो-डीजल बनाया जा सके। पचास लीटर या इससे अधिक तेल रोजाना खपत करने वाले दुकानदारों का डाटा जुटाने का मकसद यह भी है कि पैसा मिलने से व्यवसायी स्वयं खराब हो चुके तेल को बेचने के लिए आगे आएंगे, वहीं आम लोगों की सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़ भी थमेगा। माना जा रहा है कि बायो-डीजल परंपरागत ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प है। इसे भविष्य का ईंधन भी माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल काफी कम मात्रा में इस्तेमाल किए हुए खाद्य तेल से बायो-डीजल बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच रहा है, ग्रीन हाउस की स्थिति भी चिंताजनक है। ऐसे में काले तेल से बायो-डीजल बनाने की खबर स्वागतयोग्य है।

इस मुहिम में देश भर के प्रमुख होटलों को जोड़ा जाएगा। हाल ही में मुंबई तथा पुणे में एक प्रमुख रेस्टोरेंट चेन के 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट हर महीने 35,000 लीटर तेल को बायो-डीजल में बदल रहे हैं। वाहनों में कुछ तकनीकी बदलाव के साथ तकरीबन 20-25 ट्रक इसी से चल रहे हैं और रोज करीब 150 रेस्टोरेंट को माल पहुंचा रहे हैं। एफएसएसएआइ द्वारा संबंधित प्रोजेक्ट के तहत देश के सभी 26 बायो-डीजल प्लांट पर काम हो रहा है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा छह बायो-डीजल प्लांट हैं। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, रायपुर, पश्चिम बंगाल, बंगलुरु जैसे तमाम प्रदेशों में प्लांट हैं। इन प्लांटों के जरिये आने वाले दो सालों में तकरीबन 80 हजार नई नौकरियों के आसार बने हैं। देश की 12 हजार करोड़ की विदेशी मुद्रा जो तेल के निर्यात पर खर्च होती है उसका बड़ा हिस्सा भी बच सकता है।

आम लोगों की सेहत तथा पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से उठाया गया यह कदम प्रशंसनीय है। योजना को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक शहर में सेंटर खोले जाने की योजना भी है। साथ ही बचे तेल से बायो-डीजल बनाने की अनिवार्यता को लेकर अपने ई-चैनलों के माध्यम से कई अभियान भी चल रहे हैं। वैसे दो से अधिक बार खाद्य तेल का इस्तेमाल करने वालों पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 (एफएसएसएआइ) के तहत दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

सिरीफोर्ट सभागार में आयोजित दसवें जागरण फिल्म फेस्टिवल का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन करते केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फिल्म अभिनेता अनिल कपूर। साथ में दैनिक जागरण के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक महेंद्र मोहन गुप्त ● जागरण

जेएफएफ ने पूरी की कमी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : फिल्म निर्देशक केतन मेहता ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बॉलीवुड में बनने के बावजूद एक कमी महसूस की जा रही थी, जिसे जागरण फिल्म फेस्टिवल ने पूरा किया। जागरण ने एक अनोखी सिनेमा संस्कृति तैयार की है। कार्यक्रम में संजय गुप्त ने कहा कि सिनेमा सोसायटी की जरूरत को दिखा रहा है। जागरण फिल्म फेस्टिवल 18 शहरों में जाएगा, 400 फिल्में दिखाएगा और उम्मीद करता हूं भविष्य में यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ फेस्टिवल में शुमार होगा।

अब 25 साल बाद मैं शाह रुख के अलावा किसी अन्य हीरो के बारे में सोच पा रही हूं। हालांकि शाह रुख अब भी मेरे पसंदीदा हैं, लेकिन अब मैं राजकुमार राव, वरुण धवन व रणबीर कपूर जैसे अभिनेताओं को अपनी फिल्मों में लेने के बारे में सोच रही हूं।

फराह खान, कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक

फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे सिनेप्रेमियों का उत्साह देखने लायक था। उनके लिए यह हर लिहाज से यादगार अनुभव रहा। ● जागरण

मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानदायी भी है जेएफएफ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जागरण फिल्म फेस्टिवल के पहली दिन बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। हर आयु वर्ग के दर्शकों ने विभिन्न फिल्मों को लेकर उत्साह दिखाया। परिचर्चा सत्र में सेलिब्रिटीज को देखने की उत्सुकता दिखाई। रिमझिम बारिश के बीच लोगों की आवाजाही का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान कुछ लोगों ने दैनिक जागरण से जेएफएफ के बारे में अपने विचार साझा किए -

अगर फिल्मों को करीब से जानना या समझना हो, कला की बारीकियों का नमूना देखना हो तो जेएफएफ से बेहतर मंच नहीं मिल सकता। यहां पर दिखाई जाने वाली फिल्में अलग-अलग क्षेत्रों की संस्कृति व भावनाओं का आईना होती हैं।

स्मृति

मैं दो वर्षों से लगातार यहां आ रही हूं। यहां पर फिल्में, सेलीब्रिटीज से बातचीत का सत्र काफी जानकारी देने वाला होता है। पिछली बार फिल्मों का जो चयन था वह काफी अच्छा था। इस बार मैं इसी वजह से फिर से आई हूं कि नई फिल्में देखने को मिलेंगी।

सृष्टि

मैं हर फिल्म फेस्टिवल में जाती हूं। जागरण के इस आयोजन में कुछ अलग बात है। यहां का माहौल और फिल्मों की वैरायटी लोगों को आकर्षित करती है। मैं हर बार इस फेस्टिवल में आना चाहूंगी।

अदिति

यह फिल्म फेस्टिवल अपने आप में अलग है। यहां आकर आप किसी भी भाषा की फिल्में देख सकते हैं। फिल्मों का चयन हर बार उम्दा होता है। अनिल कपूर, फराह खान व अन्य फिल्म के जानकारों की बातचीत को खूब एंज्वाय किया।

ऋतिका

मैं सिक्किम से हूं और फिल्में देखकर हिंदी सीख रही हूं। थिएटर या फोन पर जो फिल्में नहीं देखी जा सकती वह फिल्में यहां देखने को मिलती हैं। मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में अभी भी बड़े पर्दे पर देखने को मैं उत्साहित हूं।'

ग्रेस

फेस्टिवल में उमड़ा सिनेप्रेमियों का हुजूम

बारिश और जाम के बावजूद पहुंचे दर्शक, देखीं फिल्में और कलाकारों से की बातचीत

मंत्रमुग्ध कर देने वाला अवसर : सिरीफोर्ट सभागार में एकाग्रचित्त दर्शक। ● जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : सुबह आसमान में बादल छाए हुए थे। झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत तो दी पर सड़कों पर जाम परेशान कर रहा था, लेकिन यह जागरण फिल्म फेस्टिवल (जेएफएफ) के प्रति सिनेप्रेमियों की दीवानगी ही है कि वे बारिश और जाम से जूझते हुए सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम पहुंचे। टिकट बुकिंग काउंटर के बाहर सिनेप्रेमियों की भीड़ थी। वे सत्र में शिरकत करने वाले कलाकारों, फिल्म निर्माताओं को लेकर बातचीत कर रहे थे। कोई अनिल कपूर को देखना चाह रहा था तो कोई फराह खान की बातचीत का सत्र सुनने को बेताब था। अनिल कपूर के आते ही सिनेप्रेमियों का हुजूम देखने लायक था। वे उनके डॉयलाग भी जोर-जोर से बोलते नजर आए। जेएफएफ में प्रदर्शित फिल्मों को देखने के लिए लिए दिल्ली के अलावा नोएडा, फरीदाबाद और अन्य जगहों से भी लोग आए। समय पर पहुंचने से फिल्म और सत्र में शामिल होने की खुशी उनकी बातों और चेहरे से झलक रही थी।

सत्र से पहले फिल्मी गपशप : जेएफएफ के पहले दिन हर सत्र में समय से पहले दर्शक पहुंचे। ऐसे भी कई दर्शक थे जो जेएफएफ में कई साल से लगातार आ रहे हैं। कई नवोदित फिल्म निर्माता भी अपनी जिज्ञासाओं को लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जेएफएफ हिंदी सिनेमा को समृद्ध कर रहा है।

अभिनेता अनिल कपूर के आते ही सिनेप्रेमियों का हुजूम देखने लायक था। वे उनके डॉयलाग भी जोर-जोर से बोलते नजर आए

चरम पर रहा सिनेप्रेमियों का उत्साह

सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम के प्रवेश द्वार पर लगे फिल्म फेस्टिवल के आयोजन संबंधी बैनर, पोस्टर और होर्डिंग के पास सिनेप्रेमी फोटो खिंचाते और सेल्फी लेते भी नजर आए। फिल्म फेस्टिवल में बड़ी संख्या में बुजुर्ग एवं महिलाएं भी आई थीं। पूर्वी दिल्ली से आए विकास कहते हैं कि वह अनिल कपूर के प्रशंसक हैं। जागरण फिल्म फेस्टिवल में जब अनिल कपूर के आने की जानकारी मिली तो खुद को यहां आने से नहीं रोक सके। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया।

जुबां पर फिल्मी डॉयलाग

सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम के बाहर हिंदी फिल्मों के डॉयलाग लिखे हुए थे, जिसे पढ़कर दर्शक भी गदगद हुए। मोगैंबो खुश हुआ... राहुल-नाम तो सुना होगा...तुमसे न हो पाएगा... ऑल इज वेल... मेरे पास मां है जैसे डॉयलाग ने उन फिल्मों की यादें ताजा की जो सुपरहिट रही हैं।

फिल्म अभिनेता अनिल कपूर कुछ इस मूड में नजर आए ● जागरण

फिल्मों का लुत्फ उठाने और कलाकारों से बातचीत करने के लिए फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे दर्शक ● जागरण

आज के आकर्षण

सुबह 11 बजे

बांग्ला फिल्म 'द टू लवर्स' का इंडिया प्रीमियर

सुबह 11.15 बजे

निर्देशक अपर्णा सेन से खास बातचीत

दोपहर 1.25 बजे

फिल्म विडोज ऑफ वृंदावन की स्क्रीनिंग और निर्देशक ओनीर के साथ बातचीत

दोपहर 1 बजे

तमिल फिल्म के डी का इंडिया प्रीमियर

दोपहर 3.10 बजे

के डी की निर्देशक मधुमिता सुंदररामन से बातचीत

शाम 5 बजे

हिंदी फिल्म तुंबाड

शाम 5.50 बजे

फिल्म क्या होगा का इंडिया प्रीमियर

शाम 6.15 बजे

मशहूर ईरानियन फिल्म निर्देशक, प्रोड्यूसर और पटकथा लेखक पोरान डेरॉखसांडे से बातचीत

शाम- 7.30 बजे

ईरानियन फिल्म निर्देशक पोरान डेरॉखसांडे की अंडर द स्मोकी रूफ का प्रदर्शन

ऐसे पहुंचें सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम

नजदीकी मेट्रो स्टेशन हौज खास और ग्रीन पार्क हैं। यहां मेट्रो से उतरकर खेल गांव मार्ग से सिरीफोर्ट इंस्टीट्यूशनल स्थित ऑडिटोरियम पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा बस से भी यहां पहुंचा जा सकता है। बस से आनेवालों को अगस्त क्रांति मार्ग से ऑडिटोरियम नजदीक पड़ेगा।

रखे विचार | जागरण फिल्म फेस्टिवल में अभिनेता आदिल हुसैन ने निर्माताओं से की अपील, कहा-दर्शकों को दिया जाए बेहतर कंटेंट

मुनाफे की होड़ छोड़कर बनाएं अच्छी फिल्में : आदिल हुसैन

फिल्म अभिनेता आदिल हुसैन ● जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जागरण फिल्म फेस्टिवल (जेएफएफ) के दसवें संस्करण के पहले दिन पहुंचे फिल्म अभिनेता आदिल हुसैन ने कहा कि जेएफएफ के हर आयोजन का हिस्सा बनने में उन्हें खुशी महसूस होती है। जिस तरह की फिल्मों का दौर चल रहा है, उसकी एकरसता से दर्शक ऊबने लगे हैं और ऐसे में वे अच्छी फिल्मों व कला की तलाश करते हैं। जेएफएफ उनकी इस तलाश को पूरी कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि फिल्म निर्माता भी अपनी जिम्मेदारी समझें और फिल्मों के इस सशक्त माध्यम का उपयोग जिम्मेदारी से करें ताकि एक बार फिर से लोगों को अच्छे सिनेमा से जोड़ा जा सके।

आदिल हुसैन ने कहा कि इस फिल्म फेस्टिवल में अगले पचास साल तक हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्हें यह आयोजन दिल के बेहद करीब लगता है क्योंकि यहां दिखाई जाने वाली फिल्मों में समाज के लिए संदेश होता है। दैनिक जागरण ऐसी फिल्मों से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिनमें जीवन मूल्यों, समाज की कुरीतियों और अच्छे समाज निर्माण की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। आजकल की फिल्मों में केवल मसाला होता है, मानवीयता, सौंदर्यबोध और मूल्यों को जगह नहीं मिलती है। ऐसे में निर्माताओं को चाहिए कि वे मुनाफे की होड़ छोड़कर अच्छी फिल्में बनाएं। तमाम माध्यमों से दर्शक मनोरंजन के हर पहलू से जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें बेहतर कंटेंट दिया जाए तो वे भी अच्छी फिल्मों की तरफ मुड़ेंगे और उनसे फिर से जुड़ेंगे।

अभिनेता आदिल हुसैन ने कहा कि जो काम दैनिक जागरण जेएफएफ के माध्यम से कर रहा है, उस काम को आदर्श रूप से तो सरकार व भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि पुरानी व अच्छी फिल्मों को केवल फिल्म फेस्टिवल में ही नहीं बल्कि पूरे साल दिखाएं ताकि दर्शकों को अच्छे बुरे का फर्क पता चल सके और निर्माताओं के ऊपर अच्छी फिल्में बनाने का दबाव बन सके।

जागरण फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हो रही फिल्मों को लेकर अभिनेता आदिल हुसैन ने कहा कि फिल्मों में भाषा से लेकर संस्कृति तक की जो विविधता होती है वह अद्वितीय है। यहां विभिन्न प्रकार की फिल्में देखने को मिलती हैं, उनमें वैविध्यता होती है। अन्य फिल्म फेस्टिवल में इतनी विविधता देखने को नहीं मिलती है।

दर्शकों को मौका मिला तो वे कैमरे के आगे आने में पीछे नहीं रह। ● जागरण

छोटे बजट की यथार्थवादी फिल्मों में समाज की दुश्वारियां, उसका दर्द, आम आदमी की कहानी है जो कि समाज में संदेश के साथ साथ संवेदना का संचार करती है। इस तरह की फिल्मों को दिखाने के लिए सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे कि शुरुआत से ही लोगों में इंसानियत की भावना भरी जा सके।

आदिल हुसैन, अभिनेता

'घरे बायरे आज' फिल्म से हुई शुरुआत

जासं, नई दिल्ली : जागरण फिल्म फेस्टिवल की औपचारिक शुरुआत अपर्णा सेन की बांग्ला फिल्म घरे बायरे आज के वर्ल्ड प्रीमियम से हुई। ये फिल्म रवींद्रनाथ टैगोर की अमर कृति घरे बायरे (घर और दुनिया) पर बनी है, जो गुरुदेव ने 1916 में लिखी थी। इस कृति पर सबसे पहले महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने 1984 में इसी नाम से एक फिल्म बनाई थी। रे की फिल्म भी बेहद सफल रही थी और इसको कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे। अब अपर्णा सेन ने इस फिल्म को नए सिरे से 'घरे बायरे आज' के नाम से बनाया है। इस फिल्म को देखने के लिए मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन समेत कई नामचीन लोग मौजूद थीं। इस फिल्म के प्रदर्शन से पहले इसकी निर्देशक अपर्णा सेन ने दर्शकों के साथ इस फिल्म को बनाने के अपने अनुभवों को साझा किया। इसके अलावा अपर्णा सेन फिल्म के प्रदर्शन के दौरान पूरे समय तक दर्शकों के साथ हॉल में बैठी रहीं। चितरंजन पार्क से आईं एक दर्शक मधुमिता घोष ने इस फिल्म को देखने के बाद खुशी जाहिर की और कहा कि अपर्णा ने इसको नए तरीके से इसको बनाया है।

जागरण फिल्म फेस्टिवल में मशहूर अभिनेता अनिल कपूर ने लोगों के सामने साझा कीं अनकहीं बातें

नसीब और मेहनत से मिलती है सफलता

जागरण फिल्म फेस्टिवल में सिनेप्रेमियों से बात करते फिल्म अभिनेता अनिल कपूर ● जागरण

सही वक्त पर अगर आपके सामने सही इंसान, सही रोल लेकर आ जाए तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ऐसा न हो तो क्या करेंगे। आपकी मेहनत काम नहीं कर पाएगी। गलत फिल्म और गलत भूमिका आपको आगे नहीं जाने देगी। मैं एक्टिंग से प्यार करता हूं, यह मेरा शौक है। मैं काम का बहुत लुत्फ उठाता हूं, लेकिन जब तक इसके साथ नसीब नहीं जुड़ता तो मैं इस मुकाम तक नहीं आता। आज भी मेरे पास कुछ न कुछ ऐसा आ जाता है कि मैं एक्साइटेड हो जाता हूं कि यह फिल्म मेरी बेस्ट फिल्म होगी। चाहे फिर वह फिल्म चले या न चले। दसवें जागरण फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन इंडिया रेट्रोस्पेक्टिव सेशन पर बोलते हुए प्रख्यात अभिनेता अनिल कपूर ने मेहनत और किस्मत के साथ अपनी सफलता के राज साझा किए।

यशा माथुर ● नई दिल्ली

अनिल कपूर ने अपनी फिल्मों से जुड़ी अनकही बातें दर्शकों को बताईं, जिनसे अब तक सभी अनजान थे। अपनी पहली फिल्म 'वो सात दिन' के बारे में उन्होंने बताया कि इस फिल्म के बाद उनका नाम 'थैले वाला एक्टर' पड़ गया था। उस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वह कहते हैं कि जब मैंने स्क्रिप्ट और रोल देखा तो सोचा कि मैं इसे कैसे कर सकूंगा। उस समय के हीरो लेदर जैकेट पहन कर बाइक पर चलते थे। मुझे गांव वाले लड़के का रोल करना था। मैं मुंबई का रहने वाला था, लेकिन मैं न कहने की स्थिति में नहीं था। मैंने तेलुगु और कन्नड़ फिल्में भी की। उस समय रमेश सिप्पी ने एक फिल्म शतरंज के लिए ऑडिशन दिया। वह फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन मेरा नाम अखबारों में आ गया। तभी से मेरी यात्रा शुरू हो गई। मैं नया था और मैं ही पहला एक्टर हूं जिसने हरियाणवी सीख कर यह भूमिका निभाई। यह वर्ष 1983 की बात है और अब 2019 है, 36 साल हो गए इस बात को।

अनिल ने कहा कि जब मेरे मन ने हां कहा मैंने फिल्म के लिए हां कह दी। केवल भूमिका को नहीं बल्कि स्क्रिप्ट को भी देखा। मिस्टर इंडिया उनकी सुपर हिट फिल्मी थी। इसके बारे में उन्होंने बताया कि इसकी कहानी उस समय की है जब सलीम-जावेद साहब साथ थे। बाद में जावेद साहब ने इसकी स्क्रिप्ट पूरी की और यह सच है कि इस फिल्म को अमिताभ बच्चन साहब के लिए लिखा गया था। पीटर परेरा ने स्पेशल इफेक्ट दिए थे।

सफलता पर घमंड नहीं करता हूं

अनिल ने यह भी बताया कि वे अपनी सफलता पर घमंड नहीं करते हैं। कभी सफल होने के बारे में नहीं सोचा। हमेशा लेबर क्लास स्ट्रगलर रहा हूं। सुबह बोरी बिस्तर उठाता हूं और काम पर निकल जाता हूं। अनिल ने बताया कि फिल्म 'राम लखन' कब शुरू हुई और कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। 'दिल धड़कने दो' जावेद साहब के कहने पर की। पहले जब मैं एक बार में एक ही फिल्म करता था तो लोग कहते कि इनके पास काम नहीं है, लेकिन मैं किरदार में घुस जाता था। किरदार को जीता था। जब 1942 लव स्टोरी की तो युवा दिखने के लिए वजन घटाया।

गानों के बोल पर ध्यान देना जरूरी : फराह खान

प्रियंका दुबे मेहता ● नई दिल्ली

बदलते दौर में समानांतर और कम बजट के सिनेमा को भी पहचान मिल रही है। ये फिल्में पैसा भी कमा रही हैं और लोगों को पसंद भी आ रही हैं। यह बात कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक फराह खान ने दसवें जागरण फिल्म फेस्टिवल के दौरान आयोजित परिचर्चा में कही। कार्यक्रम का संचालन फिल्म समीक्षक राजीव मसंद ने किया। अपने चिर-परिचित अंदाज में जब राजीव ने एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार की तो फराह भी हर सवाल पर नहले पर दहला साबित हुईं। उन्होंने हर प्रश्न का जवाब रोचक और मजाकिया अंदाज में देकर श्रोताओं का मन मोह लिया।

बात जब फराह खान की फिल्मों की आई तो बड़ी बेबाकी से उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ फिल्में इस कदर विफल हुईं कि उन्हें आज याद नहीं करना चाहतीं। उन्होंने कहा कि फिल्मों में जो बदलाव आया है वह दर्शकों की वजह से भी आया है। दर्शक बड़े बजट की फिल्मों को सराहते हैं और ऐसे में उनकी फिल्में लोगों को पसंद आती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह आज भले ही सफल फिल्म निर्देशकों की फेहरिस्त में शामिल हों, लेकिन कभी वह भी आम लोगों की तरह थीं। शुरुआती दिनों को कभी नहीं भुलाया और शायद इसी वजह से आज भी जमीन से जुड़ी हुई हैं। फिल्मों में आइटम सॉन्ग के बढ़ते प्रचलन को लेकर फराह ने कहा कि उन्हें लगता है कि आज के दौर में जो भी आइटम सॉन्ग उन्होंने बनाए हैं उनमें कहीं औरत को वस्तु के तौर पर नहीं दिखाया गया है बल्कि पहले के बजाय आज के ये गाने ज्यादा मनोरंजक हैं। पहले के आइटम सॉन्ग अगर आज सुने जाएं तो उनके बोल से लेकर कोरियोग्राफी तक में अश्लीलता का पुट नजर आता है। एक समय माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया बेहद लोकप्रिय हुआ गाना 'चने के खेत में' आज सुनें तो लगता है कि उसमें छेड़खानी के कृत्य को ग्लैमराइज किया गया है। आज ऐसा नहीं है, गानों को लेकर इंडस्ट्री थोड़ी गंभीर हुई है।

रीमेक फिल्में बनें, लेकिन खूबसूरती रहे बरकरार

फराह द्वारा अमिताभ बच्चन अभिनीत सत्ते पे सत्ता का रीमेक बनाने की खबरें हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा न होने के कारण उन्होंने इसका नाम नहीं लिया, लेकिन रीमेक के चलन पर विचार जरूर साझा किए। फराह ने कहा कि रीमेक से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। आज से पंद्रह साल पहले जब वह फिल्में बनाती थीं तो रीमेक के बारे में नहीं सोच पाती थीं, लेकिन आज उन्हें लगता है कि जो क्लासिक फिल्में उन्होंने देखी हैं उन्हें उनके बच्चे भी देख सकें। ऐसे में वह रीमेक की तरफ मुड़ीं। वह चाहती हैं कि जो भी रीमेक फिल्में बनें उनकी खूबसूरती से छेड़छाड़ न हो। उनके मुताबिक संघर्ष केवल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। यह हर जगह और हर किसी के जीवन में है।

दर्शकों के सवालों का जवाब देतीं फिल्म निर्देशक फराह खान ● जागरण

भाषाई बंधन तोड़तीं फिल्में संवार रहीं सिनेमा का भविष्य

फ्यूचर ऑफ सिनेमा सत्र में बाहुबली फिल्म के निर्माता शोबू यरलागड्डा व निर्देशक केतन मेहता ने रखे विचार

हंस राज ● नई दिल्ली

हमें स्वतंत्र हुए सात दशक बीत गए, लेकिन सिनेमा को लेकर हमारी सोच में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। भारतीय फिल्में आज भी परंपरागत दायरे तक सीमित हैं। एक भाषा की फिल्में दूसरी भाषा के दर्शकों तक न के बराबर पहुंच पाती हैं। हालांकि पिछले दो दशक में सिनेमा में काफी बदलाव आया है। भाषाई बंधन तोड़ती फिल्में अब सिनेमा का भविष्य संवार रही हैं। जागरण फिल्म फेस्टिवल (जेएफएफ) के पहले दिन 'फ्यूचर ऑफ सिनेमा- ब्रेकिंग लैंग्वेज बैरियर्स इन इंडियन सिनेमा' विषय पर फिल्म निर्माता शोबू यरलागड्डा और निर्देशक केतन मेहता से फिल्म समीक्षक राजीव मसंद की बातचीत में सिनेमा के अतीत से लेकर वर्तमान और भविष्य पर ऐसे कई तथ्य सामने आए।

थिएटर से पॉकेट थिएटर तक पहुंच चुके सिनेमा के दौर को लेकर केतन मेहता ने कहा कि बतौर दर्शक या निर्माता-निर्देशक, हम सिनेमा के सबसे खूबसूरत दौर से गुजर रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से हर व्यक्ति तक आसानी से फिल्में पहुंच रही हैं। लोग एक सप्ताह में दस-दस फिल्में देख पा रहे हैं, जिससे यह बात साबित होती है कि सिनेमा की जरूरत और मांग दोनों में इजाफा हो रहा है। वहीं, बाहुबली सरीखी फिल्म का निर्माण करने वाले शोबू यरलागड्डा ने भारतीय सिनेमा में तकनीक के बढ़ते दखल को सकारात्मक बताते हुए कहा कि वर्तमान में भारतीय फिल्में अगर वैश्विक पहचान बना रही हैं तो उसमें तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

सिनेमा को प्रभावशाली बनाती है तकनीकि: सिनेमा और तकनीक को लेकर दर्शकों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में केतन मेहता ने कहा कि सिनेमा में प्रयोग हो रही तकनीक को बदनाम किया जाता है। तकनीक सिनेमा को और प्रभावशाली बनाती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित होने के बावजूद फिल्म 'मांझी द माउंटेनमैन' के निर्माण के वक्त कई जगहों पर उन्होंने तकनीक का सहारा लिया। तकनीक कलाकारों के अभिनय पक्ष पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इसी सवाल का जवाब देते हुए शोबू यरलागड्डा ने माना कि वर्चुअल रिएलिटी (वीआर) या वर्चुअल इफेक्ट्स (वीएफएक्स) जैसी सुविधाएं सिनेमा को सिर्फ सपोर्ट करती हैं, लेकिन सफल अच्छी कहानी बनाती है।

जागरण फिल्म फेस्टिवल के रास्ते जनसामान्य तक पहुंचती हैं फिल्में : केतन मेहता जागरण फिल्म फेस्टिवल (जेएफएफ) से करीब चार साल से जुड़े हैं। वह कहते हैं कि सिनेमा को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए दस वर्ष पहले शुरू हुआ जेएफएफ सिनेमा को सही दर्शक तक पहुंचाने में सफल रहा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जागरण फिल्म फेस्टिवल के पिछले चार आयोजनों का गवाह रहा हूं। जो चयनित सिनेमा यहां प्रदर्शित होता है वह सिनेमा प्रेमियों के लिए खास होता ही है।

सीधे संवाद का मिलता है अवसर: फिल्म निर्देशक केतन मेहता ने कहा कि जागरण फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा को लेकर अभिनेता, निर्माता और निर्देशक से सीधे संवाद का मौका भी इस क्षेत्र में भविष्य तलाशते युवाओं को मिलता है। जेएफएफ ने एक दशक का सफर सफलतापूर्वक तय कर लिया है, इस लौ को जलते रहने देने की जरूरत है।

परिचर्चा में उपस्थित फिल्म निर्माता शोबू यरलागड्डा (बीच में)। साथ में फिल्म निर्देशक केतन मेहता (दाएं) व फिल्म समीक्षक राजीव मसंद। मेहता ने कहा, हम सिनेमा के सबसे खूबसूरत दौर से गुजर रहे हैं। ● जागरण

जिज्ञासा का भी किया समाधान

सत्र के आखिर में श्रोताओं को भी निर्माता-निर्देशक से सवाल-जवाब का मौका मिला। एक सवाल के जवाब में शोबू ने कहा कि यह सिनेमा का सिल्वर-गोल्डन जुबली वाला दौर नहीं है। इस समय हम किसी फिल्म के लिए यह नहीं सोच सकते कि यह फिल्म पर्दे पर सौ दिन तक रहेगी। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पहले कम फिल्में बनती थीं तो प्रदर्शन के लिए हर फिल्म को पर्याप्त पर्दा मिल जाता था। आज स्थिति अलग है। हर भाषा में फिल्में बन रही हैं और खूब बन रही हैं। साथ ही कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं, जहां लोग फिल्म का इंतजार करते हैं।

> दूसरे देशों की तरह यहां की सरकार सिनेमा की शक्ति को अभी तक नहीं समझ सकी है। अगर उस स्तर से भी भारतीय सिनेमा को सपोर्ट मिले तो यह ग्लोबल इंडस्ट्री बन जाएगी।
>
> **केतन मेहता, मशहूर फिल्मकार**

Dainik Jagran
EXPERIENCE THE WORLD'S LARGEST FILM FESTIVAL
JULY 18 - 21 | SIRI FORT AUDITORIUM, NEW DELHI
#JAGRANFILMFESTIVAL /JagranFilmFestival /jagranfilmfestival /jagranfilmfest Jagran Film Festival
Premium Rajnigandha® presents
10TH JAGRAN FILM FESTIVAL [jff bringing cinema to you]
OVER 400 SCREENINGS • 18 CITIES • 1 FILM FESTIVAL
www.jff.co.in

FRIDAY, 19 JULY, 2019

AUDI - 2

TIME	PARTICULAR	SESSION
11:15 AM	IN CONVERSATION - Aparna Sen with Rajeev Masand followed by audience Q&A	In Conversation
12:45 PM	RAJNIGANDHA ACHIEVER'S FILM - GOLD Dir. Reema Kagti/151min/Hindi/India/2018	Screening
3:15 PM	INCONVERSATION with HRITHIK ROSHAN (TBC)	In Conversation
4:30 PM	COUNTRY FOCUS - Hon'ble Ambassador of the Argentine Republic/Cultural Head (Key Note with Aseem Chhabra)	Key Note
4:50 PM	INDIA PREMIERE - THE IRISH PRISONER Dir. Carlos Jaureguialzo, Marcela Silva y sute/100min/Spanish/Argentina/2015/CF	Screening
6:15 PM	IN CONVERSATION (INTERNATIONAL RETROSPECTIVE) with Udita Jhunjhunwala Pouran Derakhshandeh (Iranian Film Maker, Producer, Director, Screen writer)	International Retrospective
7:30 PM	RETROSPECTIVE - UNDER THE SMOKEY ROOF Dir. Pouran Derakhshandeh/111min/Persian/Iran/2017/RS	Screening

AUDI - 3

11:00 AM	INDIA PREMIERE - THE TWO LOVERS Dir. Ranjan Ghosh/120min/Bengali/India/2019/IS	Screening
1:00 PM	INDIA PREMIERE - KD Dir. Madhumita Sundararaman/122min/Tamil/India/IS	Screening
3:10 PM	Q&A WITH MADHUMITA SUNDARARAMAN	Q&A
3:45 PM	PAUDHA Dir. Shashwat Dwivedi/50min/Hindi/India/2019/IS	Screening
5:00 PM	TUMBBAD Dir. Rahi Anil Barve, Adesh Prasad/104min/Hindi/India/2018/IS	Screening
7:20 PM	INDIA PREMIERE - Dirty Job Dir. Khsoro Ma'asoumi/112min/Iran/2018/WP	Screening

AUDI - 4

11:00 AM	IMAGO Dir. Karan Chavan and Vikram Patil/97min/Marathi/India/2019/IS	Screening
12:55 PM	A FLOWERING TREE, SOHNA-A FLYING KID, BINGO, CLAUDIA, ELEVATOR TO THE TOP FLOOR, SAHARA, MOMENT OF MIRACLE (SHORT DOC)	Screening
1:25 PM	INDIA PREMIERE - WIDOWS OF VRINDAVAN Dir.Onir/20min/Bengali/India/2019/Indian Shorts	Screening
1:45 PM	Q&A Onir (Director of WIDOWS OF VRINDAVAN)	Q&A
2:00 PM	NORMAL/Dir. Mragendra Singh/ 91mins/ English/ USA/ 2019/ WP	Screening
4:05 PM	Master Class by TVF + 2 episodes (Premiere)	Master Class
5:50 PM	INDIA PREMIERE - KYAA HOGAA	Screening
7:55 PM	SAWAH Dir. Adolf El Assal/87min/Arabic/Luxembourg/2019	Screening

SATURDAY, 20 JULY, 2019

AUDI - 2

TIME	PARTICULAR	SESSION
11:00 AM	JHALKI Dir. Brahmanand S Singh, Tanvi Jain/102min/Hindi/India/2018/IS	Screening
1:00 PM	INDIA PREMIERE - SATASH Dir. Tolegen Baitukenov/91min/Kazakh/Kazakhstan/2018/WP	Screening
2:45 PM	MISSING JOHNNY Dir. Xi Huang/104min./Taiwan/Mandarin/2017	Screening
5:00 PM	RAJNIGANDHA ACHIEVER'S TALK - Homage to Veeru Devgan Rohit Shetty (with Rajeev Masand)	Homage Session
6:00 PM	GULLY BOY Dir. Zoya Akhtar/153min/Hindi/India/2019/IS	Screening
8:35 PM	IN CONVERSATION Siddhant Chaturvedi with Rajeev Masand	In Conversation

AUDI - 3

11:00 AM	INDIA PREMIERE - THE LITTLE MATCH GIRL Dir. Alejo Moguillansky/71min/Spanish/Argentina/2017/CF	Screening
12:25 PM	INDIA PREMIERE - T FOR TAJ MAHAL. Dir. Kireet Khurana/104min/Hindi/India/2018/IS	Screening
2:10 PM	Q&A: T FOR TAJ MAHAL Kireet Khurana	Q&A
2:35 PM	VIRUS Dir. Aashiq Abu/152min/Malyalam/India/IS	Screening
5:10 PM	THE GOLD-LADEN SHEEP AND THE SACRED MOUNTAIN Dir. Ridham Janve/97min/Gaddi/India/2018/IS	Screening
6:55 PM	SIMIN Dir. Morteza Atash Zam Zam/78min/Iran, Islamic Republic /2019/WP	Screening
8:35 PM	MY HOME INDIA Dir. Anjali Bhushan/45min/English/India/2019/Documentary	Screening

AUDI - 4

11:00 AM	HASINA - A GREAT DAUGHTER'S TALE Dir. Piplu Khan/72min/Bengali/Bangladesh/2018/WP	Screening
12:45 PM	Master Class by TVF	Master Class
2:00 PM	SHORTS & DOCS - AAPKE AA JANE SE SWIMMING THROUGH THE DARKNESS, FOREVER YOURS BANSHO	Screening
3:45 PM	RAJNIGANDHA ACHIEVER'S FILM - I TITA, A LIFE OF TANGO Dir. María Teresa Costantini/124min/Spanish/Argentina/2017	Screening
6:30 PM	INDIA PREMIERE - WOLF Dir. Han Tao/90min/Mandarin/China/2016/WP	Screening
8:00 PM	INDIA PREMIERE - HOLY BOOM Dir. Maria Lafi/100min/Greek/Greece/2018/WP	Screening

TO SEE THE COMPLETE SCHEDULE, VISIT WWW.JFF.CO.IN
All Foreign Films are Subtitled in English Language • World Panorama (WP) • Indian Showcase (IS) • Homage (HO) • Retrospective (RS) • Master Class • In-Conversation • Shorts • Documentary Terms and Conditions: • Screening are limited to delegates/audience of age 18+ only • Seats for all audience on first come first serve basis only • Schedule is subject to change without prior notice • Rights of entry reserved by Jagran Film Festival

Country Partner: Argentina Republic | Entertainment Partner: Miss Malini | Knowledge Partner: Sharda University | OTT Partner: TVF PLAY | Magazine Partner: Stardust | Content Partner: Mountain River Films | Outdoor Partners: Jagran Engage, Pioneer | To register, visit: bookmyshow

गोएयर शुरू कर सकती है दिल्ली-भूटान उड़ान सेवा

मुंबई, प्रेट्र : वाडिया समूह की किफायती विमानन कंपनी गोएयर नई दिल्ली से भूटान के लिए उड़ान सेवा शुरू कर सकती है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि कंपनी जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है। कंपनी ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र में कदम रखा है। अभी वह फुकेट, माले, अबुधाबी और मस्कट के लिए सेवा का संचालन कर रही है। सूत्र ने कहा कि कंपनी नई दिल्ली से भूटान के पारो के लिए उड़ान सेवा शुरू करने के लिए तैयार है।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में निजी क्षेत्र में निवेश के माध्यम से देश के विकास को गति देने पर जोर है। अगले पांच वर्षों में भारत बड़े बदलावों से गुजरने वाला है।
— राजीव कुमार
वाइस चेयरमैन, नीति आयोग

सेंसेक्स	38,897.46	318.18	निफ्टी	11,596.90	90.60	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 35,670	₹170	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 41,100	₹910
डॉलर	₹ 68.97	₹0.15	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 62.82							

कारपोरेट हलचल

सीआरडब्ल्यूसी ने अपना 19वां आरडब्ल्यूसी पहलेजा में शुरू किया है। सीआरडब्ल्यूसी रेलवे के साथ एक एमओयू के तहत देश भर में गुडशेड पर ट्रेड की सहुलियत के लिए इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। डीएफसी की रेल लाइन निर्माण के कारण आरडब्लूसी, डेहरी ऑन सोन बंद हो गया था। लेकिन सीआरडब्ल्यूसी ने पहलेजा गुडशेड में आरडब्ल्यूसी टर्मिनल निर्मित करके क्षेत्र के व्यापार विकास हेतु प्रमुख आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया है। इसमें 13800 टन कवर्ड गोदाम हैं और रेल कनेक्टेड गोदाम भी हैं।

तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसीएल) ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपने भावी रोडमैप की घोषणा की है। इसके तहत सभी खेलों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की नीति पर काम होगा। आइओसी के निदेशक (एचआर) रंजन मह्मपात्रा ने बताया कि कंपनी की योजना वॉलीबाल, बास्केटबाल, शूटिंग, तीरंदाजी, कुश्ती, कबड्डी, फुटबाल व मुक्केबाजी को खेलों को शामिल करने की है। इन खेलों के खिलाड़ियों की कंपनी में भर्ती की जाएगी।

नाइजीरिया के रेल कॉरपोरेशन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का दौरा किया। अपने दो दिवसीय दौरे में प्रतिनिधिमंडल ने एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक आलोक टंडन से मुलाकात की। इस मौके पर एनएमआरसी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीडी उपाध्याय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

तैयारी ▸ मुख्यमंत्रियों की उप-समिति की बैठक में कृषि की चुनौतियों और निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा

उप-समिति कृषि जिंसों पर ईसीए के खिलाफ

मंडियों पर सीमित लोगों के कब्जे पर समिति ने जताई चिंता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गठित मुख्यमंत्रियों की उप-समिति ने गुरुवार को अपनी पहली बैठक में कृषि जिंसों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) को गैरवाजिब करार दिया है। उप-समिति के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि इसे तत्काल हटाने की जरूरत है। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्रियों की राय में गैर-कृषि उत्पादों पर भले ही यह कानून लागू हो, लेकिन कृषि जिंसों पर इसकी जरूरत नहीं है। फड़नवीस ने यह भी कहा कि कृषि उपज मंडियों पर सीमित लोगों का वर्चस्व चिंता का विषय है। उप-समिति की अगली बैठक सात अगस्त को मुंबई में होगी, जिनमें पहली बैठक में चिन्हित मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

उप-समिति का मानना था कि जिंस बाजार अब वैश्विक हो चुका है, जिसके मद्देनजर नीतियां बनानी होंगी। इनमें कृषि व वाणिज्य मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी व अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा सत्र चलने की वजह से इसमें शामिल नहीं हो सके।

खाद्य प्रसंस्करण की चुनौतियों पर भी उप-समिति ने पहली बैठक में चर्चा की। एएनआइ

पहली बैठक में शामिल सभी मुख्यमंत्रियों की राय थी कि कृषि क्षेत्र में सुधार की सख्त जरूरत है, जिसमें राज्यों का दायित्व ज्यादा है। कृषि को घाटे से उबारने और नई दिशा देने के लिए तत्काल एक नई नीति चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में फड़नवीस ने चर्चा करते हुए कहा कि इस पर गंभीरता की जरूरत है। बैठक में कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ विकास के लिए निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर खासतौर पर बल दिया गया।

फड़नवीस ने कहा कि 1991 के बाद गैर-कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधार तो हुआ, लेकिन कृषि क्षेत्र लगातार पिछड़ता गया। खेतिहर मजदूरों और औद्योगिक मजदूरों की मजदूरी में फर्क बढ़ता गया। सब्सिडी अनाज की खेती पर ज्यादा दी गई, लेकिन विकास दर बढ़ाने में मत्स्य क्षेत्र की भागीदारी ज्यादा है।

मंडी कानून पर फोड़ा ठीकरा : फड़नवीस ने कहा कि कृषि उपज मंडियों की हालत राज्यों के बनाए मंडी कानून से ही खराब हो गई है। मंडियों पर सीमित लोगों का एकाधिकार हो गया। उपज के भाव मुट्ठीभर लोग मिलकर तय करने लगे। ऐसे में किसानों को लाभ मिलना मुश्किल ही था। ई-नाम की शुरुआत हुई, मगर इसका विस्तार नहीं हो पाया, जिससे इसका पूरा उपयोग नहीं हो सका। उप-समिति इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी।

निवेश तत्काल बढ़ाने की जरूरत : उप-समिति का मानना था कि कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं बढ़ने से हालात नाजुक हो रहे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। गैर-कृषि क्षेत्र में निवेश की रफ्तार 36 फीसद है, जबकि कृषि क्षेत्र में वास्तविक निवेश की दर महज तीन फीसद है। इसमें निजी क्षेत्र को शामिल करने की जरूरत है। इसके लिए कृषि क्षेत्र के कानून में सुधार किए जाएंगे। फड़नवीस ने कहा कि जिन राज्यों में ठेके पर खेती का प्रावधान है, वहां निवेश आ रहा है।

इन पर उप-समिति एकमत

- देश में छोटी जोत वाले किसानों की संख्या ज्यादा है, जिन्हें तकनीक के प्रयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन तकनीकों को किसानों तक कैसे पहुंचाई जाए, यह विचार का विषय है।
- 13 लाख करोड़ रुपये के कृषि कर्ज को हर किसान तक पहुंचाना बड़ी चुनौती है।
- देश के लगभग 40 फीसद ऐसे किसान हैं, जिन तक संस्थागत कर्ज नहीं पहुंच पा रहा है।
- मार्केट पूर्वानुमान एजेंसी होनी चाहिए, जो समय से सूचना दे सके। उसी के अनुरूप किसान खेती करे, ताकि उसे उपज का उचित मूल्य मिल सके।

टिकटॉक और हेलो पर प्रतिबंध की तलवार

- आइटी मंत्रालय ने इनसे पूछे 24 सवाल, 22 जुलाई तक मांगा जवाब
- तय समय में जवाब नहीं देने पर दोनों को किया जा सकता है प्रतिबंधित

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने चीन के बेहद प्रचलित सोशल मीडिया एप टिकटॉक और हेलो को 24 सवालों के साथ एक नोटिस जारी किया है। अगर इन्होंने अगले सप्ताह सोमवार तक इन सवालों के माकूल जवाब नहीं दिए, तो सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन एप पर भारत में देश विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग का आरोप है।

स्वदेशी जागरण मंच ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। इस पत्र में मंच ने देश-विरोधी और गैरकानूनी गतिविधियां चलाने के लिए टिकटॉक और हेलो के प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का आरोप लगाया। मंच का कहना था कि ये एप भारत में देश विरोधी गतिविधियां चलाने का अड्डा बन गए हैं। मंच की इसी शिकायत पर इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी मंत्रालय (एमईआइटीवाई) ने दोनों एप को नोटिस जारी किया है। इस बारे में टिकटॉक और हेलो ने संयुक्त बयान में कहा कि भारत उनके लिए सबसे मजबूत बाजारों में एक है। वे सभी कानूनों के पालन के लिए सरकार के साथ पूरी तरह सहयोग करेंगे। मंत्रालय ने दोनों से यह आश्वस्त करने को कहा है कि वे भारतीय उपयोगकर्ताओंसे संबंधित डाटा कहीं अन्यत्र एकत्रित नहीं करें। इसके साथ ही वे भविष्य में भी भारतीयों से संबंधित डाटा किसी विदेशी सरकार या तीसरे पक्ष या निजी इकाइयों को नहीं सौंपेंगे।

इनसे संबंधित जवाब मांगे

- फर्जी खबरों के अलावा छेड़छाड़ की गई तस्वीरों (मॉर्फ्ड पिक्चर्स) का प्रसार रोकने के लिए क्या कदम उठाए
- हेलो से पूछा कि क्या उसने अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर 11,000 मॉर्फ्ड राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया
- उपयोगकर्ता की न्यूनतम उम्र 13 वर्ष क्यों रखी है, जब भारत में 18 वर्ष से कम उम्र को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है

एडीबी ने देश का विकास अनुमान घटाया

- विकास दर के अनुमान को 7.2 फीसद से घटाकर सात फीसद किया
- सबसे तेज विकास वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा अब भी बरकरार

नई दिल्ली, प्रेट्र : एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान पूर्व घोषित 7.2 फीसद से घटाकर सात फीसद कर दिया। विकसित देशों के विकास में सुस्ती की आशंका और इसके संभावित असर को देखते हुए उसने देश का विकास अनुमान घटाया। हालांकि एडीबी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज विकास दर वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

एशियन डेवलपमेंट आउटलुक (एडीओ)-2019 के अपडेट में एडीबी ने कहा कि चीन की विकास दर 2019 में 6.3 फीसद रहेगी और 2020 में यह और घटकर 6.1 फीसद रह जाएगी। यह गिरावट खास तौर से अमेरिका के साथ उसके ट्रेड वार के कारण आएगी।

एडीबी ने कहा कि 2020-21 में भारत की विकास दर 7.2 फीसद पर पहुंच जाएगी। कारोबारी माहौल को बेहतर करने, बैंकों को मजबूत करने और कृषि समस्याओं को दूर करने के लिए हाल में किए गए सुधारों के कारण अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था में यह तेजी आएगी। गौरतलब है कि एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान सबसे पहले 7.6 फीसद रखा था, जिसे अप्रैल में उसने घटाकर 7.2 फीसद कर दिया था।

बैंक के मुताबिक कारोबारी माहौल बेहतर बनाने, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने से तेज होगा विकास। फाइल

एडीबी के अपडेट में कहा गया है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विकास में गिरावट और 2018-19 में देश के विकास की धीमी रफ्तार के प्रभाव के कारण विकास अनुमान को घटाया गया है।

अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात की तरजीही सुविधा खत्म किए जाने के संभावित असर के बारे में एडीबी ने कहा कि इसका भारत पर नगण्य असर होगा, क्योंकि इस सुविधा का लाभ सिर्फ 1.8 फीसद भारतीय निर्यात को मिल रहा था।

एडीबी ने कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन के बारे में कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश के कृषि क्षेत्र की विकास दर बेहतर रहेगी, क्योंकि मौसम के वर्तमान रुझान को देखने से लगता है कि मानसून सामान्य रहने वाला है।

कई खातों को मिलाकर भी एक करोड़ निकाला, तो कटेगा टीडीएस

नई दिल्ली, प्रेट्र : अब यदि कोई व्यक्ति कई बैंक खातों को मिलाकर भी सालभर में एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी करेगा, तो उस पर अतिरिक्त दो फीसद टैक्स कटेगा। पांच जुलाई को पेश आम बजट में बैंक अकाउंट से एक करोड़ रुपये की निकासी पर दो फीसद टीडीएस काटे जाने का प्रावधान किया गया था। एक से अधिक अकाउंट रखने वाले लोगों द्वारा इस नियम का दुरुपयोग किए जाने की संभावना को देखते हुए वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक 2019 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। इसके तहत एक या अधिक बैंक अकाउंट्स से कुल निकासी एक करोड़ रुपये से अधिक होने पर टीडीएस काटा जाएगा।

सरकार ने इंडिगो से मांगा स्पष्टीकरण

- कंपनी के एक प्रमोटर ने कॉरपोरेट गवर्नेंस में चूक का लगाया है आरोप
- कंपनी ने कहा वह निर्धारित समय सीमा के अंदर देगी जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन से सरकार ने कॉरपोरेट गवर्नेंस में चूक के आरोप पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह आरोप कंपनी के सह-संस्थापक और प्रमोटर राकेश गंगवाल ने लगाया है। कंपनी ने गुरुवार को शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि शिकायत को लेकर उसे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से बुधवार को एक पत्र मिला। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा के कंपनियों के पंजियक (आरओसी) ने गंगवाल की शिकायत को लेकर कुछ सूचना या स्पष्टीकरण की मांग की है।

कंपनी ने कहा कि वह निर्धारित समय सीमा के अंदर पत्र का जवाब देगी। सरकार ने कंपनी कानून-2013 की धारा 206(चार) के तहत स्पष्टीकरण मांगा है। गौरतलब है कि करीब 10 दिनों पहले गंगवाल ने इंटरग्लोब एविएशन में कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित चूक का मुद्दा सार्वजनिक तौर पर उठाया था। उन्होंने सह-संस्थापक राहुल भाटिया के इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज (आइजीई) समूह द्वारा संबद्ध पक्ष लेन-देन किए जाने का खास तौर से उल्लेख किया था। गंगवाल ने इसके बारे में पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से शिकायत की थी। उन्होंने इस शिकायत की प्रतियां मंत्रालय और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण तथा अन्य को भी भेजी थी।

प्रमोटरों की तनातनी से कंपनी को हो रहा खासा नुकसान। फाइल

शुक्रवार को कंपनी के बोर्ड की अहम बैठक

नई दिल्ली : प्रमोटर्स के चल रहे विवाद के बीच इंटरग्लोब एविएशन के बोर्ड की शुक्रवार को एक बैठक होने वाली है। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि इस बैठक में तिमाही नतीजे पर विचार किया जाएगा। इस दौरान कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पर कंपनी के प्रमोटर्स के बीच उभरे विवाद पर भी चर्चा हो सकती है।

शाह संभालेंगे एयर इंडिया की बिक्री की कमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : गृह मंत्री अमित शाह सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश के लिए पुनर्गठित मंत्रिसमूह की अध्यक्षता करेंगे। उनके अलावा मंत्रिसमूह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य, उद्योग एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल तथा विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल होंगे। इससे पहले एयर इंडिया के विनिवेश के लिए 2017 में पहली बार मंत्रिसमूह का गठन हुआ था तो उसमें अध्यक्ष वित्तमंत्री अरुण जेटली समेत पांच सदस्य थे। अन्य चार सदस्यों में पिछली सरकार में विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू, रेलमंत्री सुरेश प्रभु, कोयला एवं बिजली मंत्री पीयूष गोयल तथा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल थे।

अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने पिछले वर्ष निवेशकों से एयर इंडिया की 76 फीसद इक्विटी के साथ प्रबंधकीय नियंत्रण हासिल करने के लिए आवेदन मांगे थे। परंतु निवेशकों के रुचि न दिखाने के कारण वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। उसके बाद सलाहकार फर्म ईवाई ने प्रक्रिया के विफल होने के कारणों पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें सरकार के एयर इंडिया में 24 फीसदी इक्विटी बनाए रखने, कंपनी पर भारी कर्ज, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, अर्थव्यवस्था की सुस्ती तथा निविदा में व्यक्तिगत भागीदारों पर पाबंदी को मुख्य वजह बताया गया था।

आइएलएंड एफएस की रेटिंग एजेंसियों का हो रहा फॉरेंसिक ऑडिट

- समूह की कंपनियों के फॉरेंसिक ऑडिट का पहला चरण हुआ पूरा
- आइएलएंडएफएस ने ग्रांट थॉर्न्टन को सौंपा है फॉरेंसिक ऑडिट का जिम्मा

नई दिल्ली, प्रेट्र : संकटग्रस्त समूह आइएलएंडएफएस ने गुरुवार को कहा कि पिछले 10 साल में समूह की कंपनियों के लिए काम कर रही क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के फॉरेंसिक ऑडिट का पहला चरण पूरा हो गया है। फॉरेंसिक ऑडिट की जिम्मेदारी आइएलएंडएफएस के बोर्ड ने ग्रांट थॉर्न्टन को सौंपी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एक बयान में कहा गया है कि फॉरेंसिक ऑडिट में समूह की डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के लिए विभिन्न डेट उपकरणों की रेटिंग करने और पूंजी बाजार से अत्यधिक कर्ज जुटाने में रेटिंग एजेंसियों की भूमिका का मूल्यांकन किया गया।

फॉरेंसिक ऑडिट के तहत दी गई जिम्मेदारियों में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की भूमिका का मूल्यांकन करना और 2008 से 2018 तक की अवधि में रेटिंग एजेंसियों द्वारा किए गए संभावित गलत कार्यों का पता लगाना शामिल हैं।

बयान के मुताबिक निर्धारित अवधि में केयर, इकरा, इंडिया रेटिंग्स और ब्रिकवर्क समूह की कंपनियों आइटीएनएल, आइएफआइएन और आइएलएंडएफएस की प्रमुख रेटिंग एजेंसियां थीं। 2016 से आइटीएनएल और आइएफआइएन में क्रिसिल की जगह ब्रिकवर्क ने ले ली थी। अंतरिम रिपोर्ट प्रासंगिक पक्षकार, सेक्टर विशेषज्ञों और कानूनी टीम के साथ साझा की गई है।

ऑडिटर्स की भूमिका पूरे मामले में रही संदेह के घेरे में। प्रतीकात्मक

ऑडिटर के इस्तीफे पर डिस्क्लोजर नियम सख्त करेगा सेबी

नई दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को ऑडिटर के इस्तीफे के मामले में सख्त डिस्क्लोजर नियम (जानकारी जाहिर करने से संबंधित नियम) का प्रस्ताव रखा। इसके तहत ऑडिटर को इस्तीफे का विस्तार से कारण बताना होगा। हाल में ऑडिटर के इस्तीफे के कई मामले सामने आए हैं। इस बीच सेबी ने शेयर बाजारों में सूचीबद्ध बैंकों के लिए कर्ज के विरुद्ध किए गए प्रावधान का किसी अन्य मद में उपयोग होने से जुड़े डिस्क्लोजर नियमों में बदलाव कर दिया है।

केयर ने एमडी को अवकाश पर भेजा

नई दिल्ली : केयर रेटिंग्स ने एमडी और सीईओ राजेश मोकाशी को अवकाश पर भेज दिया है। सेबी को एक अज्ञात व्यक्ति की ओर से मिली शिकायत की जांच पूरी होने तक अधिकारी को अवकाश पर भेजा गया है। उनकी जगह टीएन अरुण कुमार को अंतरिम सीईओ नियुक्त करने का फैसला किया गया है।

हलचल

सेंसेक्स में 318.18 अंकों और निफ्टी में 90.60 अंकों की गिरावट, शुद्ध लाभ 90 फीसद से अधिक घटने से यस बैंक 12.85 फीसद टूटा

तिमाही नतीजों की मार से बाजार में मायूसी

मुंबई, प्रेट्र : सुस्त तिमाही नतीजों की मार से शेयर बाजारों में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। कारोबारियों ने कहा कि विदेशी बाजारों की सुस्ती से भी घरेलू बाजारों में गिरावट को बल मिला। इसके साथ ही एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा देश का विकास अनुमान घटाए जाने से भी निवेशकों का मनोबल प्रभावित हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 318.18 अंकों की गिरावट के साथ 38,897.46 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 90.60 अंकों की गिरावट के साथ 11,596.90 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में यस बैंक में सर्वाधिक 12.85 फीसद गिरावट रही। बैंक ने जून तिमाही में अपने कंसोलिडेट शुद्ध लाभ में 90 फीसद से अधिक गिरावट दर्ज की है। ओएनजीसी और टाटा मोटर्स चार फीसद से अधिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वेदांता और मारुति तीन फीसद से अधिक, टीसीएस, बजाज ऑटो, एसबीआइ और एचसीएल टेक दो फीसद से अधिक लुढ़के। इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, एनटीपीसी, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सेन एंड टुब्रो, आइसीआइसीआइ बैंक, हिंदुस्तान यूनीलिवर, भारती एयरटेल और पावर ग्रिड में एक फीसद से अधिक गिरावट रही। दूसरी ओर एचडीएफसी में सर्वाधिक 2.52 फीसद तेजी रही।

नतीजे नहीं दे रहे बाजार को मदद। प्रतीकात्मक

बीएसई के अन्य प्रमुख शेयरों में एफएमसीजी कंपनी कॉलगेट-पामोलिव इंडिया में 3.02 फीसद तेजी रही। कंपनी ने गुरुवार को जारी नतीजे में कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 10.76 फीसद गिरकर 169.11 करोड़ रुपये रहा। डाटा एनालिटिक्स कंपनी नील्सन ने कहा है कि ग्रामीण बाजारों में मांग घटने से इस साल देश के एफएमसीजी सेक्टर में सुस्ती रहेगी। विमानन कंपनी इंडिगो का परिचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन में 0.55 फीसद गिरावट रही। शुक्रवार को कंपनी के बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें प्रमोटर्स के विवाद पर चर्चा हो सकती है।

बीएसई के सभी सेक्टरों में गिरावट रही। वाहन सेक्टर में सर्वाधिक 2.65 फीसद गिरावट रही। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में 1.23 फीसद और स्मॉलकैप में 1.15 फीसद गिरावट रही।

सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि निराशाजनक तिमाही नतीजों और अमेरिका-चीन ट्रेड वार की चिंता से भारतीय बाजार में गिरावट रही। इस बीच भारतीय डेट बाजारों में विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ी है। इस महीने के शुरू में आम बजट पेश होने के बाद से विदेशी निवेशकों ने भारतीय डेट बाजार में करीब 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

एशियाई बाजारों के गिरने से भी निवेशकों का मनोबल टूटा : एशिया और यूरोप के प्रमुख बाजारों के कमजोर रुझानों से भी भारतीय बाजार में गिरावट को बल मिला। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.04 फीसद, हैंगसेंग में 0.46 फीसद, कोस्पी में 0.31 फीसद और निक्केई में 1.97 फीसद गिरावट रही। यूरोप के बाजारों में भी शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुझान रहा।

विप्रो 3.64 फीसद उछला

नई दिल्ली : विप्रो बीएसई पर 3.64 फीसद उछलकर 269.15 रुपये पर बंद हुआ। निफ्टी में यह 3.14 फीसद उछाल के साथ टॉप गेनर रहा। कंपनी ने बुधवार को जून तिमाही के अपने शुद्ध लाभ में 12.5 फीसद बढ़ोतरी की घोषणा की थी।

पंजाब एंड सिंध बैंक 3.68 फीसद गिरा

नई दिल्ली : पंजाब एंड सिंध बैंक बीएसई पर 3.68 फीसद गिरकर 24.85 रुपये पर बंद हुआ। बैंक ने भूषण पावर एंड स्टील द्वारा 238 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किए जाने की रिपोर्ट दर्ज की है।

माइंडट्री 8.07 फीसद लुढ़का

नई दिल्ली : माइंडट्री बीएसई पर 8.07 फीसद गिरकर 691.30 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी ने जून तिमाही के अपने कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ में 41.4 फीसद गिरावट की घोषणा की है।

चांदी 910 रुपये उछली सोना 170 रुपये चढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेशी बाजारों के मजबूत रुझानों के साथ औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं द्वारा खरीदारी बढ़ाए जाने से राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी 910 रुपये उछलकर 41,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोना भी 170 रुपये उछलकर 35,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

सराफा कारोबारियों के मुताबिक सोने में विदेशी बाजारों के कमजोर रुझानों के बावजूद स्थानीय ज्वेलरों की ओर से खरीद बढ़ाए जाने के कारण पीली धातु में मजबूती आई। न्यूयॉर्क में सोने में 1,422 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 16.17 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ।

राष्ट्रीय राजधानी के हाजिर बाजार में 99.9 फीसद खरा सोना 170 रुपये उछलकर 35,670 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना भी इतनी ही मजबूती के साथ 35,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी 27,400 रुपये प्रत्येक के भाव पर कायम रही।

सोने में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं। फाइल

चांदी हाजिर 910 रुपये उछलकर 41,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वीकली डिलीवरी 1,009 रुपये चढ़कर 40,406 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई। चांदी के सिक्कों की कीमत प्रति सैकड़ा 81,000 रुपये खरीद और 82,000 रुपये बिक्री के स्तर पर कायम रही।

350 करोड़ रुपये का है इजरायल से एमआरएसएएम मिसाइल की खरीद का सौदा। भारत ने इजरायल की सरकारी कंपनी इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आइएआइ) के साथ मध्यम दूरी की सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल का सौदा किया किया है।

एक टन वजनी सोने का सिक्का

चौकिंए नही, यह दुनिया का सबसे वजनी एक टन का शुद्ध सोने से निर्मित सिक्का है। इसकी कीमत 60 मिलियन ऑस्ट्रेलिया डॉलर (करीब दो अरब 90 करोड़ रुपये) है। शुद्ध सोने से तैयार यह सिक्का 80 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसकी मोटाई लगभग 13 सेंटीमीटर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में भी इसे सबसे वजनी सिक्के के रूप में दर्ज किया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया की पर्थ मिंट गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड ने इस सिक्के को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने प्रदर्शित किया। इन दिनों यह राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग अक्सर यहां पर रुक कर सिक्के के साथ सेल्फी भी लेते हैं। एजेंसी

बीस साल से जेल में बंद अमेरिकी को डीएनए ने कराया दोषमुक्त

- दुष्कर्म और हत्या के मामले में मिली थी 30 साल की सजा
- नई तकनीक से दोषमुक्त किए जाने का अमेरिका में पहला मामला

इस तकनीक से 70 से ज्यादा मामलों को सुलझाया जा चुका है। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका में बिना जुर्म 20 साल से जेल की सजा काट रहे एक व्यक्ति को डीएनए आधारित नई तकनीक से मिले साक्ष्य के आधार पर बुधवार को दोषमुक्त कर दिया गया। अमेरिका में जांच की नई तकनीक के आधार पर दोषमुक्त किए जाने का यह अपनी तरह का पहला मामला है।

अमेरिकी मीडिया के अनुसार, 43 साल के क्रिस्टोफर टैप को 1998 में एंजी डॉज नामक महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में 30 साल की सजा हुई थी। एंजी की 1996 में हत्या कर दी गई थी। इडाहो प्रांत की एक अदालत ने बुधवार को नई तकनीक जेनेटिक जीनएलॉजी से मिले साक्ष्य के आधार पर क्रिस्टोफर को दोषमुक्त कर दिया। क्रिस्टोफर ने कहा, 'मुझे नई जिंदगी मिली है। मेरे लिए नई शुरुआत हो रही है।' इससे पहले पुलिस ने एंजी मामले में गत मई में ब्रायन ड्रिप्स नामक एक अन्य संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। उसने अपना जुर्म स्वीकार लिया है।

क्या है जेनेटिक जीनएलॉजी : जेनेटिक जीनएलॉजी तकनीक के उपयोग से डीएनए का आकलन किया जाता है। यह तकनीक अप्रैल, 2018 में उस समय पहली बार सुर्खियों में आई थी जब एक सीरियल किलर का पता लगाने के लिए कैलिफोर्निया में इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उसने 1974 से 1986 के दौरान 12 हत्याएं और 50 से ज्यादा महिलाओं से दुष्कर्म किया था। तब से इस तकनीक की मदद से 70 से ज्यादा मामलों को सुलझाया जा चुका है।

इस तरह काम करती है तकनीक

वारदात स्थल पर मिले डीएनए की जांच के बाद जीनएलॉजी वेबसाइट पर मौजूद डाटाबेस से मिलान कराया जाता है। समान जीनोम वाले लोगों की एक सूची तैयार होती है और इससे उसके रिश्तेदारों की तलाश होती है। इससे जांचकर्ता असली मुजरिम तक पहुंच सकते हैं।

जबरन शादी रोकने को ब्रिटिश एयरपोर्ट पर बढ़ी चौकसी

- भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान आने-जाने वाली उड़ानों पर रखी जा रही नजर

लंदन, एएफपी : ब्रिटेन में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के साथ ही एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ऐसा एशियाई परिवारों में होने वाली जबरन शादियों को रोकने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान आने-जाने वाली उड़ानों पर खास नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन में इसी हफ्ते छुट्टियां शुरू हुई हैं। इस दौरान इस तरह के मामले बढ़ जाते हैं। ब्रिटेन में जबरन शादी गैरकानूनी घोषित है। जबरन शादी के मामलों को रोकने के लिए विभिन्न हवाई अड्डों के गेट पर स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती की गई है। इस विशेष बल में पुलिस, इमिग्रेशन एजेंट और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं।

लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर बुधवार को जब बेंगलुरु से एक विमान उतारा तो वहां तैनात स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारी एक भारतीय परिवार को पूछताछ के लिए अलग ले गए। इस परिवार को इसलिए रोका गया था क्योंकि एक युवती के हाथ पर चोट लगी थी। जबकि 13 साल की एक लड़की डरी-सहमी दिख रही थी। इससे अधिकारियों को किसी जोर-जबरदस्ती का संदेह हुआ। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनके किसी परिचित की मौत हो गई है। इसलिए वे ब्रिटेन आए हैं और युवती को एक सड़क दुर्घटना में चोट लगी है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके गृहराज्य केरल में हाल में युवती की सगाई हुई है। उसका भावी पति भी साथ आया है। अधिकारी उनकी बातों से संतुष्ट दिखे और फिर युवती को अलग ले जाकर उसके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बेंगलुरु से लंदन आई एयर इंडिया की उड़ान में सवार 250 यात्रियों में से 72 से पूछताछ की थी।

सात साल हो सकती है जेल : ब्रिटेन ने साल 2014 में जबरन शादी को गैरकानूनी घोषित किया था। इसके उल्लंघन पर अधिकतम सात साल जेल हो सकती है।

जबरन शादी के मामले 47 फीसद बढ़े : ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, साल 2018 में जबरन शादी के 1,764 मामले सामने आए थे। 2017 के मुकाबले 2018 में जबरन शादी के मामले में 47 फीसद वृद्धि दर्ज की गई थी। ब्रिटेन में ऐसे मामलों का जुड़ाव भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से पाया जाता है।

जाधव मामले में कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा पाकिस्तान : इमरान

बड़ा मामला ▸ पाक प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर आइसीजे के फैसले की सराहना की

विदेश मंत्री शाह बोले, अदालत ने खारिज कर दी हैं भारत की कई मांगें

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की फाइल फोटो। (आर्काइव से)

इस्लामाबाद, प्रेट्र : प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) के आदेश के बाद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान 'कानून के अनुसार' आगे बढ़ेगा। आइसीजे ने बुधवार को जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर विचार करने और राजनयिक पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया था।

सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण सुधीर जाधव (49) को 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। फैसले पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए इमरान खान ने ट्वीट किया, 'कमांडर कुलभूषण जाधव को बरी, रिहा और भारत को नहीं लौटाने के आइसीजे के फैसले की सराहना करता हूं। वह पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ अपराधों के दोषी हैं। पाकिस्तान कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।' विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 'जाधव पाकिस्तान में रहेगा। उसके साथ पाकिस्तान के कानूनों के मुताबिक व्यवहार किया जाएगा। यह पाकिस्तान के लिए जीत है।' उन्होंने कहा कि भारत जाधव को बरी कराना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, 'वे उसकी रिहाई चाहते थे, इसे मंजूर नहीं किया गया। वे उसकी वापसी चाहते थे, इसे भी खारिज कर दिया गया। अगर वे फिर भी जीत का दावा करते हैं तो... शुभकामनाएं।'

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 'यह भारत के लिए एक और 27 फरवरी है क्योंकि वे फिर से स्तब्ध रह गए हैं। उन्होंने सोचा कि उनके पास जिस तरह की राजनीतिक शक्ति है उससे वे न्याय को भी बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।' वह 27 फरवरी को भारतीय वायु सेना के एक लड़ाकू विमान को मार गिराए जाने और उसके पायलट को बंधक बनाने का जिक्र कर रहे थे। इससे एक दिन पहले भारत ने बालाकोट में जैश-ए-मुहम्मद के एक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया था। आइसीजे का फैसला लागू किए जाने के मुद्दे पर सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान कानून का पालन करेगा क्योंकि वह कानून का पालन करने वाला देश है। आइसीजे के फैसले ने पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था पर भी भरोसा जताया है।

शरीफ और जरदारी के बाद पूर्व पीएम अब्बासी भी गिरफ्तार

- एलएनजी प्रोजेक्ट लगाने के नाम पर अरबों रुपये की अनियमितता का आरोप

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने गुरुवार को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में पूर्व पीएम शाहिद खाकन अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बाद अब्बासी जेल जाने वाले विपक्ष के तीसरे बड़े नेता हैं। नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रहे अब्बासी पर देश में एलएनजी प्रोजेक्ट लगाने के नाम पर अरबों रुपये की अनियमितता का आरोप है।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता अब्बासी को उस वक्त हिरासत में लिया गया, जब वह प्रेस वार्ता करने लाहौर जा रहे थे। एनएबी के अधिकारियों ने उन्हें लाहौर टोल प्लाजा पर दबोच लिया। पनामा पेपर मामला उजागर होने के बाद 2017 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कुर्सी छोड़ने के बाद अब्बासी ने पीएम पद संभाला था। वह अगस्त, 2017 से मई, 2018 तक प्रधानमंत्री रहे।

अब्बासी की गिरफ्तारी पर विपक्षी दल ने इमरान सरकार पर राजनीतिक विद्वेष से यह कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा, 'हम इस गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना करते हैं।

ट्रंप पर महाभियोग का प्रस्ताव खारिज

- डेमोक्रेट सांसद ने अमेरिकी सदन में पेश किया था प्रस्ताव, ट्रंप ने हास्यास्पद करार दिया
- प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव को 95 के मुकाबले 332 मत मिले

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रायटर

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव भारी बहुमत से खारिज कर दिया गया। ट्रंप ने इस प्रस्ताव को सबसे हास्यास्पद करार देते हुए ट्वीट किया, 'महाभियोग के खिलाफ हमारे पक्ष में अभी भारी मतदान हुआ और प्रस्ताव रद हो गया।'

विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद अल ग्रीन की ओर से पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा ने 95 के मुकाबले 332 मतों से खारिज कर दिया। प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत होने के बावजूद प्रस्ताव का गिरना जाहिर करता है कि सियासी मतभेद के बावजूद डेमोक्रेट सांसद अभी ट्रंप पर महाभियोग चलाने को तैयार नहीं हैं। जबकि, एक दिन पहले ही इसी सदन ने चार गैर-श्वेत डेमोक्रेटिक महिला सांसदों के खिलाफ ट्रंप की नस्ली टिप्पणियों की निंदा की थी। यह निंदा प्रस्ताव मंगलवार को 187 के मुकाबले 240 वोटों से पारित किया गया था। ट्रंप पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को अपने डेमोक्रेट साथियों का पूरा समर्थन नहीं मिलने पर ग्रीन ने कहा, 'मेरा मानना है कि मैं नाकाम नहीं हुआ हूं। मेरे पिछले प्रस्ताव को 66 मत मिले थे, जबकि इस बार इसके समर्थन में 95 मत पड़े।' ग्रीन पहले भी दो बार इसी तरह का प्रस्ताव लाने का विफल प्रयास कर चुके हैं।

भारतवंशी सांसद ने नहीं किया समर्थन : भारतवंशी सांसद प्रमिला जयपाल ने महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। हालांकि इससे पहले लाए गए प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया था।

सऊदी अरब को हथियार बेचने पर अमेरिकी संसद ने लगाई रोक

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिकी संसद ने सऊदी अरब को हथियारों की बिक्री से जुड़े 810 करोड़ डॉलर (करीब 56 हजार करोड़ रुपये) के सौदे पर रोक लगा दी है। संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में बुधवार को इस सौदे के विरोध में लाया गया प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। सौदे पर रोक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ इस सौदे को इसी साल मंजूरी दी थी। ट्रंप ने इसके लिए आपातकाल के प्रावधान का इस्तेमाल किया था।

संसद के उच्च सदन सीनेट ने इस सौदे के लिए मंजूरी दे दी थी। निम्न सदन से पास होने के बाद इस पर सिर्फ व्हाइट हाउस की मुहर लगनी थी। संभावना जताई जा रही है कि अब ट्रंप अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा के इस फैसले पर वीटो लगा सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन सऊदी अरब के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन को हथियारों व सैन्य साजो-सामान की आपूर्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

खशोगी की हत्या की साजिश बनी वजह : वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या से जुड़े मामले को प्रतिनिधि सभा में इस हथियार सौदे को मंजूरी नहीं मिलने की मुख्य वजह माना जा रहा है। सदन के कई सदस्यों ने खशोगी की हत्या के लिए सऊदी प्रिंस सलमान को जिम्मेदार ठहराया। सऊदी अरब के समर्थन से यमन में जारी हिंसा को भी हथियार सौदे पर रोक का कारण माना जा रहा है।

हादसों में मारे गए लोगों के परिजनों को बोइंग देगी 350 करोड़ रुपये

- मुआवजा बांटने के लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति की

वाशिंगटन, रायटर: दो 737 मैक्स विमानों की दुर्घटना के संबंध में बनाए लगभग 700 करोड़ रुपये के कोष की आधी रकम (350 करोड़) हादसों में मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए खर्च की जाएगी। यह घोषणा विश्व की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने बुधवार को की। बता दें कि दोनों हादसों (इसी साल मार्च और पिछले साल अक्टूबर) को मिला दुनियाभर के विभिन्न देशों के 346 लोगों की मौत हुई थी। इन्हें मुआवजा बांटने के लिए विमान कंपनी ने मुआवजा विशेषज्ञ केन फीनबर्ग की सेवाएं ली हैं।

फीनबर्ग की नियुक्ति अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इस संबंध में होने वाली गवाही से कुछ देर पहले हुई। अपनी नियुक्ति पर फीनबर्ग ने कहा कि उनकी टीम यथाशीघ्र काम शुरू कर देगी। इस सप्ताह के अंत में शिकागो स्थित बोइंग के साथ वाशिंगटन में बैठक प्रस्तावित है। उधर, मार्च में इथियोपियन एयरलाइंस के विमान दुर्घटना में तीन बच्चों, पत्नी और सास को गंवाने पॉल जोरोज ने प्रतिनिधि सभा में अपनी गवाही दर्ज कराई। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि अब आम लोग बोइंग पर कभी विश्वास करेंगे। क्या आप ऐसे विमानों में उड़ान भरना चाहेंगे। क्या आप ऐसे विमानों में अपने बच्चों को उड़ान भरने देंगे।

यूनाइटेड एयरलाइंस को अगले साल तक मैक्स विमान मिलने की उम्मीद नहीं: यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग को बोइंग के 737 मैक्स विमानों की डिलीवरी अगले सात तक मिलने की उम्मीद नहीं है। यह बात निवेशकों की एक बैठक में चीफ फाइनेंशियल आफिसर गैरी लैडरमैन ने कही। उन्होंने विमानों के दोबारा परिचालन में आने को लेकर संदेह जताया है। बता दें कि शिकागो स्थित इस विमानन कंपनी को इस साल 16 विमान देने की बात हुई थी, लेकिन मार्च में हुई दुर्घटना के बाद इस पर रोक लगा दी गई है।

जापान के स्टूडियो में आगजनी, 33 की जलकर मौत

- आग लगाने वाले को घायल अवस्था में पुलिस ने दबोचा

जापान के पश्चिमी इलाके क्योटो में स्थित तीन मंजिले फिल्म एवं एनिमेशन स्टूडियो में लगी भीषण आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर। रायटर

टोक्यो, एएफपी : जापान के क्योटो शहर में आगजनी की घटना में 33 लोगों के जलकर मरने और 36 के झुलसने की खबर है। घायलों में दस की हालत गंभीर है। आगजनी की घटना गुरुवार को एक एनीमेशन प्रोडक्शन कंपनी के स्टूडियो में हुई। सुलगने के कुछ ही देर बाद आग ने पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया और थोड़ी देर में ही वहां मौजूद सब कुछ धूं-धूं कर जल उठा। लोगों को बचाने के लिए चंद मिनटों में अभियान छेड़ा गया लेकिन वह नाकाफी साबित हुआ।

आग पर काबू पाने के बाद अग्निशमन विभाग ने इमारत तलाश का काम शुरू किया। जो हालात हैं उनमें मृतक संख्या बढ़ने की आशंका है। इमारत के कई हिस्सों में फंसे लोग निकल नहीं पाए, वे वहीं पर जल मरे या बुरी तरह से झुलस गए। स्थानीय मीडिया के अनुसार, घटना के समय इस तीन मंजिला इमारत में 70 लोग थे। आगजनी के समय मौके पर एकत्रित लोगों ने फंसे लोगों की चीखें सुनीं और इमारत की खिड़कियों और रोशनदानों से सफेद धुंआ निकलते देखा। बताया गया है कि आगजनी की घटना कार्यालय खुलने के सामान्य समय के कुछ ही देर बाद हो गई। पुलिस को अभी तक आगजनी के उद्देश्य का पता नहीं चला है।

नजदीक रहने वालों के अनुसार, आगजनी से पहले क्योटो एनीमेशन कंपनी के स्टूडियो में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई और उसके बाद वहां से काफी मात्रा में धुंआ निकला। इसीलिए घटना के पीछे हमले की आशंका जताई जा रही है। क्योटो पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति के तरल पदार्थ फेंककर उसमें आग लगाने की जानकारी मिली है। वह व्यक्ति खुद भी जल गया है। पुलिस हिरासत में वह अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उसकी हालत में सुधार आने पर पुलिस आगजनी के उद्देश्य के बारे में उससे पूछताछ करेगी। आगजनी का शिकार हुआ स्टूडियो कई लोकप्रिय एनिमेशन टेलीविजन सीरियलों के निर्माण के लिए जाना जाता था। इनमें द मेलानचोली ऑफ हारुही सुजुमिया और के-ऑन प्रमुख हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी के जरिये भूटान से बांग्लादेश पहुंचा पत्थर भरा जहाज

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश में पहली बार ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते भूटान का पत्थर आया है। भारतीय मालवाही जहाज में लादकर एक हजार टन पत्थर बांग्लादेश लाया गया है। यह जहाज भारत होते हुए बांग्लादेश पहुंचा है। इससे समय और भाड़े, दोनों की बचत हुई है। भारत के दोनों मित्र देश लाभान्वित हुए हैं।

इस मौके पर नारायणगंज शहर में गुरुवार को समारोह आयोजित कर जल मार्ग से माल के आने का स्वागत किया गया। समारोह में बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास, बांग्लादेश में भूटान के राजदूत सोनम टी राबग्ये और वसुंधरा समूह के उपाध्यक्ष साफवान सोभन ने प्रतीकात्मक रूप से आयातित माल का पहला पैकेट लिया। एमवी एएआइ नाम का यह जहाज असम के धुबरी से होते बांग्लादेश के नारायणगंज पहुंचा है। धुबरी को अक्टूबर 2018 में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे का बंदरगाह बनाया गया है। पहली बार भारत के दो पड़ोसी देशों ने जल मार्ग का इस्तेमाल करते हुए अपने माल का देन-लेन किया है।

बोले वक्ता

अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता पर आयोजित सम्मेलन में जुटे दुनियाभर के दिग्गज, कट्टरपंथ से मुक्ति के लिए शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा को बताया जरूरी

दुनिया की जरूरत है धार्मिक आजादी

सम्मेलन के दूसरे दिन विचार रखते ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर।

जेएनएन, नई दिल्ली : अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता पर आयोजित मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दूसरे दिन दुनियाभर में मानवाधिकारों और धार्मिक आजादी की दिशा में सक्रिय कई प्रमुख हस्तियों ने विचार रखे। इस दौरान समाज से भेदभाव मिटाने और धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।

दूसरे दिन सत्र की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात फतवा काउंसिल के प्रमुख मुफ्ती शेख अब्दुल्ला बिन बय्या के संबोधन से हुई। उन्होंने कट्टरपंथ से मुक्त समाज निर्माण के लिए शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा को जरूरी कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि पैगंबर मुहम्मद ने किसी को अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं माना था। अगर आप सभी के लिए समान कानून रखेंगे, तो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के रूप में किसी को चिह्नित करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। प्रख्यात लेखक जोएल रोजनबर्ग ने इजरायल का पक्ष रखते हुए कहा कि वहां यहूदी, मुस्लिम या ईसाई में कोई भेदभाव नहीं है। इजरायल में मुस्लिमों या ईसाइयों के उत्पीड़न का आरोप निराधार है, क्योंकि संसद, सेना, पुलिस और शिक्षा जगत हर जगह उनकी उपस्थिति है। उन्होंने कहा कि इजरायल के सबसे बड़े बैंक की कमान एक अरब मुस्लिम को मिल चुकी है। रोजनबर्ग ने कट्टरता के खिलाफ अरब के मुस्लिमों के प्रयासों की भी सराहना की।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए कट्टरपंथियों की गोली का शिकार हुए सलमान तासीर के पुत्र ने कहा, 'मेरे पिता उस वक्त कट्टरपंथियों का शिकार हो गए, जब वह देश के गलत ईशनिंदा कानून का विरोध कर रहे थे।' चीन में उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्षरत और फ्री इंडो-पैसिफिक अलायंस की प्रमुख रेबिया कदीर ने भारत से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां हजारों साल से अलग-अलग धर्म व संस्कृति के लोग खुशी से रह रहे हैं। हमारी घर वापसी में भारत मददगार हो सकता है।

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता इराक की मानवाधिकार कार्यकर्ता नादिया मुराद ने यजीदियों की मदद के लिए दुनियाभर की सरकारों से आगे आने की अपील की। कार्यक्रम के समापन सत्र को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने संबोधित किया। उन्होंने धार्मिक आजादी की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा, 'हम चौथी औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर हैं। यहां शिक्षित और खुले विचार वाले आगे बढ़ेंगे। इतिहास गवाह है कि धार्मिक आधार पर उत्पीड़न से समाज हमेशा कमजोर होता है।'

स्वास्थ्य केंद्र बंद करने के फरमान के बाद बात करेगा तालिबान

काबुल, एपी : आतंकी संगठन तालिबान ने गुरुवार को कहा कि वह अफगानिस्तान में स्वास्थ्य केंद्र चलाने वाले स्वीडन के एनजीओ से बात करेगा। तालिबान ने एक दिन पहले इस संस्था को मैदान वरदाक प्रांत में अपने स्वास्थ्य केंद्र बंद करने का फरमान सुनाया था। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने अब कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों के समाधान के लिए बातचीत की जाएगी।

एनजीओ स्वीडिश कमेटी फॉर अफगानिस्तान (एससीए) पिछले कई वर्षों से देश के कई प्रांतों में स्वास्थ्य केंद्र चला रहा है। बुधवार को संस्था के निदेशक सोनी मैनसन ने बताया था कि तालिबान आतंकियों ने स्वास्थ्य केंद्र बंद करने की धमकी देते हुए कहा है कि हुक्म की अवहेलना करने पर स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवार को इसका नतीजा भुगतना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बातचीत के जरिये तालिबान अपने रुख में बदलाव लाएगा।

चीन में सरकार दे रही अंतर सामुदायिक शादी को बढ़ावा

- बहुसंख्यक हान और तिब्बतियों में हो रहे विवाह

शिगात्से, प्रेट्र : चीन में सांस्कृतिक मेलमिलाप को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब हान और तिब्बती मूल के युवक-युवतियों की शादी को बढ़ावा दे रही है। सरकार की ओर से ऐसे जोड़ों को सुविधाएं दी जा रही हैं और उन्हें उदाहरण स्वरूप पेश किया जा रहा है। हान चीन की बहुसंख्यक मूल आबादी है।

लोंग सी जोंग और बा सैंग क्यू बा आपस में प्रेम करते थे लेकिन उनके लिए शादी में सामाजिक रुकावटें थीं। वे रुढ़िवादी हान और तिब्बती समुदाय के थे। इसलिए उन्होंने अपने रिश्ते को वर्षों तक सार्वजनिक नहीं होने दिया और वे प्रेमी-प्रेमिका की भांति ही मिलते रहे। अंततः सरकार के समर्थन से उन्होंने 2015 में शादी की। 50 की उम्र के करीब का यह जोड़ा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में सामुदायिक एकता की मिसाल बना हुआ है। उसे सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है। सरकार का सकारात्मक रुख देखकर हाल के वर्षों में कई सौ युवक और युवतियां अपने रिश्ते को स्थायी बनाने के लिए आगे आए। सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय प्रेरणास्रोत करार दिया है। लोंग और बा तथा कुछ अन्य जोड़ों के फोटो शिगात्से और कुछ अन्य शहरों के सामुदायिक केंद्रों में लगाए गए हैं। इनके जरिये आमजनों को संदेश देने की कोशिश की गई है कि उनके प्रेम संबंधों को अंजाम तक पहुंचाने में सरकार उनके साथ है।

तिब्बत की स्थानीय सरकार के अधिकारी सी डान योंग्जी ने भारतीय पत्रकारों के दल को बताया कि चीन की केंद्रीय सरकार ने अंतर सामुदायिक शादियों को लेकर नीति को बदला है। अब वह इस तरह की शादियों को बढ़ावा देने के रुख पर चल रही है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि लोंग और बा ने समाज के सामने उदाहरण पेश किया है। इससे अन्य युवक-युवती अंतर सामुदायिक विवाह के बारे में सोचने को उत्साहित हुए हैं। हाल के महीनों में जिन 500 जोड़ों ने अपने विवाह पंजीकृत कराए हैं उनमें से 40 अंतर सामुदायिक हैं।

अगर आप सीरीज दर सीरीज सोचेंगे तो इससे आपको अपने फॉर्म को कायम रखने में मदद मिलेगा। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि मैं 2023 का विश्व कप खेलूं। – **मुश्फिकुर रहीम, बांग्लादेशी विकेटकीपर**

हमारे लिए अंतिम राउंड अहम :मनप्रीत

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक क्वालीफायर के अंतिम राउंड को देखते हुए अगले तीन महीने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारी तैयारियां बेहद अच्छी चल रही हैं। उम्मीद हैं कि आने वाले तीन महीने भारतीय हॉकी टीम के लिए बहुत अच्छे जाएंगे। सभी खिलाड़ी पूरी लगन के साथ खेलकर ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना चाहते हैं।

धौनी, विराट और चयन के उलझन में फंसा बोर्ड

वेस्टइंडीज दौरे के लिए चयन समिति की बैठक स्थगित रविवार को हो सकती है बैठक नोटिस निकलने के बाद धौनी से बात कर सकते हैं चयनकर्ता

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

महेंद्र सिंह धौनी के चयन को लेकर असमंजस, कप्तान विराट कोहली की वेस्टइंडीज दौरे पर सीमित ओवर प्रारूप के लिए उपलब्धता और चयन बैठक में बोर्ड सचिव की मौजूदगी पर रोक से बीसीसीआइ पूरी तरह से उलझ गया है। ऐसे में चयन समिति की शुक्रवार को होने वाली बैठक स्थगित हो गई।

वेस्टइंडीज दौरे के लिए चयन समिति की बैठक शुक्रवार को प्रस्तावित थी लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया है। अब यह बैठक रविवार को हो सकती है लेकिन इस बारे में बीसीसीआइ द्वारा फिलहाल कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। भारत को तीन अगस्त से शुरू हो रहे वेस्टइंडीज दौरे पर तीन टी-20, तीन वनडे और दो टेस्ट खेलने हैं। यह बैठक स्थगित उस वक्त हुई, जब गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति (सीओए) ने नए संविधान के तहत फैसला किया कि चयन समिति की बैठक में बीसीसीआइ के सचिव हिस्सा नहीं ले सकते हैं।

विश्व कप खत्म होने के एक सप्ताह के अंदर ही टीम का चयन होना था और टी-20 व वनडे सीरीज में विराट कोहली को आराम मिलना था। ऐसी स्थिति के रोहित शर्मा को इन दोनों सीरीज की कप्तानी मिलती लेकिन गुरुवार को ही कोहली ने वेस्टइंडीज दौरे पर सीमित ओवर प्रारूप की सीरीज के चयन के लिए खुद को उपलब्ध बताया। माना जा रहा है कि टीम में मतभेदों की खबर बाहर आने के बाद उन्होंने यह फैसला किया।

महेंद्र सिंह धौनी • फाइल फोटो, एएफपी

वहीं, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी सीरीज में उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है।

धौनी पर फैसला: बीसीसीआइ के एक चयनकर्ता ने कहा कि अभी हमारी धौनी से कोई बात नहीं है। जब चयन समिति की बैठक का नोटिस निकलेगा तो मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद उनसे बात कर सकते हैं। फिलहाल सभी चयनकर्ता अपने-अपने शहरों में हैं और जब उनको बैठक के बारे में पता चलेगा तभी आगे की कोई वार्ता की जाएगी। वहीं, बीसीसीआइ के भी एक पदाधिकारी ने कहा कि चयनकर्ताओं को धौनी से बात करनी चाहिए। अगर धौनी घर पर विदाई सीरीज खेलने का प्रस्ताव रखते हैं तो फिर चयनकर्ता ये बात बोर्ड को बता सकते हैं, फिर अध्यक्ष या सचिव को ही इस पर फैसला लेना होगा। इतना तो तय है कि धौनी वेस्टइंडीज में वनडे और टी-20 सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

कोहली अब उपलब्ध : एक और मसला कोहली की उपलब्धता का हो गया है। विराट को पहले वेस्टइंडीज के दौरे पर नहीं जाना था। वेस्टइंडीज के दौरे पर पहले टेस्ट सीरीज और बाद में वनडे, टी-20 सीरीज खेली जानी थी, लेकिन बीसीसीआइ के आग्रह पर टी-20 और वनडे सीरीज पहले आयोजित की जा रही है। इसके पीछे मकसद यही था कि विश्व कप के बाद कोहली आराम कर सकते थे और फिर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए उतर सकते थे। पहले विराट का यही प्लान था। हाल ही में टीम में विवाद की खबरें सामने आने पर विराट ने खुद को चयन के लिए उपलब्ध बताया है। विराट के खेलने पर यह तो तय हो जाएगा कि रोहित शर्मा इन सीरीज में कप्तानी नहीं कर पाएंगे।

चौथे नंबर के लिए माथापच्ची : चयन समिति के लिए चौथे नंबर का स्थान भरना भी किसी माथापच्ची से कम नहीं है। भविष्य की तैयारियों के मद्देनजर अब चयनकर्ता इस स्थान पर एक स्थायी खिलाड़ी का चयन चाहते हैं। चयनकर्ताओं के पास कर्नाटक के मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे और मुंबई के श्रेयस अय्यर के रूप में विकल्प हैं जो घरेलू सर्किट पर लगातार अच्छा खेल रहे हैं। पांडे ने वेस्टइंडीज ए के खिलाफ भारत ए के लिए शतक बनाया था। रायडू के संन्यास लेने के बाद और विजय शंकर के नाकाम रहने से उनके लिए दरवाजे खुल सकते हैं। चयनकर्ता युवा शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ के नाम पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि शॉ कूल्हे की चोट से जूझ रहे हैं। दिनेश कार्तिक और केदार जाधव के नाम पर विचार की संभावना नहीं है जो विश्व कप में नाकाम रहे।

सीएसी में शामिल हो सकते हैं नए सदस्य

नई दिल्ली: टीम इंडिया के मौजूदा मुख्य कोच रवि शास्त्री और उनके सहयोगी स्टाफ का कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है। वेस्टइंडीज दौरे के बाद शास्त्री एंड कंपनी टीम इंडिया के साथ नहीं रहेगी। ऐसे में बीसीसीआइ ने मुख्य कोच समेत कई पदों के लिए आवेदन निकाले हैं। इसका फैसला क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी (सीएसी) को करना है, जो अब नई बनेगी। बीसीसीआइ के क्रिकेट ऑपरेशंस के जनरल मैनेजर सबा करीब ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई क्रिकेट प्रशासक समिति (सीओए) से सीएसी के लिए नए नाम देने के बारे में पूछा है। बीसीसीआइ के अधिकारी ने कहा कि इस सीएसी में इस बार भी तीन सदस्य होंगे जिन पर किसी भी तरह का हितों के टकराव का मामला ना हो। सीएसी का चुनाव बीसीसीआइ की सालाना आम सभा में होगा। सीओए के सदस्यों की बैठक 26 जुलाई को होनी है। इससे पहले सबा करीम ने सीएसी के सदस्यों के नाम मांगे हैं। बता दें कि सीएसी में इससे पहले सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण थे, लेकिन हितों के टकराव के मामले को लेकर सचिन और लक्ष्मण ने इससे इस्तीफा दे दिया था, जबकि सौरव गांगुली को लेकर अभी तक मामला साफ नहीं हो पाया।

अब चयन बैठक का हिस्सा नहीं होगा सचिव : सीओए

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढा समिति के सुधारों को लागू करने की दिशा में सीओए ने गुरुवार को निर्देश दिया कि अब बीसीसीआइ सचिव नहीं बल्कि चयन समिति का अध्यक्ष चयन संबंधी बैठकों का समंवयक होगा। विदेशी दौरों के लिए बैठक प्रशासनिक प्रबंधक बुलाएंगे। निर्देश में साफ तौर पर कहा गया कि अब से सचिव किसी चयन बैठक में भाग नहीं लेगा और ना ही उसकी सहमति की जरूरत टीम में विकल्प को मंजूरी देने के लिए रहेगी। पुराने संविधान के तहत चयन समिति सचिव के कार्यक्षेत्र में आती थी लेकिन इस फैसले के बाद सचिव के अधिकार सीमित रह जाएंगे। सीओए प्रमुख विनोद राय ने कहा कि प्रशासकों की समिति को बताया गया है कि बीसीसीआइ का नया संविधान लागू होने के बावजूद चयन समिति की बैठकें माननीय सचिव ही बुला रहे थे। इसमें कहा गया कि यह भी पता चला कि टीम में किसी बदलाव के लिए चयन समिति माननीय सचिव की मंजूरी लेती रही है। बीसीसीआइ का कामकाज सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बीसीसीआइ के नए संविधान के अनुसार चलाने के लिए ये निर्देश जारी करना जरूरी था।

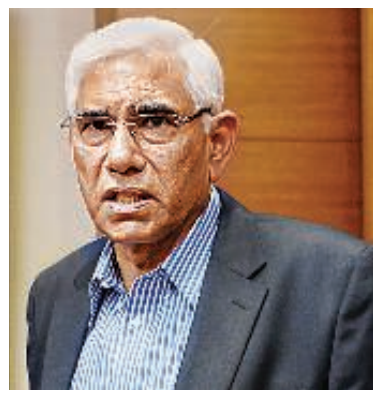

सीओए प्रमुख विनोद राय • फाइल फोटो, रायटर

यह हुए बदलाव

1. विदेशी दौरों के अलावा चयन समिति का अध्यक्ष ही चयन समिति की बैठक बुलाएगा जिसमें पुरुष चयन समिति, जूनियर चयन समिति और महिला चयन समिति शामिल हैं। विदेशी दौरों के लिए प्रशासनिक प्रबंधन बैठक बुलाएगा। कोई भी बोर्ड का पदाधिकारी या सीईओ किसी क्रिकेट समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा।
2. संबंधित चयन समितियों या प्रशासनिक प्रबंधन को बैठक का विस्तार से ब्यौरा तैयार करना होगा। भारतीय टीम के चयन या बदलाव की घोषणा के बाद अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर के साथ सचिव को यह ब्यौरा देना होगा।
3. चयन समिति को किसी चयन या बदलाव या विकल्प के लिए बीसीसीआइ के सचिव या सीईओ से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।
4. सीईओ चयनकर्ताओं के मैच देखने के लिए यात्रा और अन्य चीजों का इंतजाम करेगा। इस संबंध में ईमेल सचिव की जगह सीईओ को भेजे जाएं।

चोट के बाद पहली बार धवन ने पकड़ा बल्ला

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने विश्व कप के दौरान अंगूठे में लगी चोट के बाद पहली बार बल्ला पकड़ा, लेकिन वह अब भी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं। धवन को पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 'बॉटलकैपचैलेंज' के लिए नामित किया जिसके बाद इस बल्लेबाज ने बल्ला पकड़ा।

धवन के अलावा युवराज ने ब्रायन लारा, क्रिस गेल और सचिन तेंदुलकर को भी यह चुनौती दी। धवन ने ट्वीट करते हुए कहा, 'युवी पाजी, यह मेरा 'बॉटलकैपचैलेंज' है। चोट के बाद मैं पहली बार बल्ला पकड़ रहा हूं। वापसी करना अच्छा लग रहा है।' 'बॉटलकैपचैलेंज' इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें चुनौती दिए जाने वाले को बोतल का ढक्कन हाथ लगाए बिना खोलना होता है। कई जानी मानी हस्तियों ने इसमें हिस्सा लिया है जिसमें क्रिकेटर भी शामिल हैं।

विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में शिखर धवन के बायें हाथ के अंगूठे में चोट लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने शानदार 117 रनों की पारी खेली थी और टीम को जीत दिलाई थी। धवन ने इस दौरान ट्रीटमेंट लेने के बाद हाथ में दर्द और सूजन के साथ ही बल्लेबाजी की थी। हालांकि, जब अंगूठे में सूजन के बाद स्कैन कराया गया तो उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर पाया गया। इसके बाद धवन को तीन मैचों के लिए टीम से बाहर किया गया, लेकिन गुरुवार को टीम इंडिया की मेडिकल टीम ने उनकी चोट में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं पाया तो उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। पिछले दिनों धवन ने एनसीए में ही इंग्लैंड दौरे पर त्रिकोणीय सीरीज खेलने गई भारतीय अंडर-19 टीम के सदस्यों को भी टिप्स दिए थे। उस समय धवन के हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ था। उन्होंने तस्वीर को ट्विटर पर भी साझा किया था।

एक नजर में

पीटी ऊषा आइएएएफ के वेटरन पिन के लिए नामित

नई दिल्ली: भारत की महान ट्रैक और फील्ड एथलीट पीटी ऊषा को खेल में उनके असाधारण योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ (आइएएएफ) के 'वेटरन पिन' के लिए मनोनीत किया गया। भारत की सर्वश्रेष्ठ फर्राटा धाविका रही ऊषा को 'उड़नपरी' भी कहा जाता है। उन्होंने 1985 जकार्ता एशियन गेम्स में 100 मी, 200 मी, 400 मी, 400 मी बाधा दौड़ और चार गुणा 400 मी में स्वर्ण पदक जीते थे। ऊषा ने ट्वीट किया, 'आइएएएफ वेटरन पिन। विश्व एथलेटिक्स में लंबे समय से योगदान के लिए। इस अतुलनीय सम्मान के लिए धन्यवाद आइएएएफ।' (प्रेट्र)

एचसीए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे अजहरुद्दीन

हैदराबाद : पूर्व भारतीय कप्तान मुहम्मद अजहरुद्दीन ने गुरुवार को कहा कि जब भी चुनाव हुए तब वह हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हां, मैं एचसीए अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा। एचसीए की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 21 जुलाई को होगी जिसमें इसके चुनावों के बारे में चर्चा किए जाने की संभावना है। (प्रेट्र)

भारतीय महिला टीम के स्पिन सलाहकार होंगे हिरवानी

नई दिल्ली: भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के स्पिन कोच नरेंद्र हिरवानी देश की महिला टीम के साथ सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। भारत के लिए 17 टेस्ट और 18 वनडे खेल चुके हिरवानी चुनिंदा दौरों पर टीम के साथ जाएंगे। भारत की टी-20 कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हाल ही में टीम के लिए स्पिन कोच की जरूरत पर जोर दिया था। भारतीय टीम में पूनम यादव, एकता बिष्ट और दीप्ति शर्मा जैसे स्पिनर हैं। (प्रेट्र)

विश्व कप की हार को भुला पाना मुश्किल : बोल्ट

ऑकलैंड, एएफपी : बराबरी की टक्कर के बावजूद 'चौकों-छक्कों की गिनती' के आधार पर विश्व कप से वंचित रह जाने का गम न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए भुला पाना आसान नहीं है और सब अपने-अपने तरीकों से इससे उबरने की कोशिश में हैं। तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट अपने कुत्ते के साथ सागर किनारे टहलकर दिल हल्का करेंगे। बोल्ट इन सवालों के बीच स्वदेश लौटे हैं कि लगातार दूसरा विश्व कप फाइनल हारने की पीड़ा से वह कैसे उबरेंगे।

बोल्ट ने कहा, 'मैं चार महीने में पहली बार घर जाऊंगा। शायद अपने कुत्ते को लेकर समुद्र किनारे सैर को जाऊं और इसे भुलाने की कोशिश करूं। मुझे यकीन है कि वह मुझसे नाराज नहीं होगा। इस हार को इतनी जल्दी नहीं भूल सकेंगे। आने वाले काफी साल तक यह नासूर बनकर टीस देती रहेगी।' इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप फाइनल में निर्धारित ओवरों और सुपर ओवर में भी स्कोर बराबर रहने के बाद चौकों-छक्कों की गिनती के आधार पर न्यूजीलैंड हार गया। बोल्ट ने कहा कि वह 49वां ओवर नहीं भूल पा रहे हैं जिसमें उन्होंने जेम्स नीशाम की गेंद पर बेन स्टोक्स का कैच लिया लेकिन पैर सीमा रेखा से टकरा गया। उन्होंने कहा, 'मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं। हम अजीब हालात में वह मैच हारे।' यह पूछने पर कि क्या उन्हें लगता है कि टीम के साथ छल हुआ तो उन्होंने ना में जवाब दिया।

क्रिकेट डायरी

ट्रेंट बोल्ट • फाइल फोटो, एपी

सुपर ओपर के दौरान नीशाम के कोच की मृत्यु हुई : न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जेम्स नीशाम जब इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप फाइनल के सुपर ओवर में छक्का लगाकर टीम को जिताने की कोशिश कर रहे थे, तब उनके शुरुआती कोच डेविड गोर्डन आखिरी सांसें ले रहे थे।' नीशाम ने ट्वीट किया, 'डेव गार्डन, मेरे हाई स्कूल कोच और दोस्त। उम्मीद है कि उस मैच में हमारे प्रदर्शन पर आपको गर्व हुआ होगा। धन्यवाद। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे।'

सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच बने बेलिस

नई दिल्ली, प्रेट्र: इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कोच ट्रेवर बेलिस अब ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी की जगह आइपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच होंगे। बेलिस अगले महीने होने वाली एशेज सीरीज के बाद इंग्लैंड टीम से नाता तोड़ लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर मूडी पिछले सात साल से सनराइजर्स के साथ थे और 2016 में खिताब भी जीता था।

टीम ने कहा कि काफी सोच समझकर हमने फैसला किया है कि मूडी अब टीम के साथ नहीं होंगे। ट्रेवर के रूप में टीम के पास नया कोच होगा। ट्रेवर कोलकाता के साथ दो आइपीएल खिताब जीत चुके हैं। उन्होंने बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स को खिताब दिलाया। उम्मीद है कि उनका अनुभव सनराइजर्स के काम आएगा। उनके कार्यकाल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। टीम ने कि हम मूडी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने टीम को सात साल में पांच बार प्लेऑफ में पहुंचाया और 2016 में खिताब भी दिलाया। इस बार सनराइजर्स एलिमिनेटर में दिल्ली कैपिटल्स से हारने के बाद चौथे स्थान पर रही थी।

इंग्लैंड की तरह तैयारी करे श्रीलंका

कुमार संगकारा

बिहाइंड द स्टंप

2019 विश्व कप ने टूर्नामेंट से पहले कोई बड़ा प्रचार नहीं किया था। छक्कों की बरसात की उम्मीदें भी बेकार गई और खराब मौसम की वजह से भी टूर्नामेंट का स्तर घटा, लेकिन पिछले सभी विश्व कप में इस विश्व कप के फाइनल जैसा रोमांच नहीं दिखा। यह एक अलग तरह का फाइनल था, जो भी लॉर्ड्स में उपस्थित थे वह अहसनीय, नाखून कतरने जैसे तनाव में रहे। पवेलियन में एमसीसी की बैंच उन लोगों से भरी रही जिन्होंने 1975, 1979, 1983 और 1999 के विश्व कप मुकाबले देखे। जो भी इस मैच के साक्षी बने वह कभी भी ऐसा मैच दोबारा नहीं देख पाएंगे।

इंग्लैंड की टीम इस विश्व कप में जीत की हकदार थी। वह ऐसे हालात में खेल रहे थे जहां गेंदबाज को अपने कौशल और प्रोत्साहन से सफलता पानी होती है। न्यूजीलैंड की टीम लगातार दूसरी बार उप विजेता बनी। उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से फाइनल खेला और इतने कम अंतर से हारने के बाद सभी खिलाड़ी बिखर गए होंगे। मैं जानता हूं कि लगातार दो बार फाइनल हारने पर कैसा लगता है। हमारे साथ 2007 और 2011 में विश्व कप, साथ ही 2009 और 2012 टी-20 विश्व कप में ऐसा हुआ था। एक खिलाड़ी के तौर पर यह बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी खुद को दोषी नहीं मानते होंगे। 2015 को अगर छोड़ दिया जाए तो इस बार उन्होंने वो सब किया जो वह कर सकते थे। इंग्लैंड की टीम इस जीत की हकदार थी। वह शुरू से ही इस टूर्नामेंट को जीतने के दावेदार थे और उन्होंने टूर्नामेंट के मध्य में बाहर होने की स्थिति में खुद को दबाव के अंदर बखूबी संभाला। इंग्लैंड साफ नजरिए वाली एक बहुत ही शानदार टीम है जो जानती है कि उन्हें कैसे खेलना है। 2015 विश्व कप में बिखरने वाली इंग्लैंड की टीम की पिछले चार वर्षों का सफर किसी भी क्रिकेट खेलने वाले महत्वकांक्षी देश के लिए उदाहरण की तरह है जो भविष्य के लिए तैयारी करना चाहता है। ब्रांड क्रिकेट खेलना उनके लिए 2019 विश्व कप में बहुत जरूरी था और उन्होंने इसके लिए अपने नेतृत्वकर्ता और खिलाड़ी को बखूबी परखा। श्रीलंका को भी 2023 में भारत में होने वाले विश्व कप के लिए ऐसे ही सफर की जरूरत है। इस विश्व कप से ज्यादा परिस्थितियां तब हमारे ज्यादा अनुकूल होंगी और हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है।

THE ULTIMATE INVERTER BATTERY
EXIDE INVATUBULAR

सिंधू संघर्षपूर्ण जीत से क्वार्टर फाइनल में

जकार्ता, प्रेट्र : भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने डेनमार्क की मिया बिलिचफेल्ट के खिलाफ तीन गेम तक चले संघर्षपूर्ण मैच में जीत दर्ज करके गुरुवार को यहां इंडोनेशिया ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पांचवीं वरीयता प्राप्त सिंधू ने दूसरे दौर में एक घंटे दो मिनट तक चले मैच में बिलिचफेल्ट को 21-14, 17-21, 21-11 से हराया। सिंधू की बिलिचफेल्ट के खिलाफ यह इस साल तीसरी जीत है। इससे उन्होंने डेनमार्क की इस खिलाड़ी को इंडियन ओपन और सिंगापुर ओपन में हराया था। सिंधू का अगला मुकाबला मलेशिया की सोनिया चेह और जापान की नाओमी ओकुहारा के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। हालांकि मैच में सिंधू की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी।

टोक्यो ओलंपिक में तैरते होटलों में रहेंगे खिलाड़ी

योकोहामा, एएफपी : अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों के दौरान टोक्यो में होटलों की कमी पड़ सकती है जिसके कारण क्रूस जहाजों को पानी पर 'तैरते होटलों' में बदला जा सकता है।

ओलंपिक को देखते हुए जबर्दस्त निर्माण कार्य के बावजूद टोक्यो में 14000 कमरे कम पड़ सकते हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि बड़े-बड़े जहाजों को अस्थायी रूप से होटलों में बदला जा सकता है। जापान की सबसे बड़ी ट्रेवल एजेंसी जेटीबी ने ओलंपिक के दौरान 1011 केबिन का 'सन प्रिंसेस' जहाज बुक रखा है जिसमें जकुजी से लेकर थिएटर तक सब कुछ है। एजेंसी ओलंपिक स्पर्धाओं के टिकटों के साथ पैकेज का प्रस्ताव दे रही है, लेकिन ये सस्ते नहीं हैं।

बालकनी के साथ एक कमरे का दो रात का किराया 1850 डॉलर (127417 रुपये) है जिसके साथ ओलंपिक फुटबॉल मैच के टिकट मिल रहे हैं। वहीं, 50 स्कवेयर मीटर के सुएट का दो रात का किराया 6700 डॉलर (461456 रुपये) है जिसके साथ बेसबॉल के टिकट मिलेंगे। एजेंसी के टोक्यो 2020 प्रोजेक्ट प्रमुख मिनोरू कुज ने कहा, 'हमें पता है कि अच्छे होटलों की कमी रहेगी और हमारे पैकेज की मांग भी बढ़ेगी। हमें लोगों से अच्छा जवाब मिल रहा है।'

ओलंपिक खेलने जा सकते हैं विजेंदर

नई दिल्ली, जेएनएन : भारतीय स्टार प्रो मुक्केबाज विजेंदर सिंह का पेशेवर सर्किट में सफर अब तक शानदार रहा है और लगातार 11वीं पेशेवर जीत से वह थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। पेशेवर सर्किट में इतनी सफलता के बाद ओलंपिक खेलने के बारे में अब भी उन्होंने मन नहीं बदला है और उनका कहना है कि दोबारा देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो मैं जरूर जाऊंगा। विजेंदर ने नेवार्क में माइक स्नाइडर को तकनीकी नॉकआउट किया था। विजेंदर ने कहा, 'अभी मेरे प्रायोजक टॉप रैंक के साथ दो मैच बचे हैं और अभी मेरा ध्यान इन्हीं पर लगा है। ओलंपिक के दौरान परिस्थितियां कैसी होती हैं, मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता, अगर दोबारा मौका मिलता है तो जरूर जाऊंगा।'

अर्जुन की खिताबी हैट्रिक

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : भारतीय गोल्फर अर्जुन भाटी ने अमेरिका में आयोजित जूनियर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप का लगातार तीसरी बार खिताब जीतकर हैट्रिक लगाई। जूनियर गोल्फ के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार विश्व गोल्फ चैंपियनशिप अपने नाम की। इससे पहले अर्जुन ने वर्ष 2016, 2018 में यह खिताब जीता था।

अर्जुन ने ताइवान के जेरेमी चेन को मात देते हुए खिताब अपने नाम किया। 14 साल के अर्जुन ने कुल 199 का स्कोर किया। चेन ने 202 और न्यूजीलैंड के जोशुआ बेई ने 207 का स्कोर किया। भारतीय गोल्फर ने 13-14 आयु वर्ग के तीसरे राउंड में पार अंडर 17 का स्कोर किया। उन्होंने 13-18 आयु वर्ग में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो कि उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। अर्जुन ने कहा, 'मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और मैं इसी तरह के प्रदर्शन के साथ अपने देश के लिए चैंपियनशिप जीतना चाहता था। मैं दुनिया का नंबर एक गोल्फर बनना चाहता हूं।'

विजेता ट्रॉफी के साथ अर्जुन भाटी • परिजन

सरबजोत ने विश्व कप में जीता स्वर्ण

सुहल (जर्मनी), प्रेट्र : सरबजोत सिंह ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में गुरुवार को यहां 239.6 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीतकर आइएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत का दबदबा बरकरार रखा। सरबजोत के स्वर्ण जीतने का मतलब है कि भारत ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों में 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब जीता। इससे पहले 14 वर्षीय ईशा सिंह ने बुधवार को महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। अब जबकि इस टूर्नामेंट में एक दिन का खेल बचा है तब भारत नौ स्वर्ण, नौ रजत और चार कांस्य सहित कुल 22 पदक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है। सरबजोत फाइनल में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय थे। उन्होंने क्वालीफिकेशन दौर में 575 का स्कोर बनाकर पांचवें स्थान पर रहे थे।

मैं भारतीय कप्तान विराट कोहली का बड़ा प्रशंसक हूं : हैरी केन

साक्षात्कार

हैरी केन लंदन के एक ऐसे युवा हैं, जो न सिर्फ अपने क्लब बल्कि अपने देश के लिए भी रोल मॉडल बन गए हैं। टॉटनहम फुटबॉल क्लब और इंग्लैंड के इस स्ट्राइकर ने हाल ही में अपनी बचपन की दोस्त से शादी की। पहली बार टॉटनहम को चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचाने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। हॉलैंड के साथ नेशंस लीग में भी इंग्लैंड की भिड़ंत में उनकी अहम भूमिका रही थी। अब वह उतार-चढ़ाव भरी फुटबॉल की यात्रा से उबरते दिख रहे हैं और एक कदम आगे बढ़ते हुए खिताब जीतना चाहते हैं। वो भी अपने क्लब और राष्ट्रीय टीम की ओर से।

• पिछले सत्र के अंत में फाइनल में मिली हार से क्या उबर गए हैं?

- आपको पेशेवर होना ही होता है। निश्चित तौर पर वह काफी निराशाजनक था। कोई भी मैच हारना अच्छा नहीं होता। लिवरपूल और हॉलैंड के खिलाफ हमारे पास अच्छा मौका था, लेकिन फुटबॉल में छोटी-छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। मुझे लगता है कि इन अनुभवों से सीखकर एक अच्छा खिलाड़ी बना जा सकता है क्योंकि नियम दोनों ही टीमों के लिए बराबर थे। हम पिछली बात को लेकर नहीं बैठ सकते और हमने इससे काफी कुछ सीखा है।

• इसका मतलब यह है कि टॉटनहम और इंग्लैंड के लिए टीम अपने स्टाइल में बदलाव करेगी?

- नहीं, बिल्कुल नहीं। हार के बावजूद अपने तरीके से ही खेलते रहना काफी अहम है। एक टीम के तौर पर हमें मैनेजर द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर पूरा भरोसा है। टॉटनहम के लिए सभी खिताबों के लिए अपनी चुनौती पेश करना और इंग्लैंड के लिए यूरो 2020 जीतने की कोशिश करना काफी अहम है। हमारे खिलाड़ी अपने खेल में सुधार कर रहे हैं और उनमें जीत के लिए भूख है। मुझे लगता है कि इन चीजों से ही आप बेहतर बन सकते हैं।

• भावनात्मक और शारीरिक प्रभाव के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप नए प्रीमियर लीग सत्र के लिए तैयार हैं?

- मैं तैयार हो जाऊंगा। जब भी आप फाइनल्स या सेमीफाइनल्स हारते हैं तो दिल दुखता है और कुछ समय तक यह आपके जेहन से नहीं निकल पाता। इस सत्र में ऐसा हमारे साथ हुआ, लेकिन नए सत्र के लिए वापसी करने के लिए हम तैयार हैं। लक्ष्य एक ही है, साल दर अपने खेल में सुधार लाना। हम ऐसा कर चुके हैं और ऐसी स्थिति में हैं, जहां बड़े टूर्नामेंटों में कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हमारे मैनेजर की मौजूदगी से हमारा प्रदर्शन बेहतर ही हो रहा है। हालांकि यह समय जल्दी आ गया, लेकिन हम फिर से तैयार हैं। हाल के वर्षों में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि लगभग पूरी टीम ही काफी ज्यादा खेली है। शीर्ष स्तर पर फुटबॉल खेलने पर यह जीवन का हिस्सा है। अब हमारे पास खुद को रिचार्ज करने का समय है और हम पिछले सत्र के प्रदर्शन का इस्तेमाल इस सत्र की तैयारियों के लिए करेंगे।

• टॉटनहम से अलग क्या इंग्लैंड अगले साल यूरो कप में चुनौती पेश कर सकता है?

- यही हमारा लक्ष्य है। इस समय इंग्लैंड की टीम का हिस्सा बनना बेहद शानदार है क्योंकि हमारे पास ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जिनके प्रदर्शन में सुधार हो रहा है। ये खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होना चाहते हैं। हालांकि अभी भी हमें काफी कुछ सीखने की जरूरत है। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं, जो खेल का रुख बदल सकते हैं। पिछले साल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद हमें खुद से काफी अपेक्षाएं हैं। अब हमारे प्रशंसकों को ज्यादा बेहतर की उम्मीद है। मगर हम एक पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर यही चाहते हैं।

• आप अभी 30 साल के भी नहीं हुए हैं, इसके बावजूद आप टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं। कैसा महसूस करते हैं आप?

- मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि अब टीम में सीनियर खिलाड़ियों में से एक हूं। मुझे लगता है कि युवा खिलाड़ी मुझे एक बेहतर खिलाड़ी बनने में मदद कर सकते हैं। हमें खिताब जीतने के लिए भी उनकी मदद की जरूरत है।

• क्रिकेट विश्व कप के दौरान लॉर्ड्स में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही?

- शानदार। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है और इंग्लैंड के खिलाफ भारत के मैच को छोड़ दिया जाए, तो मुझे विराट कोहली की बल्लेबाजी देखना पसंद है। मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूं। मुझे उनके खिलाफ थोड़ी बल्लेबाजी करने का मौका भी मिला और यहां तक कि मैंने उनके लिए गेंदबाजी भी की। बहुत मजा आया। यह देखना हमेशा रोचक होता है कि क्रिकेटर मैच से पहले हमेशा वार्म अप के लिए फुटबॉल खेलते हैं क्योंकि आप हमें किसी मैच से पहले कभी क्रिकेट खेलते नहीं देखेंगे।

14000 करोड़ रुपये निवेश की योजना बनाई है रेलवे ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में। रेलवे इसके जरिये दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा जैसे व्यस्त मार्ग पर राजधानी ट्रेनों के यात्रा समय में तीन घंटे की कमी लाना चाहती है।

कश्मीर में महकने लगे आजीविका के फूल

सार्थक कदम ▶ राष्ट्रीय हिमालयी मिशन की परियोजना ने चेहरों पर खिला दी है मुस्कान

जागरण विशेष

दो साल में मिलने लगे उम्मीद के अनुरूप परिणाम, कश्मीर में फूलों की खेती बनने लगी आजीविका का आधार

बृजेश तिवारी, अल्मोड़ा

आजीविका सुधार और सशक्तीकरण कार्यक्रम के तहत कश्मीर घाटी में पिछले दो सालों से जारी गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान, कोसी, अल्मोड़ा की लघु परियोजना अब कश्मीर घाटी के लिए वरदान साबित हो रही है। कश्मीर घाटी को फूलों के उत्पादन और कारोबार के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। लंबे समय से देखा जा रहा था कि वहां आजीविका के क्षेत्र में उतना विकास नहीं हो पा रहा है, जितना होना चाहिए था। ऐसे में राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन संस्थान द्वारा विकसित फूलों की व्यावसायिक खेती की परियोजना को आधार बनाया गया, जो सफल साबित हुई।

परियोजना के तहत कश्मीर में इस तरह की जा रही है फूलों की खेती। जागरण

लिलियम, ट्यूलिप और ग्लेडियोस...: राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन संस्थान और शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर के संयुक्त प्रयासों से अब फूलों की खेती अब वादी-ए-कश्मीर में वरदान साबित हो रही है। राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के तहत चलाई जा रही इस योजना से वर्तमान में कश्मीर की तीन घाटियों में तीन सौ हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में लिलियम, ट्यूलिप और ग्लेडियोस फूलों का सफल उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में 180 लोगों को इस कार्य का प्रशिक्षण दिया जा चुका है जबकि नौ स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है।

हिमालयी राज्यों के लिए यह परियोजना अनुकरणीय है। संस्थान ने फूलों की खेती के लिए जलवायु और स्थानीय लोगों की आजीविका संवर्धन को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर को प्रोजेक्ट के लिए चुना। यहां जलवायु भी फूल उत्पादन के लिए अनुकूल है। इसी तरह उत्तराखंड में भी इसे आजीविका का सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रयास जारी हैं।

-किरीट कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक जीबी पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान,अल्मोड़ा, उत्तराखंड

सजावटी और सुगंधित फूलों की मांग दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। स्थायित्व, आय वृद्धि और समानता के साथ कश्मीरी परिवारों को आजीविका सुरक्षा मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं।

डॉ. जेडए भाट, परियोजना प्रमुख, कश्मीर

श्रीनगर, पुलवामा और कुलगाम हैं चयनित क्षेत्र : फूलों की खेती के माध्यम से कश्मीर के युवाओं और महिलाओं की आजीविका विकास के लिए श्रीनगर, पुलवामा और कुलगाम जिलों को चयनित किया गया है। इन क्षेत्रों में अब तक पंद्रह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा चुके हैं। फूल उत्पादकों के सामने यहां अब तक जो समस्याएं सामने आ रही थीं, उनमें कम उत्पादन, पुरानी पद्धति, अच्छे बीजों का अभाव, नई तकनीक की जानकारी न होना, कीटनाशकों की जानकारी व निर्यात के लिए एजेंसियों की कमी और बिचौलियों की समस्या मुख्य थी। परियोजना के तहत इन समस्याओं को दूर करने के साथ ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। बाजार में भारी मांग वाले इन फूलों के बीज शुरुआत में नीदरलैंड्स से मंगाए गए। अब यही बीज स्थानीय स्तर पर तैयार हो रहे हैं।

युवाओं ने पूरा कर दिखाया सपना : कुलगाम से बीस किमी दूर क्वादरन गांव निवासी स्नातक पास एजाज अहमद 25 हेक्टेयर भूमि के मालिक हैं। प्रशिक्षण पाने के बाद एजाज ने लिलियम की पैदावार से एक सीजन में 75 हजार रुपये की आय अर्जित की। पुलवामा के अरसद अहमद ने भी अपने पॉलीहाउस से एक सीजन में पचास हजार रुपये की आय अर्जित की। दोनों अब फूलों की खेती को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

सोन चिरैया अभयारण्य से छिन गया 111 वर्ग किमी क्षेत्र

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में ग्वालियर के घाटीगांव सोन चिरैया अभयारण्य का दायरा कम हो गया है। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने 512 वर्ग किमी में फैले अभयारण्य के 111 वर्ग किमी क्षेत्र को डि-नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी है। अगले एक माह में सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के सामने कोई आपत्ति नहीं पहुंची तो डि-नोटिफिकेशन के आदेश जारी हो जाएंगे। गुरुवार को नई दिल्ली में हुई बोर्ड की बैठक में मध्य प्रदेश के वन अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इसी बैठक में यह फैसला लिया गया है।

अभयारण्य से सटकर पत्थरों की खदानें हैं। जहां से स्टोन कारोबार चलता है, जिसे देखते हुए अभयारण्य की सीमा से सटे क्षेत्र में खनन के मापदंड पहले ही बदले जा चुके हैं। ईको सेंसेटिव जोन की परिधि 10 से घटाकर दो किमी कर दी गई है। अब अभयारण्य से 111 वर्ग किमी एरिया भी काम करने की मंजूरी मिल गई। गुरुवार को नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संरक्षित क्षेत्रों के डि-नोटिफिकेशन के लंबित मामलों को सुना। सभी राज्यों के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। मप्र के संदर्भ में मंत्री ने घाटीगांव अभयारण्य का क्षेत्र कम करने के प्रस्ताव पर चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन यू. प्रकाशम से बात करने के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव पिछले चार साल से चल रहा था। वन विभाग ने इसके एवज में पालपुर कुनो में 404 वर्ग किमी क्षेत्र बढ़ाकर इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया है। गुजरात सरकार ने मप्र को एशियाटिक लॉयन देने के लिए कुनो को नेशनल पार्क बनाने की शर्त रखी थी।

पिछले साल भेजा था प्रस्ताव : स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने सोन चिरैया अभयारण्य का क्षेत्र कम करने का प्रस्ताव पिछले साल ही मंजूरी के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड भेजा था। वन विभाग के अफसरों का तर्क था कि अभयारण्य का बड़ा भाग निजी क्षेत्र में आता है। इसमें वन्यप्राणी संरक्षण कानून के प्रावधान लागू होने के कारण लोग अपनी जमीन बेच और खरीद नहीं पा रहे थे। इसलिए लोग खुद अभयारण्य को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।

जहां, सरकार ने सोन चिरैया अभयारण्य का क्षेत्र कम कर दिया है। वहीं, वन विभाग कैंपा फंड से सोनचिरैया को बचाने का प्रस्ताव तैयार कर चुका है। विभाग ने राशि मांगी है। इसमें जनसहयोग लेने के लिए स्थानीय लोगों को आर्थिक योजनाओं से जोड़ने की बात कर रहा है।

मध्य प्रदेश के ग्रामीणों को वित्तीय लेनदेन का पाठ पढ़ाएंगे डाकिये

नईदुनिया, भोपाल

▶ **डाक विभाग ने 'नाबार्ड' के साथ किया करार, ग्रामीणों को देंगे ऑनलाइन बैंकिंग की जानकारी**

मध्य प्रदेश में डाकिये (पोस्टमैन) अब ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता (फाइनेंशियल लिटरेसी) का पाठ भी पढ़ाएंगे। डाक विभाग ने 'नाबार्ड' के साथ इसके लिए करार किया है। नाबार्ड के विशेषज्ञ डाकिये को पहले वित्तीय साक्षरता और ऑनलाइन बैंकिंग का प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद ये डाकिये गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को ऑनलाइन लेनदेन की बारीकियां समझाएंगे। केंद्र सरकार की योजना के तहत जल्दी ही मप्र के साथ देश के अन्य राज्यों में भी व्यापक स्तर पर यह कवायद शुरू की जाएगी।

केंद्र सरकार ने हाल ही में तय किया है कि शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता के लिए विशेष मुहिम शुरू की जाए, ताकि इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक जैसी घर पहुंच सेवा देने वाले डिजिटल बैंकों की सुविधा का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ डाक विभाग ने करार किया है। ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए यह कवायद की जा रही है। सरकार का मानना है कि वित्तीय मामलों का ज्ञान स्कूल एवं कॉलेजों के माध्यम से नहीं मिल पाया है, जिससे खास तौर पर ग्रामीणों में वित्तीय साक्षरता का अभाव है।

लगेंगे शिविर और मेले : 'नाबार्ड' की मदद से डाक विभाग प्रदेश में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नेटवर्क के जरिए कम आय वाले परिवारों और छोटे व्यवसाय करने वालों को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान की सुविधा मुहैया कराएगा। यह काम प्रदेश में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सभी 42 शाखाओं के जरिए ग्रामीण इलाकों में विशेष शिविर और मेले लगाकर किया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए डाकिये को विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। प्रशिक्षण में ग्रामीणों को ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर जानकारियां दी जाएंगी। यह भी समझाया जाएगा कि अपना सीक्रेट पासवर्ड किसी से साझा न करें। ऑनलाइन धोखाधड़ी के खतरों से भी उन्हें अवगत कराया जाएगा।

नाबार्ड के साथ डाक विभाग ने हाल ही में करार किया है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में नागरिकों को ऑनलाइन बैंकिंग के संबंध में जरूरी जानकारी देने का अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा।

-एस शिवकुमार, निदेशक, डाक सेवाएं, मप्र

नई पद्धति : एक हैंडपंप उतना पानी जमीन में वापस भेजेगा जितना दूसरा जमीन से खींचता है

अब धरती की प्यास बुझा रहे सालों से सूखे पड़े हैंडपंप

हरिओम गौड़, श्योपुर

भूजल स्तर घटने के कारण सूख चुके हैंडपंपों से एक बूंद पानी नहीं निकलता। देशभर में ऐसे सूखे हैंडपंपों को मुंह चिढ़ाते हुए देखा जा सकता है। लेकिन आपसे यदि यह कहा जाए कि यही हैंडपंप धरती को लाखों लीटर पानी लौटा सकते हैं, तो सुनकर अचंभा होगा। श्योपुर, मध्य प्रदेश के आदिवासी विकास खंड कराहल के चार गांवों में ऐसा होते हुए देखा जा सकता है।

जल संरक्षण

इन चार गांवों के 11 सूखे हैंडपंप और दो कुएं जमीन के अंदर बारिश और गांव से उपयोग के बाद निकलने वाले दूषित पानी को फिल्टर करके जमीन के अंदर पहुंचा रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि क्षेत्र का भूजल स्तर लौट आया। गांव में जो हैडपंप और कुएं सूखे पड़े थे, उन्होंने पानी देना शुरू कर दिया।

दरअसल, आदिवासी बहुल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम करने वाले श्योपुर के गांधी सेवा आश्रम ने जर्मनी की संस्था जीआइजेड और हैदराबाद एफप्रो संस्था के साथ मिलकर सबसे पहले 2016 में यह प्रयोग कराहल के डाबली, अजनोई, झरेर और बनार गांव में किया। यह गांव इसलिए चुने गए क्योंकि यहां के अधिकांश हैडपंप सूख चुके थे। इन गांवों में अंधाधुंध बोर इस तरह हुए थे कि दो बीघा खेत में आधा दर्जन बोर थे। नतीजतन गांवों का भूजल स्तर गर्त में जा समाया था। गांव के सभी जलस्रोत सूख गए।

इधर, पिछले कुछ सालों से हो रहे इस प्रयोग का असर यह हुआ कि बारिश के सीजन के बाद अजनोई, डाबली, झरेर और बनार गांव की बस्तियों के आसपास के वह सूखे हैंडपंप पानी देने लगे जो दस साल से सूखे पड़े थे।

श्योपुर, मप्र : खराब हैंडपंप के चारों ओर गड्ढा बना फिल्टर प्लांट की सफाई करते मजदूर। नई दुनिया

इसे इंजेक्शन पद्धति कहते हैं। इसके तहत वर्षाजल और उपयोग में लाए जा चुके पानी को फिल्टर कर जमीन के अंदर पहुंचाया जाता है। एक सूखा हैंडपंप इतना पानी जमीन को लौटाता है, जिनता दूसरा हैडपंप जमीन से खींच लेता है।

-सत्यनारायण घोष, सोशल साइंटिस्ट, जीआइजेड संस्था

श्योपुर, मप्र के बनार, अजनोई, डाबली और झरेर गांव के अधिकांश बोर और कुएं सूख चुके थे, इसलिए इन गांवों में यह प्रयोग किया गया। परिणामों से बेहद खुशी है, सूखे हैंडपंपों के रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में तब्दील हो जाने के कारण ही दूसरे सूखे हैंडपंप अब पानी दे रहे हैं।

-जयसिंह जादौन, प्रबंधक, गांधी सेवा आश्रम, श्योपुर

इंजेक्शन पद्धति से ऐसे पहुंचा जमीन में पानी : इस पद्धति को इंजेक्शन पद्धति कहा जाता है। जर्मनी की संस्था ने श्योपुर से पहले इसका सफल प्रयोग गुजरात और राजस्थान के सूखे इलाकों में किया था। इस पद्धति के तहत हैंडपंप के चारों ओर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। हैंडपंप के केसिंग पाइप में जगह-जगह एक से डेढ़ इंच व्यास के 1200 से 1500 छेद किए जाते हैं। इसी पाइप के जरिए पानी जमीन में जाता है। इससे पहले पानी को साफ करने के लिए गड्ढे में फिल्टर प्लांट भी बनाया जाता है। इस फिल्टर प्लांट में बोल्डर, गिट्टी, रेत और कोयले जैसी चीजें परत दर परत जमाई जाती हैं। इनसे छनने के बाद ही बारिश का पानी हैंडपंप के छेदयुक्त पाइप तक पहुंचता है। पाइप पर भी जालीदार फिल्टर लगाया जाता है। इस तरह बेहद कारगर रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार हो जाता है।

एक सूखा हैंडपंप 4 लाख लीटर पानी लौटा रहा धरती को... : सूखे हैंडपंप को जलस्रोत रीचार्ज यूनिट बनाने में 45 हजार का खर्च आया है, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। अब यह खराब हैंडपंप एक साल में साढ़े तीन से चार लाख लीटर पानी जमीन के अंदर पहुंचा रहा है। रिकार्ड के अनुसार एक सामान्य हैंडपंप से हर साल 3 लाख 60 हजार लीटर तक पानी निकाला जाता है। यानी खराब हैंडपंप उतना ही पानी जमीन में वापस भेज रहा है, जितना एक सही हैंडपंप जमीन से खींच रहा है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

चीन, नेपाल, बांग्लादेश के अधिकारी करेंगे पंचकोसी परिक्रमा

प्रमोद यादव, वाराणसी : बनारस की पंचकोसी परिक्रमा अंतरराष्ट्रीय स्वरूप पाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से इस मार्ग के सुंदरीकरण, सुविधा विस्तार के बाद प्रचार-प्रसार की कवायद बाबा के प्रिय मास सावन में मूर्त रूप पाने जा रही है। काशी में शुक्रवार से शुरू होने जा रहे ट्रैवेल मार्ट (यात्रा बाजार) में इस परिक्रमा पथ को भी शामिल किया गया है। इसमें शामिल होने आ रहे चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भारत के विभिन्न प्रांतों के पर्यटन अधिकारी और इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न प्रतिभागियों को पंचकोसी परिक्रमा कराई जाएगी। उन्हें शिवनगरी की इस खास परंपरा के इतिहास और महात्म्य का महत्व बताया जाएगा।

पर्यटन विभाग व श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद ने सावन के पहले दिन से पंचकोसी परिक्रमा का पैकेज शुरू किया है। इसमें 1250 रुपये में श्रीकाशी विश्वनाथ का दर्शन, मणिकर्णिका घाट पर संकल्प, नाव से असि होते हुए पांचों पड़ावों (कंदवा, भीमचंडी, रामेश्वर, पांचो पंडवा और कपिलधारा) की यात्रा और जलपान की व्यवस्था है। ट्रैवेल आश्रम की ओर से कूच विहार काली बाड़ी में 19 से 21 जुलाई तक लगाए जा रहे पर्यटन मेला के कार्यक्रम में इसे भी शामिल कर लिया गया है।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

नारियल तेल से डेंगू रोकने का दावा फर्जी

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नारियल तेल की मदद से डेंगू को फैलने से रोका जा सकता है। इस पोस्ट को श्री साईंसुधा अस्पताल के डॉक्टर बी सुकुमार के नाम से वायरल किया जा रहा है। विश्वास न्यूज की टीम की पड़ताल में यह दावा फर्जी साबित होता है।

पड़ताल: विश्वास न्यूज की टीम ने श्री साईंसुधा अस्पताल के डॉ. बी सुकुमार से संपर्क कर अपने पड़ताल की शुरुआत की। टीम ने उनसे बात की तो पता चला कि वायरल पोस्ट फर्जी है। उन्होंने बताया कि चार सालों से यह मैसेज मेरे नाम से फैलाया जा रहा है। इसके बाद टीम ने डेंगू रोकने के संबंध में ऑनलाइन मौजूद कई रिपोर्ट्स देखीं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, डेंगू मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी प्रजाति की मादा मच्छरों से फैलता है। टीम ने इस संबंध में डॉक्टर सजीव कुमार से भी संपर्क किया। उन्होंने कहा कि नारियल तेल डेंगू का कोई इलाज नहीं है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, वर्जिन नारियल तेल में कुछ एंटीमाइक्रोबायल गुण होते हैं, लेकिन ऐसा कोई ट्रायल मौजूद नहीं है, जो यह साबित करता हो कि यह एक्टिव इंफेक्शन में कारगर है। ऐसा कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, जो यह साबित करे कि नारियल तेल डेंगू को रोक सकता है।

क्या है वायरल पोस्ट में

पोस्ट में लिखा है 'यह मैसेज आप सभी लोगों को सूचित करने के लिए है कि डेंगू फैल रहा है। कृपया अपने घुटनों से लेकर नीचे पंजों तक नारियल का तेल लगाएं। यह एंटीबॉयोटिक है। डेंगू का मच्छर घुटनों से अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। इस मैसेज को जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएं। आपका एक मैसेज कई जिंदगियां बच सकता है।' Time News International नाम के फेसबुक पेज पर इस पोस्ट को शेयर किया गया है।

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें:
9205 270 923

ट्रेनों को बेपटरी होने से बचाएगी लेजर लाइट

देवव्रत त्रिवेदी, वाराणसी : रेल अफसरों की मानें तो ज्यादातर ट्रेन हादसे हॉट एक्सल या ब्रेक जाम होने के कारण होते हैं। इस समस्या से निजात के लिए आइआइटी कानपुर ने हॉट एक्सल डिटेक्टर बॉक्स बनाया है। यह इंफ्रारेड लेजर लाइट की मदद से ट्रेनों के पहियों का तापमान और अन्य खराबी जांच लेता है। इससे ब्रेक जाम होने की समस्या से भी निजात मिलेगी। इसे आरडीएसओ लखनऊ ने परीक्षण कर इस्तेमाल की हरी झंडी दे दी।

ऐसे करता है काम: डिटेक्टर लेजर पटरियों पर लगा दिया जाता है। ट्रेन के आने का सिग्नल मिलते ही उपकरण सक्रिय हो जाता है। लेजर की किरणें जैसे ही ट्रेन के पहिए पर पड़ती है कोड के माध्यम से पहिए का तापमान व अन्य तकनीकी जानकारी उपकरण की स्क्रीन पर दर्ज हो जाती है। इसके बाद सारी जानकारी पास के स्टेशन पर लगे डाटा लॉगर में दर्ज हो जाती है। इससे पहले पहिए की जांच रेल कर्मी अपने तजुर्बे के आधार पर करते थे। पहिए और पटरी से उठने वाली आवाज और रंग पहिए की हालत बयान करते थे।

अभी हाथ के उपकरण से चल रहा काम: अभी पटरियों में लगने वाले उपकरण लग नहीं पाए हैं। ऐसे में हाथ में पकड़े जाने वाले लेजर-गन की मदद से कर्मचारी डाटा रिकार्ड करते हैं और उसे कागज पर लिखकर काम चलाते हैं।

छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाकों में खुला चलता-फिरता थाना

सुकमा जिला मुख्यालय स्थित नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष कलेक्टर चंदन कुमार, एसपी शलभ सिन्हा व एएसपी सिद्धार्थ तिवारी ने अंजोर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नईदुनिया

नईदुनिया, सुकमा

▶ **अब पुलिस पहुंचेगी गांव-गांव, मौके पर ही दर्ज करेगी एफआइआर**

▶ **कलेक्टर व एसपी ने अंजोर रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना**

नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसी कई घटनाएं होती हैं, जिनमें ग्रामीण एफआइआर तक दर्ज नहीं करवा पाते। इसके पीछे थानों की दूरी व जागरुकता की कमी वजह होती है। इसके अलावा नक्सलियों की सक्रियता के चलते भी मामले थाने तक कम पहुंच पाते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में चलता-फिरता थाना खोला गया है। इससे अब पुलिस गांव-गांव खुद पहुंचेगी। मौके पर ही एफआइआर दर्ज की जाएगी। इस चलते-फिरते थाने को नाम दिया गया है अंजोर रथ।

गत दिवस जिला मुख्यालय स्थित नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष कलेक्टर चंदन कुमार, एसपी शलभ सिन्हा व एएसपी सिद्धार्थ तिवारी ने अंजोर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंजोर का मतलब उजाला होता है। यह रथ एक चलित थाना है, जो जिले के विभिन्न इलाकों में जाएगा। खासकर ग्रामीण इलाके, जो नक्सल प्रभावित हैं। रथ के साथ चल रही टीम ग्रामीणों को यातायात के नियमों के बारे में भी जानकारी देगी। नक्सलवाद को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करेगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में यह रथ काफी कारगर साबित होगा। इस रथ के माध्यम से पुलिस अब ग्रामीणों तक पहुंचेगी।

नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां पुलिस पहुंच नहीं पाती, उन इलाकों में अंजोर रथ के माध्यम से पुलिस पहुंचेगी। रथ के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ ही नक्सलियों की आत्मसमर्पण नीति के बारे में भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा। ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनेंगे। एफआइआर भी दर्ज होगी।

-शलभ सिन्हा, पुलिस अधीक्षक, सुकमा

सरोकार

उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद ने डिकंपोजेबल कूड़े के निस्तारण का एक विकल्प बायोसीड्स डिस्क तैयार किया है

बायोसीड्स डिस्क के जरिये देश में फैलेगी हरियाली

सुरेंद्र कुमार वर्मा, पंतनगर (ऊधमसिंहनगर)

उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) ने पर्यावरण को सहेजने के साथ-साथ डिकंपोजेबल कूड़े के निस्तारण का एक विकल्प बायोसीड्स डिस्क तैयार किया है। देश में इस तरह की पहली तकनीक से कम समय में आदमी की पहुंच से दूर वाले स्थानों में सीड डिस्क फेंककर पौधरोपण किया जा सकेगा। इस एक डिस्क में जमैका चेरी, पीपल, पाकड़, बड़, बेडू, काफल, किलमोड़ा, हिसालू, बांज आदि समेत 50 तरह के पौधों के बीजों का प्रयोग किया गया है। ड्रोन के माध्यम से डिस्क को गिराने के बाद उसके टूटने पर यह बीज जगह-जगह फैल जाएंगे और बीजारोपण हो जाएगा।

यूकॉस्ट के वैज्ञानिक डॉ. सुमित पुरोहित के मुताबिक परिषद में विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों का उत्पादन पादप ऊतक संवर्धन (टिशू कल्चर) विधि से किया जा रहा है। सीड डिस्क बनाने में बीज के पौधा बनने के लिए जरूरी 13 तरह के न्यूट्रीएंट को मिट्टी के साथ गूंथकर कुछ दिनों के लिए सुखाने हेतु धूप में रख दिया जाता है। इस मिट्टी को पुनः पानी से मुलायम बनाकर उसमें बीज डालकर एक डिस्क का आकार दिया जाता है और पुनः सूखने के लिए रख देते है।

ऐसे बनाई जाती है डिस्क : बायो सीड्स डिस्क बनाने में आनुपातिक रूप से मिट्टी, बायो कचरा (घास, कागज, लुग्दी, बचा हुआ भोजन आदि) को जैव प्रौद्योगिक विधि खाद में तब्दील कर उसमें बीज मिला दिया जाता है। निर्धारित तापमान व नमी में इसे डिस्क का आकार दिया जाता है।

डिस्क को बंजर भूमि या व्यक्ति की पहुंच से दूर कहीं भी फेंक दिया जाता है। बरसात में पानी की उपयुक्त मात्रा एवं मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों के कारण बीजों को अंकुरित होने में सहायता मिलती है।

▶ **उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) के वैज्ञानिकों ने ईजाद की तकनीक**

▶ **इंसान की पहुंच से दूर वाली जगहों पर ड्रोन से पहुंचाई जाएगी डिस्क**

▶ **50 तरह के पौधों के बीजों का प्रयोग किया गया है।**

उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) ने तैयार की बायोसीड्स डिस्क। ड्रोन के जरिए इस डिस्क से बीज फेंककर उन स्थानों को भी हराभरा किया जा सकता है, जहां पौधरोपण मुश्किल हो। जागरण

बायोसीड्स डिस्क के निर्माण में डिकंपोजेबल कूड़ा, 13 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी, बीज आदि प्रयोग किया गया है। डिस्क का आकार उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तय किया गया है। ताकि इसका प्रयोग पहाड़, मैदान कहीं भी हो सके।

-डॉ. राजेंद्र डोभाल, निदेशक यूकॉस्ट, उत्तराखंड

मौसम विशेष

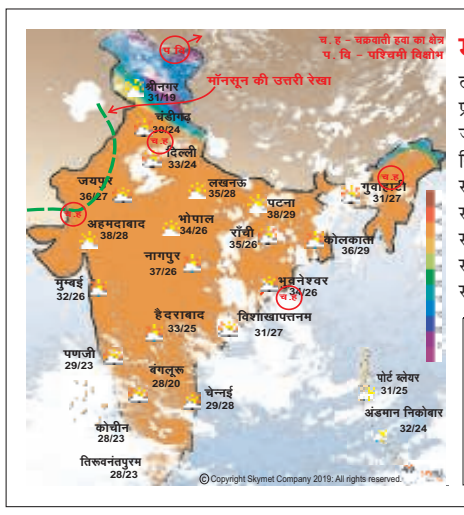

दक्षिणी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज के साथ हल्की वर्षा जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली के कुछ भागों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क व गर्म बना रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/27/व	अहमदाबाद	38/28/व
कोलकाता	36/28/व	बड़ौदा	37/26/आंबा
चेन्नई	36/25/व	नागपुर	35/26/व
हैदराबाद	32/24/व	इन्दौर	34/24/आंबा
बंगलूरू	28/20/व	रांची	36/27/व
त्रिवेन्द्रम	28/22/व	पटना	36/28/आंबा
गुवाहाटी	31/28/व	जमशेदपुर	38/28/आंबा
गंगटोक	19/11/व	पुणे	25/23/व

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 19 जुलाई 2019
आजकल
16
www.jagran.com

भारत के चौदह निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पचास साल पूरे

1969 में आज ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के चौदह सबसे बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही राष्ट्रीयकरण हुआ था। 85 फीसद बैंक जमा पर इन्हीं का नियंत्रण था।

टिहरी गढ़वाल रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ

1949 को आज ही के दिन उत्तराखंड राज्य में स्थित टिहरी गढ़वाल रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। इस रियासत पर कत्यूरी, चांद और शाह के वंशजों ने राज किया। ब्रिटिश शासन के दौरान यह रियासत पंजाब हिल्स स्टेट्स एजेंसी के अधीन थी।

मंगल पांडे ने फूंका था स्वतंत्रता की लड़ाई का पहला बिगुल

अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर समूची अंग्रेजी हुकूमत के सामने चुनौती पेश करने वाले मंगल पांडे का जन्म 1827 में आज ही उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव नगवा में हुआ था। वह कलकत्ता (अब कोलकाता) के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों का विरोध करने और एक अंग्रेज अधिकारी को घायल करने पर उन्हें 8 अप्रैल, 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे द्वारा फैलाई गई विद्रोह चिंगारी आगे जाकर भारतीय स्वतंत्रता की सूत्रधार बनी। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1984 में एक डाक टिकट भी जारी किया था।

इधर-उधर की

सौ वर्ष की आयु में भी कर रहे बागवानी

बुडापेस्ट, एजेंसी : हंगरी के रहने वाले ज्योर्गी बालिंट सौ वर्ष की आयु में भी बागवानी कर रहे हैं। हर रोज हजारों लोग फेसबुक पर उनसे इस संदर्भ में सलाह मांगते हैं। उनके पोते-पोती उनकी वेबसाइट पर लोगों के सवालों के जबाव देने में सहायता करते हैं। उनके फेसबुक पर करीब साढ़े चार लाख प्रशंसक हैं। 1960 से बागवानी कर रहे बालिंट बागवानी पर कई किताबें भी लिख चुके हैं। उन्होंने अपने घर के बाहर बड़े करीने से बाग सजाया हुआ है। इस बाग में चेरी का एक पेड़ भी है, जो लगभग उन्हीं की उम्र का हो चला है। वह प्रकृति प्रेम को अपनी लंबी आयु का राज बताते हैं। बालिंट का मानना है कि आधुनिक समाज को प्रकृति के साथ नजदीकी बनाए रखनी चाहिए। वह हर किसी को बगीचा लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बालिंट के मुताबिक खेती करना सबसे अद्भुत काम है।

निजता पर भारी ना पड़ जाए फेसएप

रहें सतर्क ▶ खास एल्गोरिदम की मदद से एप्लीकेशन दिखाती है बुढ़ापे की तस्वीर

न्यूयॉर्क टाइम्स से

अमेरिकी सीनेटर ने एफबीआइ और एफटीसी से जांच की मांग की

वाशिंगटन : इंटरनेट की दुनिया में कब क्या ट्रेंड करने लगे, कोई नहीं जानता। कभी लोग राजनेताओं से अपनी शक्ल मिलाने लगते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अपने लिए पद तलाशने लगते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित एल्गोरिदम पर काम करने वाले ऐसे कई एप हैं, जो लोगों को लुभाते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक एप सोशल मीडिया पर छाया है, जिसका नाम है फेसएप। यह एप खास एल्गोरिदम की मदद से आपकी तस्वीर को कुछ ऐसा बना देता है, जैसे आप शायद कुछ दशक बाद दिखेंगे।

इस एप को लोग हाथोंहाथ ले रहे हैं। आम यूजर्स ही नहीं, बल्कि बड़ी फिल्मी हस्तियां और अन्य चर्चित लोग भी इस एप की मदद से बनी बुढ़ापे की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में यह एप सोशल मीडिया की सनसनी बन गया है। इसके बढ़ते ट्रेंड के साथ ही इसके खतरे को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कई लोगों को संदेह है कि यह एप लोगों की निजी जानकारियां चुरा सकता है। अमेरिका में सीनेटर चक शुमर ने तो इस पर चिंता जताते हुए जांच की मांग भी कर दी है। उन्होंने संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआइ) और उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने वाली सरकारी इकाई एफटीसी से इस एप के खिलाफ जांच की अपील की है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता के लिए खतरा बताया है।

आम लोग ही नहीं चर्चित हस्तियां भी कर रही हैं फेसएप का उपयोग। फाइल

क्या है डर की वजह ? : इस एप को लेकर अमेरिकी सीनेटर के डर की वजह है इसकी लोकेशन। इस एप को रूस में सेंट पीटर्सबर्ग स्थित वायरलेस लैब कंपनी ने विकसित किया है। चक शुमर के डर की असली वजह यही है। उनका कहना है कि यह एप मूलरूप से रूस का है और कंपनी कब अमेरिकी नागरिकों का डाटा किसी तीसरे पक्ष को या विदेशी सरकारों को मुहैया करा दे, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने शंका जताई है कि अगर अमेरिकी नागरिकों के संवेदनशील डाटा किसी ऐसे देश के हाथ लग गए, जो पहले से ही अमेरिका के खिलाफ साइबर युद्ध में लगा है, तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। इतना ही नहीं, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने राष्ट्रपति चुनाव अभियान से जुड़े सभी सदस्यों को तत्काल यह एप अपने फोन से हटाने का अलर्ट जारी किया है।

क्या है विशेषज्ञों की राय ? : ज्यादातर विशेषज्ञ एप से किसी तरह का खतरा होने की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सुरक्षा से जुड़े शोध में सक्रिय फ्रांस के बाप्टिस्ट रॉबर्ट ने कहा, 'यह एप केवल मेरे स्मार्टफोन के मॉडल, उसकी डिवाइस आइडी और एंड्रॉयड वर्जन के बारे में जानकारी भेजता है। किसी भी एप के लिए यह बेहद सामान्य बात है।' उनका कहना है कि इस एप के पास बस एक ही चीज अतिरिक्त है, वह है आपकी तस्वीर, जिसकी मदद से आप अपनी बुढ़ापे वाली शक्ल बनाते हैं।

कंपनी ने दी है सफाई : सुरक्षा के सवाल उठने के बाद कंपनी ने भी इस बारे में सफाई दी है। कंपनी का कहना है कि यूजर का डाटा किसी भी तीसरे पक्ष से शेयर नहीं किया जाता है। यूजर की तस्वीर को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से उसकी बुढ़ापे की तस्वीर में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में तस्वीर को क्लाउड पर स्टोर किया जाता है, ताकि यूजर को बार-बार इसे अपलोड ना करना पड़े।

फिल्म रिव्यू

...पर किंग बनते-बनते रह गई

द लॉयन किंग

वॉयसओवर : शाह रुख खान, आर्यन खान, असरानी, आशीष विद्यार्थी, श्रेयस तलपड़े, संजय मिश्रा
निर्देशन : जॉन फेवरु
अवधि : 2 घंटे

वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स लगातार अपनी सुपरहिट एनिमेटेड फिल्मों का लाइव एक्शन बना रहा है। उसने अब वर्ष 1994 में रिलीज एनीमेटेड फिल्म 'द लॉयन किंग' का लाइव एक्शन बनाया है। क्लासिक एनिमेटेड फिल्म 'द लॉयन किंग' की कहानी उत्तराधिकार व सत्ता को हासिल करने के नापाक मंसूबों और विनाशवाद जैसे विषयों को समेटते हुए एक शेर के परिवार और कुछ जानवरों के ईदगिर्द गढ़ी गई थी। नई फिल्म भी उसी कहानी को दोहराती है।

कहानी गौरवभूमि के राजा मुफासा और उनके बेटे सिंबा की है। पिता बचपन में सिंबा को बहुप्रजाति वाले राज्य से परिचित कराते हैं। उनकी मां सराबी और उसके भविष्य की प्रेमिका नाला उन्हें देखते हैं। सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगा मुफासा का भाई स्कार षड्यंत्र के तहत अपने भाई को मार देता है और हत्या का इल्जाम भतीजे पर मढ़ देता है। शेनजी और उसके लकड़बग्घों की सेना इस षड्यंत्र में उसका साथ देते हैं। सिंबा गौरवभूमि से दूर चला जाता है। वयस्क होने के बाद वह अपनी सत्ता को कैसे दोबारा हासिल करता है, यह फिल्म में दिखाया गया है। जॉन फेवरू निर्देशित इस फिल्म के हिंदी संस्करण की डबिंग रियल लाइफ के पिता-पुत्र बॉलीवुड के किंग खान शाह रुख और उनके बेटे आर्यन खान ने की है। शाह रुख ने मुफासा की, जबकि आर्यन ने सिंबा की डबिंग की है। शुरुआत में दोनों की जुगलबंदी को स्क्रीन पर सुनना अच्छा लगता है। हालांकि कई बार दोनों की आवाज काफी मिलती-जुलती सुनाई देती है। फिल्मों के विजुअल्स बेहद खूबसूरत हैं। बस कहानी प्रभावहीन हो गई है।

जॉन फेवरू ने अपनी सुपरहिट फिल्म 'जंगल बुक' की तरह यहां पर भी बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया है। हालांकि वह 'द लॉयन किंग' को उसकी टक्कर की नहीं बना पाए हैं। मूल फिल्म में इमोशन, रंगीन एनिमेशन, जानवरों की भाव-भंगिमाओं और संगीत ने उसे कालजयी बनाया था। जॉन फेवरू की फिल्म में इनकी कमी साफ झलकती है। सिंबा के वयस्क होने और अपने राज्य को दोबारा हासिल करने के वृत्तांत को लेखक-निर्देशक रोमांचक और भावनात्मक नहीं बना पाए हैं। हिंदी में कहानी को रोचक बनाने के लिए किरदारों के साथ प्रयुक्त भोजपुरी भाषा जबरन थोपी गई लगती है। संगीत भी प्रभावी नहीं बन पाया है।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

शोध अनुसंधान

त्वचा रोग पीड़ित नवजात में खाद्य एलर्जी का खतरा

एक्जिमा के शिकार नवजात बच्चों में भविष्य में खाद्य एलर्जी और अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। हालिया शोध में यह बात सामने आई है। एक्जिमा एक प्रकार का त्वचा रोग है, जिसमें त्वचा सूख जाती है और बच्चे को खुजली होती है। विज्ञान पत्रिका 'साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन' में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, एक्जिमा के मरीजों की सूखी त्वचा अस्थमा और एलर्जी जैसी समस्याओं का कारण बनती है। ऐसी स्थिति में बच्चों की त्वचा को नरम रखने के लिए शुरुआत से ही मॉइस्चराइजर लगाना लाभकारी हो सकता है। यह कदम एक्जिमा के साथ-साथ खाद्य एलर्जी एवं एलर्जी से जुड़ी अन्य परेशानियों से बचा सकता है। शोधकर्ता डॉ. डोनाल्ड लुंग ने कहा, 'अगर भोजन के कण पाचन तंत्र से इतर त्वचा के रास्ते शरीर में पहुंचें, तो एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। एक्जिमा के मरीजों की फटी त्वचा आगे चलकर अक्सर ऐसी एलर्जी का कारण बन जाती है।' - एएनआइ

चींटी जैसे रोबोट की मदद से हो सकेगा इलाज

कोई भी अपने शरीर पर चींटी चलना शायद ही पसंद करे, लेकिन आने वाले दिनों में शरीर के अंदर भी चींटियां रेंगती नजर आ सकती हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने चींटी के आकार का ऐसा रोबोट तैयार किया है, जो शरीर के अंदर जाकर इलाज में मदद कर सकता है। अमेरिका के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने इस विशेष रोबोट को तैयार किया है। 3-डी प्रिंटिंग की मदद से तैयार इस रोबोट का आकार दुनिया की सबसे छोटी चींटी जितना है। यह रोबोट किसी अल्ट्रासाउंड या छोटे स्पीकर से पैदा होने वाले कंपन (वाइब्रेशन) की मदद से चलता है। शोधकर्ताओं ने बताया अभी जो प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं, उनमें से कुछ छह पैर वाले और कुछ चार पैर वाले हैं। इन्हें अलग-अलग फ्रिक्वेंसी पर चलने के लिहाज से तैयार किया गया है। जरूरत के हिसाब से सतह पर इनकी पकड़ भी बनी रहती है। - एएनआइ

वैज्ञानिकों ने निकाला महंगे बल्ले का तोड़

कंप्यूटर की मदद से तैयार किया बेहतरीन और सस्ता बल्ला एल्गोबैट

नई दिल्ली, प्रेट्र : विराट कोहली, इयोन मोर्गन या स्टीव स्मिथ बनने की ख्वाहिश पाले लाखों बच्चे महज इसलिए अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास बेहतर बल्ले नहीं होते। लेकिन, अब वैज्ञानिकों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। उन्होंने कंप्यूटर की मदद से विश्व का सर्वश्रेष्ठ, मगर बेहद सस्ता बल्ला बनाने बनाने का उपाय खोज लिया है।

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एल्गोरिदम (एक तरह का गणितीय नियम) विकसित किया है जिसकी मदद से बल्ले की ज्यामिति यानी आकार प्रकार को उन्नत किया गया है और इससे खिलाड़ियों को अधिक आसानी से गेंद पर करारा प्रहार करने में मदद मिलेगी। उच्च क्षमता वाला यह 'एल्गोबैट' बाजार में उपलब्ध बेहतरीन बल्ले की तरह है, मगर दाम बहुत कम है। परियोजना के प्रमुख और प्रतिष्ठित प्रोफेसर फिल इवांस ने पाया कि दुनिया में करीब 10 लाख लोग क्रिकेट का खेल खेलते हैं और ढाई अरब की आबादी इसे देखती है जिसकी वजह से क्रिकेट, फुटबॉल के बाद लोगों का सबसे पसंदीदा खेल बन गया है। इवांस ने कहा कि जो बच्चे इस खेल में अच्छा करना चाहते हैं, उनके आगे बढ़ने में बढ़िया बल्ले की कीमत बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे बच्चों के लिए एल्गोबैट एक ऐसा तरीका हो सकता है जिसकी मदद से वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और गेंद को मैदान से बाहर का रास्ता दिखा सकेंगे। विलो की लकड़ी से बढ़िया गुणवत्ता के जो बल्ले बनते हैं उनकी कीमत सैकड़ों में ही नहीं कई बार हजारों डॉलर के पार तक चली जाती है। पर अब ऐसा बल्ला महज 30-40 डॉलर (करीब दो से तीन हजार रुपये) में एक उभरते सितारे के पास हो सकेगा और क्रिकेट की दुनिया को दूसरे तेंदुलकर, गावस्कर मिल सकेंगे। एल्गोरिदम को लिखने वाले पीएचडी स्कॉलर सदेग मजलूमी ने ईमेल से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए बैट की कंप्यूटर मॉडलिंग और ऑप्टीमाईजेशन एल्गोरिदम का प्रयोग किया। इस तरह बने बल्ले को बाजार में आने में आने में अभी वक्त है।

ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ऐसी एल्गोरिदम विकसित की है, जिससे सर्वश्रेष्ठ बल्ले तैयार किए जा सकते हैं। फाइल

वैज्ञानिकों ने कहा कि अच्छे रन बनाने के लिए खिलाड़ी के पास रणनीतिक कुशलता तो होनी ही चाहिए। साथ ही यदि अच्छे और बेहतर बल्ले भी उपलब्ध हों तो वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस बल्ले के बाजार में आने से खिलाड़ी क्रिकेट के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर सकेंगे और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।

अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियों को बचाएगा 'रिस्वेराट्रोल'

बोस्टन, प्रेट्र : रेड वाइन में पाया जाने वाला यौगिक 'रिस्वेराट्रोल' अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियों को सिकुड़ने से बचा सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने चूहों पर इस यौगिक का सफल परीक्षण करने के बाद कहा कि 'रिस्वेराट्रोल' भविष्य में मंगल मिशन पर जाने वाले वैज्ञानिकों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

फ्रंटियर इन साइकोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि 'रिस्वेराट्रोल' की मदद से मंगल के कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण में भी चूहों की मांशपेशियां जस-की-तस बनी रहीं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मैरी मोर्ट्रेक्स ने कहा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद अंतरिक्ष में केवल तीन सप्ताह में ही मनुष्य की कई मांसपेशियां एक तिहाई सिकुड़ जाती हैं। ये ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो विपरीत मौसम को शरीर को उसके अनुकूल रखने में मदद करती हैं। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों का काम प्रभावित होता है, लेकिन 'रिस्वेराट्रोल' की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल मिशन पर भी सुरक्षित रूप से काम करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तित्व के बारे में बता सकता है पैसे खर्च करने का तरीका : अध्ययन

लंदन, प्रेट्र : किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसकी पहचान होता है और व्यक्तित्व को पहली नजर में समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा है कि किसी व्यक्ति के पैसे खर्च करने के व्यवहार के जरिये उसके व्यक्तित्व का पता चल सकता है। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने दो हजार लोगों के खर्च करने के व्यवहार का विश्लेषण कर यह दावा किया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि 20 लाख से अधिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जब लोग किसी विशेष वर्ग के उत्पादों पर पैसा खर्च करते हैं, तो इससे यह पता चलता है कि वे कितने भौतिकवादी हैं या खुद पर नियंत्रण रखने की उनके पास कितनी क्षमता है। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से जुड़े जोए ग्लेडस्टोन ने कहा कि दुनिया भर में ज्यादातर लोग अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के जरिए भुगतान करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि इन खर्चों के पैटर्न का अध्ययन कर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है।

टारोल्स नदी में हैं दुनिया के सबसे ज्यादा मगरमच्छ

दुनिया में लोगों को अजीबो-गरीब शौक होते हैं। यह जनाब हैं मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका के जुआन केर्डस, उन्हें मांसाहारी खूंखार मगरमच्छों को भोजन कराने का शौक है। वे मगरमच्छों के साथ इस कदर घुल-मिल गए हैं कि उन्हें इस तरह किस करने में भी डर नही लगता। यहां स्थित टारोल्स नदी, दुनिया में इकलौती ऐसी नदी हैं, जहां मगरमच्छों की सर्वाधिक संख्या है। मगरमच्छों को देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग दुनियाभर से यहां आते हैं। रायटर

व्हाइट ड्रेस डिनर

न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन के बोरो नेल्सन रॉकफेलर पार्क में करीब 5500 लोग 'डिनर एन ब्लैंक' (व्हाइट ड्रेस डिनर) में शामिल हुए। इसमें शामिल मेहमानों और स्थल का चुनाव ऑनलाइन किया जाता है। इसमें शामिल मेहमानों के अलावा सभी चीजें सफेद रंग की होती हैं। इसकी शुरुआत 1988 में फ्रांस के शहर पेरिस से हुई थी, लेकिन अब दुनिया के अनेक देशों में इसका आयोजन होता है। इस इवेंट की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है। रायटर

सप्लीमेंट से बढ़ता है स्ट्रोक का खतरा

▶ कैल्शियम और विटामिन डी का मिश्रण हृदय के लिए है खतरनाक

▶ एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित हुआ अध्ययन

नई दिल्ली, आइएएनएस : शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए लोग अक्सर विटामिन, मिनरल (खनिज पदार्थ) समेत कई अन्य तरह के सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन हाल ही में हुए कई अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि सप्लीमेंट हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक भी हैं।

स्वास्थ्य पत्रिका 'एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन' में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, कैल्शियम और विटामिन डी का संयोजन (मिश्रण) स्ट्रोक का जोखिम बढ़ा सकता है। इस अध्ययन के लेखक और वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर सफियू खान ने कहा कि हालांकि, अब तक विटामिन डी और कैल्शियम को अलग-अलग लेने से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने का कोई भी सबूत नहीं है। हो सकता है हृदय संबंधी रोग किसी अन्य कारणों की वजह से भी हो रहे हों, लेकिन हमारा विश्लेषण यह बताता है सप्लीमेंट और हृदय रोगों के बीच कुछ न कुछ संबंध जरूर है। उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट हृदय रोगों के जोखिम कम करने के बजाय और बढ़ा देते हैं, जिससे लोगों की मौत तक हो जाती है।

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने दुनिया भर से 992,129 प्रतिभागियों का डाटा एकत्र कर उसका विश्लेषण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि कम नमक वाला भोजन, ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य सप्लीमेंट शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसन के इरिन मिकोस ने कहा कि लोगों को अपने शरीर के लिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन और सप्लीमेंट लेने की बजाय अपने खानपान पर ध्यान देना चाहिए। यदि वह अपने आहार में स्वस्थ भोजन लेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अध्ययन के दौरान पता चला कि सप्लीमेंट लेने वालों में युवा वर्ग की संख्या सर्वाधिक है, जो कि चिंता का विषय भी है।

वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अध्ययन कर सप्लीमेंट के खतरों के प्रति आगाह किया है। फाइल

उन्होंने कहा कि वर्तमान में लोगों की जीवनशैली काफी बदल गई है, जिसके कारण लोग संतुलित आहार नहीं ले पाते और बीमार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए कई बार लोग सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन यह शरीर के लिए बेहद घातक सिद्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जितना हो सके इनके प्रयोग से बचना चाहिए।

सावधान

लोगों तक पहुंचने तक पीने लायक नहीं रहता बोतलबंद पानी, प्लास्टिक के कणों के साथ पानी की गुणवत्ता का नहीं चल पाता पता, पैकिंग के दौरान प्रदूषित होता है पानी

प्लास्टिक की बोतल से पानी नहीं, कैंसर पी रहे आप !

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला

लोग जिस बोतलबंद पानी को सुरक्षित मानकर पैसे देकर खरीद रहे हैं, वो उन्हें बीमार कर रहा है। न्यूयार्क की स्टेट यूनिवर्सिटी में हुए शोध में दावा किया गया है कि बोतलबंद पानी में प्लास्टिक के कण होने के साथ कई तरह के रसायन शामिल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक हैं। बोतलबंद पानी के सेवन से कैंसर तक हो सकता है।

शोधकर्ताओं ने भारत के अलावा अमेरिका, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मैक्सिको, केन्या व लेबनान के बोतलबंद पानी के नमूनों की जांच की। शोधकर्ताओं का मानना है कि बोतलबंद पानी में प्रदूषण पैकिंग के दौरान पनपता है। सामान्य पानी को उबाल कर इस्तेमाल करने से उसमें जो भी कीटाणु होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बोतलबंद पानी में प्लास्टिक के जो घातक कण होते हैं, उनका कोई हल नहीं है। बोतलबंद पानी की प्लास्टिक की बोतलें व पाउच पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं।

अधिक तापमान से पानी में घुलते हैं प्लास्टिक के कण : प्लास्टिक की बोतल में बंद पानी की बोतलें जब कंपनियों से निकल कर दुकानों व गोदामों में जाने के लिए ट्रकों में लोड होती हैं तो उस समय बाहर का तापमान अगर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस है तो ट्रक के अंदर का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है। उस दौरान कई रसायनों से बनी प्लास्टिक की बोतलों से इनका रिसाव होने लगता है और यह पानी में मिल जाता है। इसके अलावा पानी में प्लास्टिक के कण भी घुल जाते हैं। इससे पानी प्रदूषित हो जाता है। पानी की जांच की तो व्यवस्था की जाती है लेकिन जिन बोतलों, प्लास्टिक की थैलियों या कप में पानी भरा जाता है, उनकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है।

09 देशों में बेची जा रही 11 ब्रांड की 250 बोतलों को टेस्ट किया न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने

खतरनाक है बोतल बंद पानी। प्रतीकात्मक

01 लीटर बोतलबंद पानी में शोधकर्ताओं को मिले हैं 4500 से 10390 प्लास्टिक के कण

बोतलबंद पानी को लेकर शिकायत आने पर सैंपल लेकर जांच की जाती है। सैंपल सही न पाए जाने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई होती है। लोगों को चाहिए कि ऐसी बोतलों को इस्तेमाल के बाद नष्ट कर या छेद कर फेंका जाए जिससे उनका दुरुपयोग न हो सके।

-नरेश कुमार लट्ठ, निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा विनियमन निदेशालय

सेहत के लिए रसायन हानिकारक : देश के अधिकांश राज्यों में कंपनियां पानी की बोतलों के लिए पीवीसी पाइपों में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक व बीपीए पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक व बिसफेनोल नामक रसायनों का प्रयोग करती हैं। ये रसायन सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं।

प्लास्टिक बोतल में पानी के नुकसान : जब प्लास्टिक बोतलें गर्मी के संपर्क में आती हैं तो इनसे 55 से 60 जहरीले रसायन निकलते हैं जो पानी में मिल जाते हैं। ऐसा पानी सेहत के लिए हानिकारक होता है। अधिकतर लोग गर्म खाने व पानी को भी प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं। लेकिन खाना व पानी गर्म होने की वजह से प्लास्टिक से जहरीले रसायन इसमें मिल जाते हैं। यदि गर्म खाना रेफ्रिजरेटर में भी रखा जाए तो भी खाने की गर्मी के कारण जहरीले रसायन मिलने से वह नुकसान पहुंचाता है। ऐसा खाना खाने से हार्मोन का असंतुलन हो सकता है। इससे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज (पीसीओडी), ओवरी से संबंधित समस्याएं, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर आदि कई रोग हो सकते हैं।

बरतें एहतियात : पानी पीने से पहले उसे प्लास्टिक बोतल से शीशे की बोतल, स्टेनलेस स्टील या तांबे के बर्तन में डालें। खाने को प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं बल्कि स्टेनलेस स्टील या शीशे के बर्तन में रखें। यदि आप बाहर खाना चाहते हैं तो किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाएं न कि खाना घर पर मंगवाने के लिए ऑर्डर करें। घर पर खाना प्लास्टिक के बर्तन में लाया जाएगा जो सेहत के लिए घातक होगा। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने बच्चों को प्लास्टिक की बोतल में दूध न पिलाएं। इसके लिए शीशे की बोतल सबसे बेहतर उपाय है।

खास तकनीक से चीन ने किया मच्छरों का सफाया

▶ रेडिएशन की मदद से मच्छरों को नपुंसक बनाकर किया जाता है खात्मा

▶ कृषि क्षेत्र में कीटों पर 60 साल से हो रहा है इस तकनीक का प्रयोग

वाशिंगटन, प्रेट्र : मच्छरों से होने वाली बीमारियां दुनियाभर में असमय मौत का बड़ा कारण हैं। अब चीन ने इससे निपटने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहां वैज्ञानिकों ने एक खास तकनीक की मदद से दो द्वीपों से मच्छरों का सफाया करने में कामयाबी पाई है। इस काम में दो साल का वक्त लगा।

विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के मुताबिक, चीन के वैज्ञानिकों ने इस काम के लिए इनकंपैटिबल और स्टराइल इंसेक्ट तकनीक (आइआइटी/एसआइटी) को मिलाकर प्रयोग किया। इनकी मदद से गुआंगझाओ में पर्ल नदी के किनारे स्थित दो द्वीपों से एशियन टाइगर कही जाने वाली मच्छरों की प्रजाति को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। एसआइटी ऐसी तकनीक है, जिसमें रेडिएशन की मदद से नर मच्छरों को नपुंसक बना दिया जाता है। ऐसा होने के बाद धीरे-धीरे कुछ समय में मच्छर पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में चीन के वैज्ञानिकों ने वोल्बाचिया बैक्टीरिया की भी मदद ली। शोधकर्ताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में चीन एक बड़े शहरी इलाके में इस तकनीक का परीक्षण करने की तैयारी में हैं। दुनियाभर में जिस तरह से मच्छरों के कारण जीका, मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियां फैल रही हैं, उसे देखते हुए इस तकनीक का इस्तेमाल और भी अहम हो गया है। यह विभिन्न रसायनों और पारंपरिक तरीके के प्रति प्रतिरोधी हो चुके मच्छरों के मामले में भी कारगर हो सकता है।

कृषि क्षेत्र में कुछ कीटों को खत्म करने के लिए एसआइटी का प्रयोग दशकों से हो रहा है, लेकिन मच्छरों को लेकर इनका प्रयोग करने की कोशिश हाल ही में हुई है।